भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

अगस्त 2022

खंड 76 अंक 8

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देब प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितिकंठ पट्टनायक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बरन दास
पुलस्त्य बंद्योपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2022

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **https://bulletin.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

भाषण

भविष्य की बैंकिंग
शक्तिकांत दास 13

75वें वर्ष में भारत
माइकल देबब्रत पात्र 19

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 35

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य 77

तूफानी समुद्र में एक स्थिर जहाज:
हाल के दिनों में एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण 87

भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्काल निगरानी 103

निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और
2022-23 के लिए दृष्टिकोण 119

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर में अस्थिरता 131

वर्तमान सांख्यिकी **143**

हाल के प्रकाशन **196**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

हम अगले दस दिनों में अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएंगे। यह हम सभी के लिए एक महान क्षण है। मैं इस अवसर पर इस ऐतिहासिक सुअवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लगातार झटके, वैश्वीकृत मुद्रास्फीति की वृद्धि, वित्तीय स्थितियों के कड़े होने, अमेरिकी डॉलर की तेज बढ़ोत्तरी और भौगोलिक क्षेत्रों में कम वृद्धि के संदर्भ में अपना असर डाल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहित बहुपक्षीय संस्थानों ने वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमानों में अधोगामी संशोधन किया है और मंदी के बढ़ते जोखिमों को उजागर किया है। चिंताजनक रूप से, मुद्रास्फीति का वैश्वीकरण व्यापार के अवैश्वीकरण के साथ मेल खा रहा है। महामारी और युद्ध ने अधिक विखंडन, आपूर्ति शृंखलाओं को फिर से शुरू करने और पूंजी प्रवाह की छंटनी की प्रवृत्ति को प्रज्ज्वलित किया है, जो वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए दीर्घकालिक चुनौतियां उत्पन्न करेगा।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए, इन जोखिमों को बढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें घरेलू वृद्धि-मुद्रास्फीति समझौताकारी समन्वयन (ग्रोथ-इन्फ्लेशन ट्रेड-ऑफ) और विश्व भर में मौद्रिक नीति के सबसे समकालिक कड़ेपन से स्पिलओवर, दोनों का सामना करना पड़ता है। एसएमई एक साथ बाहरी वित्तीय स्थितियों, पूंजी बहिर्वाह, मुद्रा मूल्यह्रास और आरक्षित निधि घाटे के तेजी से कड़े होने का सामना कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऋण और चूक के बढ़ते बोझ का भी सामना कर रहे हैं। उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतें और कमियाँ उनकी आबादी को आजीविका की असुरक्षा के प्रति संवेदनशील बना रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से जूझ रहे हैं। रुक-रुक कर सुधार के बावजूद वित्तीय बाजार असहज बने हुए हैं। हमने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक (3 अगस्त तक) 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े पोर्टफोलियो का बहिर्वाह देखा है। तथापि, आईएमएफ के अनुसार, मजबूत और प्रत्यास्थ आधार सहित वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में कमी के संकेत के साथ, 2022-23 के दौरान भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है। प्रेषण के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से चालू खाता घाटे को स्थायी सीमा के भीतर रखने की उम्मीद है। 2021-22 के दौरान जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य ऋण में गिरावट, जीडीपी अनुपात की तुलना में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति और ऋण सेवा अनुपात, बाहरी झटकों के विरुद्ध लचीलापन प्रदान करते हैं[1]। वित्तीय क्षेत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत और मजबूत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, निवल वायदा आस्तियों द्वारा पूरक, वैश्विक स्पिलओवर के विरुद्ध बीमा प्रदान करता है। हमारा छत्र मजबूत है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 3 से 5 अगस्त को बैठक की और समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावनाओं की समीक्षा की। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.15 प्रतिशत; तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 5.65 प्रतिशत पर समायोजित की गई है। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

अब मैं एमपीसी के नीतिगत दर और रुख पर उसके निर्णयों के औचित्य पर संक्षेप में बताता हूं। मौजूदा प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के विरुद्ध, एमपीसी ने पाया कि घरेलू आर्थिक गतिविधि लचीली है और एमपीसी के जून के संकल्प की तर्ज पर व्यापक रूप से प्रगति कर रही है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में अपने उछाल से कम हुई है, लेकिन यह असुविधाजनक रूप से उच्च और लक्ष्य की ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। मुद्रास्फीति

* गवर्नर का वक्तव्य: 5 अगस्त, 2022

[1] बाह्य ऋण/ जीडीपी अनुपात मार्च 2021 में 21.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2022 में 19.9 प्रतिशत हो गया, जबकि निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति/ जीडीपी अनुपात (अर्थात् अनिवासियों के निवल दावे) में इसी अवधि के लिए (-) 13.2 प्रतिशत से सुधार होकर (-) 11.6 प्रतिशत हो गया। ऋण सेवा अनुपात 2020-21 में 8.2 प्रतिशत से कम हो कर 2021-22 में 5.2 प्रतिशत हो गया।

गवर्नर का वक्तव्य

के दबाव व्यापक-आधारित हैं और मुख्य मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता मुद्रा बाजार सहित घरेलू वित्तीय बाजारों पर प्रभाव डाल रही है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति बढ़ रही है।

मुद्रास्फीति के, दूसरी और तीसरी तिमाही में ऊपरी सीमा से ऊपर रहने की प्रत्याशा के साथ, एमपीसी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निरंतर उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को अस्थिर कर सकती है और मध्यम अवधि में वृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः, एमपीसी ने निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर रखने और दूसरे दौर के प्रभावों को शामिल करने के लिए मौद्रिक निभाव को अंशशोधित रूप से वापस लेने की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे वृद्धि का समर्थन करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

वृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

वृद्धि

घरेलू आर्थिक गतिविधियां व्यापक होने के संकेत दे रही हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा और जलाशय का स्तर सामान्य से ऊपर है; खरीफ की बुवाई अच्छी प्रगति कर रही है, हालांकि असमान वर्षा के वितरण[2] के कारण यह पिछले वर्ष के स्तर से थोड़ा कम है। मांग पक्ष पर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, घरेलू हवाई यात्री यातायात और यात्री वाहनों की बिक्री जैसे संकेतक शहरी मांग में सुधार का संकेत देते हैं। हालांकि, ग्रामीण मांग संकेतकों ने मिश्रित संकेतों का प्रदर्शन किया - जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई, ट्रैक्टर की बिक्री जून में उच्च आधार पर संकुचित हुई। रेलवे माल ढुलाई यातायात, पोर्ट माल ढुलाई यातायात, ई-वे बिल, टोल कलेक्शन और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जैसे सेवा क्षेत्र के उच्च आवृत्ति संकेतक जून और जुलाई में मजबूत रहे। निवेश गतिविधि भी बढ़ रही है - मई में लगातार दूसरे महीने पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में भी जून में मजबूत वृद्धि देखी गई। जुलाई में पीएमआई विनिर्माण बढ़कर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पीएमआई सेवाओं ने जुलाई में निरंतर विस्तार का संकेत दिया, हालांकि यह जून के 11 साल के उच्च स्तर से गिर गया। विनिर्माण क्षेत्र में पीएमआई क्षमता उपयोग अब अपने दीर्घकालिक औसत[3] से ऊपर है, जो अतिरिक्त क्षमता निर्माण में नए निवेश गतिविधि की आवश्यकता का संकेत देता है। बैंक ऋण वृद्धि 15 जुलाई 2022 को एक वर्ष पहले के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई है। पहली तिमाही के लिए कॉरपोरेट्स से प्राप्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बिक्री और मांग की स्थिति और विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता में उछाल रहा।

आगे देखते हुए, दक्षिण-पश्चिम मानसून की अच्छी प्रगति और खरीफ की बुवाई से ग्रामीण खपत को समर्थन मिलेगा। संपर्क-गहन सेवाओं की मांग, कॉरपोरेट के बेहतर प्रदर्शन और उपभोक्ता आशावाद में सुधार से शहरी खपत को लाभ होने की उम्मीद है। क्षमता उपयोग में वृद्धि, सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि और बैंक ऋण में व्यापक बढ़ोत्तरी से निवेश गतिविधि को समर्थन मिलना चाहिए। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार, निर्माण फर्मों को 2022-23 की दूसरी तिमाही में उत्पादन की मात्रा और नए ऑर्डर में निरंतर सुधार की उम्मीद है, जिसकी चौथी तिमाही तक बने रहने की संभावना है। साथ ही, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक ताकतों- प्रलंबित भू-राजनीतिक तनाव; वैश्विक वित्तीय बाजार की बढ़ती अस्थिरता; वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती; और वैश्विक मंदी के जोखिम, से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत पर; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत पर, तथा जोखिम व्यापक रूप

[2] संचयी मौसमी वर्षा 4 अगस्त 2022 को दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत अधिक थी, जिसमें 36 उप-मंडलों में से पिछले वर्ष 28 उप-मंडलों की तुलना में 30 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई थी। 29 जुलाई 2022 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्रफल एक वर्ष पहले की तुलना में 2.2 प्रतिशत कम था। 28 जुलाई को प्रमुख जलाशयों में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 119 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत का 139 प्रतिशत था।

[3] आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 की चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग इसके दीर्घकालिक औसत 73.7 प्रतिशत के सापेक्ष 75.3 प्रतिशत था।

गवर्नर का वक्तव्य

से संतुलित रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.7 प्रतिशत पर अनुमानित है।

मुद्रास्फीति

जून 2022 में लगातार छठे महीने हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन सीमा स्तर पर या उससे ऊपर रही। आगे देखते हुए, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र, उभरती भू-राजनीतिक गतिविधियां, अंतरराष्ट्रीय पण्य बाजार की गतिशीलता, वैश्विक वित्तीय बाजार की गतिविधियां और दक्षिण-पश्चिम मानसून के स्थानिक और अस्थायी वितरण पर काफी ज्यादा निर्भर है। हालांकि, एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से वैश्विक पण्य की कीमतों में कुछ कमी आई है - विशेष रूप से औद्योगिक धातुओं की कीमतों में - और वैश्विक खाद्य कीमतों में कुछ सौम्यता आई है। प्रमुख उत्पादक देशों से आपूर्ति में सुधार और सरकार के आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के कारण घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में और सौम्यता आने की उम्मीद है। काला सागर क्षेत्र से गेहूं की आपूर्ति की बहाली, अगर ऐसी ही बनी रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, आपूर्ति शृंखला का दबाव बढ़ा हुआ है, लेकिन यह धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति कुल मिलाकर पटरी पर है और हाल के सप्ताहों में खरीफ की बुवाई में तेजी आई है। तथापि, खरीफ में धान की बुवाई पर कमी बारीक नजर रखने की जरूरत है, हालांकि बफर स्टॉक काफी अधिक है। हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा कम हुई है, लेकिन वे अभी भी उच्च बने हुए हैं।

बेमौसम और अत्यधिक वर्षा की घटना, यदि कोई हो, खाद्य कीमतों, विशेषकर सब्जियों की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बिक्री की कीमतों पर इनपुट लागत दबावों का बृहद् संचरण भी नया मूल्य दबाव उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, यदि फर्मों की मूल्य निर्धारण शक्ति मजबूत होती है तो, जीवन स्तर की लगातार बढ़ती लागत, उच्च मजदूरी और कीमतों में और बढ़ोत्तरी के रूप में परिलक्षित हो सकती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, और 2022 में सामान्य मानसून और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के अनुमान पर, 2022-23 में मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर तथा जोखिम समान रूप से संतुलित रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत पर अनुमानित है।

मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र अब निर्णायक बिंदु पर है। हालांकि कारकों के संगम के शुरुआती संकेत हैं जो घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों को और सौम्य कर सकते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। इस तरह के माहौल में, बाह्य क्षेत्र से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वृद्धि की गति का आघात सहनीय होने की उम्मीद के कारण, मौद्रिक नीति को निभाव को वापस लेने के अपने अपने रुख को आगे बरकरार रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति वृद्धि का सहारा प्रदान करते हुए मध्यम अवधि में 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब पहुंच जाए। एक सुविचारित दृष्टिकोण वर्तमान अनिश्चित वातावरण में मौद्रिक नीति को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करेगा।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

अप्रैल 2022 में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरूआत, जिसने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की न्यूनतम दर को 40 आधार अंकों (बीपीएस) तक बढ़ा दिया, से मई और जून की नीतिगत रिपो दर वृद्धि के साथ, 130 बीपीएस से प्रभावी रूप से निभाव को वापस लिया गया। परिणामस्वरूप, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – आनुपातिक रूप से दृढ़ हो गया है। मुद्रा बाजार में दीर्घावधि के, 91-दिवसीय खजाना बिल, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर ब्याज दरों में भी अप्रैल से बढ़ोत्तरी हुई है। दरों में बढ़ोतरी ने बैंकों द्वारा बेंचमार्क उधार दरों में एक ऊर्ध्वगामी समायोजन को भी प्रेरित किया। सावधि जमा दरों में भी वृद्धि हो रही है जो ऋण मांग में निरंतर उछाल के संदर्भ में बैंकों के पास निधियों की उपलब्धता के लिए शुभ संकेत होना चाहिए।

बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि, जैसा कि एलएएफ (एसडीएफ और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रिपो नीलामियों दोनों में) के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण में परिलक्षित होता है, अप्रैल-मई में ₹6.7 लाख करोड़ से घटकर जून-जुलाई 2022 में ₹3.8 लाख करोड़ रह गई। मुख्य रूप से कर और पूंजी बहिर्वाह के कारण 20 जुलाई से अधिशेष चलनिधि में भारी कमी के परिणामस्वरूप मुद्रा बाजार दरें रिपो दर से अधिक हो गईं। चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने 26 जुलाई 2022 को 3 दिन परिपक्वता की ₹50,000 करोड़ की परिवर्तनीय दर रिपो नीलामी आयोजित की। आने वाले समय में, और जैसा कि मेरे फरवरी 2022 के वक्तव्य में इंगित किया गया है, आरबीआई चलनिधि के मोर्चे पर सतर्क रहेगा और आवश्यकतानुसार दो-तरफा परिष्कृत कार्य परिचालन करेगा - उभरती चलनिधि और वित्तीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न अवधियों के परिवर्तनीय दर रिपो (वीआरआर) और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रिपो (वीआरआरआर) दोनों का परिचालन।

वर्तमान वित्त वर्ष (4 अगस्त तक) के दौरान, प्रमुख मुद्राओं के समूह की तुलना में अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस परिस्थिति में, भारतीय रुपये में इसी अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से 4.7 प्रतिशत की गिरावट आई जो कि कई आरक्षित मुद्राओं के साथ-साथ इसके कई ईएमई और एशियाई मुद्राओं की तुलना में बहुत बेहतर है। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांतों में कमजोरी के बजाय अमेरिकी डॉलर की मूल्य-वृद्धि के कारण अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप ने अस्थिरता को नियंत्रित करने और रुपये की व्यवस्थित गति सुनिश्चित करने में मदद की है। हम भारतीय रुपये की स्थिरता बनाए रखने हेतु सतर्क हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

भारतीय वित्तीय प्रणाली आघात-सह बनी हुई है। इससे अर्थव्यवस्था को महामारी और यूरोप में युद्ध के कुप्रभाव से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जहां बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत और लाभदायक बनी हुई है, वहीं एक डिलीवरेज्ड कॉरपोरेट क्षेत्र बहाली को बनाए रखने के लिए अच्छा संकेत देता है।

बाह्य क्षेत्र

भारत के बाह्य क्षेत्र ने हाल के वैश्विक स्पिल ओवर से मार्गनिर्देशित करते हुए तूफान का सामना किया है। अप्रैल-जुलाई 2022 में पण्य निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि के कारण पण्य आयात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। परिणामस्वरूप, अप्रैल-जुलाई 2022 में पण्य व्यापार घाटा बढ़कर 100.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अनंतिम आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद सेवाओं के निर्यात, विशेष रूप से आईटी सेवाओं की मांग में पहली तिमाही के दौरान तेजी बनी रही। यात्रा और परिवहन सेवाओं के निर्यात में भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान सुधार हुआ।

बाह्य वित्त पोषण के दृष्टिकोण से, वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), 2021-22 की पहली तिमाही में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिक था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान निकास मोड में रहने के बाद, जुलाई 2022 में सकारात्मक हो गया। जुलाई में किए गए कई अन्य उपायों के साथ, रिज़र्व बैंक ने विनिमय दर में अस्थिरता को रोकने के लिए वर्षों से संचित अपने विदेशी मुद्रा भंडार का भी उपयोग किया है। परिणामी गिरावट के बावजूद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा है।

अतिरिक्त उपाय

अब मैं कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा, जिनका विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों (भाग बी) पर वक्तव्य में दिया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं।

विनियामक उपाय - एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी)

एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) ने भारत में वित्तीय बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय बाजार के विकास को और सुगम बनाने में उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एसपीडी के लिए निम्नलिखित दो उपायों की घोषणा की जा रही है।

गवर्नर का वक्तव्य

i. यह प्रस्ताव है कि एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन, उन सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया जाए जो वर्तमान में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमत है। यह उपाय ग्राहकों को अपने विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बाजार निर्माताओं का एक व्यापक समूह प्रदान करेगा। इससे भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का आयाम भी बढ़ेगा।

ii. एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को गैर-निवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ विदेशस्थ रुपया ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति होगी। यह उपाय बैंकों के लिए इस वर्ष फरवरी में घोषित समान उपाय का पूरक होगा। इन उपायों से देशस्थ और विदेशस्थ ओआईएस बाजारों के बीच संवर्गीकरण को दूर होने और मूल्य खोज में सुधार की आशा है।

वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन

आरबीआई ने समय-समय पर विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा कुछ गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। आउटसोर्सिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरई के ढांचे को उपयुक्त रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। अतः, मौजूदा दिशानिर्देशों को सुसंगत और समेकित करने के लिए, हितधारकों की टिप्पणियों के लिए वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर एक मसौदा मास्टर निदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

सीमापार आवक बिल भुगतान के प्रसंस्करण हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) मानकीकृत बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। इसने भारत में उपयोगकर्ताओं के बिल भुगतान अनुभव को बदल दिया है। 20,000 से अधिक बिलर प्रणाली का हिस्सा हैं, और मासिक आधार पर 8 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रसंस्कृत की जाती है। अब बीबीपीएस को सीमापार आवक बिल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। यह अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में अपने परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और ऐसे अन्य भुगतानों के लिए बिल भुगतान करने में सक्षम करेगा। इससे विशेषतया वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ होगा।

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2021 के अंतर्गत साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शामिल करना और आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र की शुरुआत

रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) ने ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया है। आरबी-आईओएस के अंतर्गत शिकायत निवारण के टर्नअराउंड समय में काफी गिरावट आई है। आरबी-आईओएस को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को आरबी-आईओएस ढांचे के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह सीआईसी के विरुद्ध शिकायतों के लिए एक लागत मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, स्वयं सीआईसी द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि सीआईसी को अपना आंतरिक लोकपाल (आईओ) फ्रेमवर्क रखने के लिए अनिवार्य किया जाए।

माइबोर बेंचमार्क समिति

रिज़र्व बैंक समय-समय पर भारत में ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार विकसित करने के उपाय करता रहा है। इस तरह के उपायों से भागीदार आधार का विविधीकरण हुआ है और आईआरडी लिखतों, यथा मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (ओआईएस) संविदा के उपयोग में वृद्धि हुई है। वैकल्पिक बेंचमार्क दरों को विकसित करने के हाल के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के मद्देनजर, एमआईबीओआर हेतु वैकल्पिक बेंचमार्क में परिवर्तन की आवश्यकता सहित मुद्दों की गहन जांच करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

समापन टिप्पणी

भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है और अशांति और अनिश्चितता के सागर में आगे बढ़ रही है। जैसा कि हम आज़ादी का अमृत

गवर्नर का वक्तव्य

महोत्सव मना रहे हैं, यह हमारी अर्थव्यवस्था की बेहतरी हेतु पहचान करने, गहन चिंतन और नए संकल्प लेने का क्षण है। हम, आरबीआई में, अपनी अर्थव्यवस्था को वृद्धि के एक सतत पथ पर बनाए रखने हेतु मूल्य और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हमारे कार्यों ने पिछले ढाई वर्षों में अर्थव्यवस्था को कई आघातों से उबरने में मदद की है। हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी भूमिका से अवगत हैं और सुरक्षित और सौम्य लैंडिंग सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में कार्यरत रहेंगे। मुझे महात्मा गांधी का एक उद्धरण याद आ रहा है: "मेरे लिए मुक्ति का मार्ग मेरे देश की सेवा में निरंतर परिश्रम के माध्यम से है और वह भी मानवता के माध्यम से"[4]।

धन्यवाद। नमस्कार।

[4] स्रोत: यंग इंडिया, 3-4-1924, पृ.114

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प अगस्त 3-5, 2022

*मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प**

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (5 अगस्त 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.65 प्रतिशत हो गई है।

- एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय में अंतर्निहित मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. जून 2022 में एमपीसी की बैठक के बाद से, वैश्विक आर्थिक और वित्तीय वातावरण, विश्व भर में मौद्रिक नीति की सख्ती और यूरोप में जारी युद्ध, जिससे मंदी का खतरा बढ़ गया है, के संयुक्त प्रभाव के कारण बिगड़ गया है। जोखिम से बचाव की जकड़न से, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और बड़ी बिकवाली में वृद्धि देखी गई है। अमेरिकी डॉलर सूचकांक जुलाई में दो दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई), दोनों ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्राओं को कमजोर होते देखा। ईएमई, पूंजी बहिर्वाह और आरक्षित निधि संबंधी हानि का सामना कर रहे हैं जो उनकी संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

3. घरेलू आर्थिक गतिविधियां लचीली बनी हुई हैं। 4 अगस्त 2022 तक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत अधिक थी। खरीफ की बुआई में तेजी आ रही है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में सुधार हो रहा है। शहरी मांग मजबूत हो रही है, जबकि ग्रामीण मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वस्तु निर्यात में अप्रैल-जून 2022 के दौरान 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें जुलाई में कुछ कमी देखी गई। गैर-तेल गैर-सोने का आयात मजबूत था, जो मजबूत घरेलू मांग का संकेत देता है।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति मई-जून 2022 के दौरान अप्रैल में 7.8 प्रतिशत से घटकर 7.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष, व-द-व) हो गई, हालांकि अभी भी यह ऊपरी सहन-सीमा बैंड से ऊपर बनी हुई है। विशेष रूप से खाद्य तेल की कीमतों में सौम्यता और दालों और अंडों में अपस्फीति को गहन बनाने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ कमी दर्ज की गई है। मुख्य रूप से एलपीजी और केरोसिन की कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन मुद्रास्फीति जून में दोहरे अंकों में वापस आ गई। जबकि 22 मई 2022 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल पंप की कीमतों पर उत्पाद शुल्क में कटौती के पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण मई-जून में मूल मुद्रास्फीति (अर्थात्, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में कमी आई, यह उच्च स्तर पर बनी हुई है।

5. जून-जुलाई के दौरान एलएएफ के अंतर्गत ₹3.8 लाख करोड़ के औसत दैनिक अवशोषण के साथ कुल प्रणाली चलनिधि अधिशेष में बनी हुई है। वाणिज्यिक बैंकों से मुद्रा आपूर्ति (एम 3) और बैंक ऋण में 15 जुलाई 2022 तक क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत की वृद्धि (व-द-व) हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 जुलाई 2022 तक 573.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

* 5 अगस्त 2022 को प्रकाशित

संभावना

6. भू-राजनीतिक आघातों से उत्पन्न स्पिलओवर से मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में काफी अनिश्चितता बनी हुई हैं। हाल ही में, खाद्य और धातु की कीमतें अपने चरम पर आ गई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हाल के सप्ताहों में कमी आई है, लेकिन वैश्विक मांग के कमजोर होने के संभावनाओं के बावजूद आपूर्ति की चिंताओं पर यह उच्च और अस्थिर बनी हुई है। अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि, आयातित मुद्रास्फीति दबावों में परिलक्षित हो सकती है। खरीफ की बढ़ती बुवाई घरेलू खाद्य कीमतों की संभावनाओं के लिए शुभ संकेत है। तथापि, धान की बुआई में कमी पर बारीक नजर रखने की आवश्यकता है, हालांकि चावल का स्टॉक, बफर मानदंडों से काफी अधिक है। रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों में मतदान करने वाली फर्मों को उम्मीद है कि दूसरी छमाही में सभी क्षेत्रों में इनपुट लागत दबाव कम होगा। तथापि, लागत दबावों का तेजी से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादन कीमतों पर प्रसारित होने की उम्मीद है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और 2022 में सामान्य मानसून और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के अनुमान पर, 2022-23 में मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत पर तथा जोखिम समान रूप से संतुलित रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत पर अनुमानित है (चार्ट 1)।

7. संवृद्धि की संभावना पर, ग्रामीण खपत को बेहतर कृषि संभावनाओं से लाभान्वित होने की उम्मीद है। संपर्क-गहन सेवाओं की मांग और कारोबार तथा उपभोक्ता मनोभावों में सुधार से विवेकाधीन व्यय और शहरी खपत को आधार मिलना चाहिए। निवेश गतिविधि को सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि, बैंक ऋण में सुधार और क्षमता उपयोग में वृद्धि से समर्थन मिलने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में मतदान करने वाली फर्मों को 2022-23 की दूसरी तिमाही में उत्पादन मात्रा में क्रमिक विस्तार और नए ऑर्डर की उम्मीद है, जिसकी चौथी तिमाही तक बने रहने की संभावना है। दूसरी ओर, प्रलंबित भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न उच्च जोखिम, वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता में वृद्धि और वैश्विक वित्तीय स्थितियों में मजबूती का संभावना पर भारी प्रभाव जारी है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि अनुमान 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत पर; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत पर; तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत पर; और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत पर, तथा जोखिम व्यापक रूप से संतुलित रहने की उम्मीद है। 2023-24 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.7 प्रतिशत पर अनुमानित है (चार्ट 2)।

चार्ट 1: सीपीआई मुद्रास्फीति (व-द-व) का त्रैमासिक पूर्वानुमान

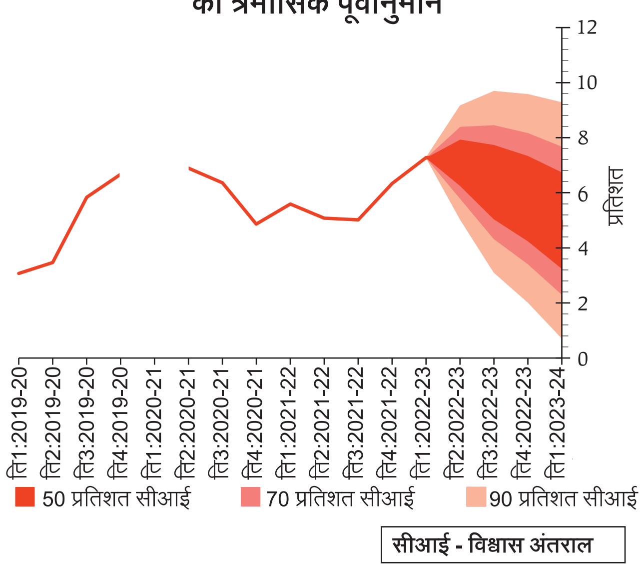

चार्ट 2: वास्तविक जीडीपी वृद्धि (व-द-व) का त्रैमासिक पूर्वानुमान

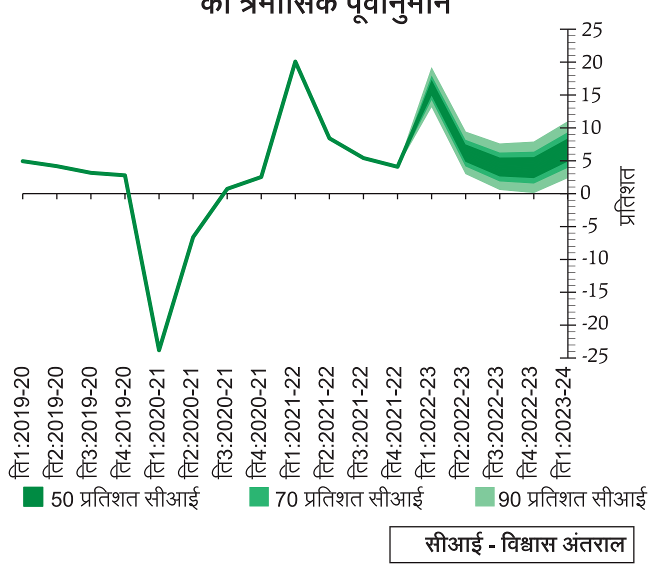

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

8. हेडलाइन मुद्रास्फीति हाल ही में शिथिल हुई है और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं में कमी के कारण आपूर्ति संभावना में सुधार हो रहा है। हालांकि, एमपीसी ने यह पाया है कि 2022-23 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन सीमा से ऊपर रहने का अनुमान है, जिससे मुद्रास्फीति की उम्मीदों को अस्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभावों को ट्रिगर करने का जोखिम है। मुद्रास्फीति के उच्च स्तर और घरेलू आर्थिक गतिविधि में लचीलेपन को देखते हुए, एमपीसी ने यह विचार किया कि मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने, हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्ष्य के करीब सहन-सीमा बैंड के भीतर वापस लाने और संवृद्धि को बरकरार रखने को सुनिश्चित करने हेतु मुद्रास्फीति के अनुमान को स्थिर रखने के लिए और अधिक सुविचारित मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

9. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40 प्रतिशत करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

10. प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर सभी सदस्यों अर्थात् डॉ. शशांक भिड़े, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मतदान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस भाग पर आपत्ति जताई।

11. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 19 अगस्त 2022 को प्रकाशित किया जाएगा।

12. एमपीसी की अगली बैठक 28-30 सितंबर 2022 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और पर्यवेक्षण; (ii) वित्तीय बाजार; और (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मास्टर निदेश

विनियमित संस्थाएं (आरई) लागत को कम करने के साथ-साथ आंतरिक रूप से अनुपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के साधन के रूप में आउटसोर्सिंग का उत्तरोत्तर उपयोग कर रही हैं। यद्यपि एक अनुमत गतिविधि की आउटसोर्सिंग आरई का एक परिचालनगत निर्णय है, यह आरई को विभिन्न जोखिमों के प्रति उजागर करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर), गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सहकारी बैंकों को वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन पर विभिन्न दिशानिर्देश/निदेश जारी किए हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों को अद्यतन और सुसंगत बनाने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और समाविष्ट करने के साथ-साथ आरई को संदर्भ हेतु एक ही स्थान पर वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी वर्तमान दिशा-निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए, शीघ्र ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन) निदेश, 2022 का मसौदा जारी करने का प्रस्ताव करता है। इन निदेशों के दायरे का विस्तार, आरआरबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऋण सूचना कंपनियों और गैर-अनुसूचित भुगतान बैंकों को भी शामिल करने के लिए किया जा रहा है।

2. रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2021 के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शामिल करना और आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र का विस्तार करना

रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2021 के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और ₹50 करोड़ और उससे अधिक की कुल जमा राशि वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) शामिल हैं। आरबी-आईओएस को और अधिक व्यापक बनाने के लिए, ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को भी आरबी-आईओएस 2021 के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। यह सीआईसी के विरुद्ध शिकायतों के लिए आरई के ग्राहकों को एक लागत मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अलावा, सीआईसी के आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने और इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए, सीआईसी को आंतरिक लोकपाल (आईओ) ढांचे के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया गया है।

II. आर्थिक बाज़ार

3. स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) - अनुमत गतिविधियों के दायरे में विस्तार

वर्तमान में, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को सीमित उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार करने की अनुमति है। प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय का संचालन करने वाले बैंकों के समान, बाजार निर्माताओं के रूप में एसपीडी की भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अधीन, वर्तमान में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमत सभी विदेशी मुद्रा निर्माता सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसपीडी को सक्षम बनाया जाए। यह उपाय विदेशी मुद्रा ग्राहकों को अपने मुद्रा जोखिम के प्रबंधन में बाजार निर्माताओं का एक व्यापक समूह प्रदान करेगा, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तार होगा। व्यापक बाजार उपस्थिति सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक निर्गमन और द्वितीयक बाजार गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए एसपीडी की क्षमता में सुधार करेगी, जो प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। इस संबंध में विनियम अलग से जारी किए जाएंगे।

4. स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों को अपतटीय विदेशी मुद्रा सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप बाजार में लेनदेन करने की अनुमति देना

भारत में बैंकों को फरवरी 2022 में, तटवर्ती और अपतटीय ओआईएस बाजारों के बीच विभाजन को दूर करने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से, अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ अपतटीय विदेशी मुद्रा सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। तटवर्ती ओआईएस बाजार में बैंकों की तरह स्टैंडअलोन

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) भी बाजार-निर्माता हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत एसपीडी को भी अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ सीधे एफसीएस-ओआईएस लेनदेन करने की अनुमति होगी। जल्द ही आवश्यक निदेश जारी किए जाएंगे।

5. माइबोर बेंचमार्क संबंधी समिति

मुंबई अंतर बैंक एकमुश्त दर (माइबोर) आधारित ओवरनाइट इंडेक्सेड स्वैप (ओआईएस) संविदा, तटवर्ती बाजार में ज़्यादातर उपयोग की जाने वाली ब्याज दर डेरिवेटिव्स (आईआरडीएस) हैं। सहभागी आधार में विविधता लाने और नए आईआरडी लिखतों की शुरूआत की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ माइबोर आधारित डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग बढ़ गया है। साथ ही, बाजार खुलने के बाद पहले घंटे में एनडीएस-मांग प्लेटफॉर्म पर निष्पादित मांग मुद्रा सौदों के आधार पर गणना की गई माइबोर बेंचमार्क दर, लेनदेन की एक संकीर्ण विंडों पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक भागीदार आधारों (बैंकों से परे) और उच्च चलनिधि के कारण वैकल्पिक बेंचमार्क दरों में बदलाव किया गया है। इन घटनाक्रमों के बीच, एक वैकल्पिक बेंचमार्क में परिवर्तन की आवश्यकता सहित मुद्दों की गहन जांच करने और आगे के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

6. सीमापारीय आवक बिल भुगतान को प्रसंस्कृत करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को सक्षम बनाना

एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा संचालित भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) ने देश में बिल भुगतान के अनुभव को बदल दिया है। बीबीपीएस मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, एकसमान ग्राहक सुविधा शुल्क आदि के लिए एक अंतःप्रचालनीय (इंटरऑपरेबल) प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। 20,000 से अधिक बिलर्स को प्रणाली में शामिल किया गया है और मासिक आधार पर आठ करोड़ से अधिक लेनदेन प्रसंस्कृत किए जाते हैं। बीबीपीएस वर्तमान में केवल भारत के निवासियों के लिए उपलब्ध है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारत में अपने परिवारों की ओर से उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए, बीबीपीएस को सीमा पार से आवक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। इससे बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर इंटरऑपरेबल तरीके से शामिल किए गए किसी भी बिलर के बिलों के भुगतान में भी लाभ होगा। आवश्यक अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

भाषण

भविष्य की बैंकिंग
शक्तिकांत दास

75वें वर्ष में भारत
माइकल देबब्रत पात्र

भविष्य की बैंकिंग*

शक्तिकांत दास

बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंकिंग सम्मेलन में, इस विशिष्ट जनसमूह के बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और सम्मेलन के विषय के रूप में 'भविष्य की बैंकिंग' (बैंकिंग बियोंड टुमॉरो) का चयन करने के लिए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को बधाई देता हूँ। यह देखते हुए कि तीव्र गति से हो रहे नवोन्मेष, महत्वपूर्ण बदलावों और नए कारोबारी मॉडलों के उभरकर आने से बैंकिंग परिदृश्य दूरगामी परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है; मैं समझता हूँ कि इस विषय पर सक्रिय चर्चा करना समीचीन होगा।

आज मैं अपने सम्बोधन में वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थिति पर बात करूंगा और बैंकों द्वारा निभाई जा रही विशेष भूमिका तथा बैंकिंग क्षेत्र की नई प्रवृत्तियों को रेखांकित करूंगा। मैं भविष्य की बैंकिंग के संभाव्य स्वरूप और उससे जुड़े अवसरों और चुनौतियों को भी रेखांकित करने का प्रयास करूंगा।

समष्टि आर्थिक परिस्थिति: आज हम कहाँ खड़े हैं

हम एक अस्थिर समय में जी रहे हैं। यूरोप में लगातार जारी युद्ध और महामारी ने वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य को अत्यधिक अनिश्चित बना दिया है। कई देश अनपेक्षित रूप से उच्च मुद्रास्फीति और खाद्य महंगाई, आपूर्ति शृंखला बाधाओं और उत्पाद एवं श्रम बाज़ारों में मांग-आपूर्ति असंतुलनों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक तेज गति से मौद्रिक नीति को सख्त बनाए जा रहे हैं, जिससे एक आसन्न मंदी का भय पैदा हो रहा है। वस्तुओं की कीमतों में जून की तुलना में गिरावट जरूर हुई हैं, पर अब भी ऊपर बनी हुई हैं। अमेरिका में उच्चतर ब्याज दरों और इसके साथ-साथ वैश्विक निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृति के कारण, सुरक्षित निवेश की मांग और अमेरीकी डॉलर की मजबूती तीव्र हो गई है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई), यहाँ तक कि कुछेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) की मुद्राएँ भी अमेरिकी डॉलर *के मुक़ाबले* कमजोर हो रही हैं। परिणामस्वरूप, मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ रहे हैं और बाहरी स्रोतों से निधियाँ जुटाना महंगा होता जा रहा है, जिससे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। समग्र रूप से देखें तो अस्थिर भू-राजनीतिक परिस्थिति के बीच वैश्विक परिदृश्य संकटपूर्ण बना हुआ है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को विघटित और खंडित करने वाली ताकतों को युद्ध और महामारी से शह मिल रही है।

ऐसे वातावरण में, भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसका समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार मजबूत है। वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त पूंजी है, आस्ति गुणवत्ता संकेतक बेहतर हुए हैं, तुलनपत्र ज्यादा सुदृढ़ हैं, और बैंक लाभप्रदता की स्थिति में लौट आए हैं। ऋण-मांग में भी अच्छा सुधार हो रहा है। व्यापारिक आघातों और पूंजी के बाहर जाने से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए बाह्य क्षेत्र पर्याप्त रूप से निधिकृत है। आरबीआई की हाल ही में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली आघातसह बनी हुई है और चल रही आर्थिक बहाली को समर्थन दे रही है। बैंक अपनी न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के स्तर से नीचे खिसके बिना ही गंभीर दबाव परिदृश्यों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। रिज़र्व बैंक प्रतिकूल चुनौतियों के प्रति लगातार सजग है और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सक्रियतापूर्वक कदम उठाने के लिए तत्पर रहेगा।

विदेशी मुद्रा बाजार में हुई हालिया गतिविधियों से तीखी बहस छिड़ गई है और रुपये के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक गिर जाने के अंदाज लगाए जा रहे हैं क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो फंड भारत से बाहर निकल रहे हैं। मैं इस मुद्दे के सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए तथ्यपरक ढंग से अपनी बात रखना चाहूँगा।

सबसे पहले यह स्वीकारना जरूरी है कि मौद्रिक नीति में वैश्विक सख्ती के प्रसार-प्रभाव, भूराजनीतिक परिस्थिति, वस्तुओं- खासकर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि बनी रहना और महामारी के प्रभावों का लंबा खिंचते चले जाना- इन सभी के एक साथ आ जाने से, दुनिया के सभी देश अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि आरक्षित मुद्राएँ (रिज़र्व करेंसी) जैसे कि जापानी येन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी इससे अछूती नहीं रही हैं। पोर्टफोलियो फंड आस्तियां बेच रहे हैं और सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) पूंजी के

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 22 जुलाई 2022 को मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में भाषण दिया गया।

बाहर जाने, मुद्रा अवमूल्यनों और रिज़र्व में गिरावटों से विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे इन देशों में समष्टि आर्थिक प्रबंधन जटिल हो गया है।

दूसरी बात, भारत पर इन भारी प्रसार-प्रभावों का असर अपेक्षाकृत कम पड़ा है। वस्तुतः, भारतीय रुपया अपने उन्नत और ईएमई समकक्षों की तुलना में बेहतर बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आधारभूत व्यवस्था सुदृढ़, आघातसह और अक्षुण्ण है। आर्थिक बहाली क्रमशः मजबूत हो रही है। चालू खाता घाटा अधिक नहीं है। मुद्रास्फीति स्थिर हो रही है। वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह पूंजीकृत और सुदृढ़ है। जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज अनुपात कम हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है।

तीसरी बात, इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि आयात और कर्ज चुकौती संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा पोर्टफोलियो बहिर्वाहों के कारण बाजार में मांग के मुक़ाबले विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वास्तव में कमी है, पर्याप्त विदेशी मुद्रा चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए, आरबीआई बाजार में अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति कर रहा है। आखिरकार, यही वह उद्देश्य है जिसके लिए हमने विदेशी मुद्रा भंडार जमा किए थे, जब पूंजी के अंतर्वाह मजबूत थे। और, मैं यह भी जोड़ना चाहूँगा, आप छाता इसलिए खरीदते हैं कि जब बारिश हो तो वह काम आए!

चौथे, बकाया ईसीबी के सर्वाधिक भाग को हानि से सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी ढंग से बचाव-व्यवस्था की गई है। इसे मैं विस्तार से बताता हूँ। भारतीय रिज़र्व बैंक की जून 2022 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाया ईसीबी में से 44 फीसदी यानी 79 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए बचाव-व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम, रेलवे और बिजली क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की देयताएं शामिल हैं जिनके पास ऐसी आस्तियां हैं जो स्वाभाविक रूप से बचाव/ हेज करने की विशेषता रखती हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के मामले में विदेशी मुद्रा जोखिम होने की स्थिति में सरकार द्वारा भार उठाया जा सकता है। ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। शेष 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ईसीबी बकाया कुल ईसीबी का 22% है। इसमें भी उन कंपनियों के उधार शामिल हैं जिनके पास विदेशी मुद्राओं में प्राप्त होने वाली आय के रूप में स्वाभाविक हेजिंग है। इस प्रकार कुल बकाया ईसीबी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा वास्तव में बिना किसी सुरक्षा के (अनहेज्ड) है। कॉरपोरेट संस्थाओं को अंततः समझौताकारी तालमेल बैठाना पड़ता है क्योंकि एक ओर यदि कॉरपोरेट संस्थाएं अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को पूरी तरह से हेज करते हैं, तो उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा में सस्ते उधार लेने का लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर, विनिमय दर दबाव में होने की स्थिति में उन्होंने जितनी राशि को हेज नहीं किया है उतनी ही ऋण चुकौती की राशि बढ़ जाती है। इसी कारण यथायोग्य हेज अनुपात की अवधारणा अस्तित्व में आई, जो हेजिंग के अनुपात की गणना करता है, जिससे पोर्टफोलियो में परिवर्तन कम होता है। हमारे आंतरिक शोध का अनुमान है कि भारत के लिए यथायोग्य हेज अनुपात 63 प्रतिशत के आसपास होना चाहिए। स्वाभाविक हेजिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, भारत के विदेशी ऋण में ईसीबी के स्टॉक के मामले में इष्टतम हेजिंग अनुपात को बनाए रखने की शर्त को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया है।

अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के उपायों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण, रुपये का मूल्य अपेक्षाकृत सुचारू और व्यवस्थित रहा है। अचानक होने वाले और अस्थिर कर देने वाले बदलावों से बचते हुए, हमने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदें बरकरार रहें तथा विदेशी मुद्रा बाजार स्थिर तरीके से काम करे और अर्थसुलभ बने रहे। विदेशी मुद्रा बाजार पर हमारा ध्यान बना रहेगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रुपये का स्तर बुनियादी स्तर के अनुरूप हो। मैं यह दोहराना चाहूंगा कि हमारे मन में रुपये को लेकर कोई विशिष्ट स्तर नहीं है, लेकिन हम इस स्तर के उचित विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसकी अस्थिर चाल और तीव्र उतार-चढ़ाव हमें पूर्णतः अमान्य है।

बैंक विशेष संस्थाएं होती हैं- उनमें स्थायित्व अपेक्षित है

बैंक विशेष हैं और वे किसी अन्य वाणिज्यिक संस्था की तरह नहीं हैं। वे केवल शेयरधारकों के हितों के संरक्षक नहीं हैं बल्कि मूल रूप से जमाकर्ताओं के विश्वास के संरक्षक अधिक हैं। बैंकिंग प्रणाली के केंद्र में जमाकर्ता होते हैं। देश में एक मजबूत, विश्वसनीय और स्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बैंकों के लिए यह हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा नियोजित धन जमाकर्ताओं का है और यह उचित जोखिम प्रबंधन, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में परिलक्षित होना चाहिए।

बैंकों के संबंध में यहां भी अपेक्षा की जाती है कि विनियामकीय लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वे स्थायी संस्था बने रहें। वे सुदृढ़ विनियामकीय और पर्यवेक्षी प्रथाओं द्वारा शासित होती हैं। सुदृढ़ कार्यप्रणाली और जोखिम प्रबंधन, जो बैंक के कामकाज का अभिन्न अंग है, को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की होती है। पूंजी, चलनिधि और प्रावधानीकरण मानदंडों के संदर्भ में विनियामकीय निर्देशों से परे जाना और उनसे आगे जाना सुशासन और मजबूत जोखिम प्रबंधन का संकेत होगा। यह बैंकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें तनाव की स्थितियों के दौरान अपने स्वयं की बैलेंस शीट का सहारा लेने में सक्षम बनाएगा।

इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि जहां बैंकिंग के कारोबार में शेयरधारकों का हित महत्वपूर्ण है, वहीं जमाकर्ताओं का हित और भी महत्वपूर्ण है। बैंकों के शेयरधारकों को दीर्घावधि लाभप्रदता और बाजार मूल्यन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह निवेशकों को मध्यम से दीर्घावधि में सृजित होने वाले मूल्य के लिए बैंकिंग संस्था की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगा। यह दृष्टिकोण बैंकिंग के एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगा।

भविष्य के लिए बैंकों की तैयारी

बैंकिंग का बदलता परिदृश्य

बैंकिंग क्षेत्र मंथन के दौर से गुजर रहा है। भविष्य में ग्राहकों की बैंकिंग उद्योग से अपेक्षाएँ बढ़ जाएँगी और बैंकों को ग्राहकों की पसंद और प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रत्येक बदलाव मौजूदा और नई संस्थाओं के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियां पेश करेगा। यह ध्यान में रखना होगा कि कभी-कभी बदलाव इतने अचानक हो सकते हैं कि उनका अनुमान लगाना असंभव होगा। हालांकि, मुझे लगता है कि 'भविष्य की बैंकिंग' (i) उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, उत्पादों और सेवाओं के अनुकूलन, उन्नत व्यवसाय और प्रक्रिया स्वचालन और (ii) सुदृढ़ अभिशासन ढांचे, बेहतर सूचना प्रबंधन, काम करने के तरीके में बदलाव, आघातों को सहने की बढ़ी हुई क्षमताओं के निर्माण और बैंकों के लिए एक अधिक जिम्मेदार सामाजिक और पर्यावरणीय भूमिका के साथ उपयुक्त व्यवसाय मॉडल के विकास को प्राथमिकता देगी। मैं उपर्युक्त बातों को विस्तार से रखना चाहता हूँ।

डिजिटलीकरण में वृद्धि, व्यक्ति अनुकूल सेवाओं की पेशकश और फिनटेक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम

बाजार संरचना और प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिनटेक कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम से अथवा स्व-उन्नयन के माध्यम से पारंपरिक बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में हुई वृद्धि ने नए जमाने के बैंकिंग के विचार को प्रतिध्वनित किया है। इससे अभिनव उत्पादों, सेवाओं और नए व्यापार मॉडल का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस संदर्भ में, यह अक्सर कहा जाता है कि बैंकों को फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जो पहले से ही वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज के ग्राहक, विशेष रूप से खुदरा ग्राहक, बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें त्वरित, विश्वसनीय और व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराएँ। इसलिए प्रासंगिक बने रहने के लिए, बैंकों को प्रभावी और समय पर व्यापार निर्णय लेने, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उन्हें व्यक्ति अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए नई और परीक्षण में उपयुक्त पाई गई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। भविष्य की बैंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक क्षमता में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।

मुक्त बैंकिंग (ओपन बैंकिंग)

वैश्विक स्तर पर देखें तो नई प्रौद्योगिकियों और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की उपलब्धता से बैंकिंग अधिक 'मुक्त' होती जा रही है जो बैंकों के साथ-साथ फिनटेक के बीच भी अंतर-संचालन की अनुमति देती है। इस आयाम ने ग्राहक अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक तेजी से और बेहतर रूप से पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के बीच पारस्परिक सहयोग हेतु अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराये हैं। अन्य विकसित देशों के विपरीत, भारत ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है, जहां विनियामक और बाजार, दोनों ने मिलकर ओपन बैंकिंग के विकास के लिए काम किया है। भारत में ओपन बैंकिंग की शुरुआत करने में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूपीआई की सफलता, अकाउंट एग्रीगेटर (एए) संरचना के क्रियान्वयन और डिजिटल

बैंकिंग सेवाओं को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के साथ भारत में नए बिजनेस मॉडल का उदय हो रहा है। ग्राहकों को, अपनी सूचनाओं का बेहतर उपयोग करने और व्यापक तथा समृद्ध सेवा समूह का लाभ उठाने के लिए, सुविधा प्रदान करने हेतु कई बैंक नए युग के सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं।

उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप, वेबसाइट नैविगेशन और उन्नत ग्राहक सेवा

नए तकनीक-प्रेमी ग्राहकों और बैंकिंग जगत में डिजिटलीकरण की लहर को देखते हुए, बैंकों के लिए जरूरी है कि वे संचार के डिजिटल और कागज आधारित रूपों के बीच एक अच्छा संतुलन भी बनाएं। हालांकि बैंकों के ऐप्स और वेबसाइटों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, फिर भी ग्राहकों के लिए आसान नैविगेशन की सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। प्रकटीकरण और सूचनाओं तक पहुंच को सरल बनाने तथा वेबसाइट और मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करने में ग्राहकों को मदद करने के लिए चैटबॉट जैसी नवोन्मेषी सुविधा देने से बैंकिंग अनुभव में काफी वृद्धि होगी।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं और उसमें सतत सुधार भी हुए हैं जो रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक में परिलक्षित होते हैं। वेतन भुगतान, सरकारी नकद अंतरण और घरेलू विप्रेषण जैसी डिजिटल भुगतान प्राप्तियां वित्तीय समावेशन अभियान में सहायक साबित हुई हैं। जनधन-आधार-मोबाइल त्रय (जेएएम ट्रिनिटी) की प्रेरणा के परिणामस्वरूप वंचित और अल्प सेवा प्राप्त लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकियां, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए बाधाओं को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका पेश कर रही हैं, फिर भी हमें उन लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है जिनकी इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है। पारंपरिक शाखा बैंकिंग में मानवीय संवाद अभी भी कई मायनों में ग्राहकों के लिए प्रासंगिक होगा। कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को समय पर और निर्बाध ऋण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। जहां आरबीआई अपने विनियामकीय परीक्षण स्थल (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) के माध्यम से एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को ऋण देने की पहल को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है, वहीं अन्य हितधारक जैसे बैंक और फिनटेक कंपनियां भी लागत-प्रभावी और निर्बाध तरीके से डिजिटल क्रेडिट वितरण तंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग कर रही हैं।

सोशल मीडिया और सूचना माध्यमों का उपयोग

सोशल मीडिया लाखों ग्राहकों तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मंच है। भारतीय लोग औसतन प्रतिदिन लगभग 2.4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया के उपयोग के विश्लेषण से बैंकों को अलग-अलग ग्राहक समूहों की पहचान करने, नए ग्राहक बनाने और वित्तीय समावेशन योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपनी कार्यनीतियों की समीक्षा करने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया का उपयोग ग्राहक शिकायत निवारण प्रबंधन में भी किया जा सकता है।

साइबर सुरक्षा

डिजिटल बैंकिंग में प्रगति के साथ-साथ, साइबर सुरक्षा सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेगी। बैंकों द्वारा आईटी सिस्टम का बढ़ता उपयोग, दूरस्थ कार्य व्यवस्था, ग्राहकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को त्वरित रूप से अपनाने के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भरता बढ़ने से व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की वहनीय क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसमें साइबर हमलों के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करने, अक्षम करने या नष्ट करने या गोपनीय जानकारी और डेटा चोरी करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास के खिलाफ मजबूत सुरक्षा का निर्माण करना शामिल है। बैंकों को अपने कर्मियों की क्षमता में निरंतर वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। निरंतर ज्ञान अर्जन और समय से आगे रहना और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

जलवायु संबंधी जोखिमों के संबंध में व्यापक और रणनीतिगत दृष्टिकोण

आने वाले समय में जलवायु संबंधी जोखिम एक प्रमुख जोखिम क्षेत्र होगा। इस तरह के जोखिम बैंकों की कारोबारी प्रणाली को प्रभावित करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यवसायों

[1] ग्लोबल वेब इंडेक्स सोशल मीडिया ट्रेंड्स 2019 रिपोर्ट।

और उद्योग को वित्त पोषण की बढ़ी हुई आवश्यकताएं, जलवायु संबंधी जोखिम प्रबंधन पर उठाए गए वैश्विक परिवर्तनों से काफी प्रभावित होंगी। निवेश संबंधी निर्णय लेते समय विभिन्न हितधारक पहले से ही पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। वैश्विक जलवायु के प्रति स्थिरता बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तपोषण वाली आस्तियों के मूल्यांकन सहित बैंक अपने व्यवसायों को तेजी से इनके अनुरूप बना रहे हैं। बैंकों को उचित व्यावसायिक कार्यनीति विकसित करने और संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए आभिशासन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, जलवायु जोखिमों को दूर करने के लिए एक दूरदर्शी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता होगी।

समग्र रूप से

आने वाले समय में उम्मीद है कि बैंकिंग की दुनिया अधिक परस्पर सहयोगी होने के साथ-साथ ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगी, जिसमें नए भागीदार होंगे जो नवीन वित्तीय उत्पादों की पेशकश लेकर आएंगे। बैंकों को उचित व्यवसाय मॉडल, संवहनीयता, स्थिरता और उपभोक्ता को केंद्र में रखते हुए इस गतिशील वातावरण का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उचित अभिशासन सफलता का मूल है और इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हितधारकों को डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराधों से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अंततः, बैंकिंग एक सेवा है, और बेहतर ग्राहक सुरक्षा और अनुभव को वह प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। विनियामक की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए, नए परिवर्तनकारी नवोन्मेषों को स्थायी तरीके से समायोजित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतिहास गवाह है कि जब-जब प्रौद्योगिकी, बाजार सहभागियों और विनियामकों ने हाथ मिलाया है, तब-तब क्रांतिकारी नवोन्मेष और संवृद्धि हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल के हमारे बैंक इसे साकार करेंगे।

धन्यवाद।

*75वें वर्ष में भारत**

माइकल देबब्रत पात्र

डॉ. हृदयानंद पांडा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भुवनेश्वर, ओडिशा सरकार से आरबीआई के विशिष्ट अतिथि, शिक्षाविद, बैंक, वित्तीय संस्थान, उद्योग संघ, मीडिया, विद्वान और छात्र, भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सहयोगी, देवियों और सज्जनों !

हमारी आजादी के 75वें वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में इस संबोधन के लिए आमंत्रित किए जाने पर मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं, डॉ. पांडा को मुझे आमंत्रित करने और उससे भी अधिक अभिनव पहल और शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उनकी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिसने इस कार्यक्रम को संभव किया है। इस उल्लेखनीय क्षण में, ऊर्जा, प्रेरणा, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत हमें एक उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे सपनों की पूर्ति से शोभित होगा। कई मायनों में, भुबनेश्वर इस महोत्सव का प्रतीक है - एक समृद्ध और गौरवशाली विरासत; एक सजग वर्तमान; और भविष्य का एक स्मार्ट शहर - हर मामले में, त्रिभुवन।

मेरी बात, पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की यात्रा को बहुरूपदर्शक बनाने का प्रयास करेगी लेकिन हमारा ध्यान अगले 10-50 वर्षों में भारत के भविष्य पर होगा।

कहा जाता है कि उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ गया हो।[1] मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का समय आ गया है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस में गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत है[2]- आप कह सकते हैं कि मैं एक सपने देखने वाला हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बात के बाद, मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम भी मेरे साथ सपने देखोगे, और दुनिया एक जैसी हो जाएगी। इसलिए, मैं आपको सपनों की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि भारत अपनी नियति का साक्षात्कार के लिए तैयार है।

उड़ान के लिए तैयार भारत

ऐसा कहा जाता है कि यदि ब्रह्मांड के इतिहास की तुलना 100 किमी की यात्रा से की जाए, तो 71वें किमी या उससे थोड़ी दूर आगे तक जीवन का सामना नहीं होगा, बल्कि मानव अस्तित्व 1-2 मीटर की अंतिम अवधि में होगा। इस विनम्र नजरिये से देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की 75 साल की यात्रा काफी आश्चर्यजनक रही है। 2006 और कोविड-19 महामारी के बीच, भारत में 300 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, दुनिया में कहीं भी गरीबी में कमी की यह उच्चतम दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। 2021 में, भारत दुनिया के नंबर 1 चावल निर्यातक के रूप में उभरा है जो दुनिया के नंबर 2 और 3 के संयुक्त निर्यात से अधिक है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का सबसे व्यापक आधार विनिर्माण है, जिसमें यह, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक होने के साथ-साथ, स्मार्टफोन, कार और अंतरिक्ष यान के शीर्ष 10 निर्यातकों में शामिल है। शिपिंग कर्मियों और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई सेवाओं में, भारत विश्व में अग्रणी है। आईटी के मामले में भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाने लगा है।

किसी देश की आर्थिक प्रगति का एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, जो एक तिमाही या एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यदि कोई पिछले 75 वर्षों में पीछे मुड़कर देखे, तो सांख्यिकीय परीक्षण (बाई-पेरोन संरचनात्मक ब्रेक टेस्ट) से पता चलता है कि भारत का संवृद्धि पथ तीन चरणों से गुजरा है। 1970 के दशक तक, भारत की औसत जीडीपी संवृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी - तथाकथित हिंदू संवृद्धि दर - जो उस अवधि में अपनाई गई अंत:अवलोकी नीतियों से जुड़ी हुई है। 1980-2002 के दौरान उदारीकरण, खुलेपन और एक बाह्य उन्मुखीकरण के कारण संवृद्धि दर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके बाद, महामारी आने तक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि औसतन लगभग 7 प्रतिशत हो गई। 2020-21 में महामारी के

* 13 अगस्त 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक, भुबनेश्वर द्वारा आयोजित **आज़ादी का अमृत महोत्सव** के निमित्त एक कार्यक्रम में डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण। राजीव जैन, अत्रि मुखर्जी, वी. धन्या, धीरेंद्र गजभिए, आशीष थॉमस जॉर्ज, हरेंद्र बेहरा, सोना थंगजानसन और कुणाल प्रियदर्शी के मूल्यवान इनपुट और टिप्पणियां; और विनीत कुमार श्रीवास्तव और समीर रंजन बेहरा की संपादकीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

[1] विक्टर ह्यूगो, हिस्टोर डी'न क्राइम, 1877

[2] इमैजिन, जॉन लेनॉन।

कारण जीडीपी में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2021-22 में, यह 8.7 प्रतिशत तक बहाल हो गया और जीडीपी को अपने पूर्व-महामारी स्तर से 1.5 प्रतिशत ऊपर ले गया। चालू वित्त वर्ष, यानी 2022-23 के लिए, आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में रखता है।

भारत की संवृद्धि के कारक क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था "हम" लोगों के निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) द्वारा संचालित है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, किराए, बीमा, पेंशन अंशदानों और इस तरह अन्य व्यय - जो दैनिक आजीविका से संबद्ध हैं - पर परिवारों के खर्च शामिल हैं। निजी खपत सकल घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत है, हालांकि यह हिस्सा 1960 के दशक के 75 प्रतिशत से अधिक से नीचे आ गया है। निर्यात-आधारित और निवेश-आधारित संवृद्धि के चरण रहे हैं, जो कायम नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने संवृद्धि पथ में महत्वपूर्ण मोड़ दिए। विशेष रूप से, निवेश को - जो वस्तुओं का उत्पादन है और जिसके बदले अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है - भारत की काया पलट करने वाला माना जा रहा है क्योंकि अधिकांश विकासशील देशों में पूंजी की कमी है। निवेश दर (कुल निवेश बटा जीडीपी) को व्यापक रूप से भारत में संवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है।

भारत में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि हमारी संवृद्धि घरेलू-वित्तपोषित है - निवेश मुख्य रूप से घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित है, विदेशी बचत केवल एक पूरक भूमिका निभाती है। एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2007-08 से बचत दर धीमी होने लगी है। आखिरकार, इसने निवेश दर को नीचे खींच लिया, जिसने 2012-13 से मंदी का प्रदर्शन किया है। उच्च संवृद्धि हासिल करने के लिए इस प्रवृत्ति को उलटना महत्वपूर्ण है।

देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) में चालू खाता घाटा (सीएडी) यह निर्धारित करता है कि देश में कितनी बाह्य बचत या निवल पूंजी अंतर्वाह को अवशोषित अथवा संवृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं जबकि आयात के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। भारत जैसा देश उन वस्तुओं के आयात के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों पर निर्भर है जिनका हम उत्पादन नहीं करते हैं जैसे कि कच्चा तेल और ऐसी मशीनरी, उपकरण और तकनीक जैसी वस्तुएं जिनमें या तो अन्य देशों के पास तुलनात्मक लाभ है या उनके पास उपलब्धता अधिक है। भारत के लिए, आयात आम तौर पर निर्यात से अधिक होता है, इसलिए आयात भुगतान की पूर्ति हेतु विदेशी मुद्रा से पर्याप्त कमाई नहीं होती है। इस अंतराल को विदेश से उधार लेकर भरा जाता है, हालांकि, इसको मूलधन और ब्याज का भुगतान कर चुकाया जाता है। यदि कर्ज़ की चुकौती हमारी आय से अधिक हो जाती है, तो हमें या तो आयात कम करना होगा और अपनी संवृद्धि संभावनाओं को संकुचित करना होगा या कर्ज़ अदायगी में चूक करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय अलगाव को झेलना पड़ेगा। हमारा अनुभव रहा है कि भारत बाहरी क्षेत्र के संकट में पड़े बिना 2.5-3.0 प्रतिशत का चालू खाता घाटा बनाए रख सकता है। वास्तव में, इस तथ्य की याद दिलाते हुए, तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि और स्वर्ण-आयात आधिक्य ने चालू खाता घाटा को प्लिमसल लाइन से ऊपर और 2011-13 के दौरान ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँचा दिया। जब यूएस फेडरल रिज़र्व ने 2013 की गर्मियों में सहज मौद्रिक नीति के अंत पर विचार किया, तो भारत को टेपर घटनाक्रम का सामना करना पड़ा और उसे कमज़ोर पांच का नाम दिया गया।[3]

अंतर-देशीय परिप्रेक्ष्य

थोड़ा पीछे जाकर, अंतर-देशीय परिवेश में भारत की प्रगति का निरीक्षण करना उपयोगी होगा। मैं 1960 के दशक की शुरुआत से दुनिया की शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं के उत्थान और पतन की ओर मुड़ना चाहता हूं जब एशिया के विकासशील देशों ने दो शताब्दियों के पश्चिमी वर्चस्व के बाद नई शुरुआत के लिए रणनीतियां बनानी शुरू कीं। जापान का युग ध्यान देने योग्य है जो 1960 के दशक में शुरू हुआ और 1970 और 1980 के दशक तक चला। चीन का युग 1990 के दशक के आरंभ में शुरू हुआ, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति में ले गया। 2015 से भारत का समय आता दिख रहा है। आज भारत बाजार विनिमय दरों के मामले में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

[3] कमज़ोर पांच- ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की थे।

वर्ष 2022 के लिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 में 3.2 प्रतिशत की वैश्विक संवृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2021 के 6.1 प्रतिशत से कम है। भारत को 2022 में 7.4 प्रतिशत की संवृद्धि का अनुमान है। महामारी और यूरोप में युद्ध के बावजूद, भारत वैश्विक संवृद्धि में लगभग 14 प्रतिशत का योगदान करने जा रहा है। वास्तव में, भारत चीन के बाद 2022 में वैश्विक संवृद्धि का **दूसरा** सबसे महत्वपूर्ण चालक हो सकता है।

जीडीपी द्वारा मापे गए आर्थिक प्रदर्शन की परस्पर-तुलना के लिए बाजार विनिमय दरों के उपयोग पर सवाल उठाए गए हैं। आखिरकार, विनिमय दरें अस्थिरता और विचलन-वृत्ति से प्रभावित होती हैं जो उन्हें वास्तविकता से अलग कर देती हैं। क्रय शक्ति समता एक वैकल्पिक उपाय है। यह माल (वस्तु) और सेवाओं की एक औसत बास्केट की कीमत है जिसकी प्रत्येक देश में आजीविका के लिए एक परिवार को आवश्यकता होती है। एक अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण मैकडॉनल्ड का बर्गर है, जिसके बारे में माना जाता है कि हर देश में हर आउटलेट में एक ही गेहूं, आलू और अन्य सामग्री होती है। आपको यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, एक बड़े मैक के लिए यूएस में भुगतान किए गए पैसे से भारत में 2.5 मैक खरीद सकते हैं।

तो, यह हमें विनिमय दर और जीडीपी के बारे में क्या बताता है? वर्तमान में भारत, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका वैश्विक जीडीपी में 7 प्रतिशत हिस्सा है [चीन (18 प्रतिशत) और अमेरिका (16 प्रतिशत) के बाद]। बाजार विनिमय दरों में भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उस वर्ष तक, क्रय शक्ति समता के संदर्भ में भारत की जीडीपी 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2021 में यूएस $ 10 ट्रिलियन से अधिक) से अधिक हो जाएगी। ओईसीडी की 2021 की गणना बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2048 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगी। यह भारत को चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा।

पीपीपी के संदर्भ में, विनिमय दर किसी राष्ट्र की समृद्धि और उसकी उत्पादकता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। इंडोनेशियाई रुपिया दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा बनने के लिए तैयार है, जबकि भारतीय रुपया दूसरी सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में उभर रहा है।

अवसर

आज भारत जहां है, उसकी विहंगम छवि के साथ, मैं उन चार इंजनों की चर्चा करूँगा जो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने हेतु उदीयमान अर्थव्यवस्था रूपी कक्षा से उन्नयन के लिए पलायन वेग और शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

(i) जनसांख्यिकीय स्थिति

मैं, बहु-उद्धृत जनसांख्यिकीय लाभ की अंतर्निहित वास्तविकताओं के साथ शुरूआत करूँगा। 2021 में पहली बार दुनिया की जनसंख्या वृद्धि 1 प्रतिशत से नीचे गिर गई। यह इस सदी के बाकी समय में धीमी हो जाएगी। 1.38 बिलियन की भारत की आबादी 28.4 वर्ष की दुनिया की सबसे युवा आबादी है। 2023 तक (यानी अगले साल), भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश (1.43 बिलियन) होगा।[4]

2045 तक वृद्धावस्था के कारण भारत के युवा होने के लाभ बंद हो जाएँगे, जैसा कि 2004 में जापान और 2002 में इटली में हुआ था। यह जनसंख्या की बदलती संरचना से स्पष्ट है। एक प्रमुख संकेतक कुल प्रजनन दर है - एक महिला के अपने जीवनकाल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या। भारत के नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2019-21) के निष्कर्षों के अनुसार, 2.0 की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (2015-16 में 2.2 से नीचे और 2005-06 में 2.7) पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, 2.1 से कम कुल प्रजनन दर[5] वाली पीढ़ी अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप उस देश की जनसंख्या में एकमुश्त कमी आती है। दूसरी ओर, भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और 2099 तक लगभग 70 वर्षों के वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 82 वर्ष होने की संभावना है।

भारत की कामकाजी-आयु[6] जनसंख्या (डब्ल्यूएपी) के अनुपात की कुल जनसंख्या के साथ अन्य देशों, अर्थात, चीन, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की तुलना से पता चलता है कि भारत लाभप्रद स्थिति में है। इन देशों की कामकाजी

[4] विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2022; संयुक्त राष्ट्र, जुलाई 2022।

[5] प्रति महिला बच्चों की संख्या।

[6] 15 - 64 वर्ष के रूप में परिभाषित।

आयु वाली आबादी पहले से ही घटनी शुरू हो गई है, जबकि भारत का डब्ल्यूएपी अनुपात 2045 तक बढ़ जाएगा, यहां तक कि 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगा। इस जनसांख्यिकीय लाभ का अधिकतम उपयोग करना भारत के लिए अवसर के साथ-साथ एक चुनौती भी है।

(ii) विनिर्माण

उड़ान के लिए एक और इंजन विनिर्माण है। भारत के विकास के अनुभव को व्यापक रूप से उल्लेखनीय माना गया है क्योंकि यह प्राथमिक गतिविधियों से द्वितीयक और फिर तृतीयक गतिविधियों की ओर बढ़ने वाले देश के सामान्य पथ से अलग हो गया है।[7] भारत ने द्वितीयक चरण के उपर छलांग लगाकर प्राथमिक गतिविधियों से तृतीयक क्षेत्र की ओर आ गया। आज सेवा क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में दो-तिहाई हिस्सा है।

पीछे देखने पर, भारतीय अनुभव का यह चमत्कार नहीं हो सकता था जैसा अभिहित किया जाता है - भारत, कृषि से पलायन करने वाले अपने कम-कुशल श्रम बल को बड़े पैमाने पर लाभकारी रोजगार में अवशोषित करने में विफल रहा। इस श्रम अवशोषण क्षमता के अलावा, विनिर्माण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ पश्चगामी और अग्रगामी संबंध हैं। भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण में सशक्त वृद्धि जरूरी है। इसलिए यह आवश्यक है कि पारंपरिक विवेक को बदलकर और दुनिया के अन्य अग्रणी विनिर्माताओं के साथ रफ्तार बना ली जाए।

विश्व बैंक के अनुसार, भारत का विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में (स्थिर 2015 के अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) विश्व औसत के साथ-साथ अधिकांश साथी-देशों से बहुत नीचे है। भारतीय विनिर्माण की वृद्धि काफी अस्थिर रही है, जो 17.8 प्रतिशत (2006-07) के शिखर और -3.2 प्रतिशत (1979-80) के निचले स्तर के बीच रही है। 1990 के दशक से विनिर्माण में औसत वृद्धि 7.0-7.5 फीसदी रही है। यदि अगले दशक में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की जाती है, तो विनिर्माण 2030-31 तक समग्र वर्धित सकल मूल्य (जीवीए) के 20.4 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अगर विनिर्माण को - 'मेक इन इंडिया' अभियान द्वारा निर्धारित लक्ष्य -10 फीसदी की दर से बढ़ना है तो इसका हिस्सा 2030-31 में 25 फीसदी तक पहुंच जाएगा। रोजगार और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव के साथ भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर बन जाएगा।

इसे हासिल करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, विनिर्माण क्षेत्र को चौथी औद्योगिक क्रांति (ऑटोमेशन; डेटा एक्सचेंज; साइबर-फिजिकल सिस्टम; इंटरनेट ऑफ थिंग्स; क्लाउड कंप्यूटिंग; कॉग्निटिव कंप्यूटिंग; स्मार्ट फैक्ट्री; और उन्नत रोबोटिक्स)[8] के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, भारत को मानव पूंजी में निवेश बढ़ाकर एक कुशल श्रम शक्ति का विकास करना चाहिए। तीसरा, विनिर्माण को वैश्विक बाजारों में उपस्थिति की तलाश हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। वैश्विक विनिर्माण केंद्र (हब) बनने के लिए भारत को जीडीपी के कम से कम 25 फीसदी तक विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।

(iii) निर्यात

निर्यात राष्ट्रीय सीमाओं से परे बाजारों और उत्पादन क्षमताओं के विस्तार के लिए एक अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत के माल और सेवाओं का निर्यात 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है, जो दुनिया के कुल निर्यात का 2.7 प्रतिशत है। भारत सरकार ने 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे भारत की हिस्सेदारी वैश्विक कुल का 5 प्रतिशत हो जाएगी और भारत एक निर्यात महाशक्ति बन जाएगा। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए कई पहल की जा रही हैं:

- एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' की अवधारणा को एकीकृत करती है;
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना निर्यातित माल पर - निर्यात मूल्य के 0.5 - 4.3 प्रतिशत के रेंज में - प्रतिदेय करों के

[7] प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खनन और उत्खनन से संबंधित है; द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि विनिर्माण, बिजली उत्पादन और निर्माण से संबंधित है; तृतीयक गतिविधि सेवाओं से संबंधित है।

[8] पहली औद्योगिक क्रांति 1760-1900 के दौरान हुई, जो कोयला, भाप के इंजन और ट्रेनों द्वारा संचालित थी। दूसरी क्रांति 1870-1940 के बीच तेल, बिजली, अंतर्दहन इंजन और कार द्वारा संचालित हुई। तीसरी क्रांति 1930-2000 के बीच हुई और यह परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कंप्यूटर, रोबोट और विमानों पर आधारित थी।

रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है जो लगभग 8555 उत्पाद लाइनों को कवर करता है।

- उभरते सितारे योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनकी निर्यात क्षमता को साकार करने में सहायता करती है;
- राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) योजना का उद्देश्य परिधान/गारमेंट्स के निर्यात को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस योजना के तहत, परिधान, वस्त्र और मेड-अप के निर्यातकों को एम्बेडेड टैक्स और लेवी वापस कर दिए जाते हैं, जिस पर वर्तमान में किसी अन्य तंत्र के तहत छूट नहीं दी जा रही है;
- आईटी और डिजिटल सेवाओं, उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों, उच्च मूल्य वाले पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, खुदरा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में निर्यात क्षमता का दोहन किया जाना है।

विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कम से कम 5 प्रतिशत तक बढ़ाना पहुंच के भीतर है।

(iv) अंतरराष्ट्रीयकरण

भारतीय दुनिया में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीयकृत लोगों में से हैं। भारतीय डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है और भारत धन-प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता है। भारतीय रुपया देशस्थ की तुलना में तीन गुना अधिक विदेशस्थ व्यापार करता है। फिर भी हम अभी भी अंतरराष्ट्रीयकरण की बात करते हैं जैसे कि यह एक अंतिम सीमा है। अर्थशास्त्री नियाल फर्ग्यूसन लिखते हैं कि मानव इतिहास में 70 साम्राज्य हुए हैं। 69वां और 70वां साम्राज्य क्रमशः चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ हैं। 68वें साम्राज्य में एक साम्राज्य के सभी गुण हैं, जिसमें अपनी सीमाओं से परे युद्ध छेड़ना भी शामिल है। फिर भी यह मौलिक तरीके से भिन्न है - यह विदेशी भूमि को अपने में शामिल नहीं करता है। फर्ग्यूसन इसे उदासीन साम्राज्य कहते हैं - यह यूएसए है। एक सादृश्य बनाते हुए, भारत को एक उदासीन अंतरराष्ट्रीयकारी के रूप में माना जा सकता है। यदि भार.रु. (आईएनआर) का कुल कारोबार वैश्विक विदेशी मुद्रा कुल कारोबार (4 प्रतिशत) में गैर-अमेरिकी गैर-यूरो मुद्राओं के हिस्से के बराबर हो जाता है, तो आईएनआर एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में सामने आ चुका होगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को दर्शाएगा।

चुनौतियाँ

आइए अब मैं उन चुनौतियों का समाधान करता हूं जो उड़ान भरते समय रनवे पर हमारे सामने आती हैं। मेरे विचार से फोकस चार प्रमुख चुनौतियों पर होना चाहिए। पहली, **महामारी के कारण उत्पादन और आजीविका का नुकसान है।** आपूर्ति में व्यवधान, स्वास्थ्य संकट, एक ऐतिहासिक सामूहिक प्रवासन और शत्रुतापूर्ण वैश्विक वातावरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला। मांग में कमी और आपूर्ति में व्यवधान का संयोजन जो महामारी में शुरु हुआ था, से गंभीर प्रभाव पड़ा। जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6.6 प्रतिशत तक सिकुड़ गई। उस वर्ष की पहली तिमाही में जब महामारी की पहली लहर भड़की थी, जीडीपी 24 प्रतिशत तक सिकुड़ गई थी, जो दुनिया में सबसे तीव्र थी। यदि एक ट्रेंड लाइन को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर फिट किया जाता है और 2013-20 में प्रचलित 6.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 2021-22 तक बढ़ाया जाता है, तो वास्तविक जीडीपी के साथ इस प्रवृत्ति जीडीपी की तुलना में 2020-21 और 2021-22 महामारी के कारण हुए नुकसान का एक स्थूल आकलन मिलेगा।

इस उत्पादन हानि की भारपाई में कई साल लग सकते हैं – मैं, इसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मानता हूँ।

दूसरी चुनौती भारत का **अवसंरचना अंतराल** है। अवसंरचना (बुनियादी ढांचा) में भारत का प्रति व्यक्ति निवेश दुनिया में सबसे कम है (स्थिर 2015 डॉलर में 88.6 अमेरिकी डॉलर)। भारत द्वारा अवसंरचना निवेश वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.6 प्रतिशत है। यदि भारत सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के बराबर अवसंरचना में निवेश करता है, तो यह 2030 तक यूएस $7.5 ट्रिलियन का जीडीपी स्तर हासिल कर लेगा- जैसा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब[9] द्वारा अनुमान लगाया गया है; और अवसंरचना अंतराल समाप्त हो जाएगा। यह 2027 तक 5 ट्रिलियन

[9] जी20 द्वारा समर्थित एक गैर-लाभकारी संगठन।

अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप भी है।

अवसंरचना निर्माण (इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव) के लिए मुख्य आवश्यकताएं पारदर्शी और तेज विनियामक प्रक्रियाएं; स्पष्ट, पारदर्शी और कुशल भूमि अधिग्रहण और जलवायु मंजूरी नीतियां; और व्यवहार्य अवसंरचना वित्त हैं जो अवसंरचना परियोजनाओं की संकल्पनात्मक अवधि को भी ध्यान में रखे। विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण भारत की उड़ान के लिए अगली बड़ी चुनौती है।

तीसरी चुनौती एक **उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति** का विकास करना है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में, गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में श्रम का योगदान विकसित और कई उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है। 83 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे-जैसे भारत एक विनिर्माण केंद्र और निर्यातक महाशक्ति के रूप में बदल रहा है, कार्यबल को समय के साथ विस्तार और अधिक कुशल बनना होगा। मात्रा के बजाय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। भारत की कुल श्रम शक्ति में, रोजगार योग्यता (किसी विशेष नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल) 50 प्रतिशत से कम है। इस बाधा को तोड़ने का एक महत्वपूर्ण उत्तोलक, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। विश्व बैंक, (वैश्विक विकास संकेतक) के अनुसार, भारत 2020 में महिला श्रम बल भागीदारी दर के मामले में 187 देशों में 178वें पायदान पर है।

हमें ऐसे कार्यस्थलों का निर्माण करना चाहिए जो कार्यस्थल पर महिलाओं को कलंकित न करें और इसके बजाय उन्हें सम्मान और संतुष्टि के साथ अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए कामकाजी महिलाओं के पक्ष में सामाजिक सोच निर्मित करने; छात्रों और कर्मचारियों की विविधता बनाए रखने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन देने; काम के सुविधाजनक घंटे; कार्यस्थलों पर महिलाओं की सहूलियत के लिए नीतियां और सुविधाएं, सहित जो कामकाजी माता-पिता के लिए अनुकूल कराधान प्रणाली, कार्यस्थलों पर अनिवार्य मातृत्व/पितृत्व अवकाश, घर के करीब काम की उपलब्धता और नौकरियों के अधिक अवसर निर्मित करने, की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति विकसित करने के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

चौथी चुनौती **हरिततर और स्वच्छतर** भारत है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन 26 (सीओपी26) में, भारत ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पंचामृत नामक पांच प्रतिज्ञाएँ लीं। इनमें शामिल हैं (i) 2030 तक 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना; (ii) 2030 तक 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा युक्त ऊर्जा मिश्रण; (iii) अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करना; (iv) 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45 प्रतिशत से कम करना; और (v) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को यथासंभव शून्य के करीब लाकर 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त-स्तर महत्वपूर्ण है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद[10] ने अनुमान लगाया है कि 2070 तक निवल-शून्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए यूएस $10.1 ट्रिलियन के संचयी निवेश की आवश्यकता है। इसमें से, यूएस $8.4 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता अकेले बिजली क्षेत्र रूपांतरण - नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव - को पूरा करने के लिए है। उद्योग (कोयले में कमी और हाइड्रोजन के उपयोग में वृद्धि) के लिए यूएस $1.5 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी, और जंगम क्षेत्र (मोबिलीटी सेक्टर) को यूएस $198 बिलियन की आवश्यकता होने का अनुमान है।

हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में उम्मीद की किरण है। 2030 तक 500 जीडब्ल्यू तक पहुंचने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को 14.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ना चाहिए। विकास की वर्तमान औसत दर 18.7 प्रतिशत (2014-15 से 2020-21) पर, हम 2027 तक 500 जीडब्ल्यू लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वास्तविक बिजली खपत के समय के बीच अंतर को कम करने के लिए भारत को पर्याप्त ऊर्जा भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता होगी। हमें संचार और वितरण में होने वाली क्षति को कम करना होगा। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रीय संकेन्द्रण को ठीक करना होगा क्योंकि यह स्थान विशिष्ट - ज्यादातर दक्षिणी राज्य - है और समान रूप से वितरित नहीं है। उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वाली क्रॉस-सब्सिडी से बचते हुए टैरिफ संरचना में वास्तविक लागत प्रतिबिंबित होना चाहिए। साथ ही, हमें डिस्कम्स के पुराने कर्ज की समस्या का समाधान खोजना होगा।

[10] एशिया का अग्रणी गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान।

निष्कर्ष

यदि भारत अपने अवसरों को भुनाता है और इस वार्ता में मैंने जिन चुनौतियों का उल्लेख किया है, उन पर काबू पा लेता है, तो यह व्यापक रूप से माना जा सकता है कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए, क्रय शक्ति समता अनुमानों पर फिर से विचार करते हुए, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में 11 प्रतिशत की संवृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगा। यदि यह हासिल हो जाता है, तो भारत 2048 तक नहीं बल्कि 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जैसा कि पहले कहा गया है। यहां तक कि अगर यह इस गति को बनाए नहीं रखता है और 2040-50 के दौरान 4-5 प्रतिशत तक धीमा हो जाता है, तो यह 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

जैसा कि मैंने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा था, आप सोच सकते हैं कि मैं एक सपने देखने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब इतिहास खुद को दोहराता नहीं है तो यह अक्सर अपनी चाल की पुनरावृत्ति करता है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री आंगस मैडिसन जो आर्थिक संवृद्धि और विकास के मापन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं, ने दुनिया के हर महाद्वीप के प्रमुख देशों के आर्थिक प्रदर्शन का लंबे समय तक दस्तावेजीकरण किया है। उनके कार्यों के अनुसार 1 से 1000 ईस्वी के दौरान विश्व जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अगले 600 वर्षों में, भारत रुक-रुक कर दूसरे स्थान पर आ गया, लेकिन 1700 ईस्वी तक विश्व जीडीपी के 24.4 प्रतिशत हिस्से के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान पुनः प्राप्त कर लिया। तब से, इस हिस्सेदारी की अपूरणीय क्षति हुई है। देवियो और सज्जनो, समय आ गया है कि इस गिरावट को रोका जाए और इसे पलट कर विश्व मंच पर अपना उचित स्थान पुनः हासिल किया जाए।

धन्यवाद !

अनुबंध

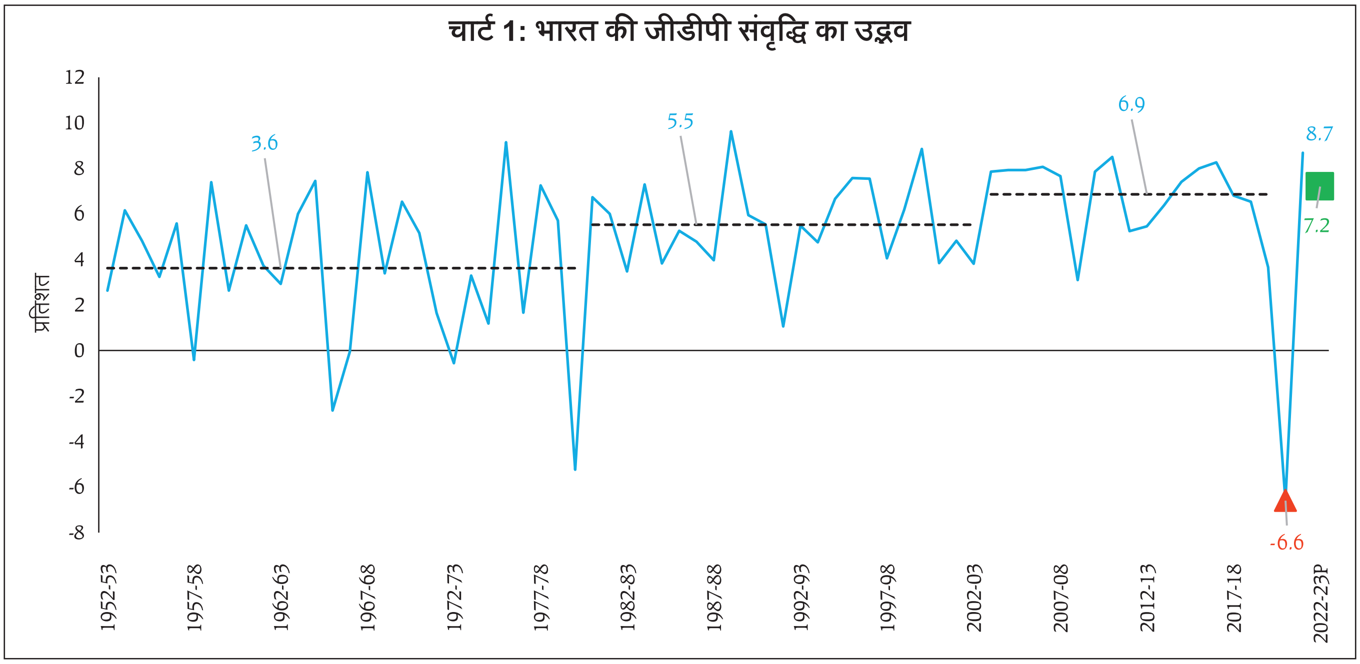

चार्ट 1: भारत की जीडीपी संवृद्धि का उद्भव
प्रतिशत
3.6
5.5
6.9
8.7
7.2
-6.6
1952-53
1957-58
1962-63
1967-68
1972-73
1977-78
1982-83
1987-88
1992-93
1997-98
2002-03
2007-08
2012-13
2017-18
2022-23P

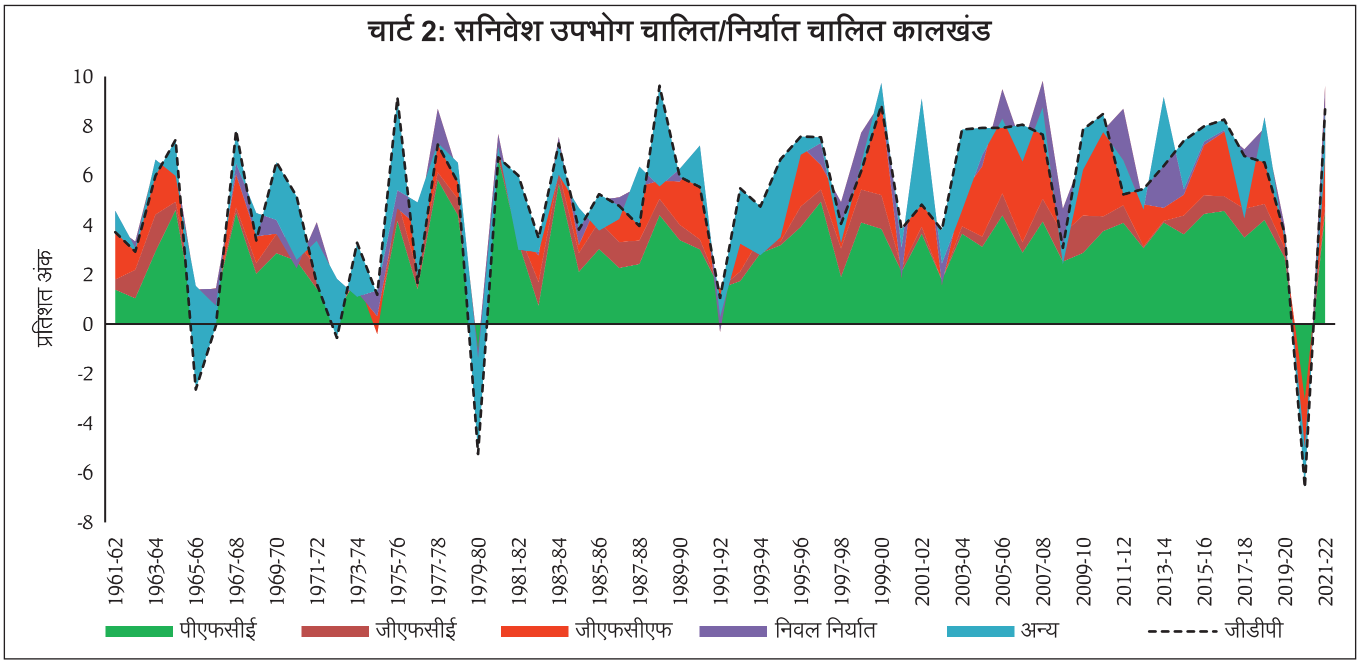

चार्ट 2: सनिवेश उपभोग चालित/निर्यात चालित कालखंड
प्रतिशत अंक
पीएफसीई
जीएफसीई
जीएफसीएफ
निवल निर्यात
अन्य
जीडीपी

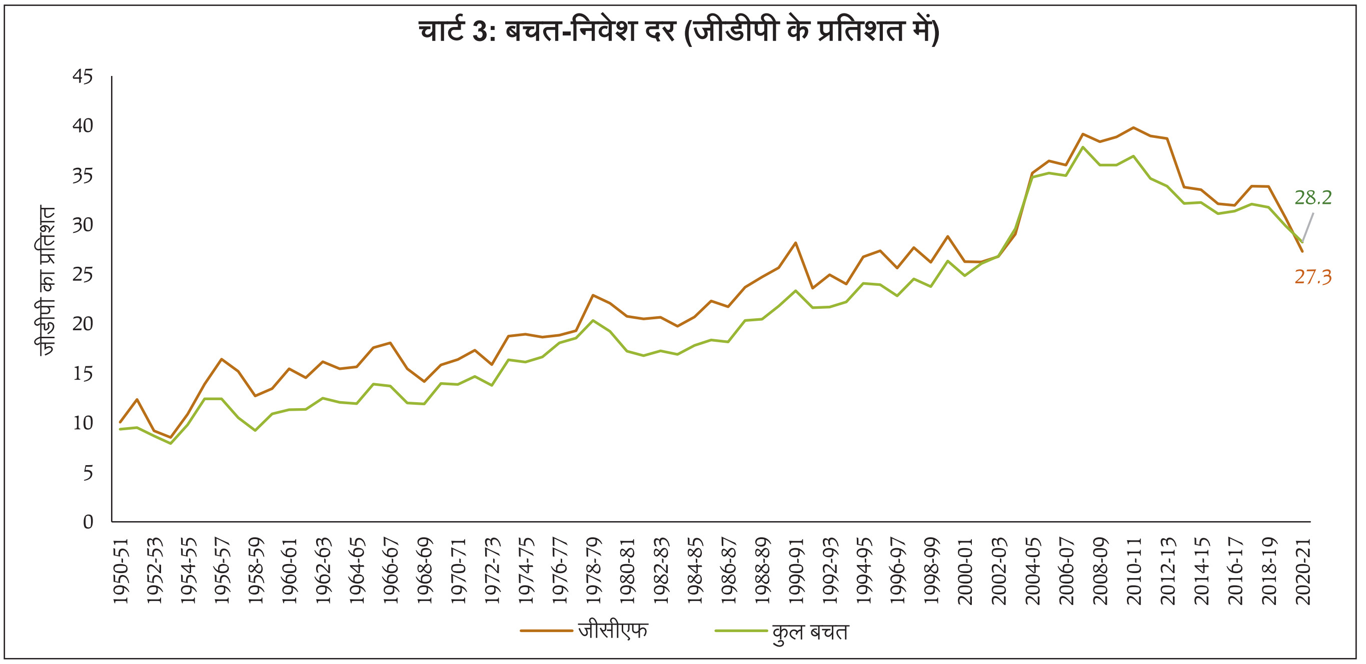
चार्ट 3: बचत-निवेश दर (जीडीपी के प्रतिशत में)
जीडीपी का प्रतिशत
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
28.2
27.3
1950-51
1952-53
1954-55
1956-57
1958-59
1960-61
1962-63
1964-65
1966-67
1968-69
1970-71
1972-73
1974-75
1976-77
1978-79
1980-81
1982-83
1984-85
1986-87
1988-89
1990-91
1992-93
1994-95
1996-97
1998-99
2000-01
2002-03
2004-05
2006-07
2008-09
2010-11
2012-13
2014-15
2016-17
2018-19
2020-21
जीसीएफ
कुल बचत

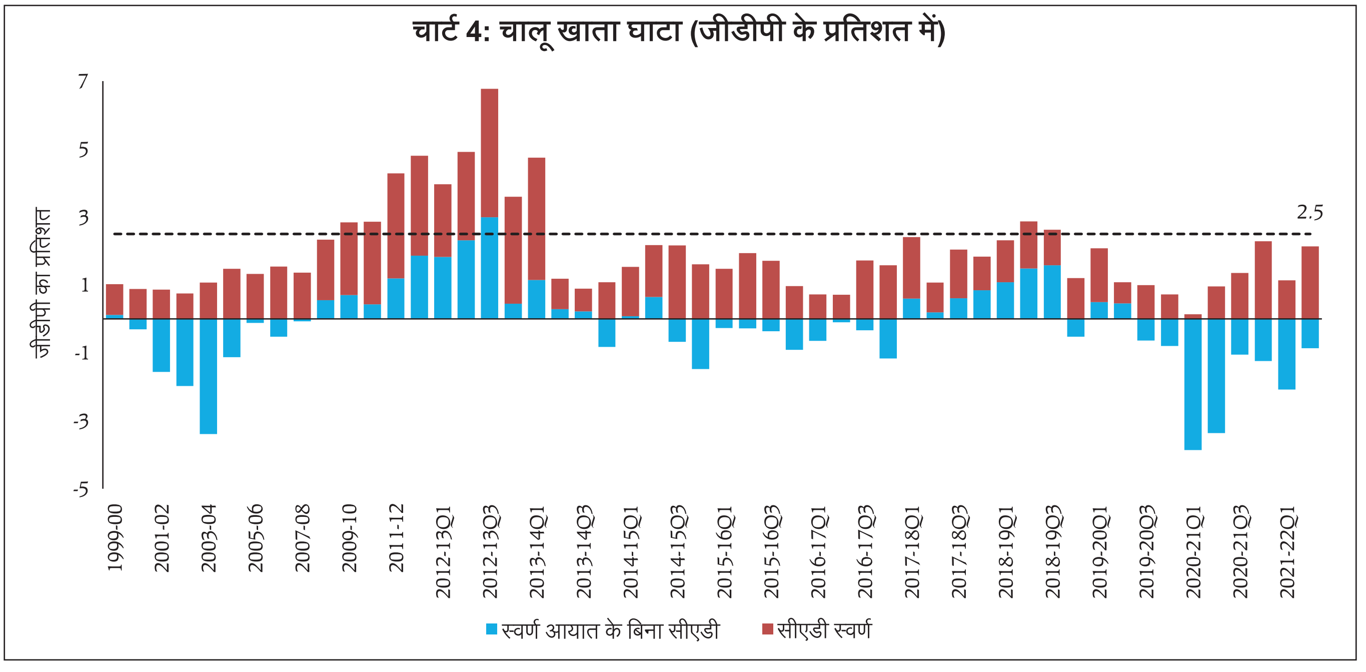
चार्ट 4: चालू खाता घाटा (जीडीपी के प्रतिशत में)
जीडीपी का प्रतिशत
7
5
3
1
-1
-3
-5
2.5
1999-00
2001-02
2003-04
2005-06
2007-08
2009-10
2011-12
2012-13Q1
2012-13Q3
2013-14Q1
2013-14Q3
2014-15Q1
2014-15Q3
2015-16Q1
2015-16Q3
2016-17Q1
2016-17Q3
2017-18Q1
2017-18Q3
2018-19Q1
2018-19Q3
2019-20Q1
2019-20Q3
2020-21Q1
2020-21Q3
2021-22Q1
स्वर्ण आयात के बिना सीएडी
सीएडी स्वर्ण

चार्ट 5: विश्व जीडीपी : संवृद्धि में योगदान

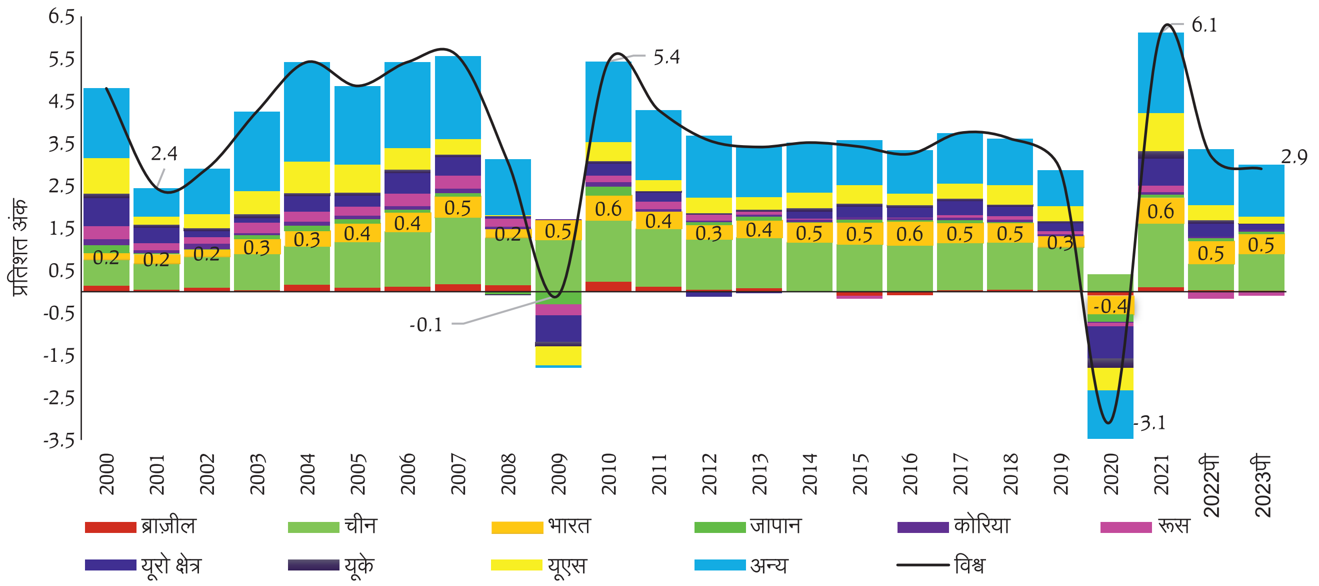

चार्ट 6: 2020 में विश्व जीडीपी में हिस्सेदारी (पीपीपी के रूप में)

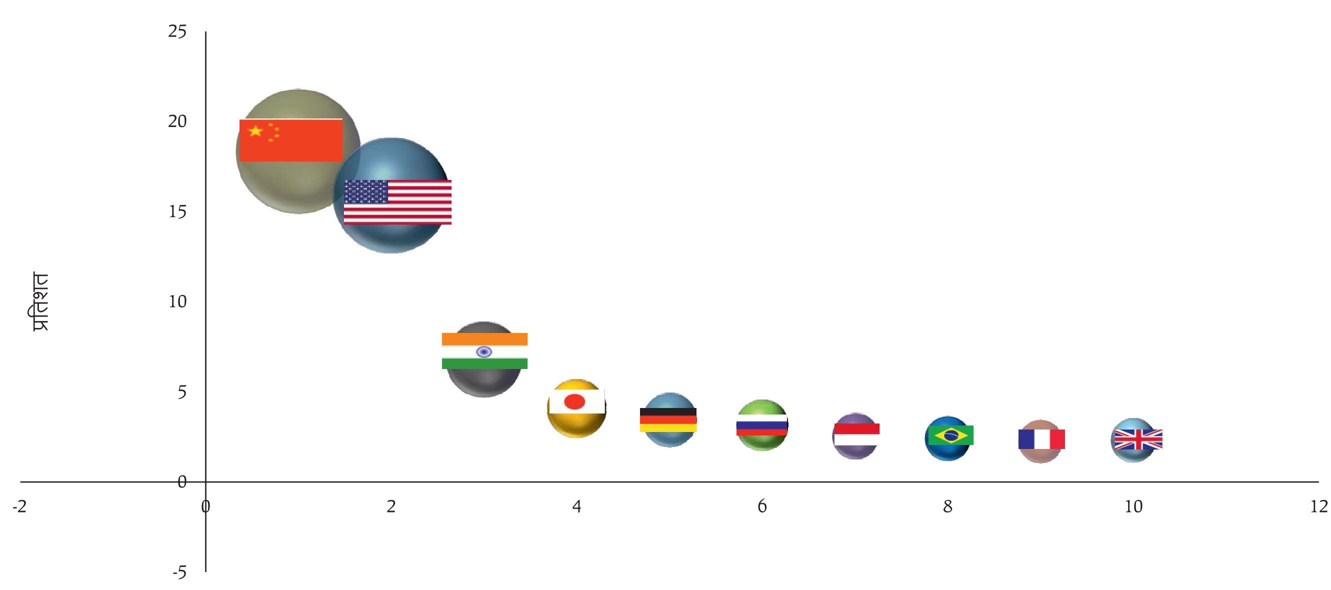

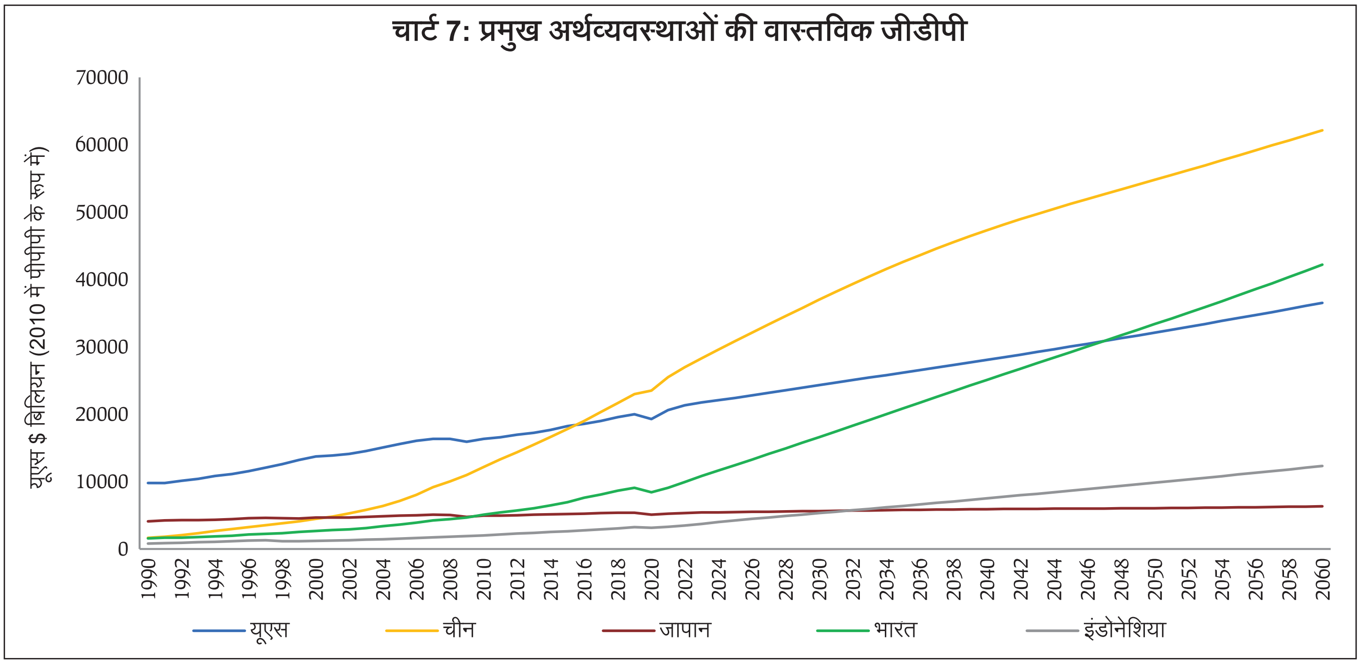
चार्ट 7: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जीडीपी
यूएस $ बिलियन (2010 में पीपीपी के रूप में)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060
यूएस
चीन
जापान
भारत
इंडोनेशिया

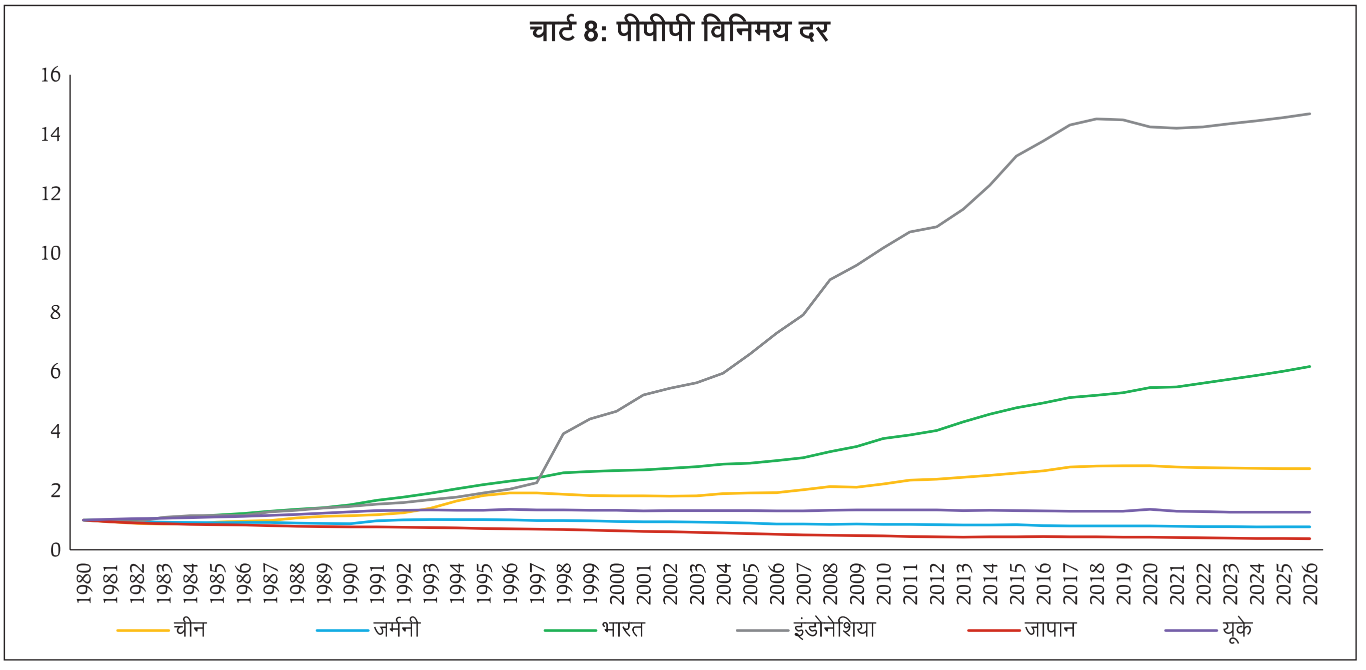
चार्ट 8: पीपीपी विनिमय दर
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
चीन
जर्मनी
भारत
इंडोनेशिया
जापान
यूके

चार्ट 9: जनसांख्यिकीय लाभ

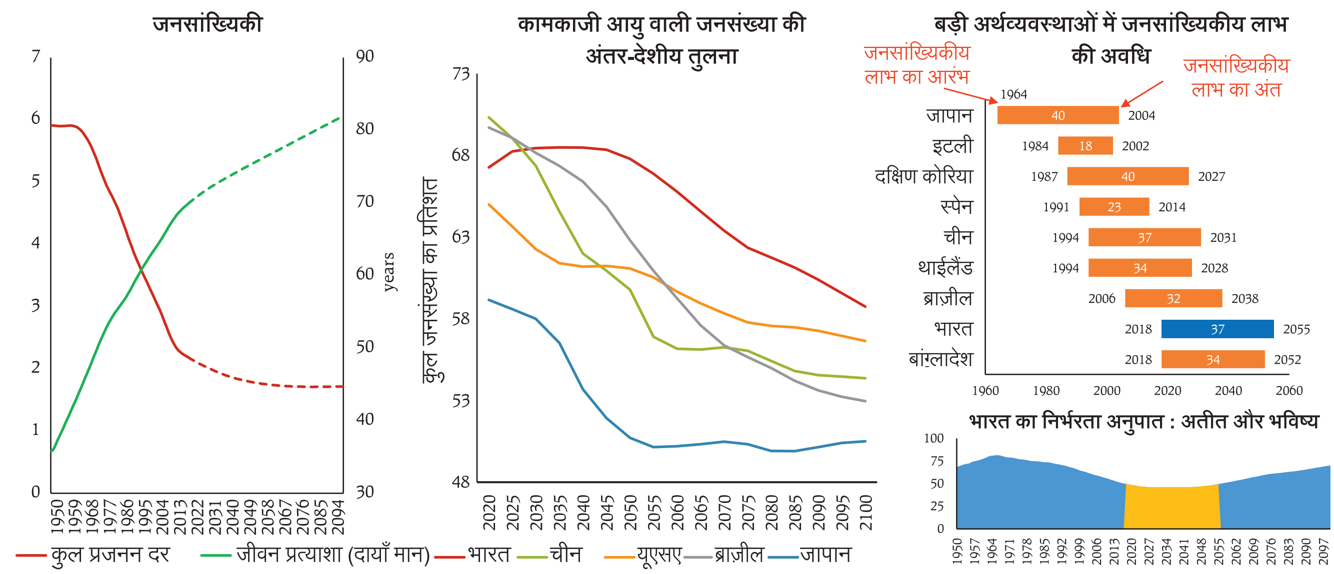

चार्ट 10: विश्व का विनिर्माण केंद्र

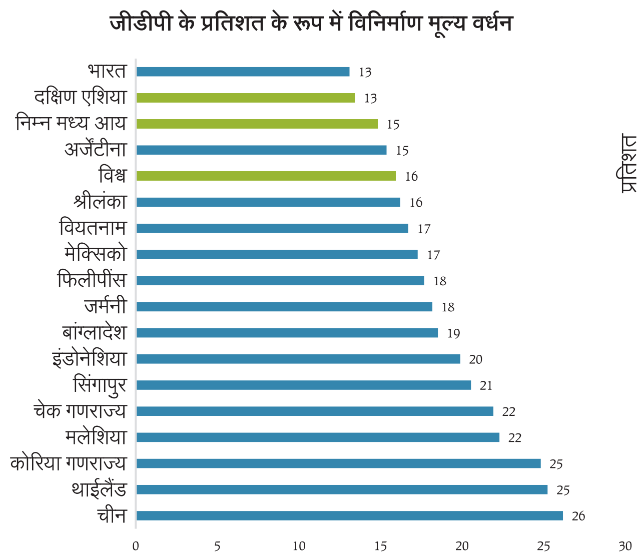

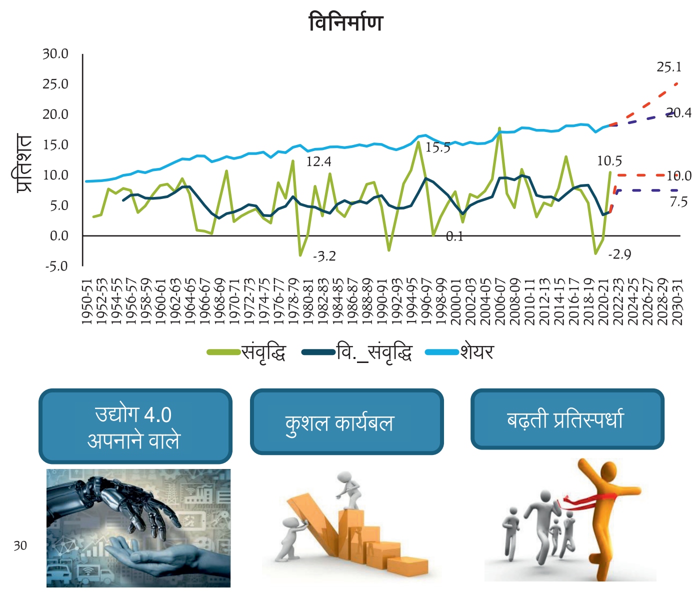

स्रोत: विश्व बैंक, वैश्विक विकास संकेतक

चार्ट 11: निर्यात महाशक्ति

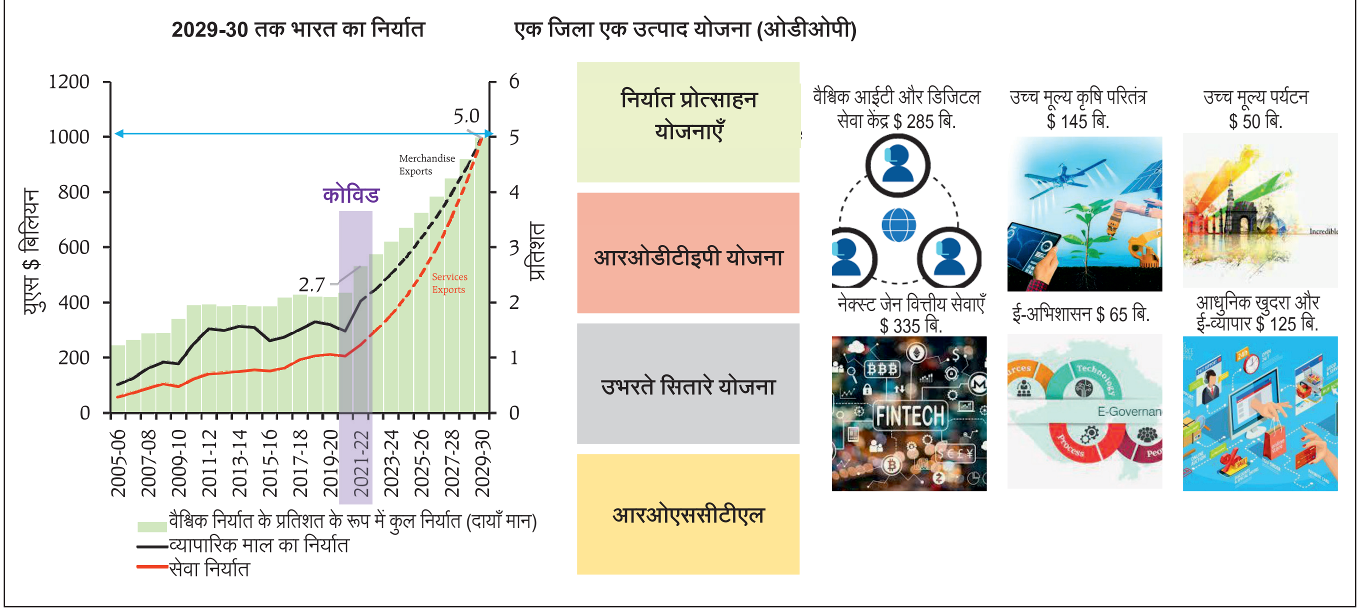

चार्ट 12: अंतरराष्ट्रीयकरण

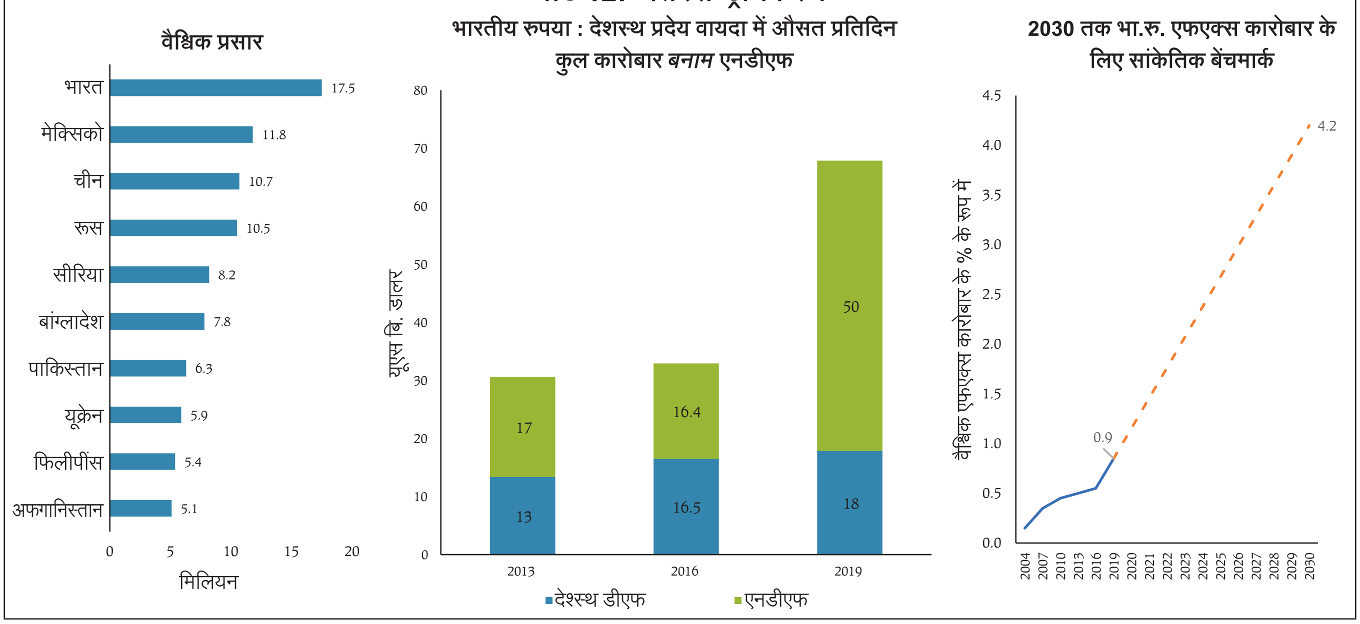

चार्ट 13: कोविड के आघात

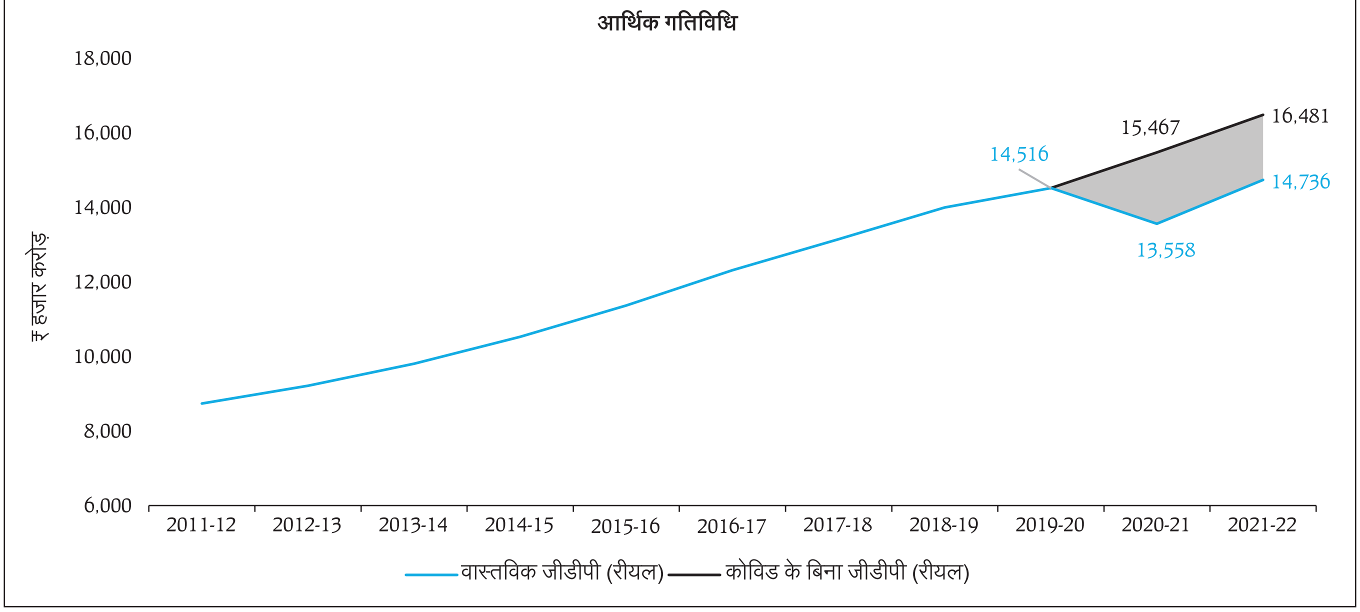

चार्ट 14: विश्व-स्तरीय अवसंरचना

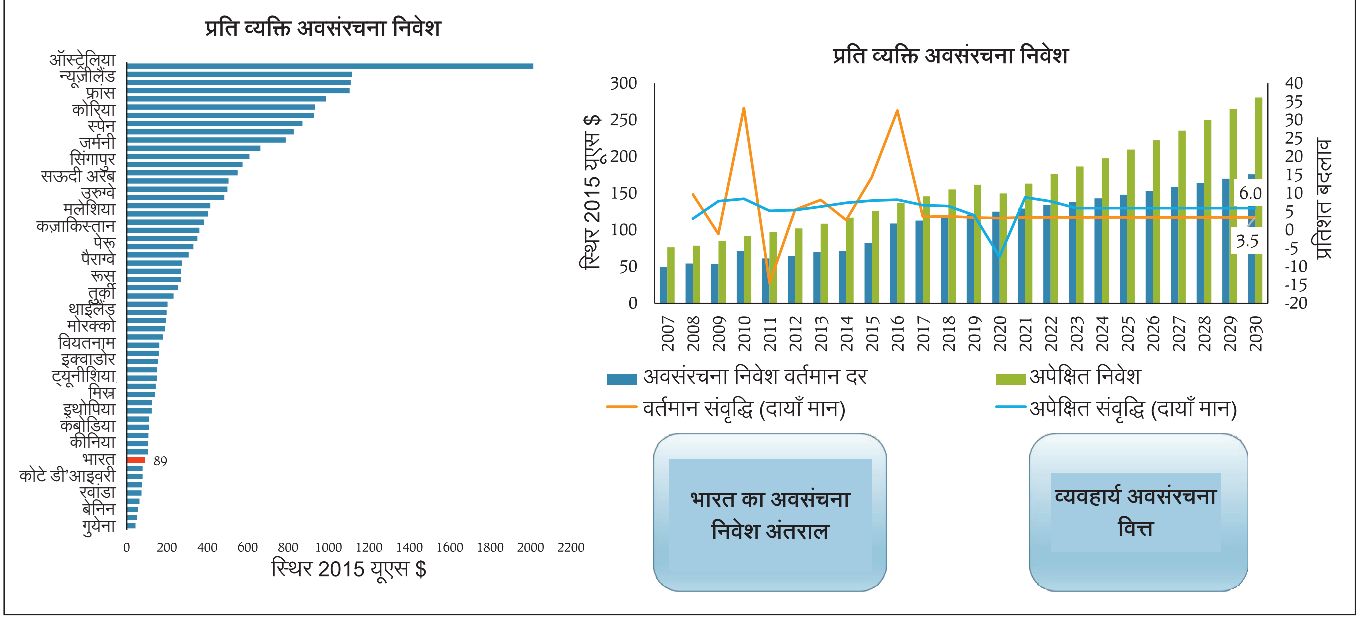

चार्ट 15: उच्च गुणवत्ता श्रम बल

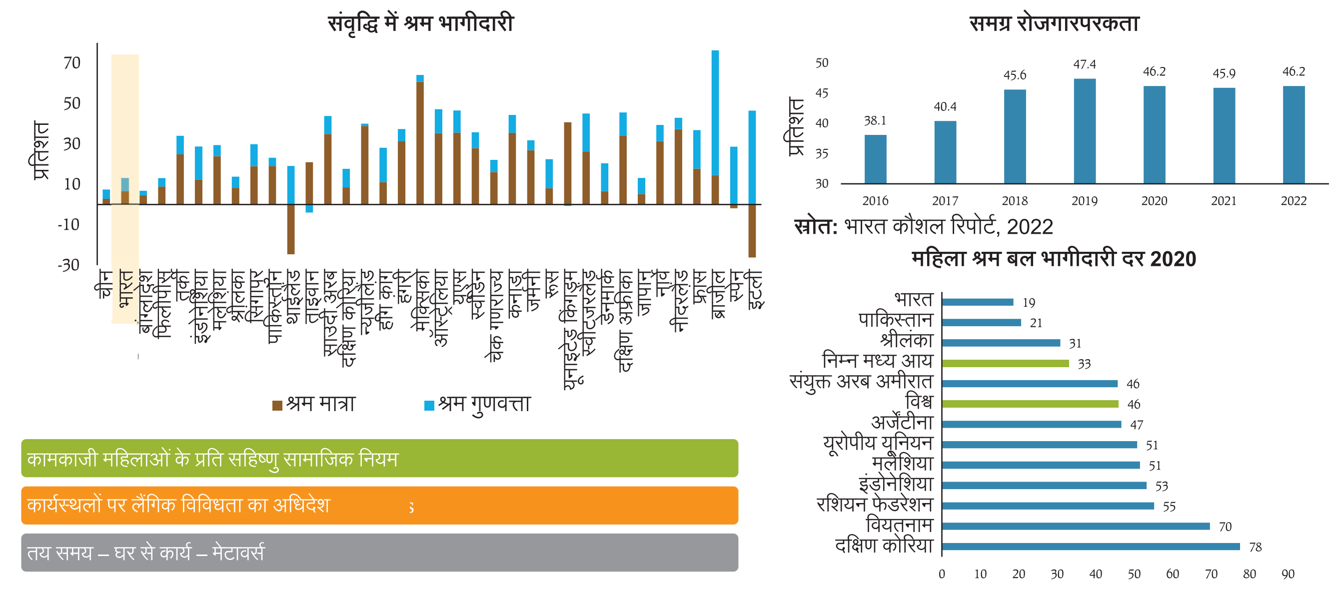

चार्ट 16: हरित भारत

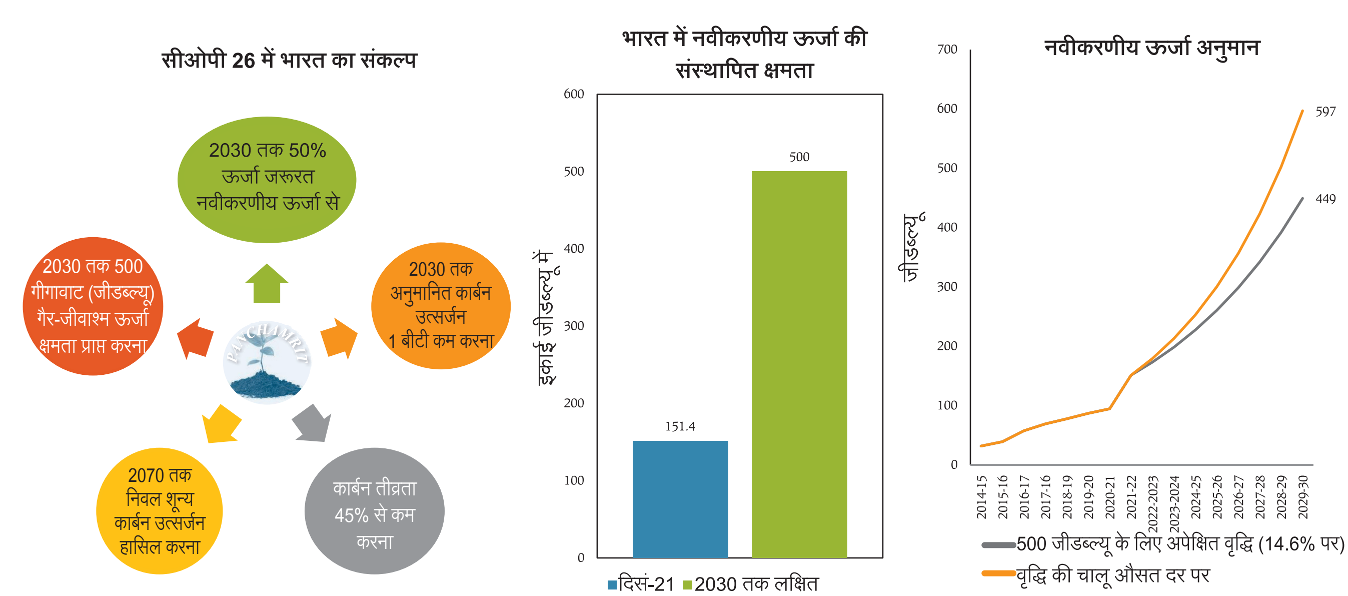

चार्ट 17: परस्पर तुलना

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक जीडीपी

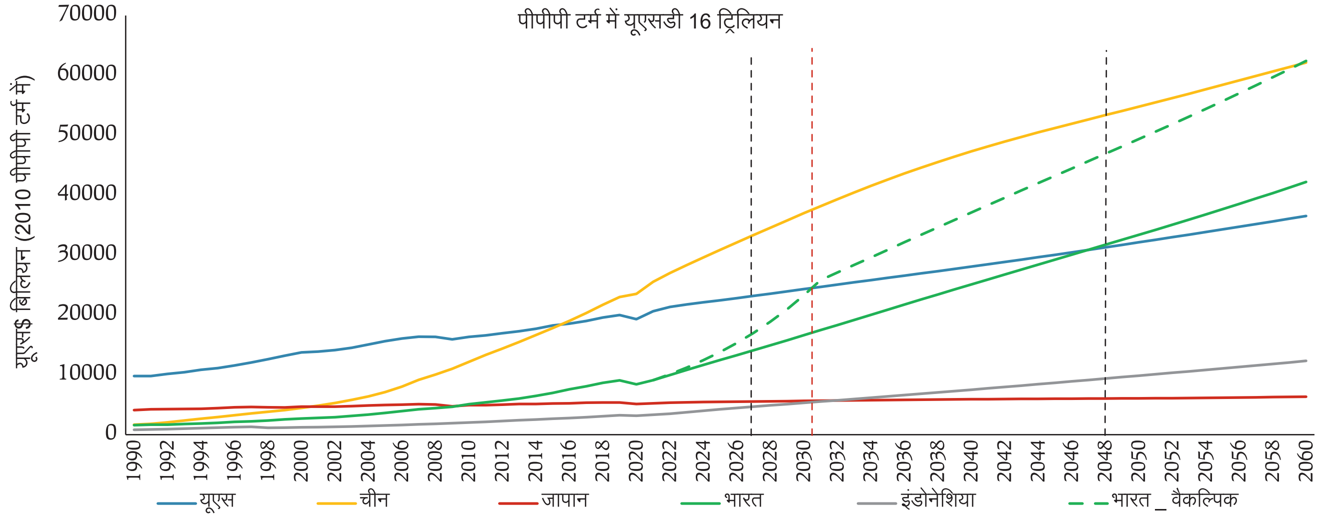

स्रोत: ओईसीडी (2021)

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य

तूफानी समुद्र में एक स्थिर जहाज: हाल के दिनों में एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्काल निगरानी

निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 के लिए दृष्टिकोण

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर में अस्थिरता

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

इस माह के दौरान वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं धूमिल हुई हैं। आपूर्ति शृंखला के दबाव में कमी और पण्य कीमतों में हालिया गिरावट, रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति से कुछ राहत प्रदान कर रही है। भारत में हाल ही में मॉनसून में तेजी, विनिर्माण में मजबूत गति और सेवाओं में सुधार के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है। त्योहारी मौसम की शुरुआत और बुवाई की गतिविधि में तेजी आने से ग्रामीण सहित उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सुदृढ़ पूंजी परिव्यय, निवेश गतिविधि का समर्थन कर रहे हैं। मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन इसके बढ़े स्तर की निरंतरता, आगे चलकर प्रत्याशाओं के लिए उचित नीतिगत प्रतिक्रिया की मांग करती है।

भूमिका

यह कहा गया है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, लेकिन यह अक्सर मिलता-जुलता है[1]। ठीक 25 वर्ष पहले, जैसे ही दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट का संक्रमण रूस, लॉन्ग-टर्म कैपिटल मैनेजमेंट (एलटीसीएम) और अंततः लैटिन अमेरिका तक फैला, इसने भारत में भी दस्तक दी। पहले से ही परमाणु परीक्षण के जवाब में भारत पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के उत्तर प्रभावों से जूझ रहे, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा बाजार को अस्थिर करने से उभरी चिंतनशील भावनाओं को खत्म करने के लिए अगस्त 1998 में उपायों के एक पैकेज की घोषणा की। नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की वृद्धि की गई और रिपो दर में 300 आधार अंकों की वृद्धि की गई। अलग डेटा की एक दुर्लभ इकाई बनी - रुपये की विनिमय दर की मौद्रिक नीति रक्षा। साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए वायदा रक्षा (फॉरवर्ड कवर) सुविधाओं को बढ़ाया गया, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति दी गई, आयात के लिए रद्द किए गए अनुबंधों को फिर से बुक करना और फॉरवर्ड और स्पॉट लेग्स को विभाजित करना अस्वीकृत कर दिया गया तथा निर्यात आय के प्रत्यावर्तन के प्रावधान और अधिक नियंत्रित हुए थे। ये उपाय रीसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स (आरआईबी) की योजना के सूत्रपात के साथ हुए।[2] भारत को 1998-99 में उच्च मुद्रास्फीति की चुनौती का भी सामना करना पड़ा - रिज़र्व बैंक की पसंदीदा मीट्रिक - थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में 6.9 प्रतिशत और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में 13.1 प्रतिशत। उस वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में इसे स्वीकारा गया: "सख्त विश्लेषणात्मक आधार पर, इस स्थिति में चलनिधि को नियंत्रित करने और कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए कठोर मौद्रिक उपायों की आवश्यकता थी। हालांकि लगातार औद्योगिक मंदी, सख्त मौद्रिक नियंत्रण की उपस्थिति वास्तविक क्षेत्र में शुरुआती सुधार के उभरते संकेतों को कम कर देती। यह सरकार के लिए राजस्व में कमी और सरकार की उच्च उधारी आवश्यकता के रूप में परिणत हो सकता था।

वर्ष 2022 में, भारत फिर से विदेशी मुद्रा बाजार में उच्च अस्थिरता के साथ-साथ बाहरी प्रभाव-विस्तार द्वारा लायी गई उच्च और लगातार मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। हालांकि अपने मैक्रो-फंडामेंटल्स और सुरक्षित भंडार (बफर) की आघात-सहनीयता और नीतिगत वातावरण में एक संरचनात्मक परिवर्तन द्वारा पाई गई सुदृढ़ता के साथ भारत अब इन चुनौतियों का सामना करता है।

सबसे पहले, हमारे पास आज एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क है जो स्पष्ट रूप से वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक संख्यात्मक लक्ष्य और उसके चारों ओर एक सहनशीलता बैंड के साथ कीमत स्थिरता के लक्ष्य को प्राथमिकता देता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को कम करने, प्रत्याशाओं को स्थिर करने और समग्र समष्टि-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मौद्रिक नीति कार्रवाई कर रहा है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अपनी अगस्त 2022 की बैठक में रिपो दर को 50

* इस लेख को जी.वी. नधानियल, शहबाज खान, कुणाल प्रियदर्शी, राजीव जैन, हर्षिता केशन, गौतम कुमार, अभिनंदन बोराड, ऋषभ कुमार, आशीष थॉमस जॉर्ज, रोहन बंसल, प्रियंका सचदेवा, युवराज कश्यप, विजया अग्रवाल, अक्षरा अवस्थी, जितेंद्र सोकल, आशीष संतोष खोबरागड़े, थंगझासोन सोना, इप्सिता पाढ़ी, आयुषी खंडेलवाल, रमेश बलिराम गोलाईत, सप्तर्षि घोषाल, मनीष त्रिपाठी, हरेंद्र बेहरा, पंकज कुमार, कौस्तुभ, विनीत कुमार श्रीवास्तव, समीर रंजन बेहरा, देब प्रसाद रथ और माइकल देवव्रत पात्रा ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करें।

[1] सैमुअल क्लेमेंस उर्फ मार्क ट्वेन को समर्पित।

[2] विवरण के लिए, वार्षिक रिपोर्ट, आरबीआई (1998-99) देखें।

आधार अंकों तक बढ़ाने का निर्णय लिया - दर वृद्धि में अगस्त 1998 के सापेक्ष बहुत कम वृद्धि की गई - और निभाव को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के बयान से एक शांत आत्मविश्वास झलकता है: "भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है और अशांति और अनिश्चितता के महासागर में गोते लगा रही है ... आरबीआई में हम अपनी अर्थव्यवस्था को वृद्धि के एक धारणीय पथ पर रखने के लिए कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हमारी कार्रवाइयों ने अर्थव्यवस्था को कई आघातों से उबारने में मदद की है... हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी भूमिका को बखूबी समझते हैं और एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहेंगे।"

दूसरा, आज रिज़र्व बैंक एक असाइनमेंट नियम का पालन करता है, जिसका श्रेय 1969 में अर्थशास्त्र के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जेन टिनबर्गेन को जाता है। नियम के अनुसार जितने लक्ष्य हैं, उतनी ही लिखतें होनी चाहिए और प्रत्येक लिखत को उस लक्ष्य के अंतर्गत आना चाहिए जिसे प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन अब अपनी प्राथमिकता के रूप में मुद्रास्फीति को अत्यधिक उच्च स्तर से नीचे लाने के लिए पूरी तरह से उन्मुख है। साथ ही, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिरता प्रदान करने के अपने प्रयासों में अडिग और दृढ़ रहा है, न कि मौद्रिक नीति द्वारा बल्कि पूंजी अंतर्वाह के हस्तक्षेप और उदारीकरण के माध्यम से।

दोनों प्रकार की कार्रवाइयों से रिज़र्व बैंक ने विश्वसनीयता अर्जित की है और यह पहले से ही परिवारों और व्यवसायों के रुख में परिलक्षित हो रहा है। मुद्रास्फीति शिथिल हो गई है और जल्द ही इसमें गिरावट की उम्मीद है, पहले 2-6 प्रतिशत के सहिष्णुता बैंड में और फिर 4 प्रतिशत के लक्ष्य पर। भारतीय रुपया दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक है, अमेरिकी डॉलर की बेहद मजबूत स्थिति के मुकाबले इसका मूल्यह्रास सबसे कम है। और जैसा कि गवर्नर श्री दास बताते हैं "... मजबूत और आघात-सह बुनियादी सिद्धांतों के साथ, भारत के 2022-23 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की उम्मीद है।"

वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, त्रैमासिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हमारा तात्कालिक अनुमान (नाउकास्ट) और मॉडल-आधारित पूर्वानुमान, जिसे हमने बुलेटिन के जून 2022 के अंक[3] में पहली बार निर्धारित किया था, की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जुलाई 2022 के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक में अपडेट में पुष्टि की गई है। पहली तिमाही में सामान्यता आने के बाद 2022 की दूसरी तिमाही में वैश्विक जीडीपी में कमी आई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के बीच संकुचन के साथ, लेकिन उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच थोड़ी आघात-सहनीयता के साथ जुलाई 2022 वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) - विस्तार के मौजूदा 25 महीने के अनुक्रम में अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया। क्या मौद्रिक नीति के दंश और यूरोप के भीषण सर्द माहौल से पहले मंदी आ गई है? आपूर्ति श्रृंखला के दबावों और पण्य कीमतों में हालिया ढील के बावजूद, मुख्य समस्या वैश्विक मुद्रास्फीति है।

एई और ईएमई के रास्ते पुनः अलग-अलग हैं। वाशिंगटन से वेलिंगटन तक, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि या तो धीमी हो रही है या ऋणात्मक हो रही है और फिर भी प्राप्त होने वाले डेटा इंगित करते हैं कि श्रम बाजार में ऐतिहासिक रूप से कड़ी स्थिति है। एक पूर्ण रोजगार या नौकरी होने के बाद भी मंदी एक विरोधाभास प्रतीत होती है, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है। ओकुन का नियम[4], जो मानता है कि बेरोजगारी में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में गिरावट आती है, इसके उलट होने वाला है। इसका उत्तर उम्र बढ़ने, धीमी गति से होने वाले आप्रवासन, और कम श्रमिकों और नौकरी की चाह रखने वालों में निहित है। महामारी के कारण नौकरियों में हुई कमी में भले ही तेजी आ गई हो, लेकिन श्रम भागीदारी की स्थिति कमजोर बनी हुई है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में श्रम शक्ति में कमी आ रही है और बेरोजगारी दर अभी तक के निचले स्तर पर आ गई है।

हमारे आस-पड़ोस में घटनाक्रम एक प्रतिरूपी ईएमई संकट की आशंका पैदा करते हैं जिसकी हर बार यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के समय आने की संभावना उत्पन्न होती है। वैश्विक

[3] गुप्ता, आरके, प्रताप, बी, एंथोनी, जेएम, और सोना, टी (2022)। 'वैश्विक संवृद्धि का तात्कालिक अनुमान', आरबीआई बुलेटिन, जुलाई।

[4] ओकुन, आर्थर एम. (1962), पोटेंशियल जीडीपी, इट्स मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंस, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स सेक्शन ऑफ द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन।

अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भले ही कम हो गए हों लेकिन ईएमई में रहने वाले लोगों द्वारा सामना की जाने वाली मानवीय चुनौती भयावह है। दि इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि कमजोर तिरपन देश - 53 निम्न और मध्यम-आय वाले देश पहले से ही कर्ज संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या उनके बॉन्ड तनावग्रस्त स्तरों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या वे चूक गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भले ही अतीत से कम प्रभाव हों, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।

दुनिया से वापस भारत में, दूरगामी लक्षण का घटनाक्रम उल्लेखनीय है। दोस्ती (फ्रेंड शोरिंग) की शुरुआत हो चुकी है और भारत इस मौके का फायदा उठा रहा है। भारत ने 20 जुलाई 2022 को 2022 की आपूर्ति श्रृंखला मंत्रिस्तरीय फोरम के अवसर पर 17 देशों के साथ नियर-टर्म परिवहन, रसद और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और बाधाओं के साथ-साथ दीर्घकालिक आघात-सह चुनौतियों को कम करने के लिए भागीदारी की। संयुक्त वक्तव्य में इन बातों पर जोर दिया गया (ए) घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप पारदर्शिता; (बी) स्रोतों और रसद अवसंरचना क्षमताओं का विविधीकरण; (सी) आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा आपूर्ति निर्भरता और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित कमजोरियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को संबोधित करती है; और (डी) आपूर्ति श्रृंखलाओं में धारणीयता और जिम्मेदार व्यवसाय आचरण। अगले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट को हल करने की कुंजी इसे होने से पहले ही इसे रोकना है।

उच्च आवृत्ति संकेतकों द्वारा मिल रहे कुछ मिश्रित संकेतों के बीच, शेष विश्व के सापेक्ष घरेलू आर्थिक गतिविधि की स्थिति का वर्णन करने के लिए शायद सबसे अच्छा शब्द आघात-सहनीयता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, आगामी त्यौहारी मौसम में वृद्धि के लिए तैयार है, जिससे मंद ग्रामीण मांग में भी तेजी आनी चाहिए क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के हाल के पुनरुद्धार के साथ खरीफ चावल की बुवाई में कमी आ रही है। केंद्र सरकार के पूंजी परिव्यय में 54 प्रतिशत की भारी वृद्धि से निवेश मांग को लाभ मिल रहा है, लेकिन मजबूत बिक्री वृद्धि और मुनाफे में वृद्धि के बावजूद व्यावसायिक निवेश सुस्त बना हुआ है। हालांकि जुलाई में निर्यात में कमी आई है, ऐसा केवल इसमें हुआ हो सकता है क्योंकि विश्व व्यापार की मात्रा में तेजी आई है। ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लेवी कम/ हटा दिए जाने के साथ, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात जो कि कुल व्यापारिक निर्यात का 16 प्रतिशत है, का फिर से बढ़ना तय है। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल ही में आई कमी से भी आयात बिल में कमी आनी चाहिए, जिससे कुल मांग में निवल निर्यात के योगदान में सुधार होता है।

तीन घटनाक्रम विश्वास उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले, भारत पूरे देश में तेज और व्यापक डेटा सेवाओं का अनुभव करने के लिए तैयार हो रहा है। 1 अगस्त 2022 को स्पेक्ट्रम की नीलामी बंद होने के साथ 5जी, 4जी नेटवर्क की तुलना में 100 गुना तेज नेटवर्क गति प्रदान करेगा। इंटरनेट पैठ पर जोर देने से इसमें नवोन्मेषी तकनीकों से रोजगार पैदा करने, नए युग का व्यवसाय निर्माण और दूरस्थ क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन की पहुंच बढ़ाने की संभाव्यता है (चार्ट 1)। सरकारी खजाने में ₹1.5 लाख करोड़ की राशि जमा हुई है, जो 2010[5] के बाद से सर्वाधिक स्पेक्ट्रम संग्रह है। इससे राजकोषीय सुविधा मिलती है।

दूसरा, 2022-23 की पहली तिमाही के लिए प्रत्याशा से अधिक शुरुआती कॉरपोरेट कमाई हुई है, जो मुद्रास्फीतिकारक दबावों से जनित परिचालनगत माहौल में कॉरपोरेट लाभप्रदता पर चिंताओं को दूर किया है। मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद भी गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री वृद्धि दहाई अंकों में अधिक बनी रही (चार्ट 2)। पूरे बोर्ड में इनपुट लागत वृद्धि का अनुभव किया गया। परिचालन दक्षता में सुधार, उत्पादों के मिश्रण को बदलने और इसी तरह की कई कार्यनीतियों को अपनाकर परिचालनगत मार्जिन पर लगातार बने दबाव को कम करने की कोशिश की गई। बढ़ती इनपुट लागत ने कुछ लोगों को लाभान्वित किया, उदाहरण के लिए, अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनियां। क्रेडिट वृद्धि में तेजी, निम्नतर प्रावधानीकरण लागत और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के बीच बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उम्मीद से बेहतर कॉरपोरेट आय ने घरेलू इक्विटी बाजारों में तेजी लायी है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को भारत में वापस आकर्षित किया है - नौ महीने के अंतराल के बाद एफपीआई अब तक जुलाई 2022 और अगस्त में भारतीय इक्विटी में निवल खरीदार लायी है।

[5] https://www.business-standard.com/article/companies/govt-earns-rs-1-5-trn-as-spectrum-auction-ends-on-day-7-jio-biggest-bidder-122080100774_1.html

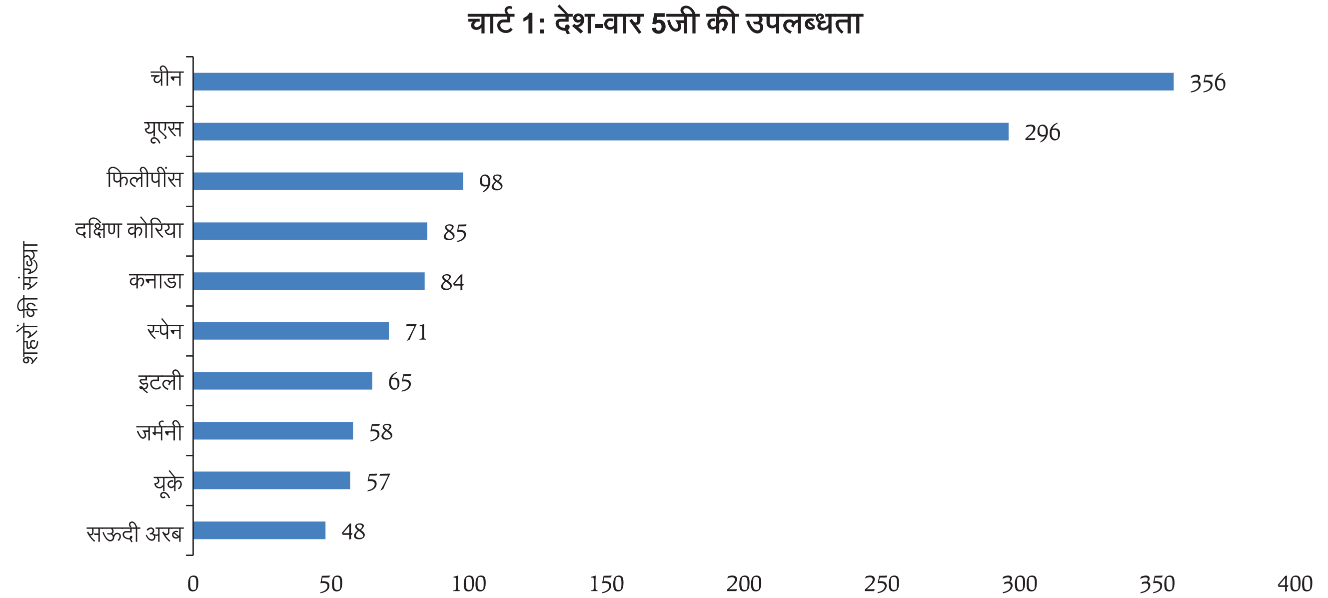

स्रोत: स्टैटिस्टा।

तीसरा, एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें चकाचौंध की कमी हो सकती है लेकिन इसका दूरगामी महत्व है - रिज़र्व बैंक द्वारा 27 जुलाई 2022 के चर्चा पत्र[6] में जलवायु परिवर्तन को वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए जोखिम के रूप में सक्रिय मान्यता

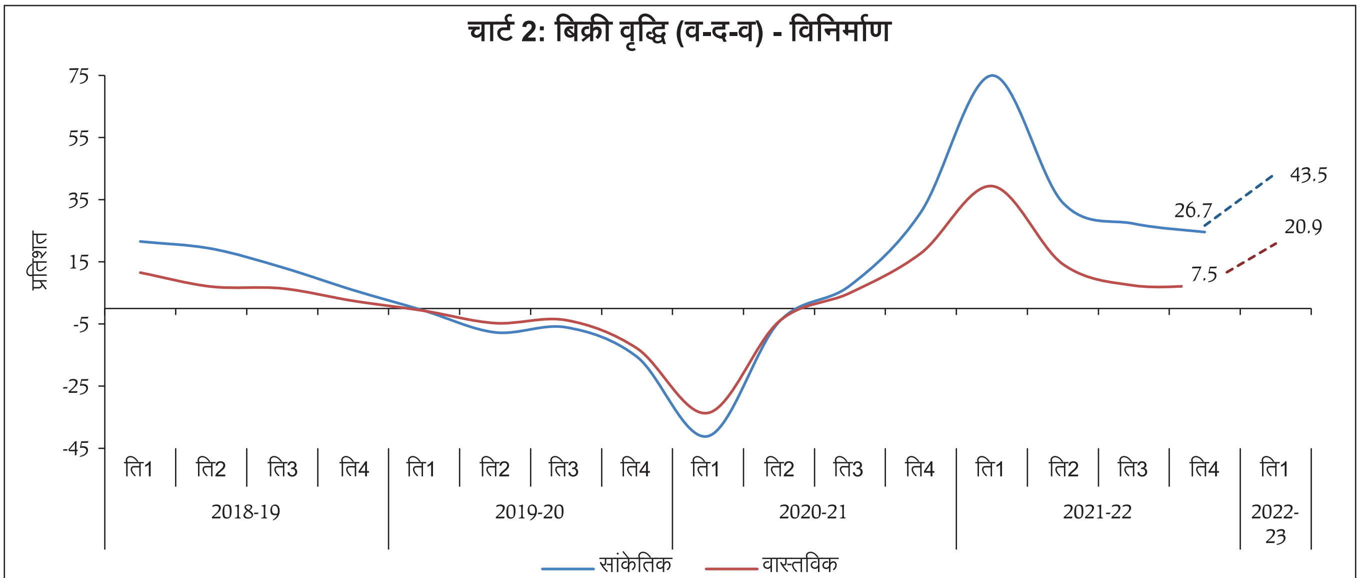

टिप्पणी: परिणाम ति4:2021-22 और ति1:2022-23 के लिए 835 सामान्य सूचीबद्ध निजी निर्माण कंपनियों पर आधारित है।
स्रोत: कैपिटलाइन और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

6 जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर चर्चा पत्र, आरबीआई, जुलाई 2022। https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21071

मिली है। यह पेपर देश के सामाजिक और विकासात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जलवायु संबंधी जोखिम की पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क की आवश्यकता को रेखांकित करता है और वित्तीय प्रणाली को हरित वित्तपोषण की ओर ले जाता है। रिज़र्व बैंक जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए मानक-निर्धारण निकायों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी सहित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक कार्यनीति तैयार करना चाहता है। शुरुआत में उचित प्रकटीकरण के माध्यम से गुणात्मक आकलन से जलवायु परिवर्तन जोखिमों की मात्रा का निर्धारण करने की चुनौती है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख के शेष भाग को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों को दर्शाता है। खंड III में घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करता है, जबकि अंतिम खंड आलेख का समापन करता है।

II. वैश्विक सेटिंग

अस्थिर वित्तीय स्थितियों और भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बनी हुई अनिश्चितता के बीच हाल के महीनों में वैश्विक वृद्धि की गति धीमी हो गई है। मंदी के बढ़े हुए जोखिम क्षेत्राधिकारों में आक्रामक और समकालिक मौद्रिक नियंत्रण को बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के अपने जुलाई 2022 के अपडेट में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2022 के लिए अपने वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को 40 आधार अंकों (बीपीएस) और 2023 के लिए 70 आधार अंकों से घटाकर क्रमश: 3.2 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत कर दिया। रूस से ऊर्जा आयात में भारी गिरावट, मुद्रास्फीति की उच्च और निरंतर प्रत्याशाएं और वित्तीय बाजारों की कठोर स्थितियों की विशेषता वाले नकारात्मक परिदृश्य में, वैश्विक वृद्धि क्रमशः 2022 और 2023 में लगभग 2.6 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत तक गिर सकती है [7] (सारणी 1)।

सारणी 1: जीडीपी विकास अनुमान – चुनिंदा एई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)

(प्रतिशत)

देश	2022		2023	
	अप्रैल 2022*	जुलाई 2022*	अप्रैल 2022*	जुलाई 2022*
विश्व	3.6	3.2	3.6	2.9
विकसित अर्थव्यवस्था				
यूएस	3.7	2.3	2.3	1.0
यूके	3.7	3.2	1.2	0.5
यूरो क्षेत्र	2.8	2.6	2.3	1.2
जापान	2.4	1.7	2.3	1.7
उभरती हुई अर्थव्यवस्था				
ब्राज़ील	0.8	1.7	1.4	1.1
रूस	-8.5	-6.0	-2.3	-3.5
भारत	8.2	7.4	6.9	6.1
चीन	4.4	3.3	5.1	4.6
दक्षिण अफ्रीका	1.9	2.3	1.4	1.4

*माह का अनुमान
स्रोत: आईएमएफ

ति2:2022[8] के लिए वैश्विक वृद्धि की गति संबंधी, वैश्विक जीडीपी के हमारे अद्यतन तात्कालिक अनुमान संकुचनकारी क्षेत्र[9] में प्रवेश कर रहे हैं (चार्ट 3)।

यह उच्च आवृत्ति संकेतकों की गति में भी परिलक्षित होता है। जुलाई 2022 में संयुक्त वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक

[7] अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2022), विश्व आर्थिक परिदृश्य, जुलाई 2022 अपडेट।

[8] ओईसीडी द्वारा संकलित जीडीपी शृंखला 2022 की पहली तिमाही तक 45 देशों के मुकाबले 2022 की दूसरी तिमाही में 15 देशों के लिए उपलब्ध है।

[9] गुप्ता आरके और अन्य, "वैश्विक संवृद्धि का तात्कालिक अनुमान", आरबीआई बुलेटिन, जून 2022। दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। पहले में, ओईसीडी द्वारा 2021 की चौथी तिमाही तक 48 देशों के लिए संकलित तिमाही जीडीपी को 45 देशों के लिए जीडीपी विकास दर की उपलब्ध आधिकारिक विज्ञप्ति के आधार पर 2022 की पहली तिमाही तक बढ़ा दिया गया था। दूसरी पद्धति में 2022 की पहली तिमाही और 2022 की दूसरी तिमाही के लिए बहिर्जात प्रतिगामी के साथ वैश्विक जीडीपी का पूर्वानुमान लगाने के लिए जनगणना और आर्थिक सूचना केंद्र (सीईआईसी) द्वारा संकलित 77 देशों की त्रैमासिक जीडीपी का इस्तेमाल किया गया।

चार्ट 3: वैश्विक जीडीपी तात्कालिक अनुमान

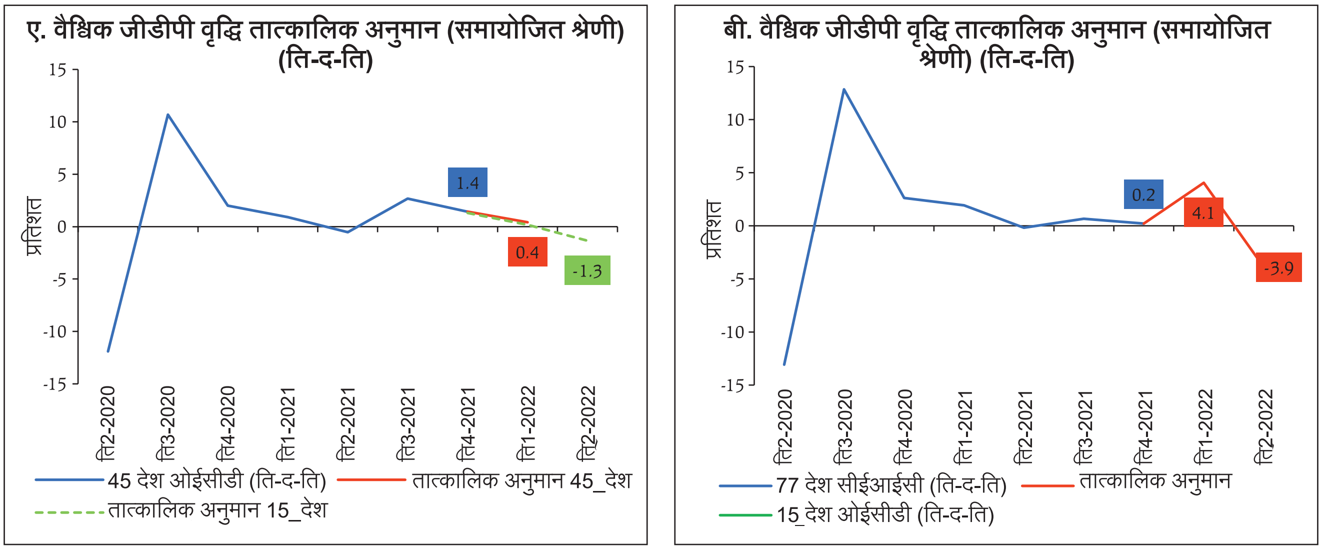

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

(पीएमआई) घटकर 50.8 हो गया, जो 2 वर्षों में सबसे कम है, यहां तक कि सेवा क्षेत्र का व्यावसायिक कार्यकलाप सूचकांक जून के 53.9 से गिरकर जुलाई में 51.1 पर आ गया। नए ऑर्डर में कमी और रोजगार में और गिरावट आई जिससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जून में 52.2 से जुलाई में 51.1 पर आ गया, जो 24 महीने के निचले स्तर पर है (चार्ट 4ए)। अधिकांश एई में विनिर्माण उत्पादन में गिरावट आई; ईएमई में से कुछ द्वारा विस्तार बनाए रखने से उनका प्रदर्शन मिश्रित था (चार्ट 4बी)।

आईएमएफ ने भी 2022 और 2023 के लिए अपने विश्व व्यापार वृद्धि के अनुमान को क्रमशः 90 और 120 आधार अंकों से घटाकर 4.1 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत कर दिया है। लाइव

चार्ट 4: क्रय प्रबंधक सूचकांक

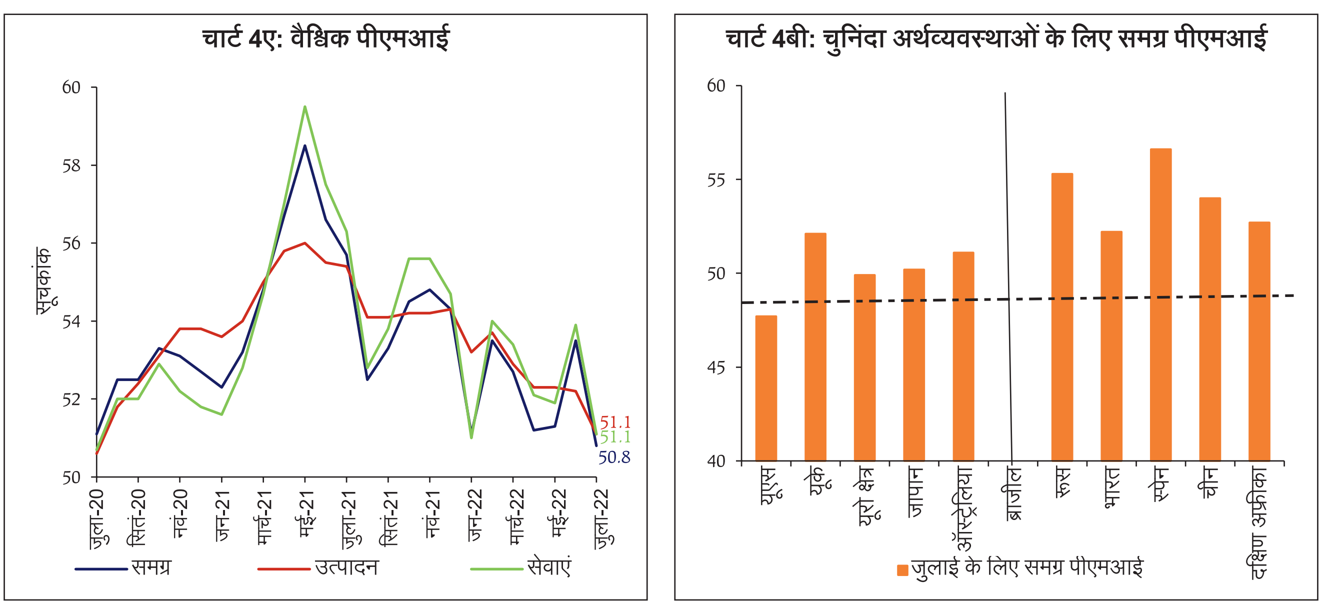

स्रोत: आईएचएस मार्किट।

चार्ट 5: विश्व व्यापार और शिपिंग लागत

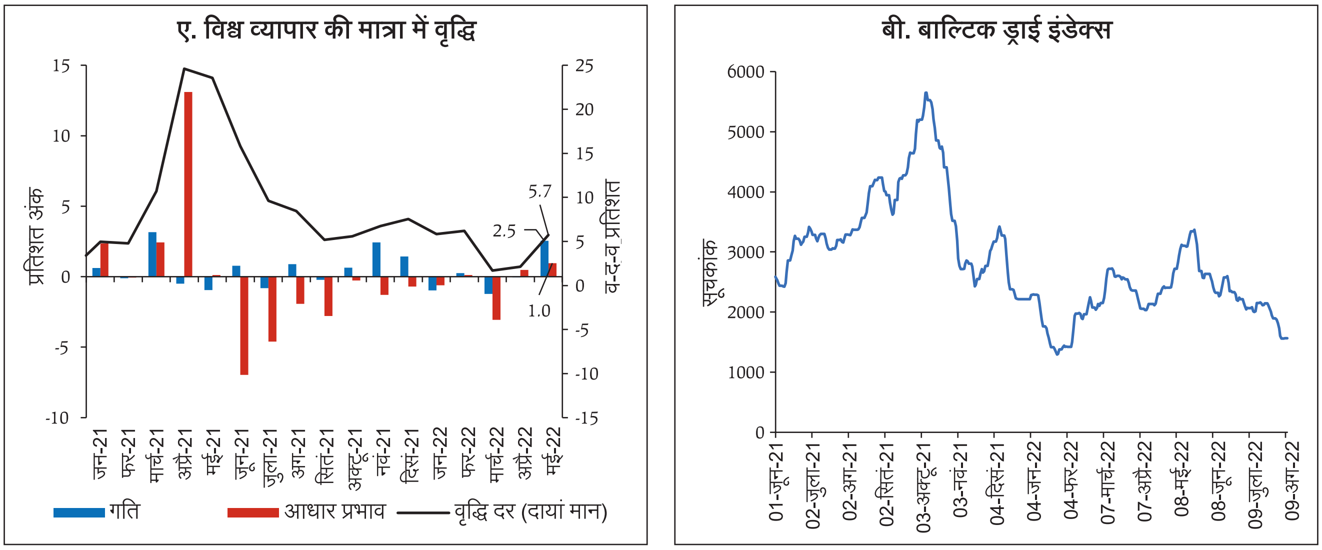

स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और ब्लूमबर्ग।

संकेतकों के संदर्भ में, मई 2022 में विश्व पण्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि अप्रैल में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई थी। ड्राई बल्क कमोडिटीज के लिए पोत परिवहन शुल्क के एक उपाय बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में लगातार दूसरे महीने कमी आई और जुलाई में 15.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण एक अनुकूल आधार प्रभाव द्वारा गति में तेजी आई थी (चार्ट 5)। जुलाई के लिए पीएमआई उप-सूचकांक ने भी आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं में कमी और कीमतों के दबाव में गिरावट का संकेत दिया, और डिलीवरी का समय 20 महीने के निचले स्तर तक कम हो गया।

आसन्न वैश्विक मंदी की आशंकाओं के कारण जून में भारी गिरावट के बाद अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें अस्थिर रहीं। ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में जुलाई की दूसरी छमाही में आंशिक तेजी देखी गई, जो कि पहली छमाही के औसत से 3 प्रतिशत अधिक है (चार्ट 6ए)। विशेष रूप से, कच्चे तेल की कीमतों में असाधारण रूप से कठोर आपूर्ति स्थितियों के कारण अत्यधिक अस्थिरता दिखाई दी। 19 जुलाई 2022 से जारी कमी के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष (17 अगस्त 2022 तक) 21.0 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है (चार्ट 6बी)। 3 अगस्त को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगियों ने 1,00,000 बैरल प्रति दिन उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। वैश्विक मांग के 0.1 प्रतिशत पर, यह समूह के इतिहास में तेल उत्पादन में सबसे निम्न वृद्धि में से एक है। 17 अगस्त 2022 तक ब्रेंट फ्यूचर्स का औसत 2022 के लिए लगभग 93 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल और 2023 के लिए 88 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहा है।

लगातार तीन महीनों तक गिरावट आने के बाद, जुलाई में सोने की कीमतों में वृद्धि हुई और अगस्त में अब तक (11 तारीख तक) इसकी वृद्धि जारी रही क्योंकि बॉन्ड के प्रतिफल में कमी आई और मंदी की प्रत्याशा द्वारा सुरक्षित हेवन मांग का कायाकल्प हुआ (चार्ट 6सी)। लगातार चौथी मासिक गिरावट को चिह्नित करते हुए, जुलाई 2022 में एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक 8.6 प्रतिशत गिर गया, यह गिरावट सभी घटकों में आ गई। इस गिरावट के बावजूद, इसने 13.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो अभी भी निरंतर बने मूल्य दबावों की ओर इंगित करती है (चार्ट 6डी)।

कई देशों ने बढ़ती वैश्विक खाद्य कीमतों से घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए व्यापार नीति के उपाय किए

चार्ट 6: पण्य वस्तु और खाद्यान्न कीमतें

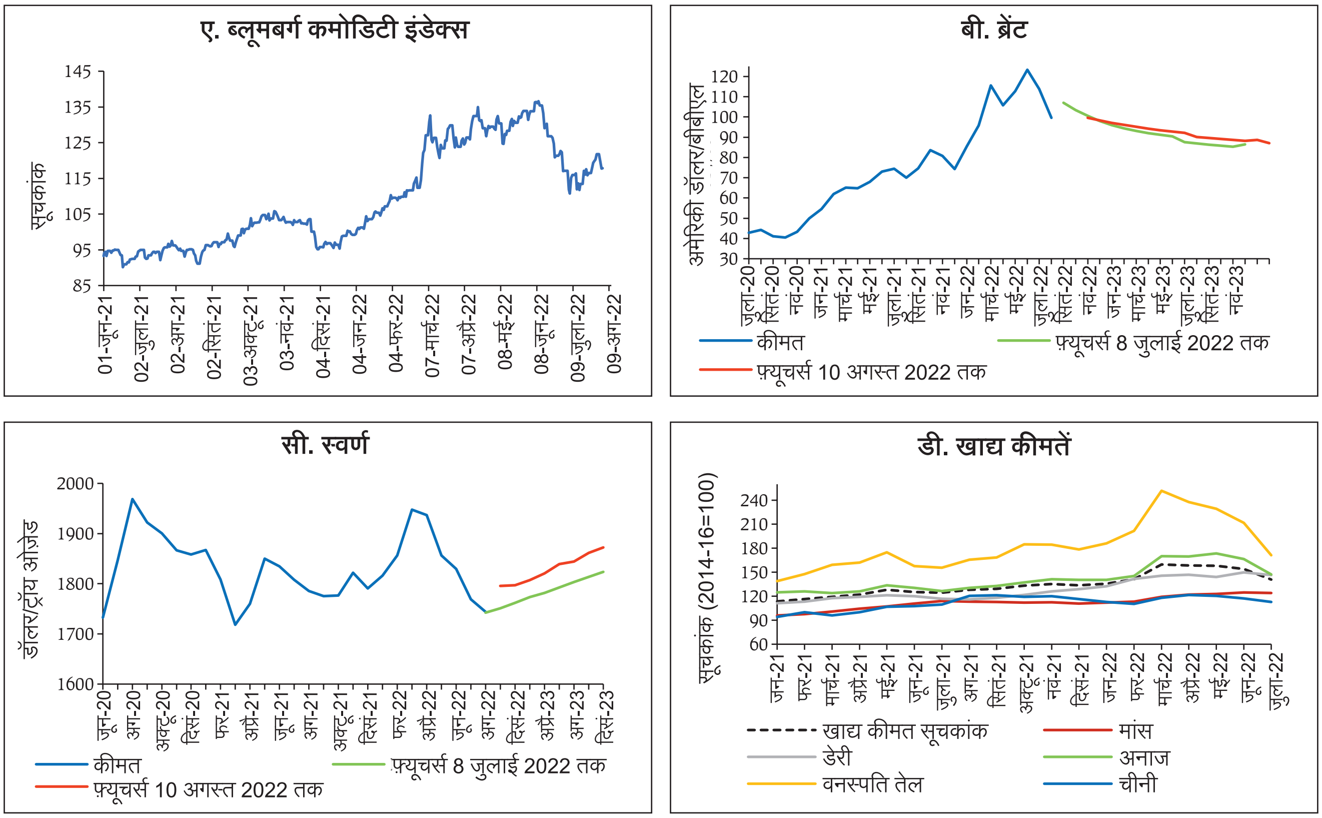

स्रोत: ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिंक शीट; और एफएओ।

थे। पिछले दो महीनों में कीमतों के दबाव में उल्लेखनीय कमी के साथ, जून 2022 की शुरुआत से व्यापार नीति प्रतिबंधों में समान गिरावट आई है (चार्ट 7)।

पण्य कीमतों में कमी आने और आपूर्ति शृंखला दबावों के बावजूद, मुद्रास्फीति का वैश्वीकरण और इसकी दृढ़ता बदलते वैश्विक दृष्टिकोण में प्रमुख समस्या बनी हुई है। जुलाई 2022 में, आईएमएफ ने एई के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 0.9 प्रतिशत अंक से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत और उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए 0.8 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया (अप्रैल 2022 डब्ल्यूईओ में पूर्वानुमानों के सापेक्ष), जो कि खाद्य और ऊर्जा की कीमतों के साथ-साथ आपूर्ति-मांग असंतुलन से प्रेरित थी।

जुलाई 2022 में यूएस हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति जून में 40 वर्षों के उच्च स्तर 9.1 प्रतिशत से कम होकर 8.5 प्रतिशत हो गई। मासिक गति जुलाई में 0 प्रतिशत (जून में 1.3 प्रतिशत) पर स्थिर रही क्योंकि गैसोलीन की कीमतों में गिरावट, भोजन और आश्रय में वृद्धि की भरपाई करती है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष बदलाव से मापी गई अमेरिका में मुद्रास्फीति मई के 6.3 प्रतिशत से बढ़कर जून 2022 में 6.8 प्रतिशत हो गई, ऊर्जा कीमतों के रूप में 1.0 प्रतिशत की मासिक गति के साथ 7.5 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि हुई जबकि खाद्य कीमतों में 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 2022 में मूल पीसीई मुद्रास्फीति भी 4.8 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो एक महीने पहले 4.7 प्रतिशत थी, क्योंकि 0.6 प्रतिशत की मासिक गति, अनुकूल आधार प्रभाव से केवल आंशिक रूप से ऑफसेट थी। यूरो क्षेत्र वार्षिक मुद्रास्फीति जुलाई में 8.9 प्रतिशत के नए उच्च स्तर तक बढ़ गई, जिसके मुख्य चालक ऊर्जा तथा इसके बाद खाद्य, शराब और तंबाकू थे। यूके में सीपीआई मुद्रास्फीति जून 2022 में 9.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) के 40 वर्षों

चार्ट 7: मासिक वैश्विक खाद्य व्यापार में नीतिगत परिवर्तन

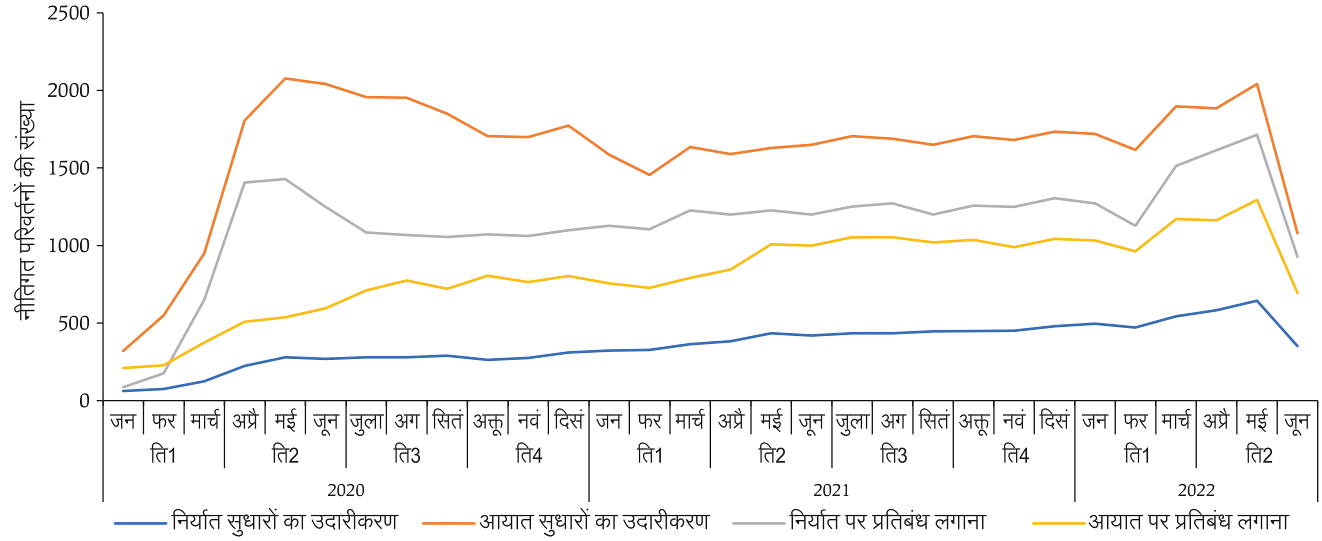

स्रोत: विश्व बैंक।

के उच्च स्तर पर पहुंच गई, परिवहन के बाद खाद्य और गैर-मादक पेय पदार्थों ने मासिक गति में सबसे अधिक योगदान दिया (चार्ट 8ए)। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील में जुलाई में 10.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति लगातार ग्यारहवें महीने दहाई अंक में रही। चीन में, यह चौबीस महीने के उच्च स्तर 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गया (चार्ट 8बी)। रूस में वार्षिक मुद्रास्फीति दर जून 2022 में गिरकर 15.1 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 15.9 प्रतिशत थी – यह मार्च के बाद से मुद्रास्फीति की सबसे निम्न दर थी।

जुलाई के अंत तक वैश्विक वित्तीय बाजार में सुधार हुआ और जून में हुए नुकसान की भरपाई हुई। एमएससीआई वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स में पुनः तेजी आई, जो एक महीने पहले की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की इक्विटी ने अपने

चार्ट 8: मुद्रास्फीति

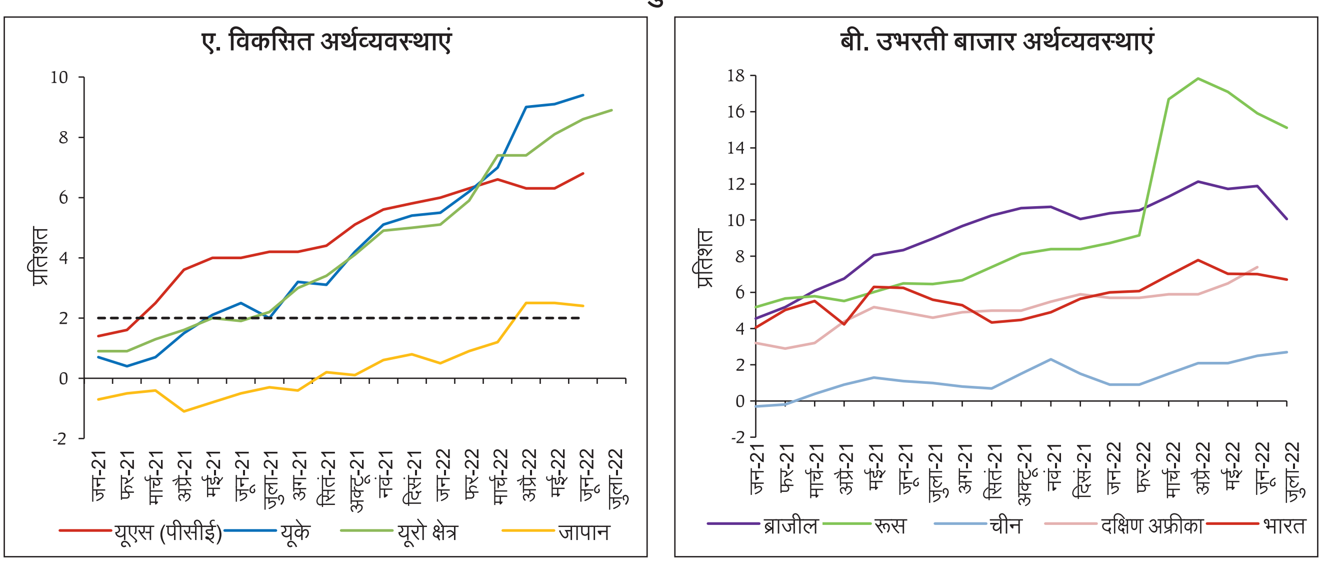

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

उभरते बाजार समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, उभरते बाजार समकक्षों में 0.1 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 9ए)। बॉन्ड बाजार में, वृद्धि दृष्टिकोण में उदासी के कारण प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में कमी आई। जुलाई के अंतिम 10 दिनों में अमेरिकी 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में 37 आधार अंकों की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से जुलाई में नीतिगत दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि के लिए बाजार में कीमत की प्रतिक्रिया के जवाब में थी (चार्ट 9बी)। वास्तव में, 05 जुलाई 2022 से अमेरिकी खजाना प्रतिफल वक्र औंधे मुंह गिर गया है, जो एक आसन्न मंदी के संकेत हैं। फेडरल रिज़र्व की आक्रामक कार्रवाई और सुरक्षित हेवन मांग पर अमेरिकी डॉलर सूचकांक जुलाई के मध्य तक तेजी से बढ़ा, लेकिन यूएस फेड द्वारा दर वृद्धि की भविष्य में धीमी गति की प्रत्याशा के कारण यह मंद पड़ गया (चार्ट 9सी)। समवर्ती रूप से, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक में जून के मध्य तक गिरावट आई और इक्विटी अंतर्वाह की शह पर मामूली सुधार हुआ (चार्ट 9डी)।

दुनिया भर में कठोर मौद्रिक नीति समकालिक रूप से इस बढ़ते विश्वास के साथ जारी रही कि ऐतिहासिक रूप से उच्च मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए आक्रामक मौद्रिक नीति कार्रवाई जरूरी है। जैसा कि पहले कहा गया है, यूएस फेडरल रिज़र्व ने लगातार चौथी बैठक में भी फेडरल फंड की दरों की लक्ष्य सीमा बढ़ा दी, लेकिन 75 आधार अंकों से 2.25-2.50 प्रतिशत की अपेक्षित सीमा पर। इसने टेपर के घोषित मार्ग को भी दोहराया - सितंबर से फेड के तुलन-पत्र में 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आएगी, यानी पिछले तीन महीनों के संकुचन की गति से दोगुनी गति से। 4 अगस्त को बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने 2022 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति के 13 प्रतिशत से ऊपर बढ़ने की प्रत्याशा लगाते हुए अपनी नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की। यूके की अर्थव्यवस्था में 2022 की चौथी तिमाही से मंदी आने का पूर्वानुमान है। ईसीबी ने एक दशक से भी अधिक समय में पहली बार दरों में 50 आधार अंकों की और रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए ऋणात्मक ब्याज दरों को समाप्त किया। इज़राइल, न्यूजीलैंड और दक्षिण

चार्ट 9: वित्तीय बाजार

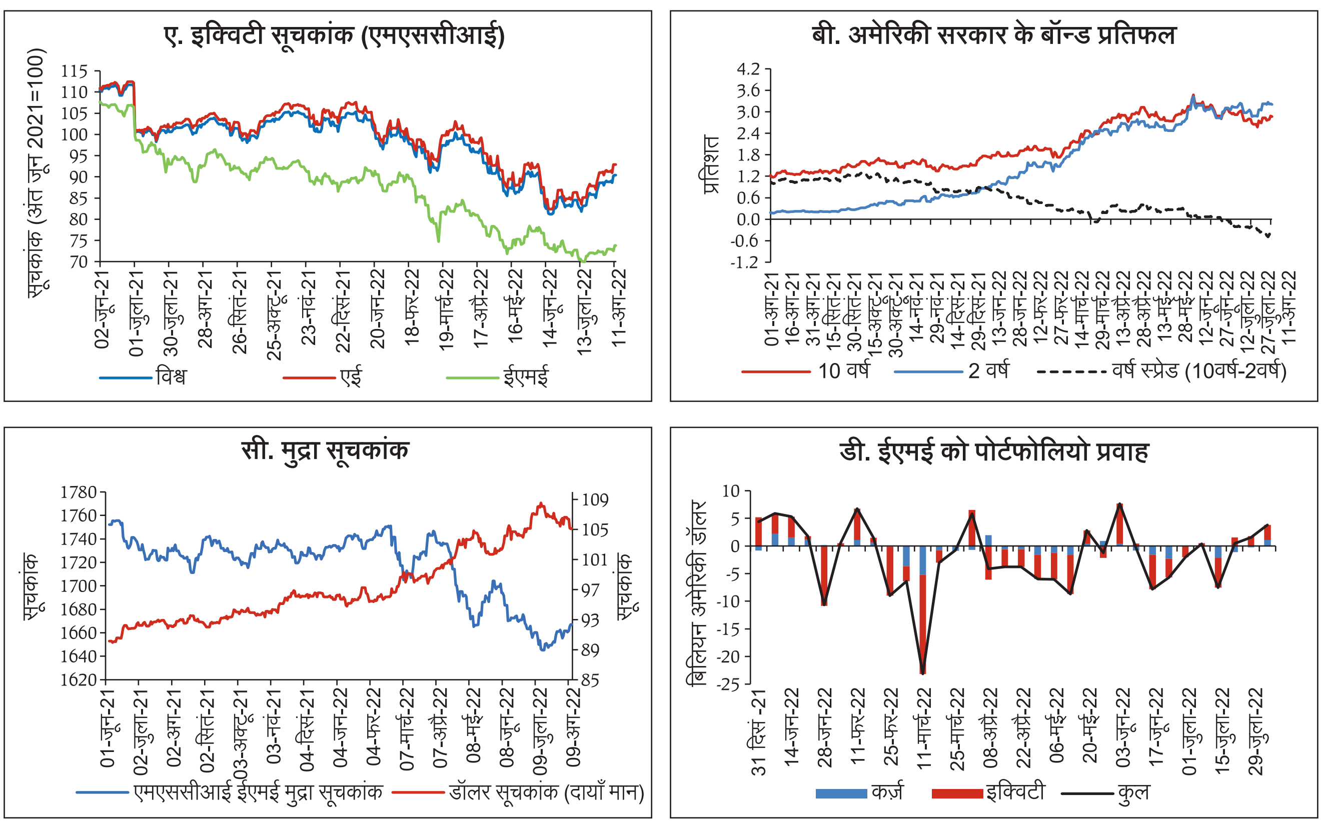

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

चार्ट 10: वर्ष 2022 से चुनिंदा देशों के केंद्रीय बैंकों की दर कार्रवाइयां

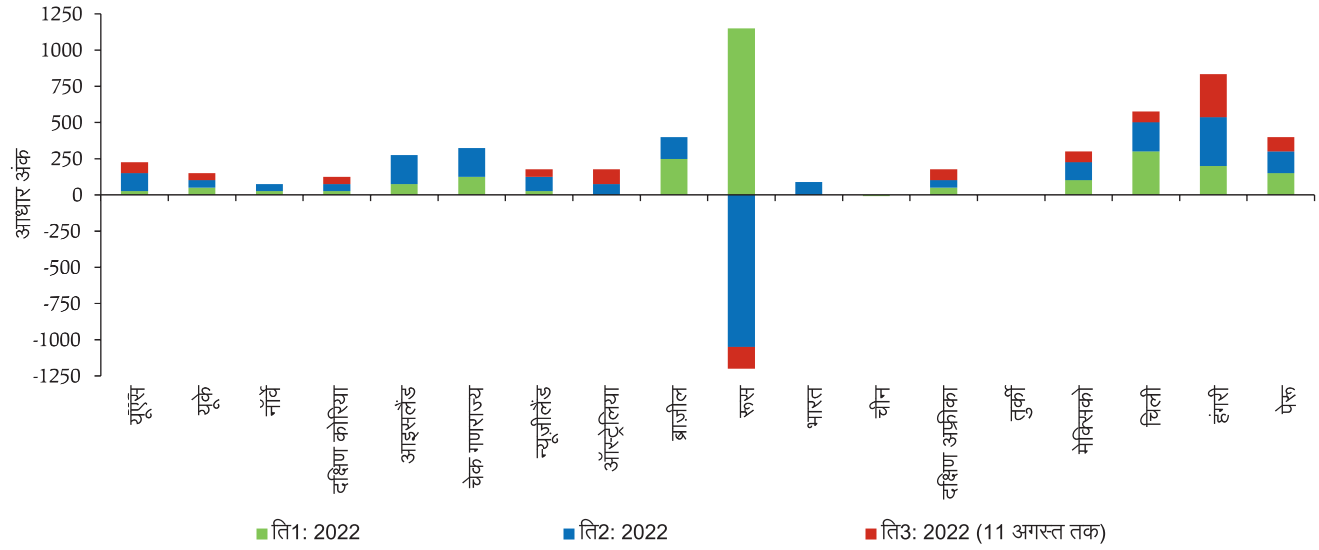

स्रोत: केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

कोरिया ने भी जुलाई में अपनी नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की वृद्धि की, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक तीसरी तिमाही में दरों में 100 आधार अंकों की वृद्धि की है। हालाँकि, जापान ने एक उदार रुख बनाए रखते हुए विचलन जारी रखा।

अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने भी कठोर नीति जारी रखी (चार्ट 10)। अधिकांश देशों ने अपने नियमित नीति चक्रों में नीतिगत दरों में वृद्धि की, जबकि हंगरी और फिलीपींस ने अलग से बैठकें आयोजित कर कार्रवाई की। इसके विपरीत, रूस ने नवीनतम नीति बैठक में अपनी नीतिगत दर में 150 आधार अंकों की कटौती की, जबकि चीन ने अपनी एक प्रमुख उधार दर - एक वर्षीय मध्यम अवधि की उधार सुविधा दर में अप्रत्याशित 10 आधार अंकों की कटौती की और अपने उदार रुख को जारी रखा।

III. घरेलू घटनाक्रम

हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक जो 15 उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ एक गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) को

चार्ट 11: गतिविधि सूचकांक (डीएफ-15)

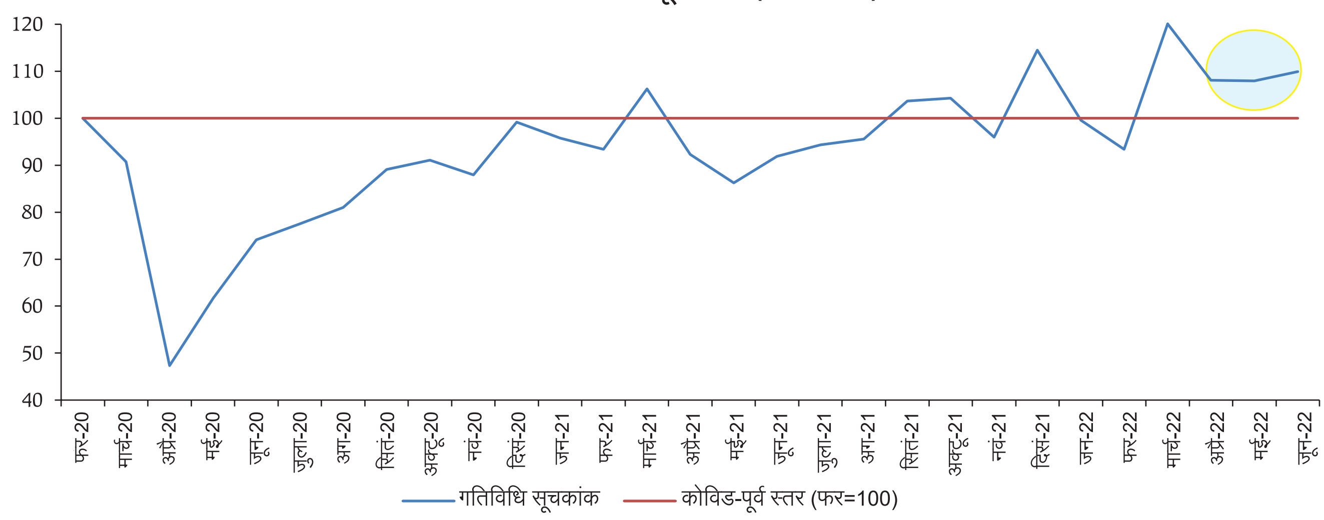

टिप्पणी: गतिविधि सूचकांक (एक्टिविटी इंडेक्स) का निर्माण डायनेमिक फैक्टर मॉडल (डीएफएम) का उपयोग करके आर्थिक गतिविधि के सावधानी से चयनित उच्च आवृत्ति संकेतकों के समूह में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्ति को निकालकर किया गया है।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 12: जीडीपी - वास्तविक और तात्कालिक अनुमान

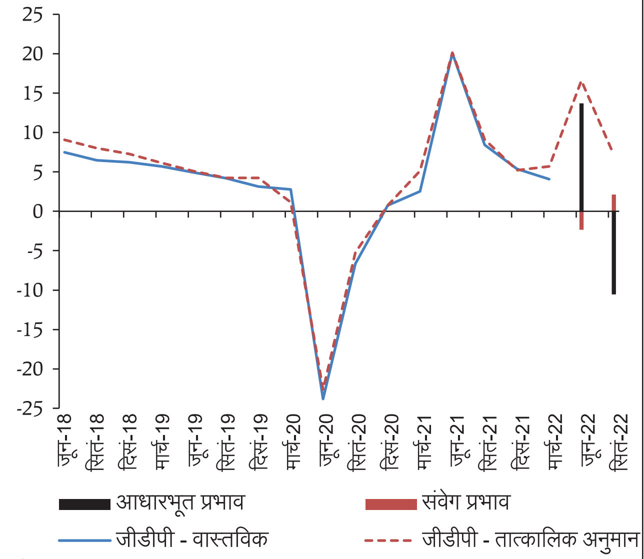

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

नियोजित करता है, मई और जून में मध्यम लेकिन स्थिर सुधार दिखा रहा है (चार्ट 11)। वैकल्पिक मॉडल विनिर्देशों के तहत, 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.2 प्रतिशत पर अनुमानित है, जो एक अनुकूल आधार द्वारा समर्थित है (चार्ट 12)।

कुल मांग

कुल मांग के निकटतम संकेतक के रूप में माल की आवाजाही सुदृढ़ बनी रही। जुलाई 2022 (चार्ट 13ए) में अंतर राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों ई-वे बिल क्रमिक रूप से बढ़ी। जुलाई 2022 में टोल संग्रह मजबूत रहा, लेकिन कुछ के लिए प्रतिकूल मौसम की स्थिति (चार्ट 13बी) के कारण मध्यम अनुक्रमिक गिरावट दिखा।

जुलाई में मौसमी कारकों के कारण ईंधन की खपत में भी गिरावट आई, जो डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन (चार्ट 14ए) की खपत में गिरावट को दर्शाता है। डीलरों को भेजे गए निरंतर यात्री वाहन के कारण जुलाई में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सुधार हुआ। प्रवेश स्तर के यात्री वाहनों को अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर तक ठीक होना बाकी है, भले ही उन्होंने क्रमिक सुधार दर्ज किया हो (चार्ट 14बी)। गैर-परिवहन वाहनों, मुख्य रूप से दोपहिया वाहनों के पंजीकरण में गिरावट के कारण, मौसमी बारिश के कारण ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री में कमी आई, जो कुल का 80 प्रतिशत है (चार्ट 14सी)। मानसून के असमान विस्तार ने भी जुलाई में ट्रैक्टर की बिक्री को प्रभावित किया, यहां तक कि दोपहिया और मोटरसाइकिल की बिक्री में भी तेजी आई और तिपहिया वाहनों की बिक्री महामारी से पहले के स्तर से नीचे बनी रही (चार्ट 14डी)।

तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) की बिक्री में जुलाई में क्रमिक गिरावट दर्ज की गई, जो पेय पदार्थ खंड में मौसमी गिरावट को दर्शाता है। वैश्विक मूल्य सुधार पर खाद्य तेल

चार्ट 13: ई-वे बिल और टोल संग्रह

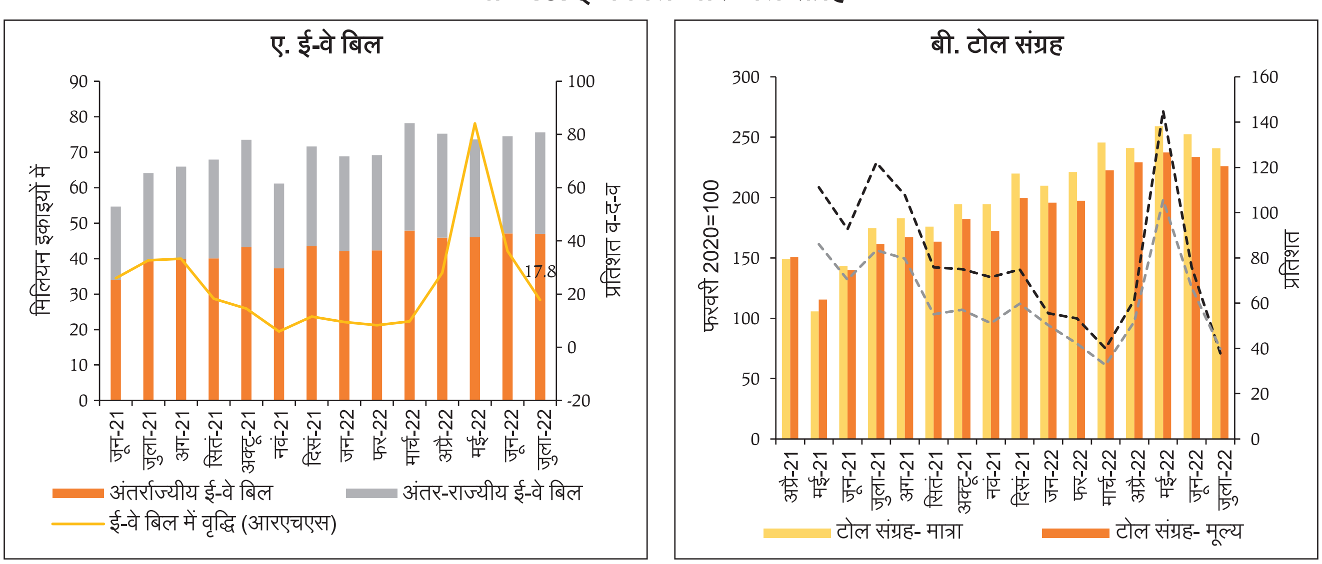

स्रोत: जीएसटीएन; भारतीय रिज़र्व बैंक; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट 14: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक

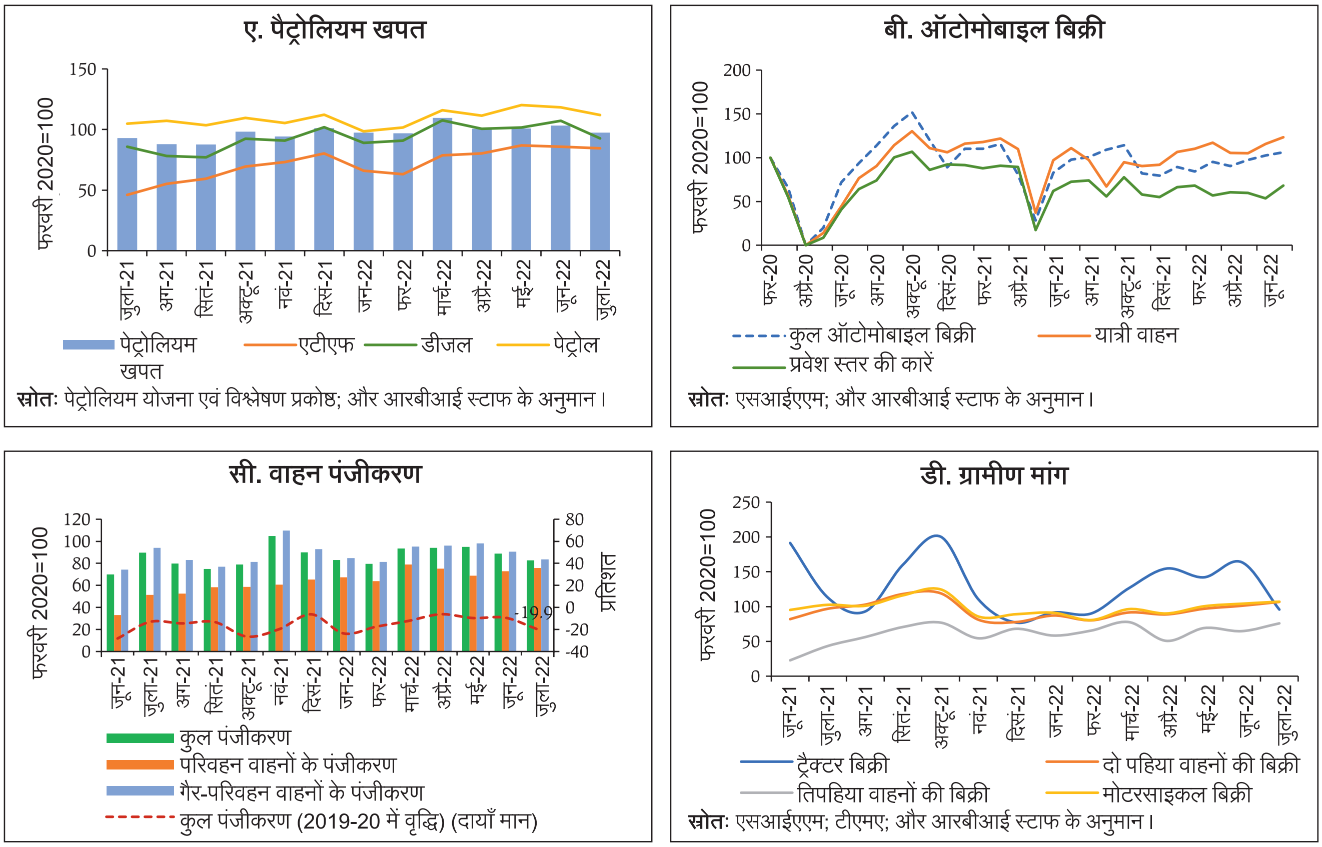

की कीमतों में गिरावट के साथ बिक्री आगे बढ़ने की उम्मीद है। आगामी त्योहारी सीजन में अपेक्षित मांग में तेजी, अच्छा मानसून और उच्च कमाई[10] सभी ग्रामीण खपत में सहायता कर रहे हैं और घर से बाहर की गतिविधियों में वृद्धि शहरी खपत को बढ़ा रही है।

धूमिल वैश्विक विकास संभावनाओं, बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति-पक्ष की रुकावटों और मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारतीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में मांग की स्थिति पर तेजी से आशावादी है, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए तिमाही उद्यम सर्वेक्षणों में परिलक्षित होता है। घरेलू निर्माताओं को उच्च उत्पादन की उम्मीद है, और सेवाओं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में उद्यम 2022-23 की दूसरी छमाही में उच्च कारोबार की उम्मीद करते हैं (चार्ट 15)।

चार्ट 15: उत्पादन/ आवर्त संबंधी प्रत्याशा

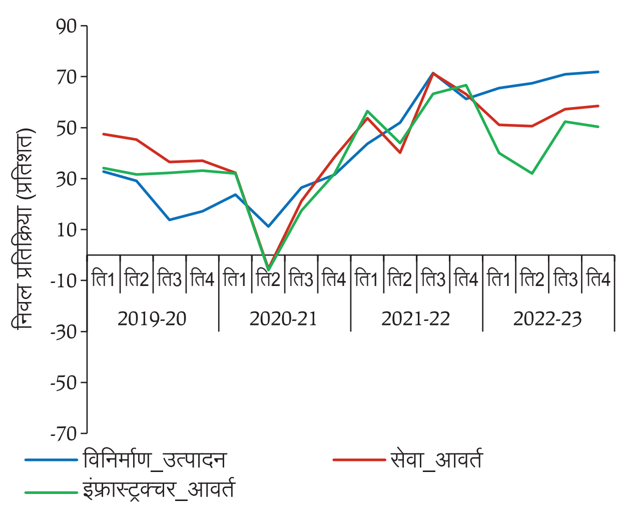

टिप्पणी: निवल प्रतिक्रिया (एनआर) आशावाद की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत और निराशावाद की रिपोर्ट करने वालों के बीच का अंतर है।
स्रोत: आरबीआई।

[10] इकोनॉमिक टाइम्स, 20 जुलाई, 2022।

चार्ट 16: रोज़गार, बेरोज़गारी, श्रम भागीदारी दरें

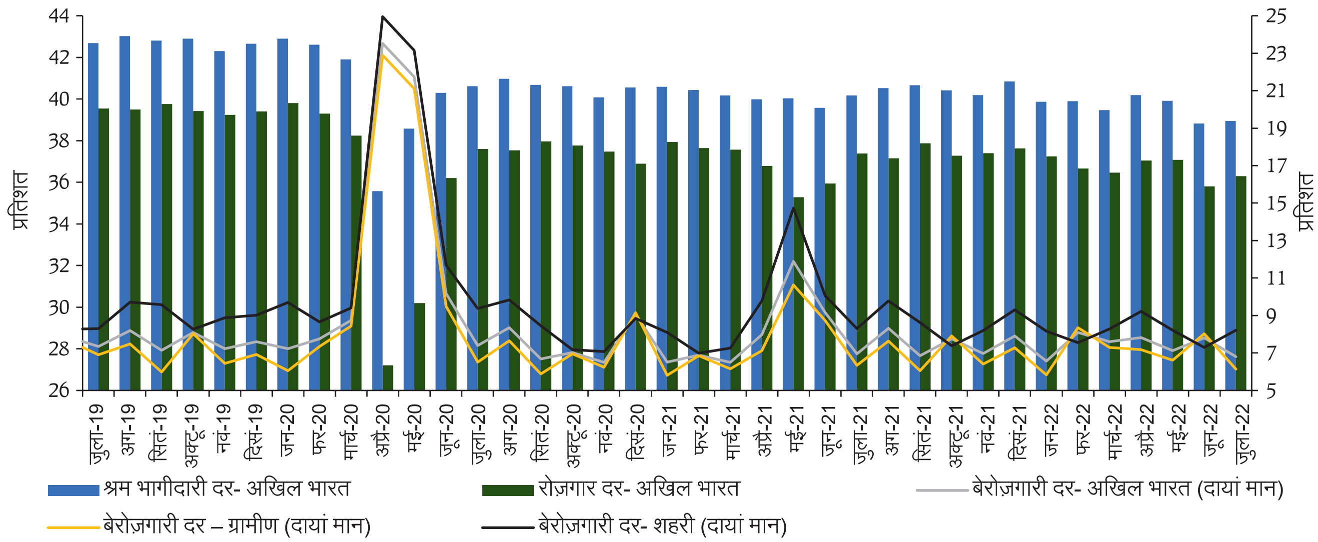

स्रोत: सीएमआईई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई में रोजगार दर में सुधार हुआ। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (चार्ट 16) में वृद्धि के बावजूद, जुलाई 2022 में बेरोजगारी दर एक प्रतिशत घटकर 6.8 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट कृषि गतिविधि में सुधार के कारण ग्रामीण बेरोजगारी दर में 2 प्रतिशत की गिरावट से प्रेरित थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम की मांग में जुलाई में काफी गिरावट आई है, जो

चार्ट 17: मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग

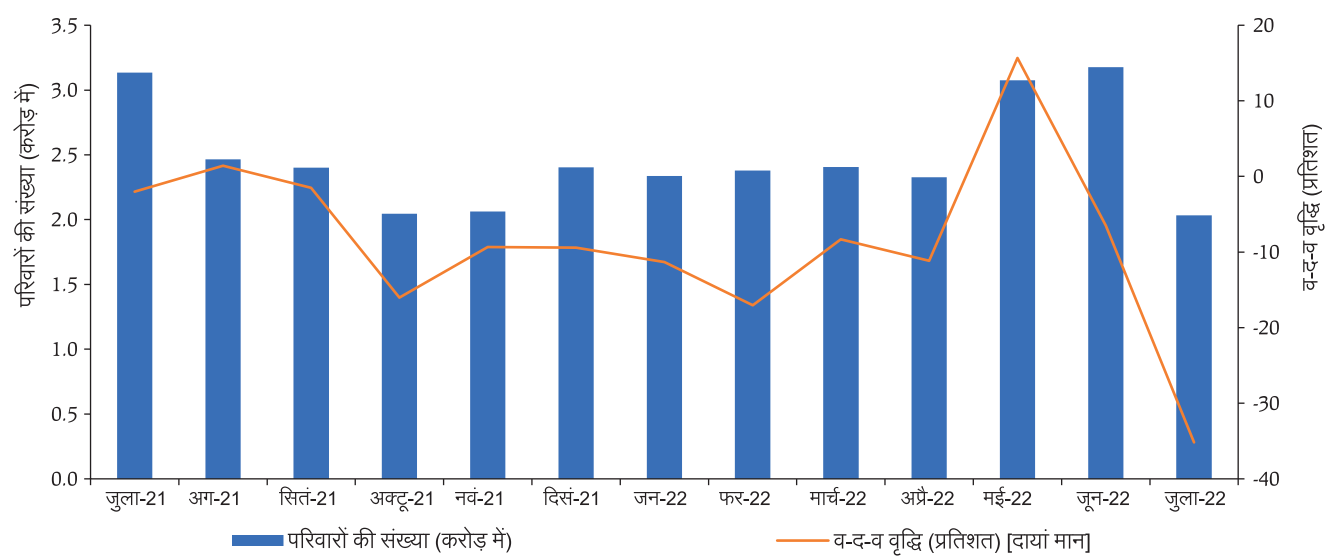

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

चार्ट 18: पीएमआई रोज़गार सूचकांक

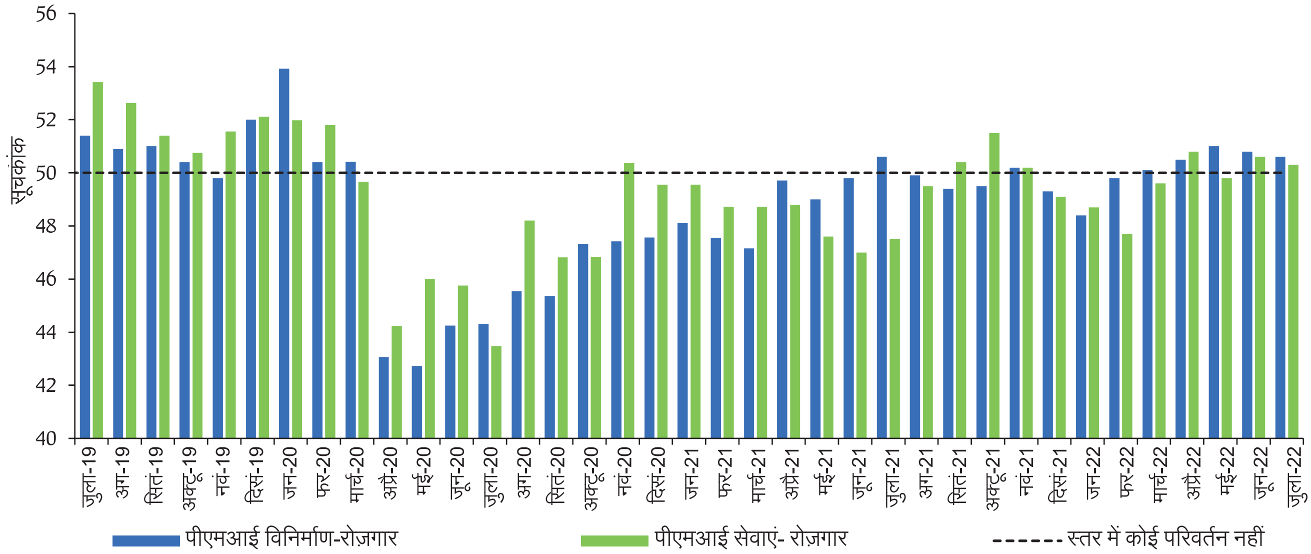

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्धता में वृद्धि का संकेत देता है (चार्ट 17)। संगठित क्षेत्र के रोजगार दृष्टिकोण के संदर्भ में, विनिर्माण और सेवाओं दोनों के लिए रोजगार उप-सूचकांक पिछले महीने की तुलना में मामूली रूप से कम हुआ है, हालांकि यह विस्तारवादी बना हुआ है (चार्ट 18)।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर भारत का माल निर्यात 36.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 2.1 प्रतिशत की धीमी वृद्धि देखी गई (चार्ट 19)। क्रमिक आधार पर, निर्यात 14.4 प्रतिशत (माह दर माह) गिर गया, जो आंशिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क/उपकर लगाने को दर्शाता है। गैर-तेल निर्यात में मामूली रूप से 0.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

शीर्ष 10 वस्तुओं के निर्यात के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चलता है कि इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, कपड़ा और कपास, जो कुल निर्यात टोकरी का 40 प्रतिशत हिस्सा है,

चार्ट 19: भारत का पण्य वस्तु निर्यात - जुलाई 2022

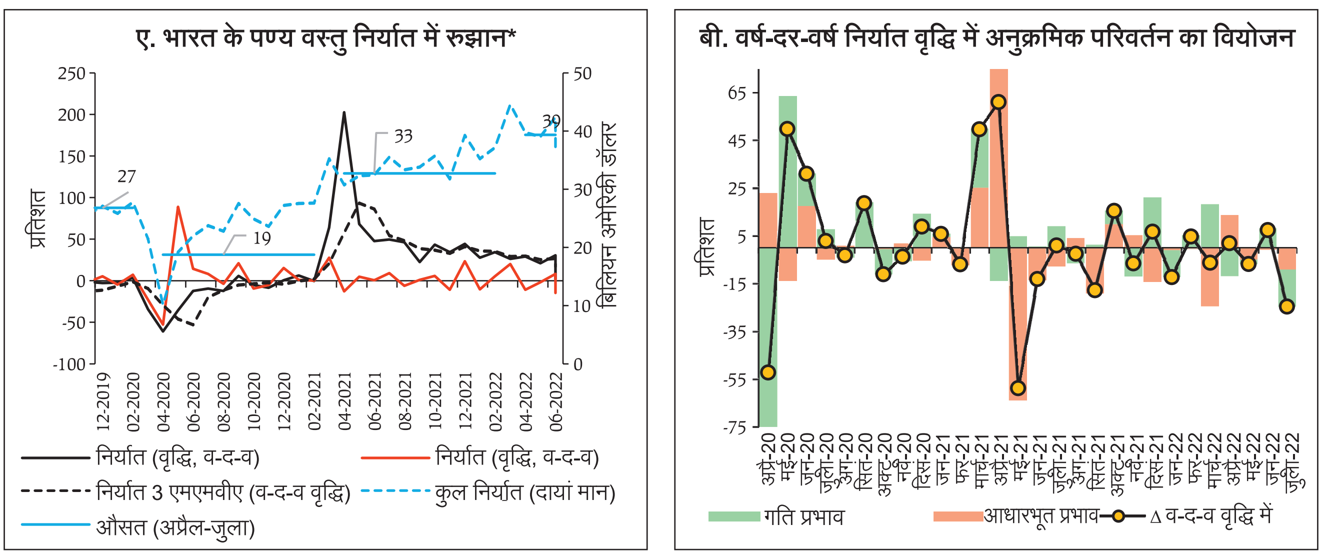

*3एमएमवीए तीन महीने का एक चल मूल्य औसत है।
स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई के स्टाफ द्वारा अनुमान।

सारणी 2: 10 प्रमुख निर्यातित और आयातित वस्तुएं

निर्यात					आयात				
10 प्रमुख पण्य समूह	जुला'22 (हिस्सा)	जुला'22 (बिलियन यूएस डॉलर)	व-द-व वृद्धि	मा-द-मा वृद्धि	10 प्रमुख पण्य समूह	जुला'22 (हिस्सा)	जुला'22 (बिलियन यूएस डॉलर)	व-द-व वृद्धि	मा-द-मा वृद्धि
इंजीनियरिंग माल	26%	9.3	-2.1	-2.4	पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद	32%	21.1	70.4	-2.0
पेट्रोलियम उत्पाद	18%	6.4	9.2	-40.2	इलेक्ट्रानिक सामान	10%	6.8	27.8	11.3
रत्न एवं आभूषण	9%	3.3	-5.2	-7.3	कोयला, कोक & बिर्केट्स इत्यादि	8%	5.2	164.4	-23.4
कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	7%	2.6	8.0	-12.1	मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल	6%	3.8	35.1	0.8
दवा एवं औषधि	6%	2.1	-1.0	0.0	मोती, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर	5%	3.2	22.3	8.6
इलेक्ट्रानिक सामान	5%	1.8	46.1	8.4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	5%	3.1	28.7	-10.4
सभी तरह के कपड़ों के रेडीमेड वस्त्र	4%	1.4	-0.6	-8.0	स्वर्ण	4%	2.4	-43.6	-13.5
सूती धागे/कपड़े	3%	0.9	-28.2	-1.8	कृत्रिम धागे और प्लास्टिक वस्तुएं	3%	2.2	66.9	-2.9
चावल	3%	0.9	30.9	-12.3	खाद्य तेल	3%	2.0	47.2	11.0
प्लास्टिक और लिनोलियम	2%	0.8	-3.5	2.1	गैर-लौह धातुएं	3%	1.8	40.0	10.8
10 प्रमुख पण्य समूहों का कुल योग	82%	29.6	2.5	-15.1	10 प्रमुख पण्य समूहों का कुल योग	78%	51.7	44.5	-2.7
कुल निर्यात	**100.0**	**36.3**	2.1	-14.4	**कुल आयात**	**100.0**	**66.3**	43.6	-0.1

स्रोत: एमओसीआई।

क्रमिक रूप से और साथ ही साल-दर-साल आधार पर अनुबंधित होता है (सारणी 2)।

जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों में सालाना आधार पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि माह दर माह आधार पर 40.2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट 20)। पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर में कटौती/समाप्ति और अप्रत्याशित कर दरों में कमी के साथ, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) के निर्यात में तेजी आने और समग्र व्यापारिक निर्यात प्रदर्शन का समर्थन करने की उम्मीद है।[11]

इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारत के कुल निर्यात का 5.2 प्रतिशत, जुलाई में निर्यात वृद्धि में अग्रणी सकारात्मक योगदानकर्ता था। 2017-18 से इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात दोगुने से भी ज्यादा

चार्ट 20: पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

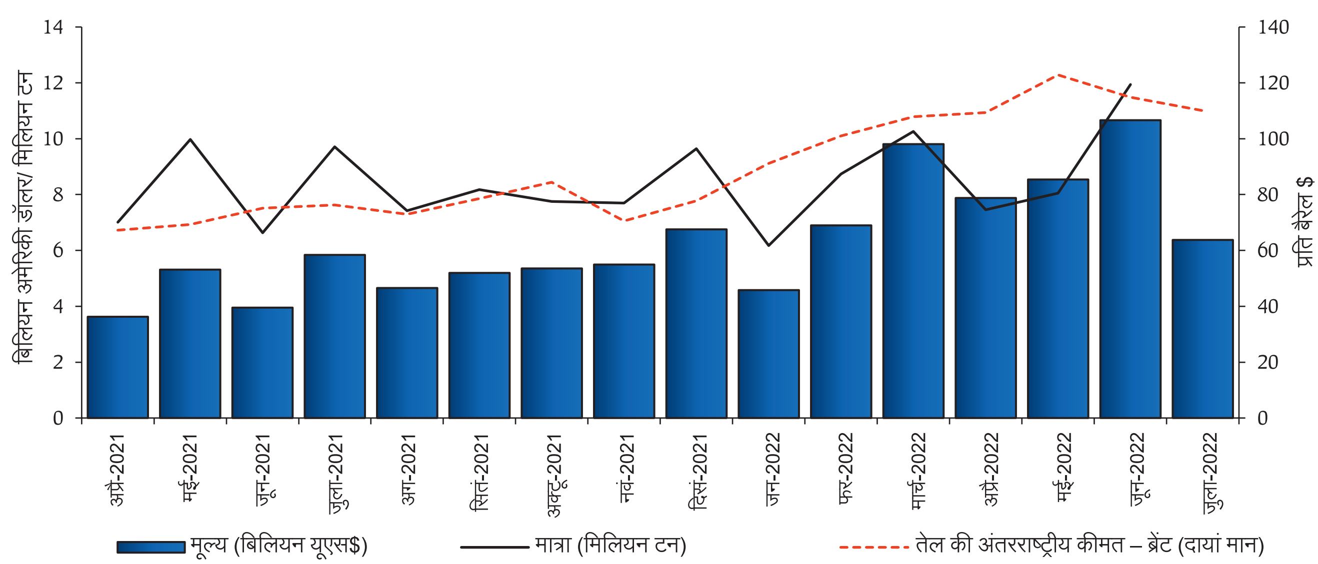

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; और रेफिनिटिव एकोन।

[11] केंद्र ने भी डीजल के निर्यात पर उपकर को ₹11 प्रति लीटर से घटाकर ₹5 प्रति लीटर कर दिया है, जबकि विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर उपकर को हटा दिया गया है (https://www.livemint.com/news/india/centre-raises-windfall-tax-on-domestic-crude-cuts-duty-on-diesel-exports-11659486847962.html).

चार्ट 21: इलेक्ट्रॉनिक समान का निर्यात

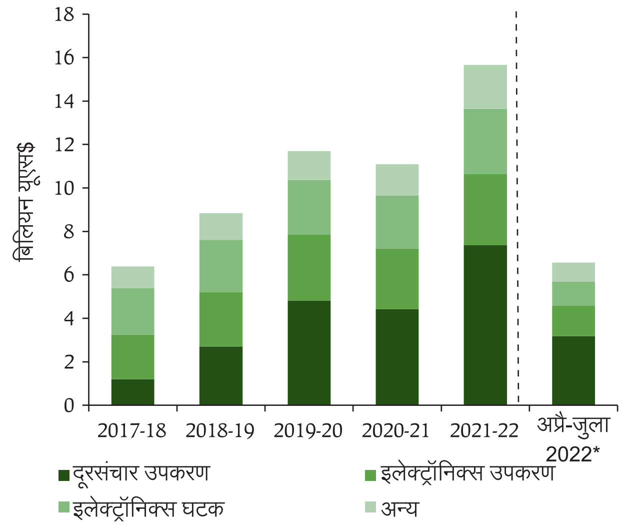

*: जुलाई के लिए संयोजन का अनुमान पिछले तीन-महीने के औसत पर आधारित है।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई के स्टाफ द्वारा अनुमान।

चार्ट 22: भारत का ऑटोमेटिव निर्यात – दुपहिया और तिपहिया वाहनों का निर्यात

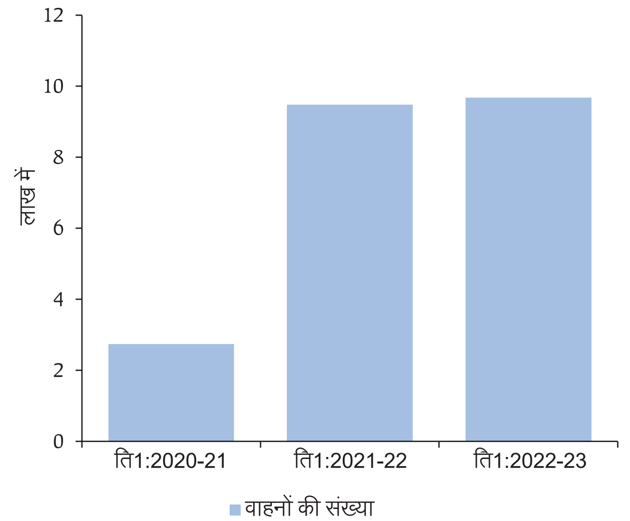

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

हो गया है। दूरसंचार उपकरण प्रमुख निर्यात रहे हैं, जो छह गुना से अधिक बढ़ रहे हैं (चार्ट 21)। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का 33 प्रतिशत हिस्सा है। 2025-26 तक, घरेलू बाजार का आकार 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और उत्पादन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर[12] तक पहुंचने की उम्मीद है । इसलिए, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के माध्यम से वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के साथ अधिक बाजार विस्तार आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में जुलाई 2022 में सालाना आधार पर 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस उप क्षेत्र में, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के पोत लदान में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (चार्ट 22)। सेमीकंडक्टर आपूर्ति की कमी और आपूर्ति शृंखला दबावों में धीरे-धीरे कमी के कारण आने वाले महीनों में मोटर वाहन निर्माताओं के निर्यात प्रदर्शन में सहयोग मिल सकता है।

भारत का पण्य आयात 66.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो साल-दर-साल आधार पर (43.6 प्रतिशत) काफी बढ़ा है; हालांकि, इसमें क्रमिक रूप से गिरावट आई है (चार्ट 23 ए)। 42.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर गैर-तेल गैर-सोने का आयात लगातार 17 महीनों के लिए दोहरे अंकों में बढ़ रहा है (चार्ट 23 बी)।

भारत का तेल आयात 106.5 मिलियन टन (एमटी) रहा जो अप्रैल-जुलाई 2018 के दौरान 93.7 मिलियन टन (एमटी) के पिछले उच्च स्तर से 13.7 प्रतिशत अधिक है। हाल के वर्षों में तेल आयात निर्भरता बढ़ रही है (चार्ट 24)। इस बीच, इथेनॉल मिश्रण से ₹41,500 करोड़[13] की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला और उर्वरक जैसी प्रमुख आयातित वस्तुएं जो कुल व्यापारिक आयात का लगभग

[12] इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, $300 बीएन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय 2026, विजन डॉक्यूमेंट वॉल्यूम 2. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jan/doc20221247801.pdf

[13] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1831289

चार्ट 23: भारत का पण्य वस्तु आयात- जुलाई 2022

ए. भारत के पण्य वस्तु आयात में रुझान*

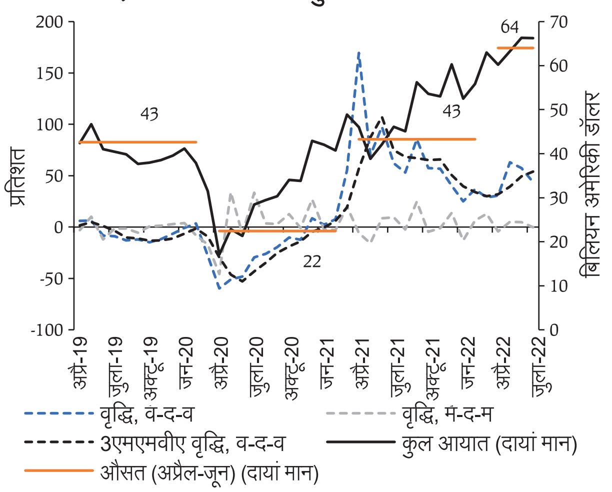

बी: वर्ष-दर-वर्ष आयात वृद्धि में अनुक्रमिक परिवर्तन का अपघटन

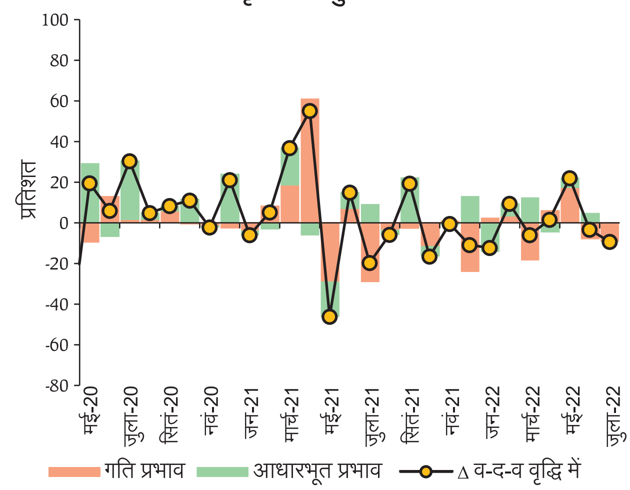

*3एमएमवीए तीन महीने का एक चल मूल्य औसत है।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

एक तिहाई हिस्सा हैं, अपनी पांच साल की औसत वृद्धि दर से ऊपर चल रही हैं, जो मूल्य प्रभावों को दर्शाती हैं (चार्ट 25)।

निर्यात में गिरावट और व्यापारिक आयात में तेज वृद्धि के कारण जुलाई में व्यापार घाटा 30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के

चार्ट 24: भारत का तेल आयात

ए. तेल आयात

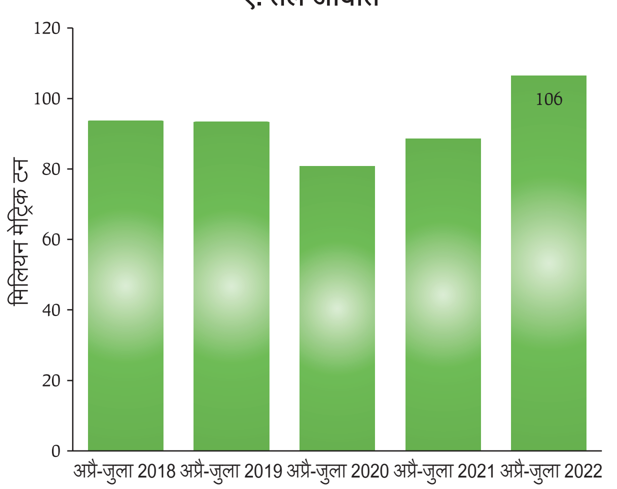

टिप्पणी: जुलाई 2022 के लिए आंकड़े अनुमानित हैं।

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई के स्टाफ द्वारा अनुमान।

बी. कच्चे तेल पर भारत की आयात निर्भरता

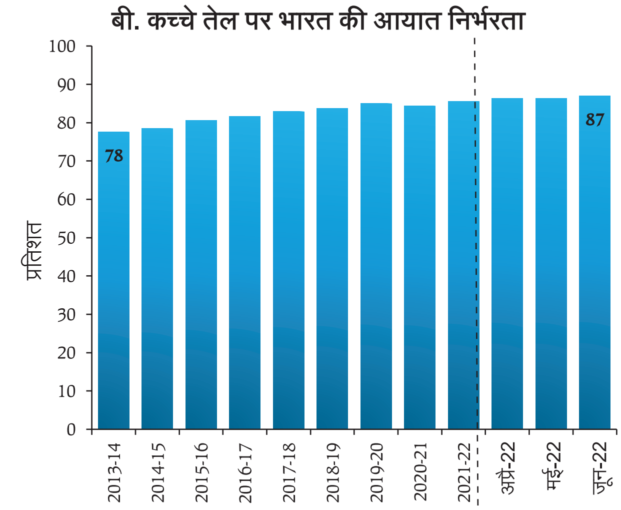

टिप्पणी: आयात निर्भरता खपत/ उपभोग के आधार पर है।

स्रोत: पीपीएसी।

चार्ट 25: मुख्य पण्य वस्तुओं में आयात वृद्धि

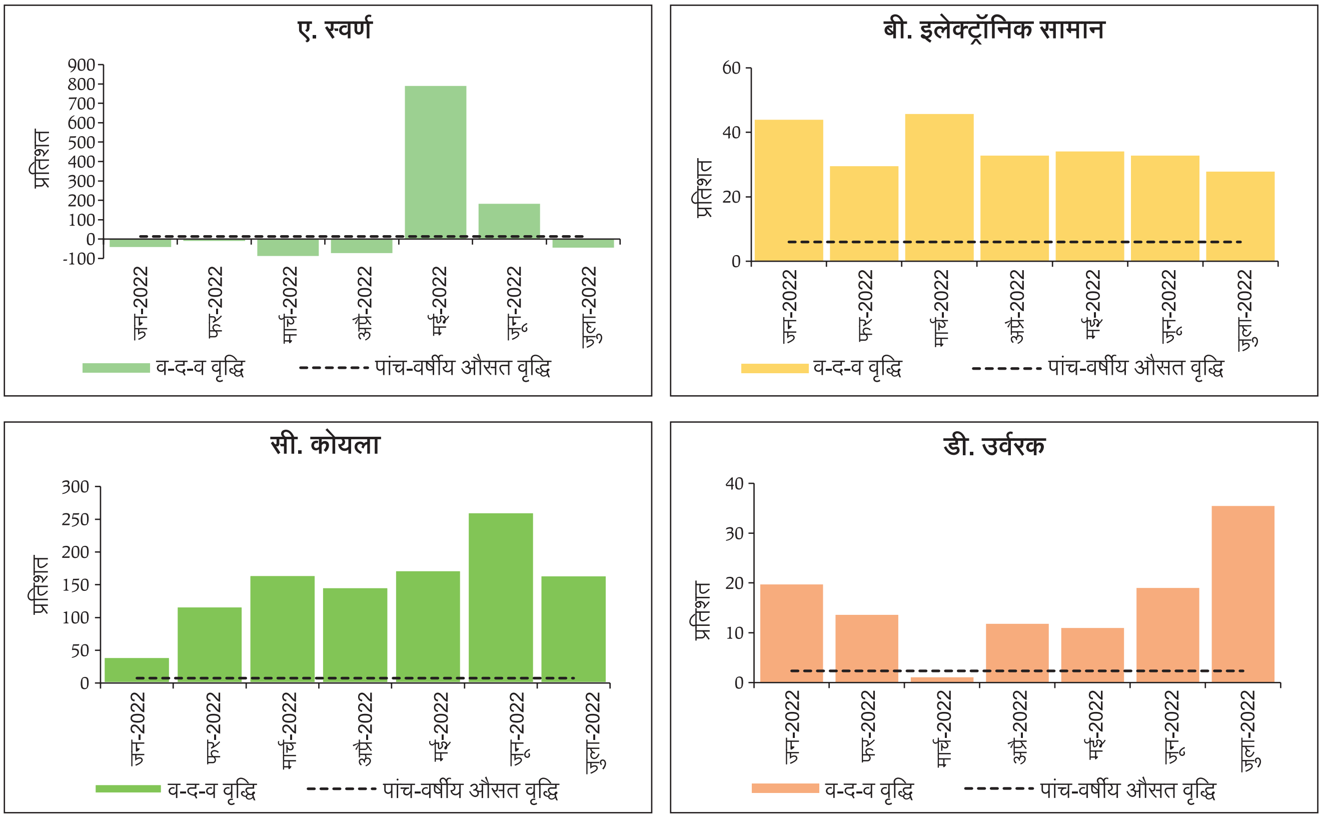

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग तीन गुना है। व्यापार घाटे के देश-वार विश्लेषण से पता चलता है कि भारत चीन के साथ सबसे अधिक अंतर रखता है, तत्पश्चात इराक और सऊदी अरब (चार्ट 26) का स्थान है।

चार्ट 26: भारत का पण्य वस्तु व्यापारिक घाटा

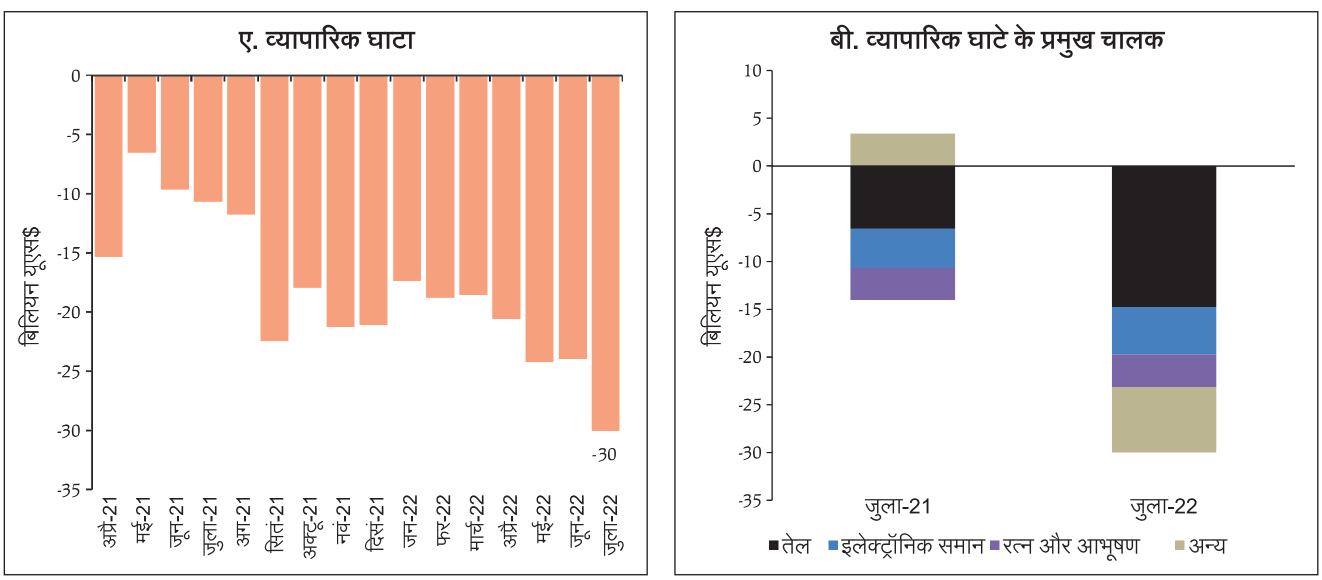

स्रोत: डीजीसीआईएस; और पीआईबी।

चार्ट 27: वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान

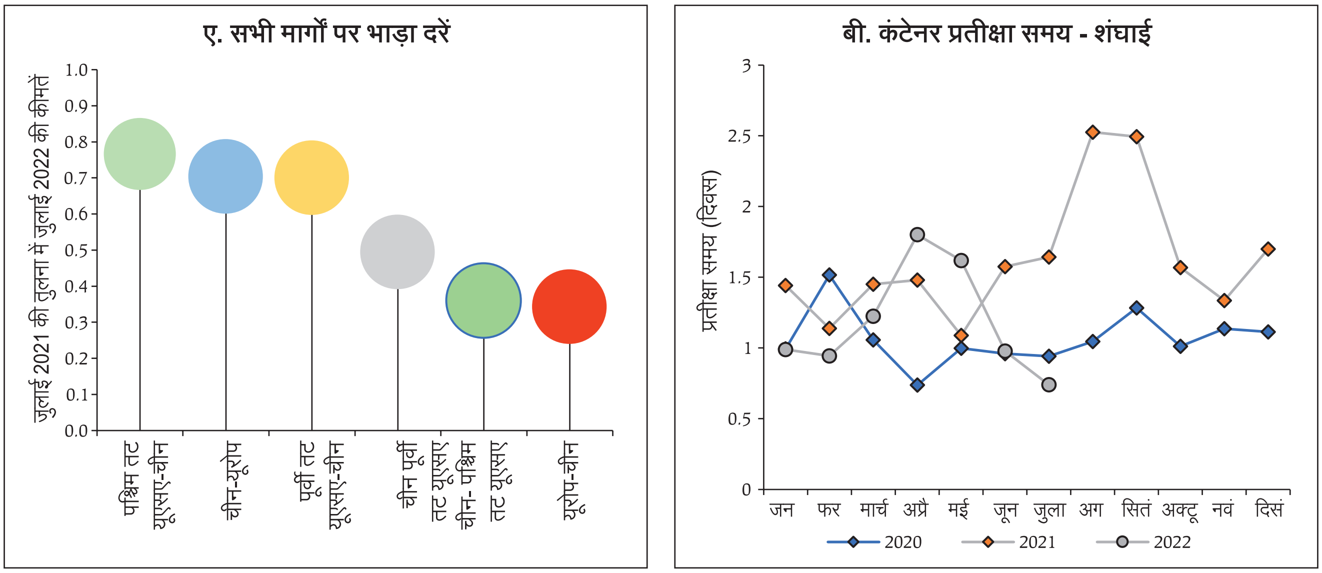

स्रोत: रेफिनिटिव एकोन।

जुलाई 2022 में सभी प्रमुख मार्गों पर माल ढुलाई की कीमतों में कमी आई (चार्ट 27 ए)। चीन के प्रमुख बंदरगाहों में कंटेनर प्रतीक्षा समय में भी सुधार के संकेत दिखाई दिए (चार्ट 27 बी)।

अप्रैल-जून 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में 53.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे खर्च की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ - पूंजी परिव्यय (आरईसीओ) की तुलना में राजस्व व्यय अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.8 से घटकर 2022-23 की पहली तिमाही में 4.8 हो गया (चार्ट 28)।

प्राप्तियों के मोर्चे पर, प्रतिकूल आधार प्रभावों के बावजूद प्रत्यक्ष करों में सकारात्मक गति से प्रेरित अप्रैल-जून के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि में तेजी आई (चार्ट 29)। इसके अलावा,

चार्ट 28: ति1 के दौरान व्यय की गुणवत्ता

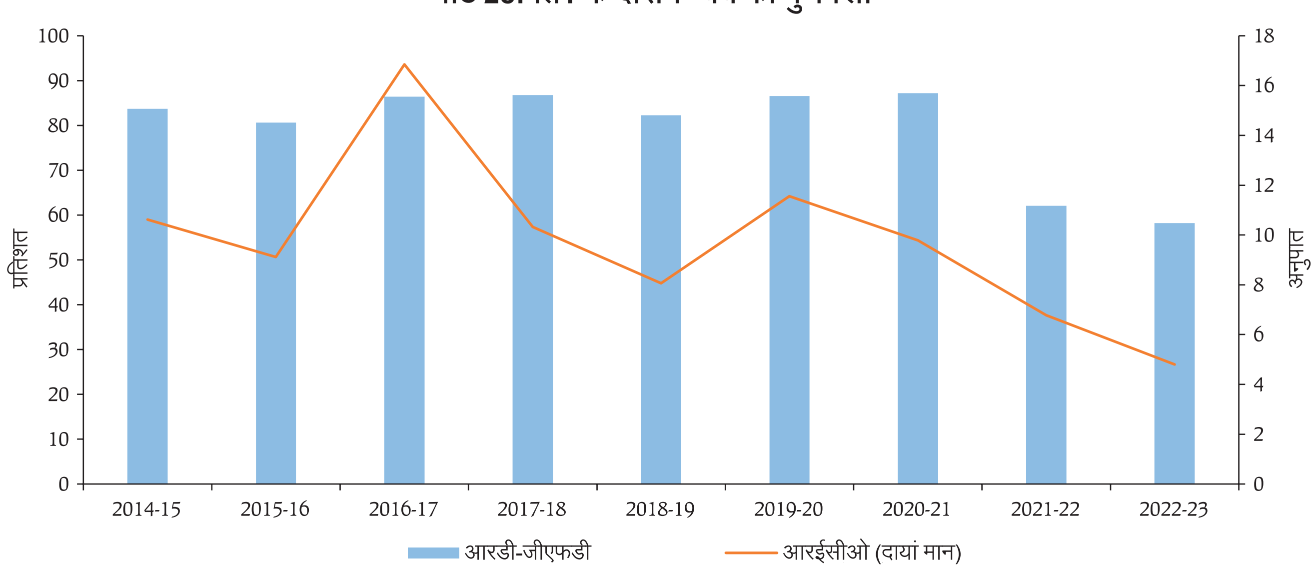

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए)।

चार्ट 29: ति: 2022-23 में कर वृद्धि का संवेग और आधारभूत प्रभाव में अपघटन

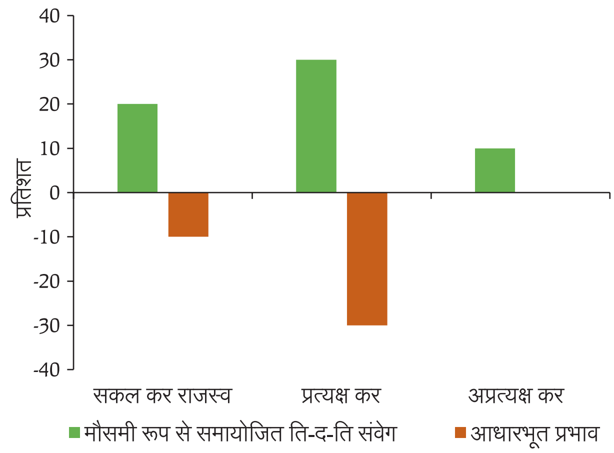

स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

चार्ट 30: ब्याजेतर राजस्व

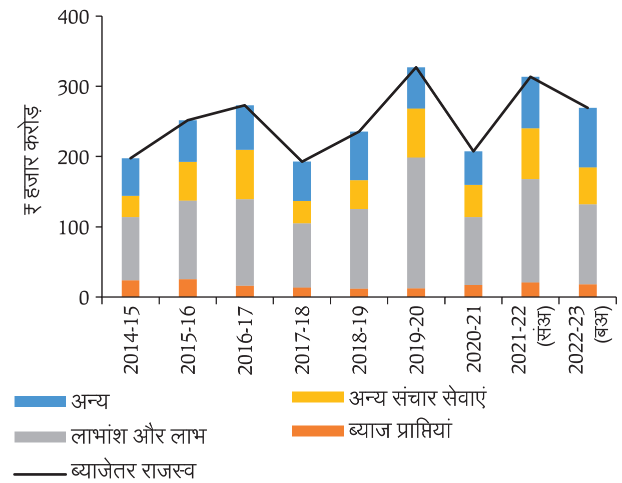

टिप्पणी: 'अन्य संचार सेवाओं' के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियों से संबंधित हैं।
स्रोत: महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 1.5 लाख करोड़ रुपये कमाए, जिसमें से कम से कम 13,365 करोड़[14] रुपये का भुगतान पहली वार्षिक किस्त के रूप में किया जाएगा, जिससे गैर-कर स्रोतों से प्राप्तियों को सहयोग मिलेगा (चार्ट 30)।

जुलाई 2022 में जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) 1.49 लाख करोड़ रुपये था, जो इसकी शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक रहा है और लगातार पांचवां महीना है जिसके लिए जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है (चार्ट 31)।

चार्ट 31: मासिक जीएसटी राजस्व

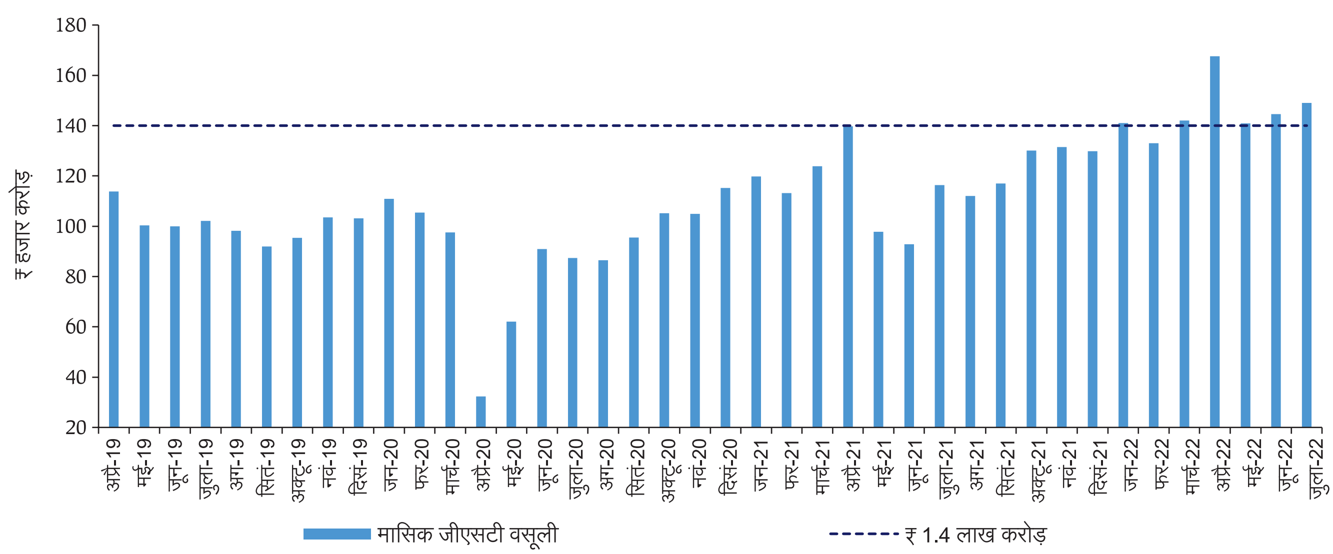

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)।

---

14 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1847279

चार्ट 32: राज्यों के बजटीय घाटे में प्रवृत्ति (अप्रैल-जून)

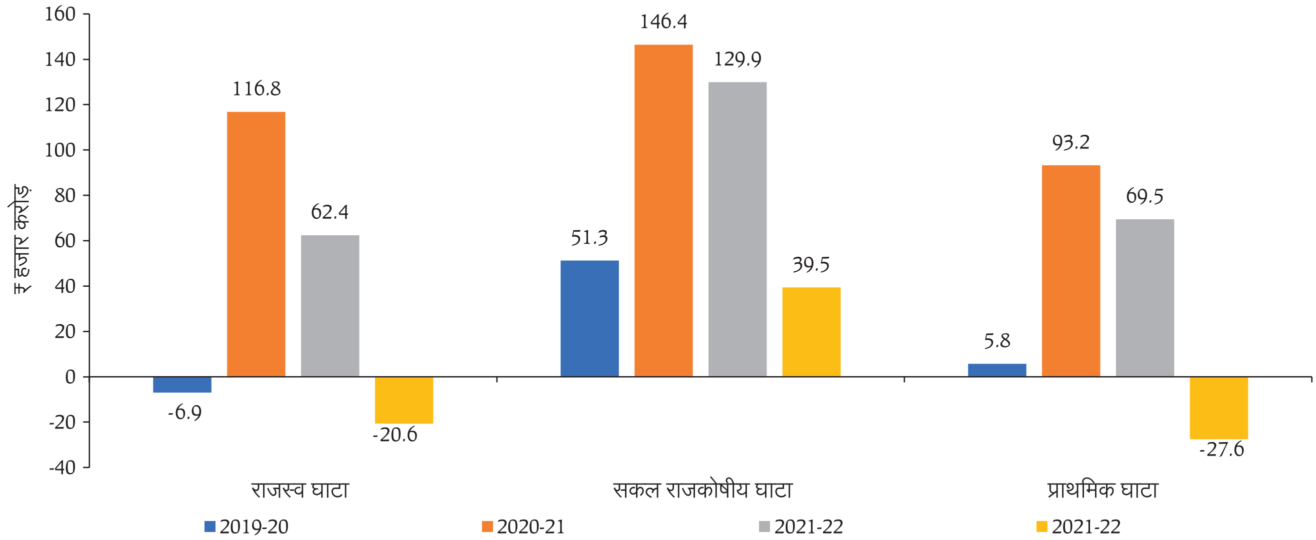

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)।

21 राज्यों के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों के प्रमुख बजटीय घाटे के संकेतकों में एक साल पहले की तुलना में 2022-23 की पहली तिमाही में सुधार हुआ है, जो मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों में लगातार सुधार और पूंजी परिव्यय में गिरावट से प्रेरित है (चार्ट 32)। राजस्व प्राप्तियों में सालाना आधार पर 33.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें सभी उप-घटकों - कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केंद्र से अनुदान में तेज वृद्धि हुई। राज्यों द्वारा किए गए राजस्व व्यय में 131 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मार्च 2022 में, केंद्र ने निर्धारित किया था कि राज्यों को अपने बजट से बाहर उधारियों को अपने ऋणों के साथ समान करना चाहिए, और 2020-21 और 2021-22 में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी ऐसे उधार को चालू वित्त वर्ष की उधार सीमा से समायोजित किया जाएगा। हाल ही में, केंद्र द्वारा बजट से बाहर उधारी के मानदंडों में ढील दी गई है, जिससे राज्यों को मार्च 2026 तक अगले चार वर्षों की उधार सीमा के मुकाबले 2021-22 के दौरान अपनी गैर-बजट उधारी निर्धारित करने की अनुमति मिल गई है। इस छूट से राज्य सरकारों के वित्त पर दबाव कम होगा और पूंजीगत व्यय करने के लिए उनके पास संसाधन उपलब्धता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र ने पूंजीगत व्यय वृद्धि का समर्थन करने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आठ राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी है।

कुल आपूर्ति

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत धीमी रही क्योंकि जून के दौरान बारिश का कुल स्तर लंबी अवधि के औसत (एलपीए)[15] वर्षा से 8 प्रतिशत कम रही, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और इस मौसम की अब तक (10 अगस्त तक) बारिश सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक है। वर्षा का असमान स्थाानिक वितरण उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक (पीआरएन)[16] की साप्ताहिक प्रगति में परिलक्षित हुआ, जबकि यह लगातार आईएमडी के कुल वर्षा सूचकांक से नीचे रहा है तथा जुलाई के दूसरे छमाही में कुछ तेजी से बढ़ा है (चार्ट 33)। पूर्वी और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में जून में एलपीए से 22 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है, इसके बाद जुलाई में एलपीए से 45 प्रतिशत कम बारिश हुई है (चार्ट 34)। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में काफी कम बारिश (सामान्य से 24-

15 दीर्घावधि औसत वर्षा की गणना 50 वर्षों के औसत (1971- 2020) वर्षा के रूप में की जाती है।

16 पीआरएन की गणना प्रत्येक राज्य द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के योगदान का उपयोग करके की जाती है।

चार्ट 33: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून वर्षा की प्रगति

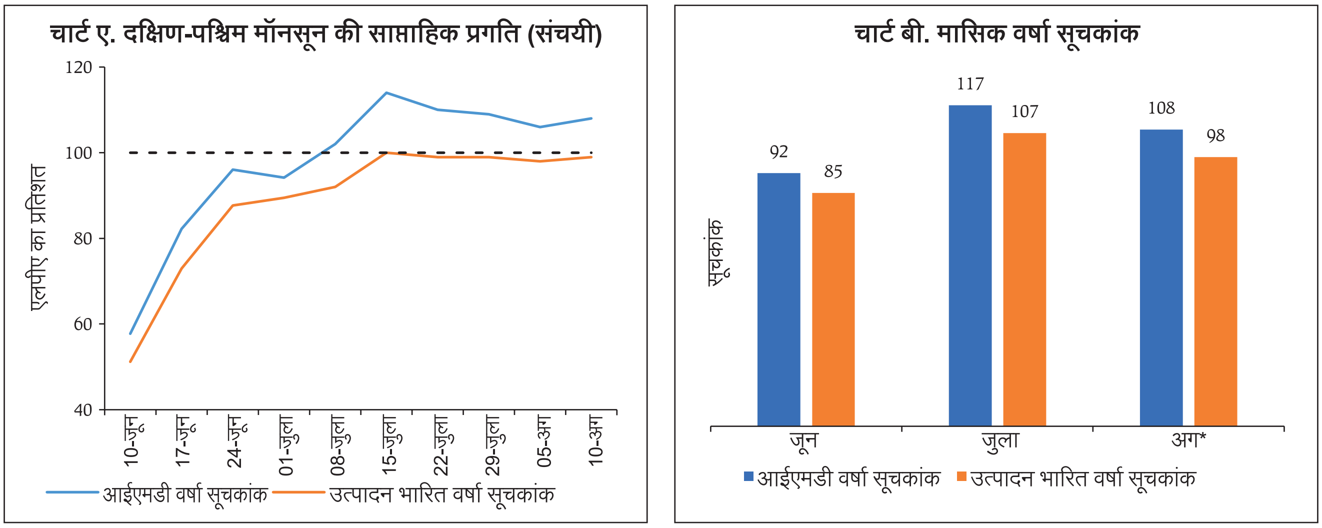

*10 अगस्त तक।
स्रोत: आईएमडी और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

48 प्रतिशत कम) के कारण खरीफ की बुवाई में देरी हुई है, जो देश के कुल खाद्यान्न का एक तिहाई उत्पादन करते हैं।

चावल प्रमुख खरीफ फसल है और एसडब्ल्यूएम बारिश पर अत्यधिक निर्भर है। धान का रकबा एक साल पहले बोए गए क्षेत्र

चार्ट 34: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून वर्षा का स्थानिक वितरण

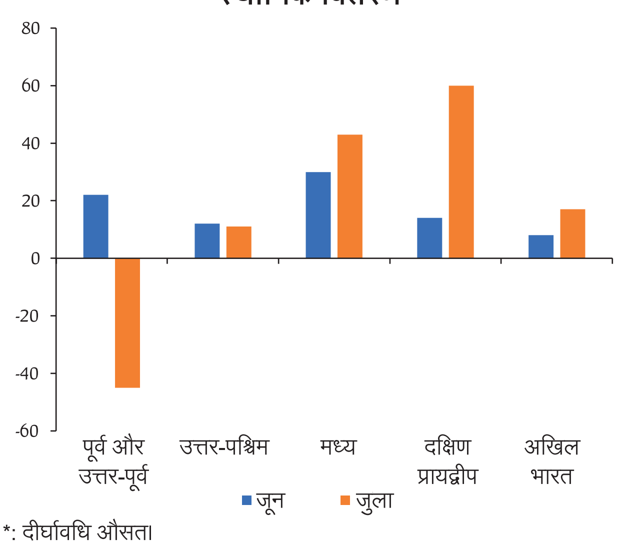

*: दीर्घावधि औसत।
स्रोत: आईएमडी।

के साथ-साथ सामान्य क्षेत्र (5 साल का औसत) से काफी पीछे है (चार्ट 35 ए)। यद्यपि चावल (-12.7 प्रतिशत) और दालों (-2.5 प्रतिशत) की अखिल भारतीय बुवाई पिछले वर्ष (05 अगस्त, 2022 तक) के स्तर से नीचे है, तिलहन (0.6 प्रतिशत), मोटे अनाज (3.9 प्रतिशत), कपास (6.7 प्रतिशत) और गन्ना (0.5 प्रतिशत) के रकबे में सालाना आधार पर वृद्धि हुई है। कुल खरीफ फसल का रकबा पिछले वर्ष की इसी तारीख को दर्ज किए गए स्तर से 3.0 प्रतिशत कम है।

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, अगस्त में सामान्य बारिश के पूर्वानुमान से धान की बुवाई की कमी में सुधार होने की संभावना है, जबकि बिहार और झारखंड में, महीने के दौरान बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है (चार्ट 35 बी)। खरीफ चावल के राष्ट्रीय उत्पादन में इन चार राज्यों का योगदान 33 प्रतिशत है। यदि दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश बुवाई के समय सीमा के भीतर एलपीए के समान होने में विफल रहती है, तो चावल के उत्पादन के लिए सिंचाई समर्थन महत्वपूर्ण होगा (चार्ट 36 ए)। यद्यपि इन राज्यों में चावल बोए गए क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुलभ है [झारखंड (4.6 प्रतिशत) को छोड़कर),

चार्ट 35: भारत में चावल उत्पादन परिदृश्य

चार्ट ए. धान की बुआई की स्थिति*

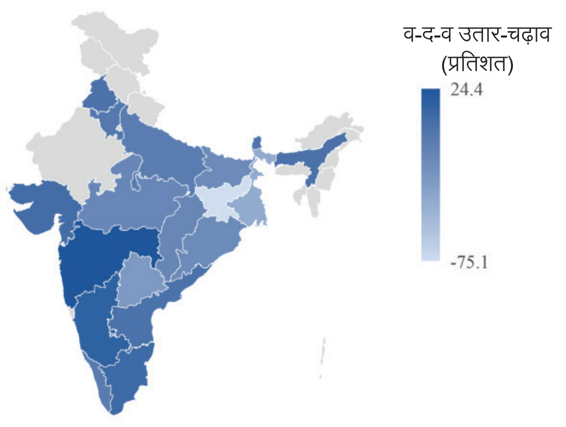

ग्रे रंग चावल के तहत नगण्य क्षेत्र वाले राज्यों को दर्शाता है।
*05 अगस्त 2022 तक।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

चार्ट बी. अखिल भारतीय *खरीफ* चावल उत्पादन में हिस्सा

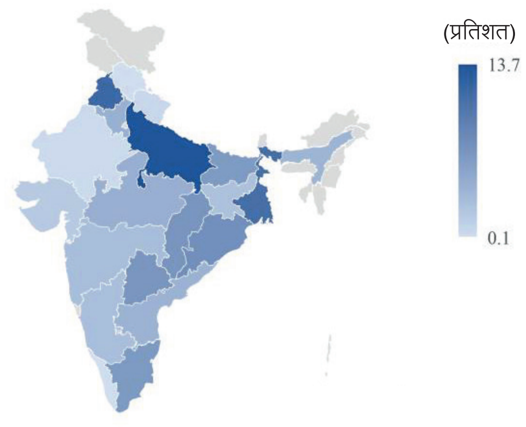

ग्रे रंग नगण्य हिस्से वाले डेटा या डेटा अनुपलब्धता वाले राज्यों को दर्शाता है।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कई सिंचाई संरचनाओं में वास्तविक पानी की उपलब्धता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। यह देश के पूर्वी क्षेत्रों में कम जलाशय स्तरों में परिलक्षित होता है (चार्ट 36 बी)[17]।

दूसरे अग्रिम अनुमान (एई)[18] के अनुसार, 2021-22 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से कुल फलों और सब्जियों (चार्ट 37) के उच्च उत्पादन से प्रेरित होने के साथ

चार्ट 36: भारत में सिंचित चावल की स्थिति

ए. चावल के रकबे में सिंचाई कवरेज

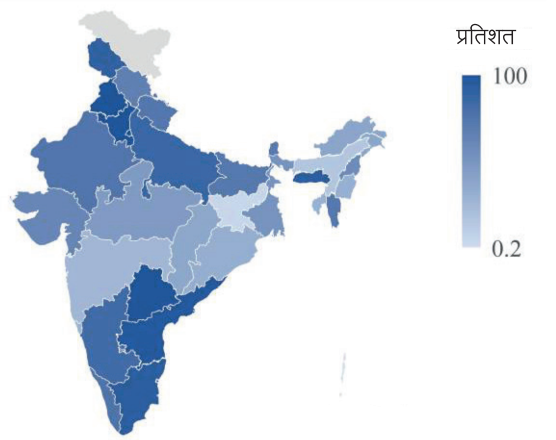

ग्रे रंग डेटा की अनुपलब्धता को दर्शाता है।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

बी. सिंचाई के रकबे *की तुलना में* वर्षा का संबंध*

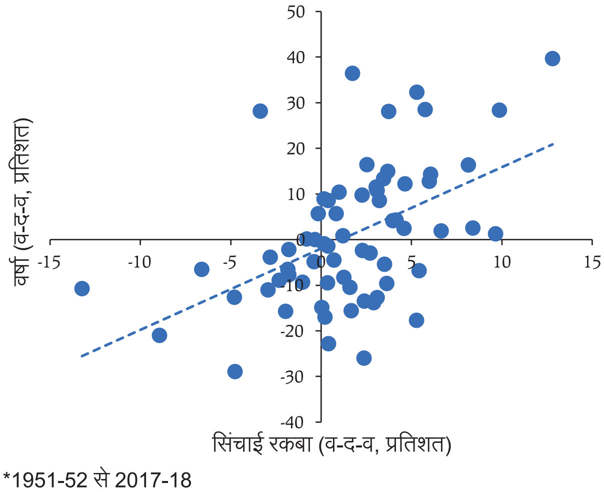

*1951-52 से 2017-18
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; और सीएमआईई।

---

[17] दिनांक 11 अगस्त, 2022 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र के जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 43 प्रतिशत की तुलना में कुल संग्रहण क्षमता का 29 प्रतिशत है और दशकीय औसत 45 प्रतिशत है।

[18] 14 जुलाई, 2022 को जारी हुई।

चार्ट 37: बागवानी फसलों का उत्पादन (2021-22)

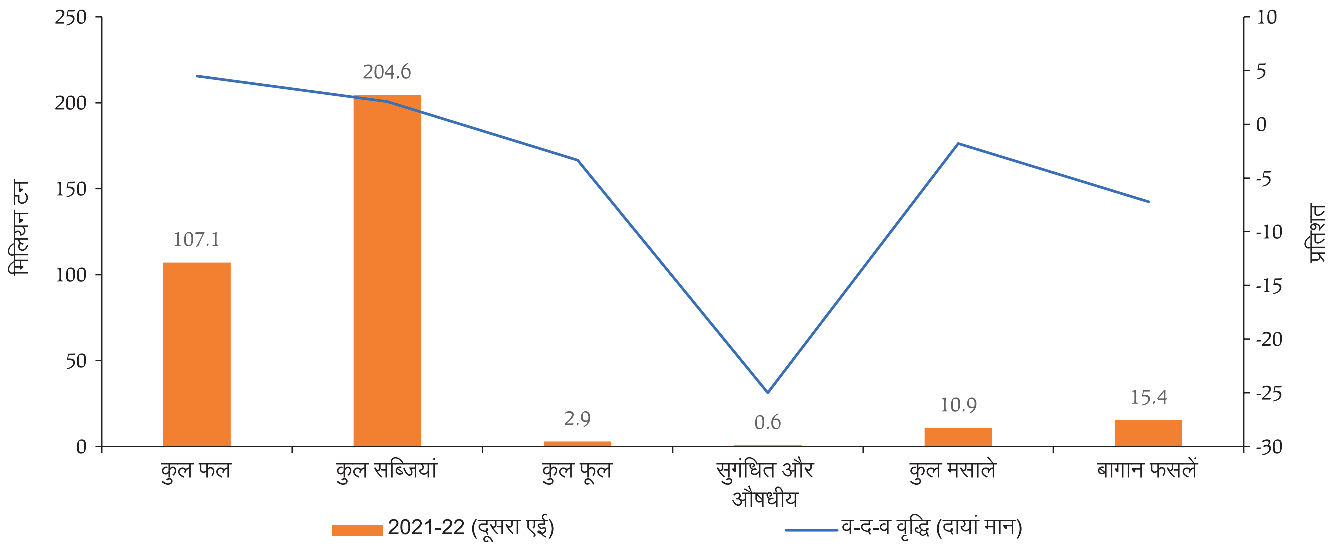

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रिकॉर्ड 341.6 मिलियन टन है, जो 2020-21 के अंतिम अनुमान से 2.1 प्रतिशत अधिक है । बागवानी क्षेत्र की समग्र उत्पादकता (उत्पादन/क्षेत्र) में 2021-22 में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फलों के उत्पादन में वृद्धि जहाँ क्षेत्र (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.3 प्रतिशत) और उत्पादकता (3.2 प्रतिशत) के दृष्टिकोण से होने की उम्मीद है, वहीं सब्जी उत्पादन में वृद्धि क्षेत्र में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ होने की संभावना है (उत्पादकता में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है)।

चालू रबी विपणन सत्र (2022-23) के लिए गेहूं की खरीद 1.88 करोड़ टन रही, जो शुरुआती लक्ष्य (4.44 करोड़ टन) का 57.7 प्रतिशत और संशोधित लक्ष्य (1.95 करोड़ टन) से 5.1 प्रतिशत कम है। 11 अगस्त, 2022 तक, चावल की संचयी खरीद 59.1 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष (58.6 मिलियन टन) की तुलना में मामूली अधिक थी। चावल का स्टॉक-टू-नॉर्म अनुपात तिमाही (जुलाई-सितंबर) बफर मानदंडों की तुलना में 3.0 गुना अधिक है, जबकि गेहूं के मामले में यह मानक से थोड़ा नीचे है। मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंधों को 14 अगस्त, 2022[19] से प्रभावी मैदा, सूजी और गेहूं के आटे (आटा) के सभी प्रकारों के निर्यात पर प्रतिबंधों से बल मिला है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई जुलाई में मजबूती से बढ़कर 56.4 हो गया, जो पिछले आठ महीनों में सबसे अधिक विस्तार है। यह आउटपुट, नए ऑर्डर और इनपुट स्टॉक में वृद्धि के कारण हुआ, जो मांग की मजबूत स्थिति (चार्ट 38 ए) को उजागर करता है।

दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र पीएमआई जून 2022 में 59.2 के 11 साल के उच्च स्तर से कम हो गया, लेकिन जुलाई में 55.5 के साथ विस्तारवादी बना रहा। नए व्यवसायों के नेतृत्व में सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, हालांकि इनपुट पर मुद्रास्फीति का दबाव उच्च बना रहा, जिससे भविष्य की व्यावसायिक अपेक्षाओं को कम किया गया (चार्ट 38 बी)।

सेवा क्षेत्र में, परिवहन संकेतकों में तेजी जारी रही क्योंकि जुलाई 2022 में रेलवे माल ढुलाई यातायात आय में 8.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, (चार्ट 39 ए)। कोयला और पीओएल

[19] https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/5f976de3-d1bc-40e4-88c5-743c9a2dec39/Notification%20in%20English.pdf

चार्ट 38: क्रय प्रबंधक सूचकांक

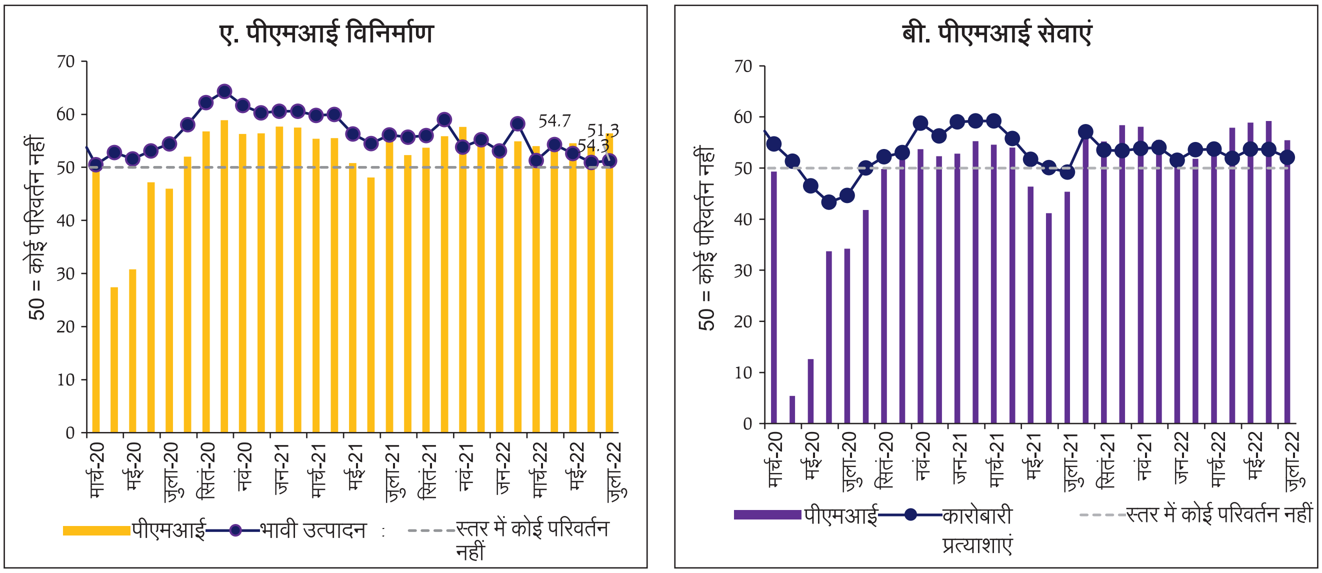

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

माल ढुलाई में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लौह अयस्क और खाद्यान्न में संकुचन देखा गया। पीओएल, कच्चे उर्वरकों, थर्मल कोयला और अन्य तरल पदार्थों में वृद्धि के कारण जुलाई में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में तेजी आई, जो कुल कार्गो का 58 प्रतिशत है (चार्ट 39 बी)।

निर्माण क्षेत्र में, जून-जुलाई 2022 में गतिविधि में तेजी जारी रही, सीमेंट उत्पादन और स्टील की खपत में लगातार सात महीनों के लिए महामारी से पहले के स्तर से वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 40)। मानसून की शुरुआत के साथ जून में सीमेंट उत्पादन में कमी आई। हालांकि, बुनियादी ढांचे पर खर्च पर

चार्ट 39: रेलवे और कार्गो ट्रैफिक

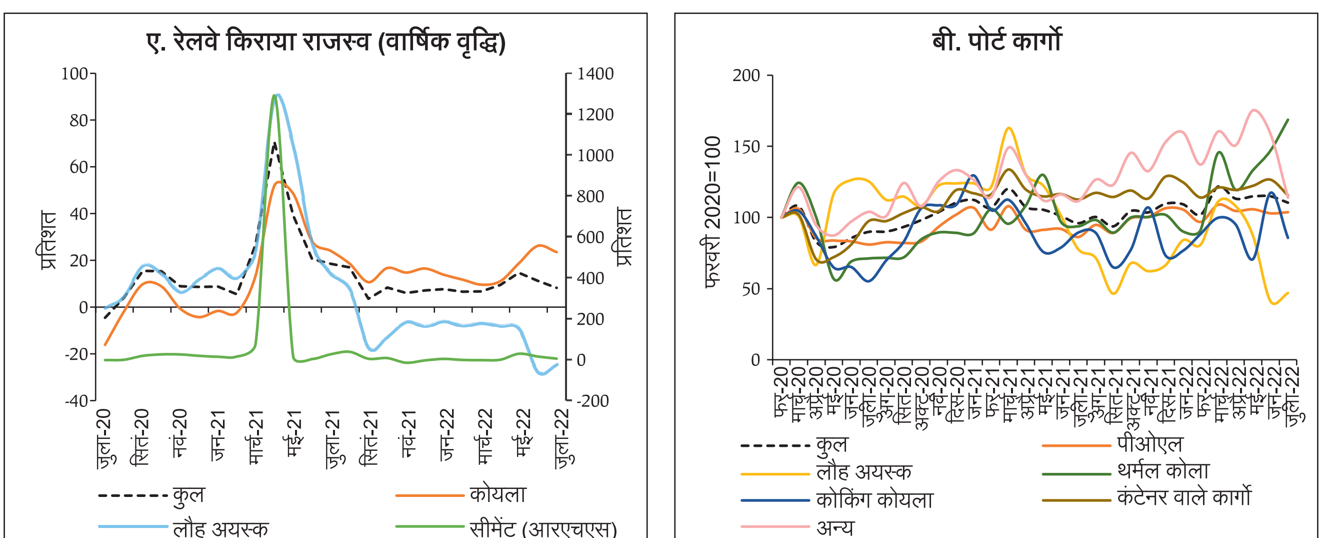

स्रोत: रेल दृष्टि।

स्रोत: भारतीय पोर्ट संघ।

चार्ट 40: स्टील खपत और सीमेंट निर्माण

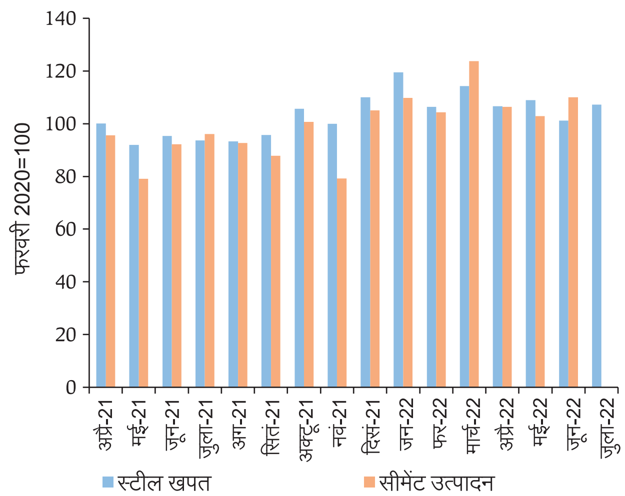

स्रोत: संयुक्त प्लांट समिति और आर्थिक परामर्शदाता, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कार्यालय।

ध्यान देने के कारण इस क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।

जून में घरेलू यात्रियों की संख्या में गिरावट जुलाई में भी जारी रही और मानसून के मौसम में यात्रियों की संख्या में क्रमिक आधार पर 8.9 प्रतिशत की गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय कार्गो के अन्य उप क्षेत्रों में जून के मुकाबले वृद्धि दर्ज की गई। अगस्त के पहले दस दिनों में घरेलू यात्री उप क्षेत्र में गतिविधियों में क्रमिक रूप से संकुचन हुआ, लेकिन अंतरराष्ट्रीय यात्री माल ढुलाई उप क्षेत्र स्थिर रहा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों श्रेणियों के लिए कार्गो उप क्षेत्र में गिरावट आई क्योंकि मानसून ने व्यापार और यात्रा गतिविधि को बाधित किया। महामारी के दौरान अचानक कीमतों में उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई हवाई किराए की सीमा को हटाने के साथ, 31 अगस्त के बाद, उन क्षेत्रों में हवाई यात्रा में तेजी आ सकती है जहां बाजार मूल्य निर्धारण बुकिंग को प्रोत्साहित कर सकता है।

कुल मिलाकर सेवा क्षेत्र जून में सुदृढ़ बना रहा और मौसमी कारकों ने गतिविधियों को प्रभावित किया। बढ़ती कीमतों के कारण मांग में गिरावट को संपर्क गहन विमानन और पर्यटन क्षेत्रों के तेजी प्राप्त करने से सहयोग मिल सकता है (सारणी 3)।

सारणी 3: उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएं

क्षेत्र	संकेतक	उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाओं की वृद्धि (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)				2019 की तुलना में वृद्धि			
		अप्रै-22	मई-22	जून-22	जुला-22	अप्रै-22/ अप्रै-19	मई-22/ मई-19	जून-22/ जून-19	जुला-22/ जुला-19
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	-3.8	185.1	19.1	11.1	1.6	10.6	31.6	54.6
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहन बिक्री	15.4	253.2	23.4	9.6	-29.9	-27.4	-20.7	-8.6
	तीन पहिया वाहन बिक्री	51.1	2161.6	183.9	72.8	-54.7	-44.7	-48.5	-43.8
	ट्रैक्टर बिक्री	40.6	47.4	-14.4	-15.3	55.5	41.1	24.5	21.2
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	100.3				11			
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	9.4	14.6	11.3	8.3	20.9	25.5	23.7	22.5
	पोर्ट कार्गो यातायात	5.6	10.2	12.2	15.1	8.1	11.4	14.6	6.8
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	7.9	54.7	40.4		2.7	1.9	4.4	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	-0.9	-4.6	0.5		-5.2	-13.6	-5.1	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	87.8	474.7	247.9		-1.5	-2.0	-10.5	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	155.6	722.8	753.6		-36.6	-28.0	-21.5	
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	28.0	84.1	36.2	17.8	43.3	35.6	49.7	44.9
	जीएसटी ई-वे बिल्स (आंतर राज्य)	28.4	83.3	38.6	19.8	50.8	45.5	58.7	51.5
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	27.4	85.5	32.2	14.7	32.9	21.8	36.4	35.2
	यात्री आगमन	399.2	2043.7	1349.2		-49.3	-31.1	-28	
विनिर्माण	इस्पात उपभोग	1.8	21.3	5.9	14.5	18.6	7.7	0.7	7
	सीमेंट उत्पादन	7.4	26.2	19.4		8.3	10.8	19.6	
पीएमआई संकेतक	विनिर्माण	54.7	54.6	53.9	56.4				
	सेवाएं	57.9	58.9	59.2	55.5				

स्रोत: सीएमआईई, सीईआईसी आंकड़े: आईएचएस मार्किट ; एसआईएएम ; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त प्लांट समिति

चार्ट 41: सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और वाहक

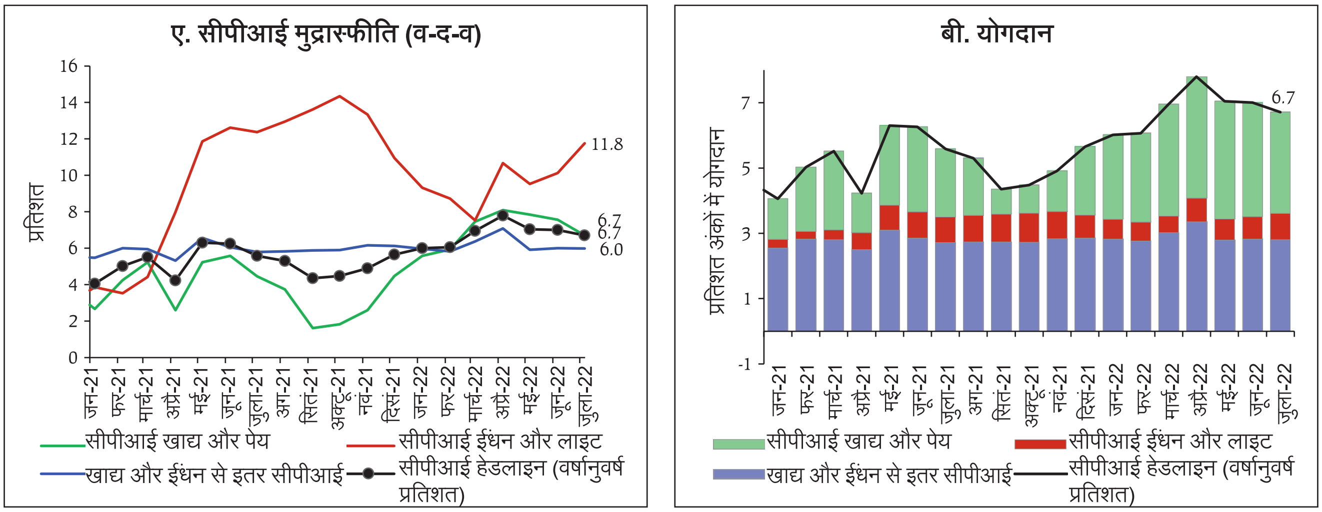

टिप्पणी: अप्रैल- मई 2021 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति की गणना अप्रैल- मई 2020 के लिए इम्प्यूटेड सीपीआई सूचकांकों के आधार पर की गई थी।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ के आकलन

मुद्रास्फीति

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 अगस्त, 2022 को जारी अनंतिम आंकड़ों से पता चला है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल बदलाव से मापी गई मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने में 7.0 प्रतिशत थी (चार्ट 41 ए)। माह-दर माह (एम-ओ-एम) गति में 46 बीपीएस की वृद्धि 74 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव (एक साल पहले कीमतों में एम-ओ-एम बदलाव) से अधिक थी, जिससे जून और जुलाई के बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति में 30 बीपीएस की गिरावट आई। यह गिरावट खाद्य और पेय समूह (चार्ट 41 बी) के योगदान में कमी से उपजी है।

खाद्य एवं पेय समूह के भीतर कीमतों में 0.1 प्रतिशत, ईंधन समूह के लिए 2.0 प्रतिशत और कोर सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) श्रेणी के लिए 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उप-समूह स्तर पर, जुलाई में मूल्य वृद्धि फलों, अंडे और मसालों तथा शिक्षा के मामले में अधिक थी, जबकि तेल और वसा, एवं मांस और मछली के मामले में कीमतों में गिरावट आई (चार्ट 42)।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई, जो एक महीने पहले 7.6 प्रतिशत थी। उप-समूहों के संदर्भ में, मांस और मछली, दूध, खाद्य तेल, सब्जियों और गैर-मादक पेय पदार्थों के मामले में मुद्रास्फीति में

चार्ट 42: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (व-द-व) और परिवर्तन (मा-द-मा)

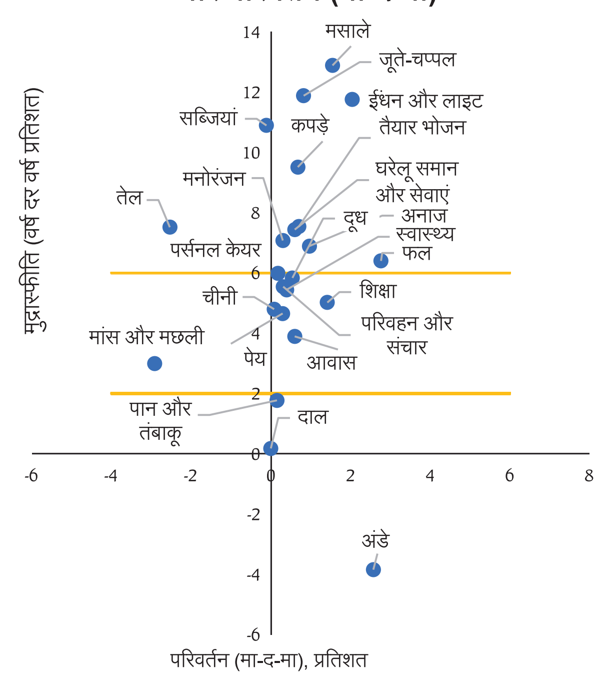

स्रोत: एमओएसपीआई और आरबीआई स्टाफ के आकलन

चार्ट 43: जुलाई *बनाम* जून 2022 उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति

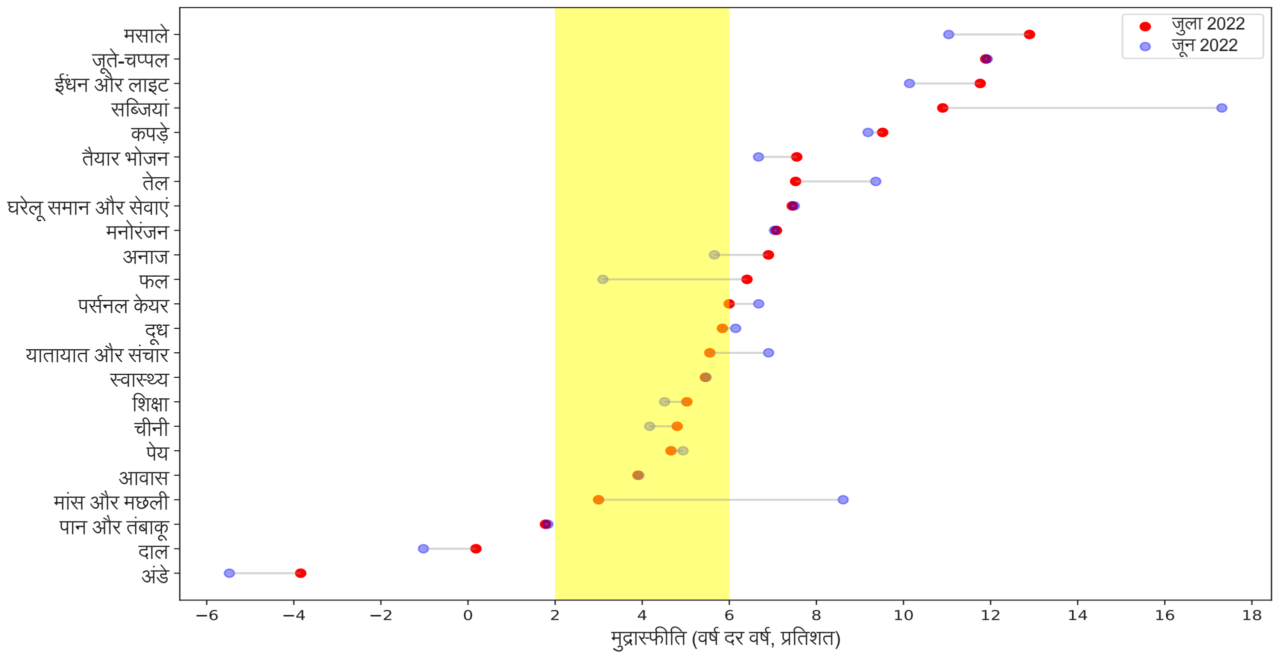

स्रोत: एमओएसपीआई और आरबीआई स्टाफ के आकलन

कमी आई (चार्ट 43)। दूसरी ओर अनाज, फल, दाल, चीनी, मसाले और तैयार भोजन की मुद्रास्फीति बढ़ी है। जून की तुलना में जुलाई में अंडे में अवस्फीति कम हो गई।

ईंधन और बिजली श्रेणी में मुद्रास्फीति जून के 10.1 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 11.8 प्रतिशत हो गई। इसकी वजह केरोसीन की मुद्रास्फीति में तेज उछाल रहा जबकि बिजली की कीमतें अवस्फीति में बनी रहीं। सीपीआई बास्केट में 6.8 प्रतिशत के भारांश वाले ईंधन समूह ने जुलाई में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 11.9 प्रतिशत का योगदान दिया।

जुलाई में मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.0 प्रतिशत रही। जबकि कपड़े और जूते तथा शिक्षा जैसे उप-समूहों ने मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की, परिवहन और संचार और निजी देखभाल और संबन्धित वस्तुएँ उप-समूहों में नरमी देखी गई (चार्ट 43)। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, आवास, मनोरंजन और मनोविनोद, घरेलू समान और सेवाओं एवं स्वास्थ्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति कमोबेश स्थिर रही। मुख्य श्रेणी के भीतर, आपूर्ति शृंखला दबावों में कमी के साथ हाल के महीनों में भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव (आईएसपीआई)[20] के सूचकांक में गिरावट के कारण माल मुद्रास्फीति में कमी आई है। दूसरी ओर, सेवा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है (चार्ट 44)।

भौगोलिक वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति 6.8 प्रतिशत थी, जो जुलाई में शहरी मुद्रास्फीति (6.5 प्रतिशत) से अधिक थी। राज्यों में, तेलंगाना, मिजोरम और सिक्किम में 8 प्रतिशत से अधिक मुद्रास्फीति रही, जबकि गोवा और मणिपुर में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे दर्ज की गई (चार्ट 45)।

उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीसीए) के अगस्त के लिए अब तक (1-12 अगस्त) उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य के आंकड़े अनाज की कीमतों में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं, जो प्रमुख रूप से गेहूं की कीमतों में वृद्धि के कारण रही हैं। दालों की कीमतों में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है जबकि खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। प्रमुख सब्जियों में, आलू और प्याज की कीमतों

[20] आईएसपीआई का निर्माण 19 घरेलू और वैश्विक चरों में निहित सामान्य कारकों को निकालकर किया गया है। उक्त पद्धति के लिए “भारत पर आपूर्ति शृंखला दबाव का मापन”, पात्र एमडी, एच. बेहरा और डी. गजभिए (2022) आरबीआई बुलेटिन, अप्रैल 2022; देखें।।

चार्ट 44ए: सीपीआई कोर मुद्रास्फीति: वस्तु *बनाम* सेवाएं

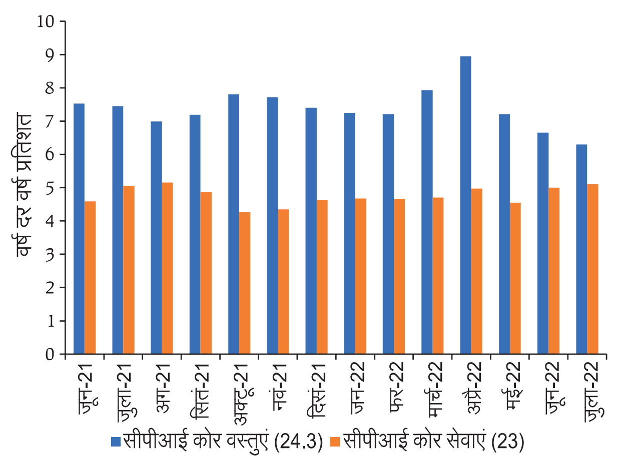

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े समग्र सीपीआई की भरिता को दर्शाता है।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और आरबीआई स्टाफ के आकलन

चार्ट 44बी: आपूर्ति शृंखला दबाव और सीपीआई कोर वस्तु मुद्रास्फीति

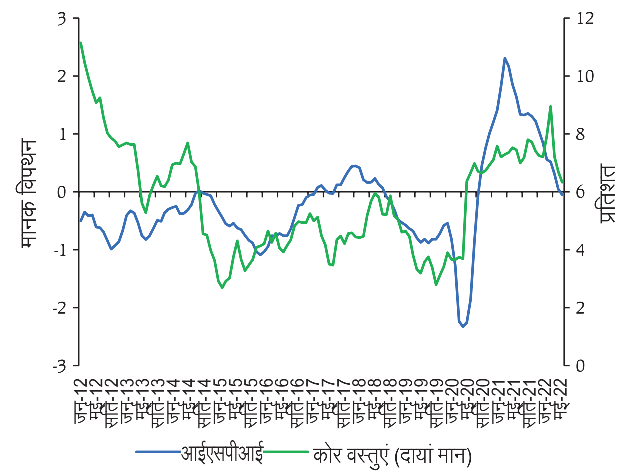

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और आरबीआई स्टाफ के आकलन

में तेजी आई है, जबकि टमाटर की कीमतों में तेज गिरावट जारी है (चार्ट 46)।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें अगस्त में अब तक स्थिर बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: पांच रुपये प्रति लीटर और तीन रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। जुलाई की तुलना में अगस्त में मिट्टी के तेल की कीमतों में तेजी से कमी आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान एलपीजी की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, दोनों नियंत्रित कीमतों में बदलाव को दर्शाते हैं (सारणी 4)।

जुलाई 2022 में विनिर्माण और सेवाओं में इनपुट लागत दबाव धीमी गति से बढ़ा, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी बिक्री मूल्य में तेजी आई।

चार्ट 45: राज्य-वार मासिक मुद्रास्फीति: सीपीआई संयुक्त जुलाई 2022

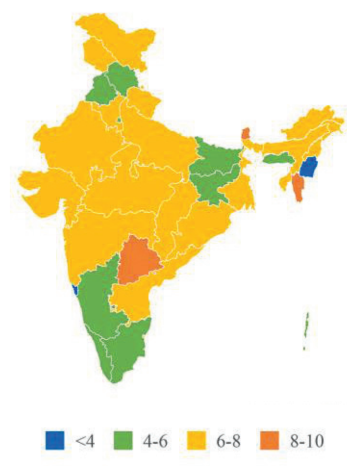

टिप्पणी: मानचित्र केवल प्रस्तुतीकरण उद्देश्य के लिए है।
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और आरबीआई स्टाफ के आकलन

सारणी 4: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		अग-21	जुला-22	अग-22 ^	जुला-22	अग-22
पेट्रोल	₹/लीटर	103.03	103.49	102.92	-0.7	-0.5
डीज़ल	₹/लीटर	93.32	93.06	92.72	-0.4	-0.4
मिट्टी का तेल (सब्सिडी)	₹/लीटर	34.29	71.44	62.73	15.2	-12.2
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	857.22	1055.19	1063.25	4.1	0.8

^: 1-12 अगस्त, 2022 की अवधि के लिए।
टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); तथा आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 46: डीसीए आवश्यक पण्य मूल्य

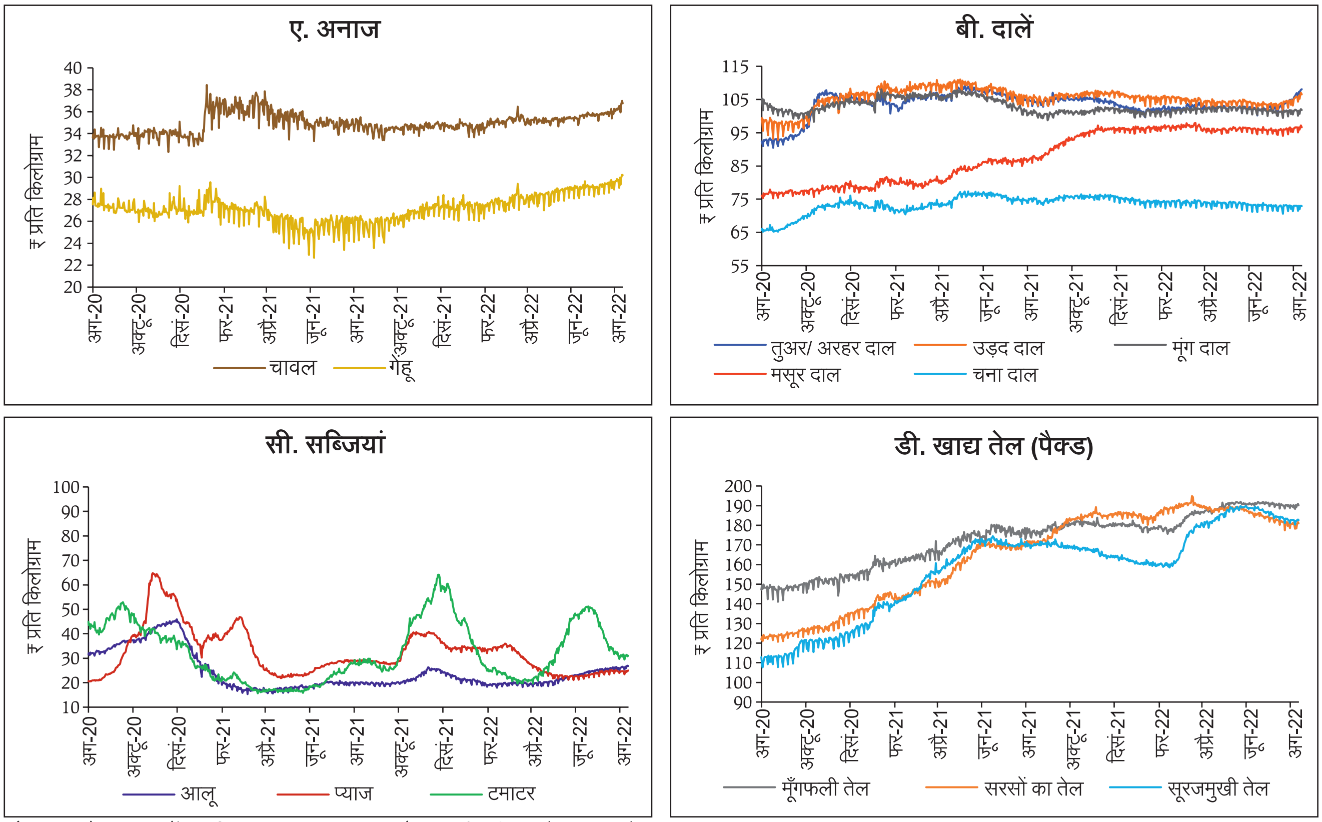

स्रोत: उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार; और भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ के आकलन

IV. वित्तीय स्थितियां

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत दैनिक औसत अवशोषण 16 जुलाई से 15 अगस्त 2022 के दौरान 8 जून से 15 जुलाई के दौरान ₹4.0 लाख करोड़ से घटकर ₹2.7 लाख करोड़ हो गया (चार्ट 47)। हाल के सप्ताहों में, ₹1.5 लाख करोड़ दैनिक औसत आधार पर एकदिवसीय स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) विंडो के माध्यम से अवशोषित किए गए हैं, जबकि शेष को 4.92 प्रतिशत की औसत प्रभावी अवशोषण दर[21] पर लंबी अवधि के परिवर्तनीय दर रिवर्स रीपो (वीआरआरआर) नीलामियों (मुख्य और फाइन-ट्यूनिंग दोनों) के माध्यम से जुटाए गए हैं। उछाल वाली जीएसटी और प्रत्यक्ष कर संग्रह के सामने धीमी सरकारी खर्च ने बैंकिंग प्रणाली में समग्र अधिशेष चलनिधि में गिरावट में योगदान दिया। रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन, जिसने रुपये की चलनिधि को बढ़ाया, ने भी चलनिधि की स्थिति को सख्त करने में योगदान दिया। तदनुसार, चूंकि जीएसटी संग्रह

चार्ट 47: चलनिधि की स्थितियां

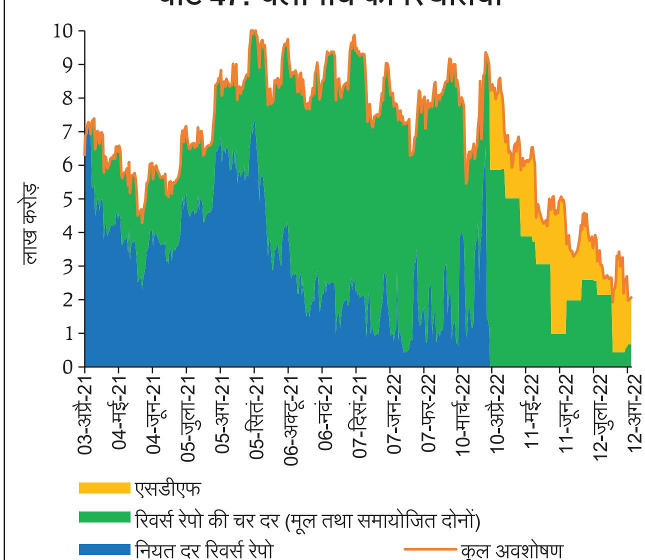

स्रोत: आरबीआई

[21] प्रभावी अवशोषण दर एसडीएफ दर का भारित औसत है और एसडीएफ तथा परिवर्तनीय दर रिवर्स रीपो विंडो के तहत भारित राशि के भार के साथ अलग-अलग परिपक्वता की वीआरआरआर नीलामियां हैं।

बैंकिंग प्रणाली से बाहर हो गया, रिज़र्व बैंक की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) विंडो से उधारी 25 जुलाई को बढ़कर ₹59,312 करोड़ (बकाया राशि) हो गई - 1 अप्रैल 2019 के बाद सबसे अधिक (₹94,263 करोड़) है। दबावों को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने ₹50,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 26 जुलाई 2022 को तीन-दिवसीय परिवर्तनीय दर रीपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की, जिसमें लगभग ₹1.52 लाख करोड़ की बोली प्राप्त हुई (3 से अधिक बोली-कवर अनुपात))। 29 जुलाई को 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी (मुख्य संचालन) के बाद एक ठंडी प्रतिक्रिया मिली - ₹2.0 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले केवल ₹12,712 करोड़ की बोलियां प्राप्त हुईं।

5 अगस्त को नीति दर में वृद्धि के साथ, एकदिवसीय मुद्रा बाजार दरों में मजबूती आई, साथ ही संपार्श्विक खंड में दरें एलएएफ कॉरिडोर के ऊपरी बैंड को पार कर गईं। औसत आधार पर, भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) और बाजार रीपो दर का रीपो दर के करीब कारोबार हुआ, जबकि ट्राई-पार्टी रीपो दर जुलाई की दूसरी छमाही के दौरान 12 अगस्त 2022 के दौरान नीतिगत रीपो दर से 8 बीपीएस नीचे कारोबार किया (चार्ट 48ए)। टर्म मनी मार्केट सेगमेंट में, 3-महीने के टी-बिल पर प्रतिफल 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो एक संक्षिप्त अवधि के लिए एमएसएफ दर से ऊपर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, 3 महीने के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) और 3 महीने के कमर्शियल पेपर (सीपी) पर प्रतिफल जुलाई की दूसरी छमाही से 12 अगस्त 2022 तक एमएसएफ दर से क्रमशः 46 बीपीएस और 70 बीपीएस के औसत स्प्रेड के साथ और सख्त हो गया (चार्ट 48बी)। बैंक जमा वृद्धि के कारण क्रेडिट ऑफटेक कम होने के कारण, बैंकों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सीडी का सहारा लिया, जिसमें 29 जुलाई 2022 को समाप्त पखवाड़े में ₹2.5 लाख करोड़ की बकाया सीडी जारी की गई। सीपी में प्राथमिक बाजार गतिविधि उत्साहहीन रही क्योंकि ब्याज दरों में तेज वृद्धि का मूल्यांकन निवेशकों की रुचि पर किया गया था। परिणामस्वरूप, 31 जुलाई, 2022 तक बकाया सीपी निर्गम घटकर ₹3.7 लाख करोड़ रह गया, जबकि एक साल पहले यह ₹4.7 लाख करोड़ था।

वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक (12 अगस्त 2022 तक), प्रभावी नीति दर में 180 बीपीएस[22] की वृद्धि हुई है और

चार्ट 48: नीति दर का उद्भव और मुद्रा बाजार दर

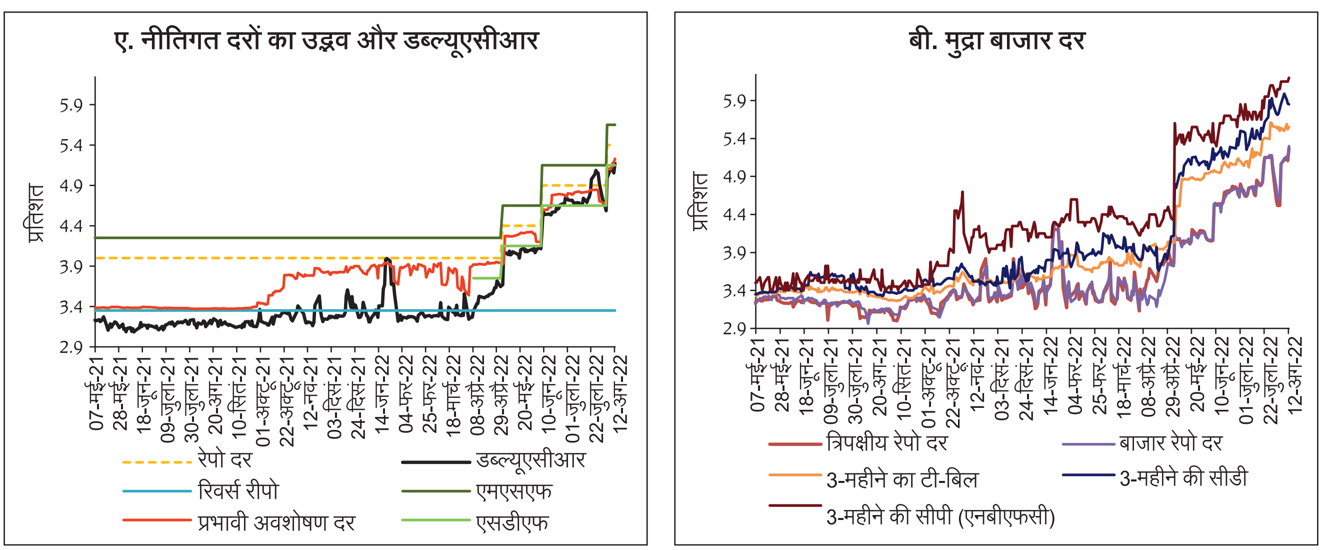

स्रोत: आरबीआई; ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ आकलन

[22] नीतिगत रीपो दर में संचयी 140 बीपीएस वृद्धि के अलावा एलएएफ कॉरिडोर की पूर्ववर्ती स्तर के ऊपर 40 बीपीएस पर एसडीएफ का प्रतिष्ठापन- नियत दर रिवर्स रीपो - शामिल है।

सारणी 5: मुद्रा बाजार दरों में उतार-चढ़ाव (12 अगस्त 2022 को संबंधित अवधि के अनुसार) (बीपीएस में)

अवधि	रेपो	डब्ल्यूएसीआर	3 महीने का टी-बिल दर	3 महीने की सीडी दर	3 महीने की सीपी दर
04-अग-22	50	58	0	6	15
07-जून-22	100	106	54	58	60
03-मई-22	140	152	146	174	185
07-अप्रै-22	140	190	166	202	202
31-मार्च-22	140	161	173	196	185

स्रोत: आरबीआई; और ब्लूमबर्ग।

डब्ल्यूएसीआर ने इसे प्रतिबिंबित किया है, जो 7 अप्रैल 2022[23] को 3.27 प्रतिशत से बढ़कर 12 अगस्त 2022 को 5.17 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, बाहरी मुद्रा बाजार खंडों में दरें 173 से 196 बीपीएस की सीमा में बढ़ीं (सारणी 5)।

नियत आय बाजार में, बॉन्ड प्रतिफल ने जुलाई के दूसरे पखवाड़े के दौरान नरमी का रुख बढ़ाया, लेकिन 5 अगस्त को रीपो रेट में बढ़ोतरी के साथ कुछ समय के लिए कठोर हो गया। 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल 12 अगस्त को 7.29 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो 15 जुलाई, 2022 को 7.44 प्रतिशत था। जहां कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और भारतीय रुपये (आईएनआर) के तेज मूल्यह्रास ने प्रतिफल में शुरुआती उछाल को प्रेरित किया, वहीं इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिफल में तेज गिरावट आई। प्रतिफल वक्र के पार, 15 साल की परिपक्वता तक प्रतिभूतियों के लिए प्रतिफल में आम तौर पर गिरावट आई (चार्ट 49ए)। 2-वर्षीय जी-सेक और 3-महीने के टी-बिल प्रतिफल के बीच प्रसार में और नरमी आई, जो मौद्रिक सख्ती के प्रभाव को दर्शाता है और परिणामस्वरूप वक्रता[24] में गिरावट आई (प्रतिफल वक्र कम कूबड़ के आकार का हो गया) (चार्ट 49बी)। जहां प्रतिफल वक्र के स्तर में ऊपर की ओर बदलाव अप्रैल के बाद से एक गिरावट वाली ढलान (10- वर्षीय और 2-वर्षीय के प्रसार द्वारा मापा गया) के साथ सह-अस्तित्व में है, वहीं वक्रता में एक स्पष्ट गिरावट जो मई नीति बैठक के बाद से स्पष्ट है विभिन्न परिपक्वता खंडों में मौद्रिक सख्ती के प्रभाव का प्रसार का संकेत दे रहा है।

चार्ट 49: सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास

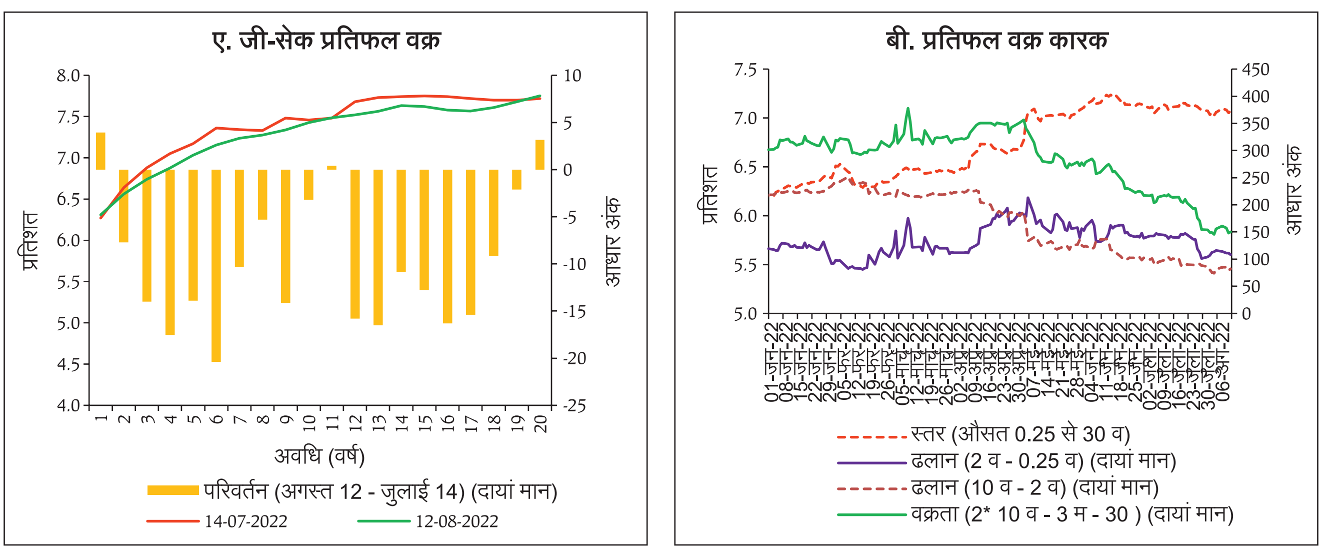

स्रोत: ब्लूमबर्ग; सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ आकलन।

23 मार्च के अंत के दौरान चलनिधि की सामान्य किल्लत को देखते हुए, 7 अप्रैल 2022 की तुलना नीति की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अधिक प्रासंगिक है। मार्च के अंत में इसी संख्या के लिए सारणी 5 देखें।

24 प्रतिफल वक्र की वक्रता लघु, मध्यम और दीर्घ परिपक्वताओं पर प्रतिफल के बीच संबंध का वर्णन करती है। उच्च वक्रता का अर्थ है वक्र की उच्च अवतलता, यानी, प्रतिफल वक्र मध्यम से दीर्घ अवधि की प्रतिफल की तुलना में लघु से मध्यम अवधि में तेज है, और इसलिए, प्रतिफल वक्र में एक कूबड़ दिखाता है। वक्रता की गणना 10-वर्ष की प्रतिफल के दो गुना घटाकर 30-वर्ष और 3-महीने के प्रतिफल के योग के रूप में की जाती है।

सारणी 6: वित्तीय बाजार - दर और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम मुक्त दर के आधार पर)		
	8 जून-15 जुलाई 2022	16 जुलाई - 11 अगस्त 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)	8 जून-15 जुलाई 2022	16 जुलाई - 11 अगस्त 2022	परिवर्तन (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉन्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	6.61	6.63	2	31	27	-4
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.47	7.33	-14	40	41	1
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.56	7.51	-5	19	30	11
(iv) एए (3-वर्ष)	8.18	8.05	-13	112	113	1
(v) बीबीबी-माइनस (3-वर्ष)	11.86	11.73	-13	480	481	1
10-वर्ष जी-सेक	7.45	7.27	-18			

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट 50: मौद्रिक और ऋण कुल राशियां

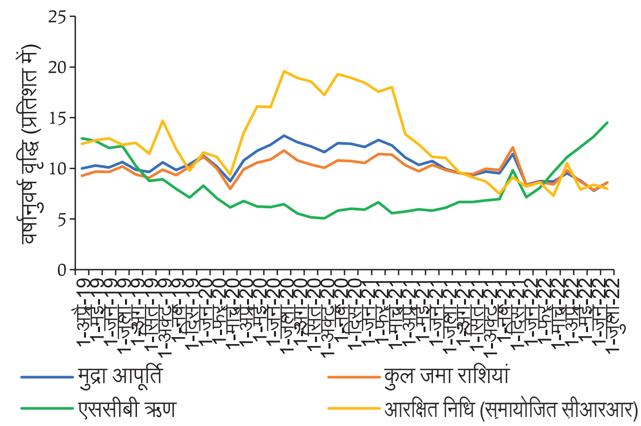

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े धन आपूर्ति, सकल जमा और बैंकों के ऋण के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबन्धित हैं; और आरक्षित निधि के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबन्धित हैं।
2. तथापि, जुलाई के लिए आरक्षित निधि से संबन्धित आंकड़े 05 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार हैं।
स्रोत: आरबीआई

जी-सेक प्रतिफल के साथ मिलकर कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल आम तौर पर सभी अवधियों और रेटिंग स्पेक्ट्रम में नरम हो गए (सारणी 6)। क्रेडिट जोखिम प्रीमियम - जैसा कि तुलनीय परिपक्वताओं के जी-सेक प्रतिफल पर कॉर्पोरेट बॉन्ड पर प्रतिफल के प्रसार में परिलक्षित होता है - मार्क-टू-मार्केट नुकसान की आशंकाओं पर जोखिम से बचने के कारण मामूली रूप से बढ़ा। इसने बड़े कर्जदारों को अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)[25] के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित धन (आरएम) 5 अगस्त 2022 (एक साल पहले 10.9 प्रतिशत) के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.0 प्रतिशत बढ़ा। संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) - आरएम में सबसे बड़ा घटक - 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (एक साल पहले 10.0 प्रतिशत) [चार्ट 50]। 29 जुलाई 2022 को मुद्रा आपूर्ति (एम3) में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक साल पहले 9.9 प्रतिशत), इसके सबसे बड़े घटक के साथ – बैंकों के पास कुल जमाराशियां – भी एक साल पहले (9.8 प्रतिशत) की समान गति से बढ़ रही हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि, जो फरवरी 2022 से लगातार बढ़ रही है, 29 जुलाई 2022 को 14.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी (एक साल पहले 6.1 प्रतिशत)। विभिन्न क्षेत्रों में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र में ऋण प्रवाह उत्प्लावक रहा। नवीनतम सिडबी-ट्रान्सयूनियन सीबील एमएसएमई पल्स रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22.की चौथी तिमाही में एमएसएमई को कुल क्रेडिट संवितरण में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई[26]। मध्यम उद्योगों के लिए बैंक ऋण जून 2022 में एक साल पहले के 59.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 47.6 प्रतिशत बढ़ा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण वृद्धि जून 2021 में 11.6 प्रतिशत से बढ़कर जून 2022 में 29.6 प्रतिशत हो गई।

बैंकों ने अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान अपनी रीपो लिंक्ड बेंचमार्क उधार दरों को ऊपर की ओर समायोजित किया है, जो जून तक पॉलिसी रीपो दर में 90 बीपीएस की संचयी वृद्धि के अनुरूप है। इसके अलावा, अगस्त पॉलिसी मीट में 50 बीपीएस रीपो रेट बढ़ोतरी को अधिकांश घरेलू बैंकों की रीपो लिंक्ड लेंडिंग दरों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि अन्य जल्द ही समायोजन पर विचार कर रहे हैं। अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान, एससीबी ने फंड आधारित उधार दरों (एमसीएलआर)

[25] 21 मई 2022 से सीआरआर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

[26] https://sidbi.in/files/article/articlefiles/MSME%20Report_August%202022.pdf

की अपनी 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में 40 बीपीएस की वृद्धि की है। नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में क्रमशः 8 बीपीएस और 14 बीपीएस की वृद्धि हुई। बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में 6 बीपीएस की वृद्धि हुई (सारणी 7)। खुदरा सावधि जमा दरों की तुलना में उधार दरों के लिए पास-थ्रू की सीमा अधिक है, क्योंकि बाद वाली ऋण की मांग के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की स्थिति पर निर्भर हैं।[27] चूंकि प्रणाली में चलनिधि सामान्य होने लगी है, बैंक ने अपनी थोक जमा दरों को आक्रामक रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया है।

जहां खुदरा जमा पर मीडियन टर्म डिपॉजिट दर में 14 बीपीएस की वृद्धि हुई है, वहीं बैंकों ने मौजूदा सख्त अवधि में अपनी बल्क डिपॉजिट दरों में काफी वृद्धि की है। यदि सावधि जमा (खुदरा और थोक जमा सहित) के लिए समग्र संचरण पर विचार किया जाता है, तो यह उधार दरों के प्रसारण के बराबर है।

सारणी 7: रेपो दर से बैंकों की जमा और उधार दरों में अंतरण

(आधार अंकों में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर	जमा दरें		उधार दरें		
		मीडियन टीडीआर (नया जमा)	डब्ल्यूए-डीटीडी-आर (बकाया जमा)	1-वर्ष एमसी-एलआर (मिडियन)	डब्ल्यूए-एलआर (नया रुपए ऋण)	डब्ल्यूएए-लआर (बकाया रुपए ऋण)
अप्रैल-जुलाई 2022*	**90**	**14**	**10**	**40**	**31**	**19**
ज्ञापन						
अप्रैल 2022	0	0	0	0	-12	-2
मई 2022	40	0	4	3	35	7
जून 2022	50	3	6	20	8	14
जुलाई 2022	-	0 (-2 से 27)	-	12 (-20 से 20)	-	-

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े घरेलू बैंकों के लिए बैंक-वार अंतर की एक शृंखला का संकेत देते हैं।

* डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर डेटा जून 2022 से संबंधित है।

डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर।

एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत; टीडीआर: सावधि जमा दर।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

विभिन्न लघु बचत लिखतों (एसएसआई) पर ब्याज दरों को पिछली नौ तिमाहियों (2022-23 की दूसरी तिमाही तक) में अपरिवर्तित रखा गया है। जी-सेक प्रतिफल में ऊपर की ओर गति के साथ, विभिन्न लघु उद्योगों पर मौजूदा ब्याज दरों और सूत्र-आधारित दरों के बीच का फैलाव अब अधिकांश छोटी बचत योजनाओं के लिए ऋणात्मक है।

इक्विटी बाजार में, बेंचमार्क इंडेक्स (बीएसई सेंसेक्स) जुलाई में 8.6 प्रतिशत बढ़ गया, जो अगस्त 2021 के बाद से इसका उच्चतम मासिक लाभ दर्ज किया गया। मजबूत कॉर्पोरेट आय, विदेशी बाजारों में पुनरुत्थान, पोर्टफोलियो प्रवाह, सकारात्मक वैश्विक संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच महीने की दूसरी छमाही के दौरान अधिकांश तेजी दर्ज की गई। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित कर में कटौती की घोषणा से भी बाजार को समर्थन मिला। घरेलू विनिर्माण डेटा और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बीएसई सेंसेक्स में 3.9 प्रतिशत (16 अगस्त, 2022 तक) की वृद्धि के साथ इक्विटी बाजार ने अगस्त में अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा। जुलाई 2022 और अगस्त में अब तक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ़पीआई) भारतीय इक्विटी में फिर से निवल खरीदार बन गए (चार्ट 51)।

कॉर्पोरेट क्षेत्र ने 2022-23 की पहली तिमाही में अच्छी कमाई की; लाभ वृद्धि के साथ बढ़ती इनपुट लागतों से विपरीत परिस्थितियों की सवारी। गैर-वित्तीय कंपनियों ने राजस्व/बिक्री के साथ-साथ व्यय में 40 प्रतिशत से अधिक की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की (चार्ट 52)[28]। व्यय में वृद्धि राजस्व से अधिक हो गई, जो तिमाही के दौरान कच्चे माल की लागत में वृद्धि दर्ज करने में परिलक्षित हुई।[29] मजदूरी और वेतन में भी दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन लाभ (वर्ष-दर-वर्ष) में वृद्धि दहाई अंकों के

[27] कुमार, ए., प्रकाश, ए. और लाटे, एस., (2022), 'बैंकों की ब्याज दरों में मौद्रिक संचरण: बाह्य न्यूनतम मानदंड प्रणाली के प्रभाव' आरबीआई बुलेटिन, अप्रैल।

[28] 2,040 सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के विश्लेषण के आधार पर, जो सभी सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 91.6 प्रतिशत है।

[29] तेल एवं गैस, बिजली, धातु और खनन और सेवा क्षेत्र से संबंधित कंपनियों को छोड़कर, बिक्री के अनुपात के रूप में कच्चे माल की लागत में तिमाही के दौरान वृद्धि दर्ज की गई।

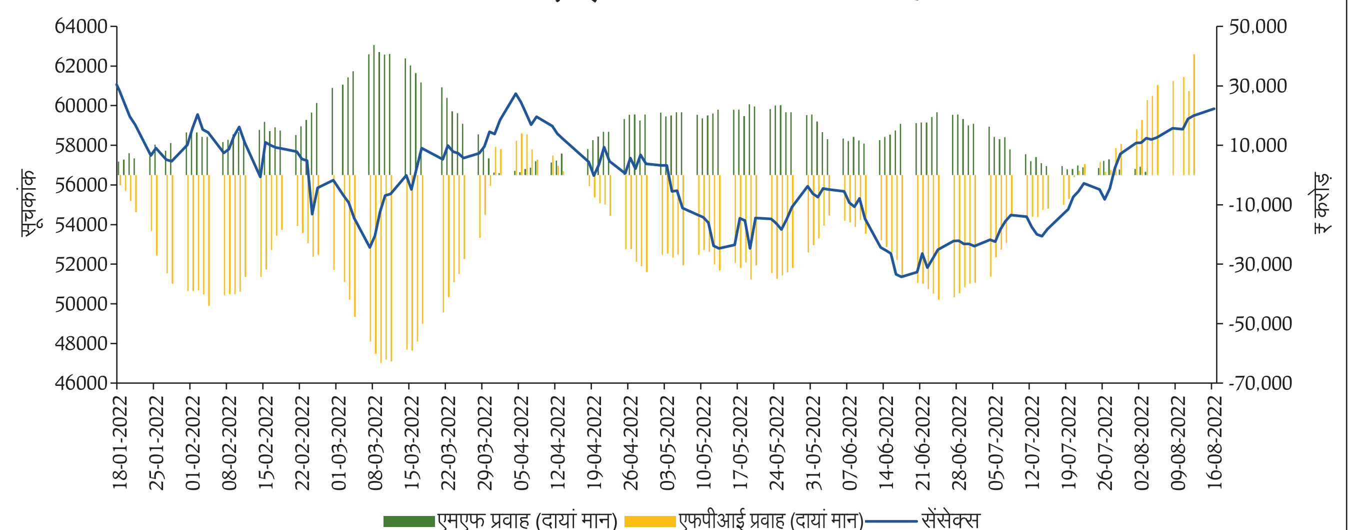

टिप्पणी: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और म्यूचुअल निधि (एमएफ) प्रवाह 15 दिनों के चक्रीय योग आधार पर दर्शाये गए हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग, एनएसडीएल और सेबी

निशान से थोड़ी कम रही। अन्य आय, जिसमें कोषागार परिचालन से आय शामिल है, में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, तिमाही के दौरान कंपनियों के ब्याज खर्च में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, निवल लाभ वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) पिछली तिमाही से कुछ नरमी दर्ज करते हुए एकल अंक में रही।

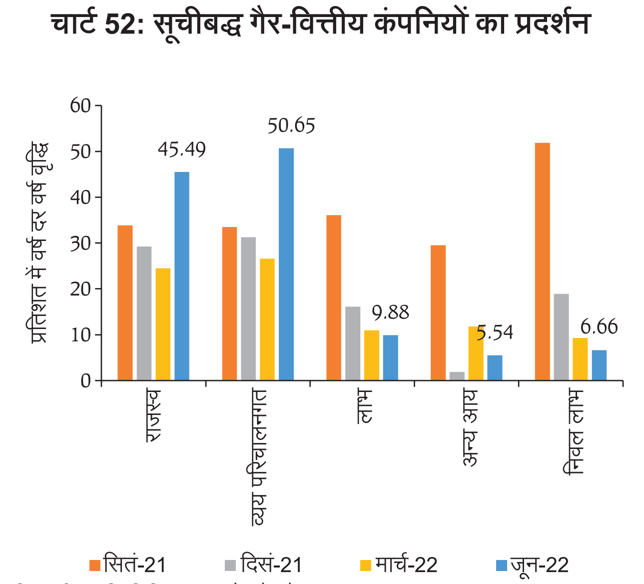

टिप्पणी: अति विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर।
स्रोत: प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने राजस्व में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की - जिसमें मुख्य रूप से ब्याज आय शामिल है - ऋण वृद्धि में तेजी से सहायता प्राप्त हुई (चार्ट 53)।[30] अन्य आय, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा लेनदेन, शुल्क और कमीशन से लाभ/हानि शामिल है, में पंजीकृत निवेश पर मार्क-टू-मार्केट नुकसान के बाद गिरावट दर्ज की गई। राजस्व की तुलना में व्यय कम दर से बढ़ा; हालांकि, अन्य आय में गिरावट के कारण परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में कमी आई। हालांकि, प्रावधान लागत में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए निवल लाभ वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया।

वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 22.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,

[30] 588 सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों के विश्लेषण के आधार पर, सभी सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का लगभग 82.9 प्रतिशत

चार्ट 53: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

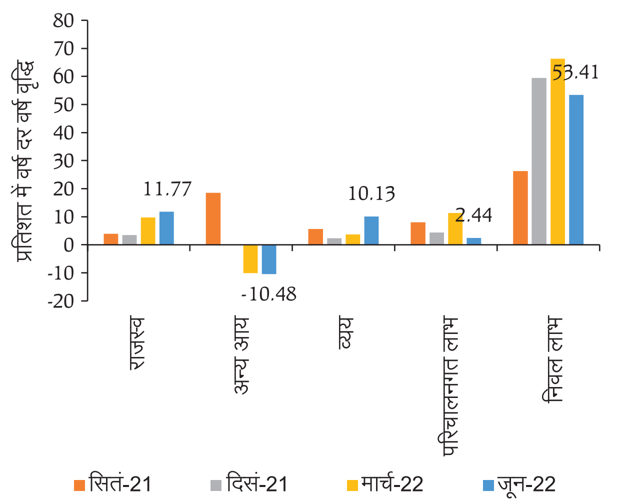

टिप्पणी: अति विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर।
स्रोत: प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

जो मोटे तौर पर एक साल पहले के स्तर के बराबर था। हालांकि, निवल एफडीआई, इस अवधि के दौरान एक साल पहले के 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो ताजा इक्विटी प्रवाह में वृद्धि और भारत से बाहरी एफडीआई में गिरावट के कारण हुआ (चार्ट 54)। अप्रैल-जून 2022 के दौरान विनिर्माण, सेवा और खुदरा और थोक व्यापार क्षेत्रों को एफडीआई इक्विटी प्रवाह का प्रमुख हिस्सा प्राप्त हुआ।

एफपीआई द्वारा इक्विटी में निवेश के कारण जुलाई 2022 में 0.5 बिलियन यूएस डॉलर और अगस्त 2022 (12वीं तक) में 4.7 बिलियन यूएस डॉलर का निवल प्रवाह हुआ, यहां तक कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और तुर्की जैसे प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में इक्विटी बाजारों में भी निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया (चार्ट 55)। वित्तीय सेवाओं, तीव्रगामी उपभोक्ता वस्तुएं (एफएमसीजी) और बिजली क्षेत्र ने एफपीआई प्रवाह को आकर्षित किया।

3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर, भारत को बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का सकल संवितरण वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में एक साल पहले के समान स्तर पर बना रहा। हालांकि, अंतर-कंपनी उधारों को छोड़कर, ईसीबी ने इस अवधि के दौरान 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल पुनर्भुगतान दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की पहली तिमाही में 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल भुगतान किया गया था। जून 2022 में, ऑन-लेंडिंग/सब-लेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कार्यशील पूंजी के उद्देश्य से ईसीबी का एक बड़ा हिस्सा जुटाया गया है। बकाया ईसीबी के दो-तिहाई से अधिक स्पष्ट हेजिंग, रुपये में मूल्यवर्गीकृत ऋण और विदेशी माता-पिता से ऋण के मामले में प्रभावी ढंग से बचाव किया जाता है (चार्ट 56)। मुद्रा की अस्थिरता के जोखिम को सीमित करते हुए, शेष राशि में स्वाभाविक बचाव वाले ऋण भी शामिल हैं (यानी, उधारकर्ताओं की आय विदेशी मुद्रा में है)।

चार्ट 54: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

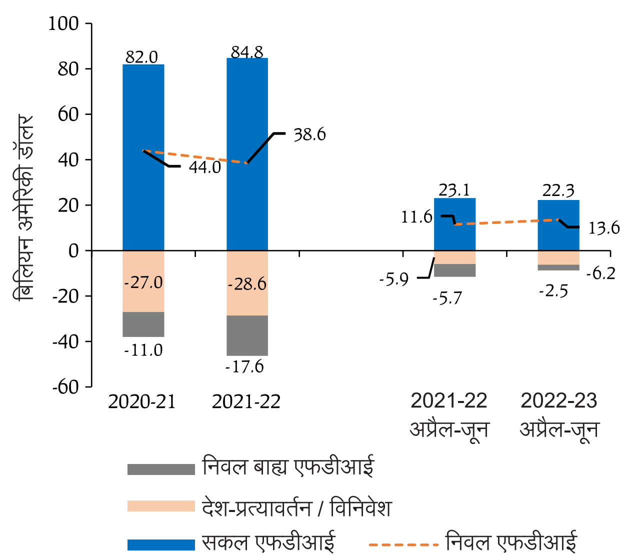

स्रोत: आरबीआई

चार्ट 55: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

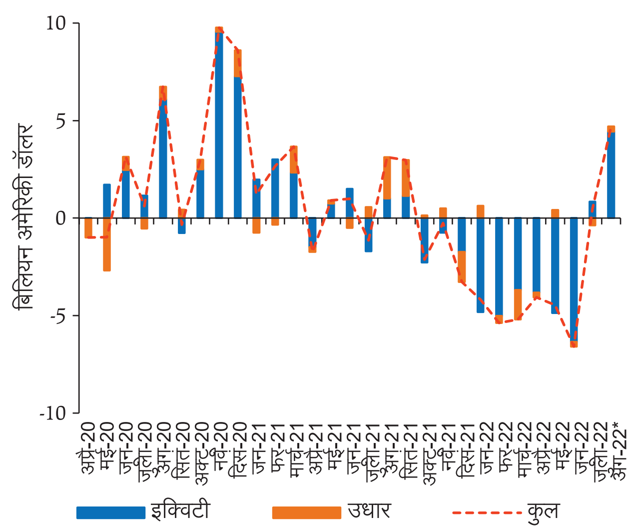

*12 अगस्त 2022 तक
स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

चार्ट 56: ईसीबी करार – हेजिंग की स्थिति

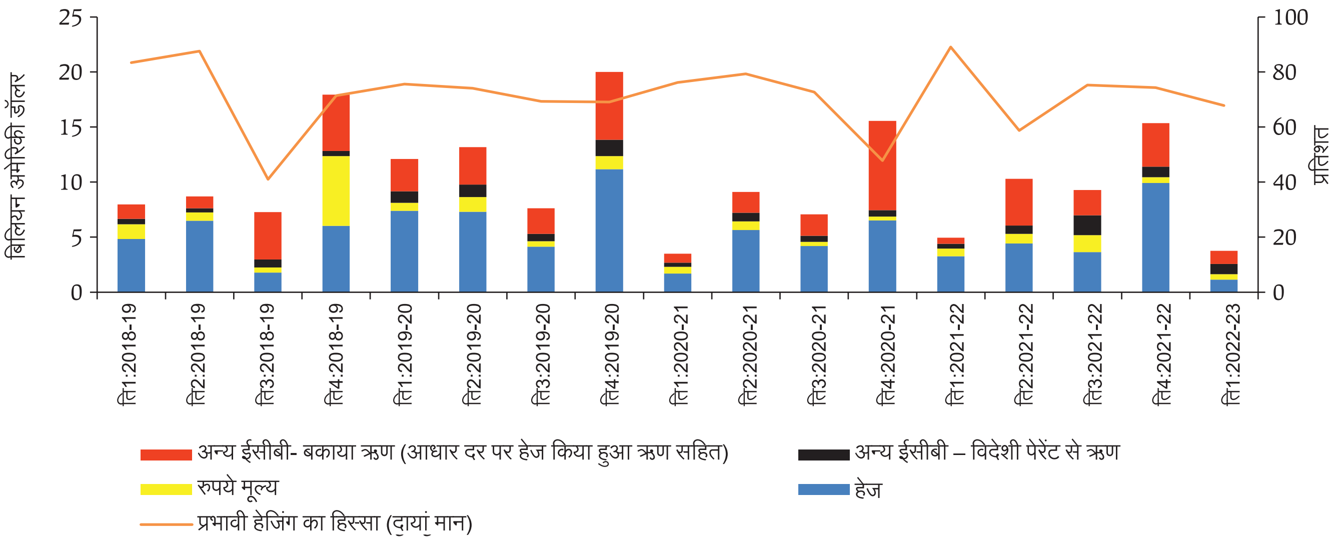

स्रोत: आरबीआई।

5 अगस्त 2022 को 573.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार 2022-23 के लिए अनुमानित 9.4 महीने के आयात के बराबर था (चार्ट 57)।

विदेशी मुद्रा बाजार में, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से ईएमई मुद्राओं पर दबाव बना रहा। जुलाई 2022 में अमेरिकी डॉलर (माह-दर-माह) की तुलना में औसतन भारतीय रुपये (आईएनआर) में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अमेरिकी डॉलर सूचकांक में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी, भारतीय रुपये ने अधिकांश प्रमुख ईएमई मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट 58)।

जुलाई 2022 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में आईएनआर में 0.4 प्रतिशत की गिरावट

चार्ट 57: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

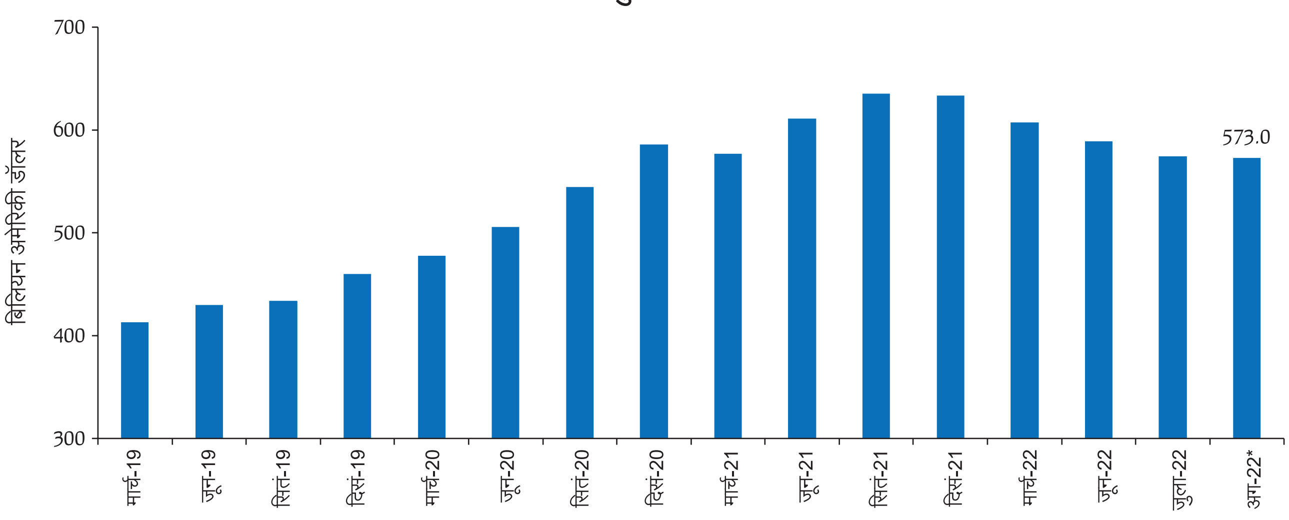

*5 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार
स्रोत: आरबीआई

चार्ट 58: अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए और ईएमई मुद्रा का उतार-चढ़ाव (जुलाई 2022, माह-दर-माह)

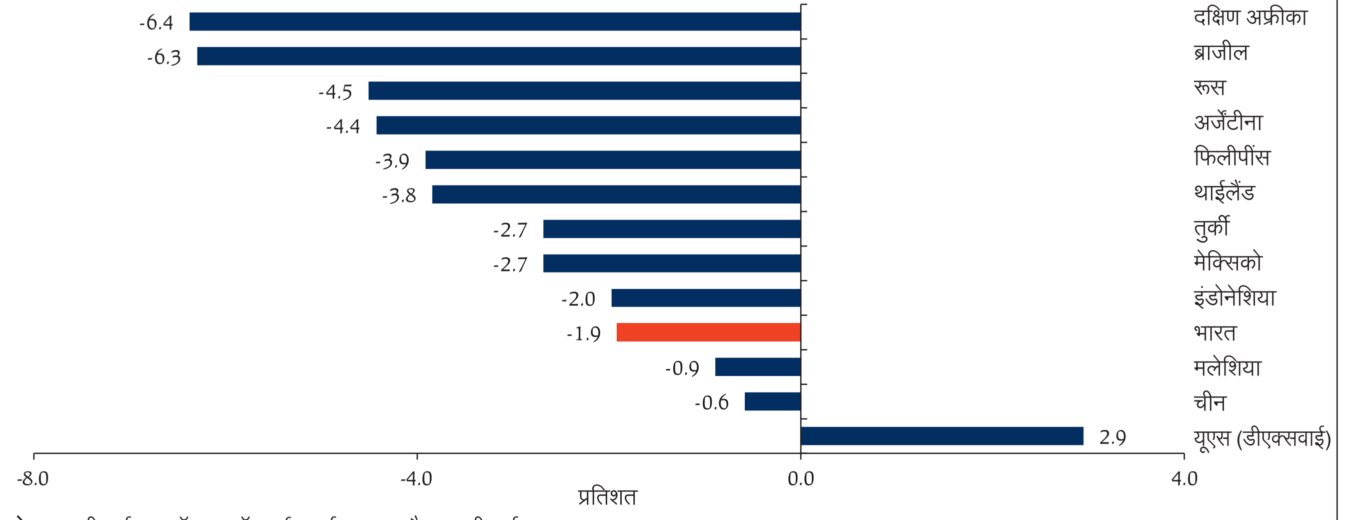

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; आईएमएफ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

आई, जो अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं में अपेक्षाकृत उच्च मूल्यह्रास दिखा रहा है (चार्ट 59)।

भुगतान प्रणाली

रिज़र्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में बढ़कर 349.30 हो गया, जो सितंबर 2021 की तुलना में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि है। मात्रा और मूल्य वृद्धि दोनों के संदर्भ में, जुलाई 2022 में विभिन्न तरीकों से डिजिटल भुगतानों में वृद्धि हुई है (सारणी 8)। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जून 2022 में कुल खुदरा लेनदेन की मात्रा में 70 प्रतिशत (एक साल पहले 59.4 प्रतिशत) की हिस्सेदारी के साथ खुदरा भुगतान पर हावी हो गया (चार्ट 60)। यह वृद्धि मूल्य के आधार पर यूपीआई लेनदेन के हिस्से में भी स्पष्ट थी, जो 4.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ

चार्ट 59: 40 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मासिक उतार-चढ़ाव

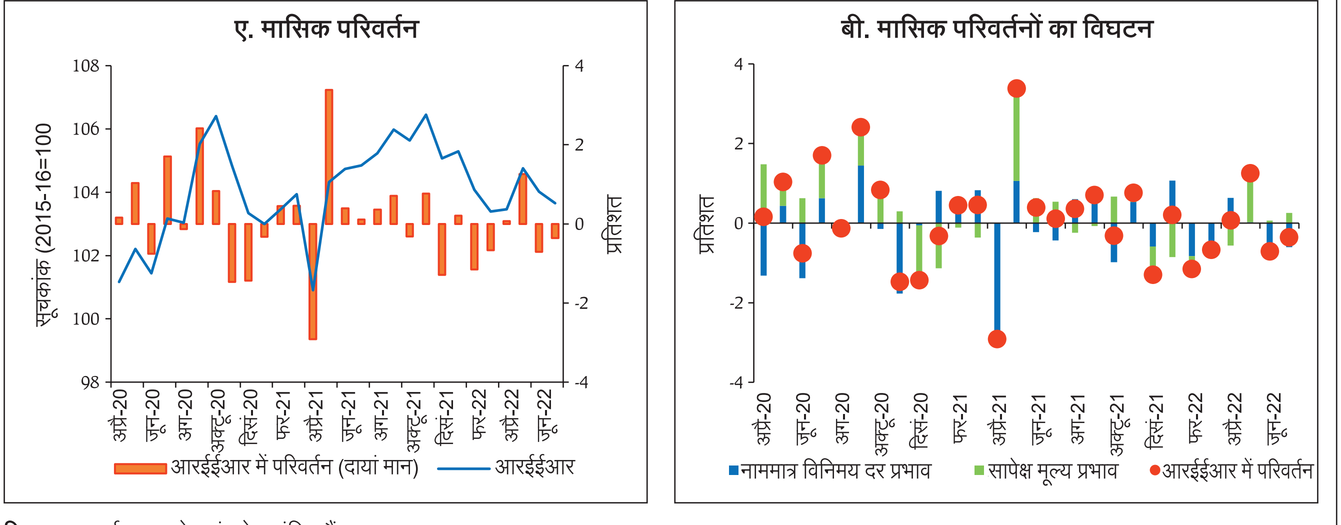

टिप्पण: जुलाई 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: आरबीआई

सारणी 8: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

(प्रतिशत)

भुगतान दर संसूचक	लेनदेन मात्रा वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)				लेनदेन मूल्य वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)			
	जून-2021	जून-2022	जुला-2021	जुला-2022	जून-2021	जून-2022	जुला-2021	जुला-2022
आरटीजीएस	28.8	26.1	34.4	12.9	17.9	21.2	28.9	7.5
एनईएफटी	28.6	37.6	32.0	26.8	10.0	29.5	12.3	19.2
यूपीआई	110.0	108.8	116.7	93.8	109.1	85.3	108.5	75.5
आईएमपीएस	52.8	50.0	58.7	30.7	37.3	56.2	37.9	42.8
एनएसीएच	0.8	6.7	1.9	36.4	-4.1	19.5	1.8	29.4
एनईटीसी	92.7	76.1	122.0	37.9	70.4	67.0	83.4	39.8
बीबीपीएस	157.7	80.6	153.7	67.9	167.2	91.0	159.3	68.7

स्रोत: आरबीआई

19.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। सरकारी हस्तांतरण के कारण जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के माध्यम से लेनदेन की वृद्धि दर में स्पष्ट वृद्धि हुई थी।

रिज़र्व बैंक ने 26 करोड़ से अधिक यूनीक यूपीआई उपयोगकर्ताओं[31] के लिए भुगतान के तरीकों के विकल्प को विस्तृत करने और सुविधा बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड को लिंक करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल से यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो जुलाई 2022 में ₹769 प्रति लेनदेन था। यह ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, कैप्चर और होल्ड सुविधा, और चालान समर्थन जैसे व्यापारियों के लिए कई उपयोग मामलों के साथ व्यवसायों में यूपीआई को अपनाने में सक्षम करते हुए कुल यूपीआई लेनदेन[32] में पी2एम

चार्ट 60: भुगतान माध्यम का गठन

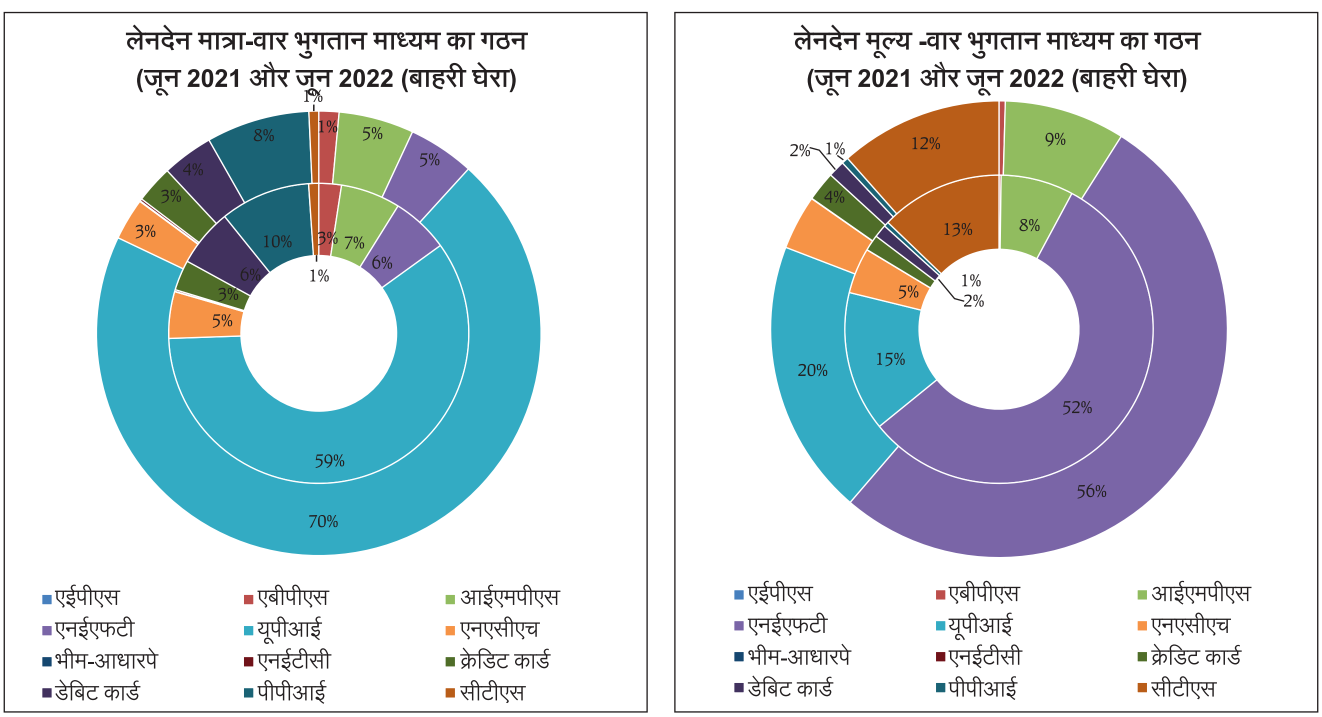

स्रोत: आरबीआई।

[31] बिजनेस स्टैंडर्ड, 'विल यूपीआई ऑन क्रेडिट कार्ड टेक ऑफ?', 27 जुलाई 2022।

[32] कुल यूपीआई लेनदेन में पर्सन-टू-पर्सन और पर्सन-टू-मर्चेन्ट लेनदेन शामिल हैं। पी2एम लेनदेन की हिस्सेदारी जून 2021 में लगभग 18 प्रतिशत थी, जो जून 2022 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई।

लेनदेन की बढ़ती हिस्सेदारी में भी योगदान देगा। टोकनाइजेशन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाते हुए, लगभग 20 करोड़ कार्ड - बकाया कार्डों का लगभग पांचवां हिस्सा - दिसंबर 2021 के बाद से पूरे कार्ड नेटवर्क में टोकनाइज़ किया गया है।[33] इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अतिथि खातों से संबंधित कार्ड-ऑन-फाइल डेटा स्टोरेज मानदंडों में ढील दी है। 5 अगस्त 2022 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की उपयोगिता, शिक्षा और अन्य बिल भुगतान की सुविधा के लिए सीमा पार आवक भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। भारत में उनके परिवारों के वित्तीय सेवाओं में दक्षता को प्रोत्साहित करते हुए सुदृढ़ और विश्वसनीय नवोन्मेशों को बढ़ावा देने के प्रयास फलीभूत हो रहा है, जो इस बात से परिलक्षित हो रहा है कि आठ में से चार संस्थाएँ सीमा पार भुगतान संबंधी रिज़र्व बैंक के विनियमकीय सैंडबॉक्स के दूसरे कोहोर्ट को सफलतापूर्वक पार कर गई हैं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने भारत से निर्यात को प्रोत्साहित करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आईएनआर में दुनिया भर के व्यापारियों के हित को सुदृढ़ करने के लिए आईएनआर में चालान, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान की व्यवस्था की घोषणा की।[34]

V. निष्कर्ष

सकारात्मक टिप्पणी के साथ निष्कर्ष की बात करें तो हाल के दिनों में शायद सबसे उत्साहजनक घटनाक्रम जुलाई 2022 में मुद्रास्फीति में जून 2022 से 30 आधार अंकों की कमी और वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए 7.3 प्रतिशत के औसत से 60 आधार अंकों की कमी रही है। इसने हमारी परिकल्पना को मान्य किया है कि अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति शीर्ष पर थी। शेष वर्ष के लिए, आरबीआई के अनुमानों से मूल्य परिवर्तन की गति में लगातार कमी आई है। मोटे तौर पर अनुमानों के अनुरूप परिणामों के वृद्धि पथ के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि गति पहली तिमाही में 3.0 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 1.7 प्रतिशत और आगे तीसरी तिमाही में 1.3 प्रतिशत हो जाएगी और मामूली रूप से पहले और मौसमी खाद्य कीमत के संबंध में 2023-24 की पहली तिमाही में 2.2 प्रतिशत तक चौथी तिमाही में मामूली ऋणात्मक हो जाएगी। सौभाग्य से, आधार प्रभाव सभी के लिए अनुकूल हैं। यदि ये प्रत्याशा बनी रहती हैं, तो मुद्रास्फीति अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7 से 5 प्रतिशत तक गिर जाएगी - टालरेंस बैंड के भीतर, लक्ष्य के करीब मँडरा रही है, लेकिन अभी तक लैंडिंग के लिए स्थिति में नहीं है। यह इसके वृद्धि पथ में एक निर्णायक बिंदु है। आयातित मुद्रास्फीति के दबाव बिंदु व्यापक जोखिम बने हुए हैं, इसके बाद इनपुट लागतों के लंबित पास-थ्रू यदि उत्पादकों ने मूल्य निर्धारण शक्ति और मजदूरी हासिल कर ली है। फिर भी, कुछ जोखिम कम हुए हैं - पण्य कीमतें, विशेष रूप से कच्चे तेल की; आपूर्ति श्रृंखला दबाव; बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण मानसूनी गतिविधियों में तेजी आई है।

वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के बाद, एमपीसी के समक्ष यह कार्य होगा कि वह मुद्रास्फीति को उसके 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक निर्देशित करे। यह टालरेंस बैंड में शीर्ष में गिरावट की तुलना में अधिक कठिन साबित हो सकता है।

अगला उत्साहजनक घटनाक्रम एक अंतराल के बाद भारत में पूंजी प्रवाह की वापसी है जब ईएमई के लिए पोर्टफोलियो प्रवाह की प्रवृत्ति कम हो गई थी क्योंकि यूएस फेड ने अपने वृद्धि चक्र को तेज करने के साथ अमेरिकी डॉलर बेतहाशा बढ़ गया था। मार्च 2022 से, अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान का अनुमान है कि पोर्टफोलियो निवेशकों ने ईएमई से 39.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निकासी की, जो ऋण खंड में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रवाह से आंशिक रूप से ऑफसेट है।[35] फिर भी, निवेशकों ने अंतर किया है। जहां जिंस निर्यात ईएमई, अर्थात, ब्राजील, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलंबिया और चिली को इक्विटी में पोर्टफोलियो प्रवाह से लाभ हुआ, वहीं चीन, भारत और तुर्की के लिए एक्सपोजर में कटौती की गई। ऋण खंड में, चीन ने ईएमई के बीच सबसे बड़ा बहिर्वाह दर्ज किया जबकि अन्य ईएमई ने मिलकर निवल अंतर्वाह दर्ज किया। भारत पोर्टफोलियो प्रवाह के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है - अगस्त में अब तक (12वीं तक), इक्विटी और डेट सेगमेंट में क्रमशः 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह दर्ज किया गया।

इन अस्थिर प्रवाहों के लिए दृष्टिकोण क्या है? ईएमई को निष्क्रिय निवेशक सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है - एक्सचेंज

[33] बिज़नेस स्टैंडर्ड, 'कार्ड डेटा स्टोरेज: आरबीआई रिलैक्सेस रूल्स फॉर चेकआउट ऑन गेस्ट ट्रांजेक्शन', 29 जुलाई 2022।

[34] भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाएँ, "भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान (आईएनआर)", 11 जुलाई 2022; https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12358&Mode=0

[35] आईआईएफ पूंजी प्रवाह ट्रैकर डेटाबेस, अगस्त 2022।

ट्रेडेड फंड, इंडेक्स संचालित फंड और ऐसे माध्यम जिनमें निवेशक सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों में से समझदार फंड मैनेजरों में विश्वास रखते हैं जो वैश्विक प्रसार-प्रभाव के प्रति सबसे संवेदनशील भी हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि निष्क्रिय पोर्टफोलियो की प्रतिक्रिया एक मानक विचलन के लिए प्रवाहित होती है, जो कि ब्याज दर के आघात से छह गुना बढ़ गई है, जो टेपर टैंट्रम के समय से अब छह गुना बढ़ गई है।[36] इसलिए, मौद्रिक नीति के अग्र-प्रयुक्त होने से वैश्विक फंडिंग की स्थिति की सख्ती से पोर्टफोलियो प्रवाह के परिदृश्य के खराब होने की उम्मीद है।

12 अगस्त 2022 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रवाह के साथ, भारत इस सीज़न के पोर्टफोलियो प्रवाह का मुख्य आकर्षण बनने के लिए सावधानी से लौट रहा है। भारत में पोर्टफोलियो निवेश का बाजार मूल्य 12 अगस्त 2022 को 623.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।[37] इस संदर्भ में , इस बुलेटिन के जून 2022 अंक में प्रस्तुत जोखिम मूल्यांकन पर पूंजी प्रवाह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विभिन्न परिमाणों - प्रवाह और बहिर्वाह की पूंजी प्रवाह घटनाओं के लिए विशिष्ट संभावनाओं को निर्दिष्ट करके - यह आकस्मिक योजना में योगदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, मॉडल इंगित करता है कि भारत से 100.6 अरब अमेरिकी डॉलर के पोर्टफोलियो निवेश के ऑर्डर के बहिर्वाह का 5 प्रतिशत मौका है, जो कि पुश और पुल कारकों के परस्पर क्रिया के कारण होता है। यह अक्टूबर 2021 से जून 2022 के दौरान बहिर्वाह के वर्तमान चरण का वास्तविक अनुभव है। "यह तरल आरक्षित निधि के स्तर का संकेत है जिसे हर समय बनाए रखने की आवश्यकता है - आयात और ऋण सेवा कवर के मानक मेट्रिक्स के अलावा - अस्थिर पूंजी प्रवाह एक गतिशील और अत्यधिक अनिश्चित वैश्विक सेटिंग में अस्थिरता के दौरों को दबा सकता है जिसमें महामारी, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, और बढ़ी हुई वस्तु की कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव परस्पर क्रिया करते रहते हैं और आपस में जुड़ते रहते हैं" (पात्र और अन्य, 2022)[38]।

[36] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2019)। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल।

[37] जुलाई 2022 के अंत में बाजार मूल्य की स्थिति के साथ एफपीआई प्रवाह (12 अगस्त, 2022 तक) को जोड़कर पोर्टफोलियो निवेश का बाजार मूल्य निकाला जाता है।

[38] पात्र, एम.डी., बेहरा, एच. और मुदुली, एस. (2022)। जोखिम में पूंजी प्रवाह: भारत का अनुभव, आरबीआई बुलेटिन, जून।

घरेलू वित्तीय बाजारों को गहरा करने से देशों को बचत जुटाने, सूचना साझा करने को बढ़ावा देने और आस्ति की कीमतों की अस्थिरता को कम करते हुए जोखिम में विविधता लाने में मदद मिल सकती है। आईएमएफ के अनुसार, हस्तक्षेप बाजार की अनकदी के मुक़ाबले झुक सकता है, और इस प्रकार अत्यधिक अस्थिरता को कम करने में भूमिका निभा सकता है। जहां कहीं भी जरूरी हो, पूंजी बहिर्प्रवाह प्रबंधन उपायों को समष्टि-आर्थिक समायोजन से बचने के बिना व्यापक नीति पैकेज का हिस्सा होना होगा। वैश्विक वित्तीय बाजारों तक उनकी सीमित पहुंच को देखते हुए ईएमई के लिए कर्ज प्रबंधन कार्यनीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, बाजार और विस्तारण जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय कार्यनीतियों का आह्वान किया गया है। समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियां बाजार की स्थितियों और अर्थव्यवस्था पर आघातों के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

अंतिम विश्लेषण में, भारत कई मूलभूत कारकों के आधार पर बाकी दुनिया की तुलना में संवृद्धि अंतर को बनाए रखने के लिए तैयार है: इस आलेख के जुलाई संस्करण में एक जनसांख्यिकीय लाभांश; अर्थव्यवस्था की बढ़ती औपचारिकता और डिजिटल वित्तीय समावेशन के साथ पूंजी की उपलब्धता में विस्तार - डिजिटल भुगतान स्थान में अनुकूलन पहले से ही भारत में दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में वास्तविक समय के लेनदेन में प्रवेश करने के लिए जिम्मेदार है; पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी बढ़ने से बचत का वित्तीयकरण; मजबूत तुलन-पत्र और लाभप्रदता की वापसी के साथ एक मजबूत और उपयुक्त बैंकिंग प्रणाली।

इन सभी कारकों के एक साथ आने से आगे चलकर उत्पादकता में उछाल आ सकता है। हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं वह हैं महामारी और इसके बाद के आघातों से खोई हुई गति को फिर से हासिल करना हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की खाई को पाटना, उच्च गुणवत्ता वाले श्रम बल का निर्माण करना और एक बाहरी उन्मुखीकरण हासिल करना है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे और विश्व मंच पर हमारे उत्पादों, हमारे पेशेवरों और व्यापार के लिए बाजारों का विस्तार करता हो।

भारत का समय आ गया है। हमें इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना है।

*सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण: एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निजीकरण को व्यापक रूप से भारत में लंबित सुधारों के प्रमुख क्षेत्र के रूप में देखा गया है। यह आलेख निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के सापेक्ष पीएसबी के प्रदर्शन की अनुभवजन्य रूप से जांच करता है। डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस (डीईए) का उपयोग करते हुए, यह पता चलता है कि जहां पीवीबी लाभ अधिकतम करने में अधिक कुशल हैं, वहीं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बेहतर प्रदर्शन किया है। पीवीबी की तुलना में पीएसबी की श्रम लागत दक्षता अधिक है। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि पीवीबी की तुलना में पीएसबी का उधार कम चक्रीय है और इस प्रकार पीएसबी प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति कार्रवाई को गति प्राप्त करने में मदद करते हैं।

भूमिका

1990 के दशक से निजीकरण दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है और पिछले चार दशकों में दुनिया भर की सरकारों ने या तो भागीदारी कम कर दी है या गतिविधियों की एक श्रृंखला से पूरी तरह से पीछे हट गई है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से पहले, बैंकिंग इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं थी। विकासशील देशों में, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की आस्ति का औसत हिस्सा 1995 में 40 प्रतिशत से घटकर 2008 में 17 प्रतिशत हो गया, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 1995 में 36 प्रतिशत से गिरकर 2008 में 10 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, जीएफ़सी के बाद, बैंकों के सार्वजनिक स्वामित्व में नए सिरे से दिलचस्पी पैदा हुई है क्योंकि कई उच्च आय वाले और विकासशील देशों ने दबावग्रस्त बैंकों को पूंजीकृत या राष्ट्रीयकृत किया। आइसलैंड, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिका बोलिवेरियन डे वेनेजुएला जैसे देशों में, बैंकिंग क्षेत्र में सरकार द्वारा धारित आस्तियों का हिस्सा 2008 और 2010 के बीच 10 प्रतिशत के बिंदु से भी अधिक बढ़ गया (कल, पेरिया और वेरियर, 2018)). तब से, बैंकों के सार्वजनिक स्वामित्व का पक्ष और विपक्ष पूरी दुनिया में एक गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है।

भारत में भी आर्थिक सोच पर निजीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, हालांकि अब तक बैंकिंग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में, सरकार ने दो पीएसबी के निजीकरण की मंशा की घोषणा की। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी पीएसबी के निजीकरण के लिए मामला बनाने के लिए हाल ही के एक नीतिगत नुस्खे में जोर दिया गया है कि '...पीएसबी ने अर्थव्यवस्था और उनके हितधारकों को कम सेवा दी है', (गुप्ता और पनगढ़िया, 2022)।

यह आलेख साहित्य के उन पहलुओं से प्रेरणा लेकर एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है जो कई आधारों पर पीएसबी की भूमिका को सही ठहराते हैं। एटकिंसन और स्टिग्लिट्ज़ (1980) द्वारा प्रचारित 'सामाजिक दृष्टिकोण' बताते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई) बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, और अक्सर उनके सामाजिक लाभ सामाजिक लागतों से अधिक होते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाले बैंक आर्थिक विकास में योगदान करते हैं और सामान्य आर्थिक कल्याण में सुधार करते हैं (स्टिग्लिट्ज, 1993)। साहित्य के एक अन्य सूत्र से पता चलता है कि सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा ऋण देना या तो प्रतिचक्रीय है या निजी बैंकों द्वारा उधार देने की तुलना में कम अनुचक्रीय है, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समष्टि आर्थिक स्थिरता में योगदान करते हैं (पनिज़ा, 2022; माइको और पनिज़ा) 2006)। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निम्न-कार्बन उद्योगों में वित्तीय निवेश को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे ब्राजील, चीन, जर्मनी, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों में हरित संक्रमण को बढ़ावा मिला है (मेज़ुकाटो और पेन्ना, 2016 और शापिरो, 2012)।

एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर निजीकरण का प्रस्ताव करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा अनदेखा किया जाता है, वह वित्तीय समावेशन में पीएसबी द्वारा निभाई गई भूमिका है। उद्देश्य कार्य में इस आयाम को शामिल करते हुए, यह आलेख इस बात का

* यह आलेख बैंकिंग अनुसंधान प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के स्नेहल एस हेरवाडकर, सोनाली गोयल और रिशुका बंसल द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक कल्याणकारी वृद्धि कर रहे हैं। इसके अलावा, आलेख अनुभवजन्य रूप से स्थापित करता है कि पीएसबी की तुलना में पीवीबी का उधार अधिक अनु-चक्रीय है और इस प्रकार पीएसबी प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति को कर्षण प्राप्त करने में मदद करते हैं। हाल के शोध के अनुसार, जो बताता है कि 'निजी स्वामित्व अकेले विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वचालित रूप से आर्थिक लाभ उत्पन्न नहीं करता है' और 'निजीकरण के अधिक सतर्क और सूक्ष्म मूल्यांकन की आवश्यकता है' (एस्ट्रिन और पेलेटियर, 2018), यह आलेख निजीकरण के लिए क्रमिक दृष्टिकोण की भी सिफारिश करता है।

उपरोक्त संदर्भ में, आलेख को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है: खंड II वित्तीय समावेशन में पीएसबी की भूमिका की खोज के लिए समर्पित है। खंड III डीईए का उपयोग करके वैकल्पिक उद्देश्य कार्यों के लिए पीएसबी और पीवीबी का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। खंड IV व्यावसायिक चक्रों की स्थिति के सापेक्ष पीएसबी और पीवीबी के क्रेडिट स्वरूप की जांच करता है। खंड V पीएसबी के प्रदर्शन पर समग्र बाजार प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए नवीनतम डेटा रुझान प्रस्तुत करता है। खंड VI समाप्त होता है और आगे का मार्ग प्रदान करता है।

II. वित्तीय समावेशन में पीएसबी की भूमिका

वित्तीय समावेशन उद्देश्य के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुपालन में पीएसबी की ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की उच्चतम हिस्सेदारी है, इसके बाद अर्ध-शहरी क्षेत्रों का स्थान है (चार्ट 1ए)। ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण मांग को पूरा करने में पीएसबी का दबदबा है (चार्ट 1बी)। हालांकि पीवीबी ग्रामीण इलाकों में कुछ पैठ बना रहे हैं, लेकिन उनकी प्रगति धीमी है।

ईंट और मोर्टार की शाखाओं को खोलना और उनका रखरखाव करना महंगा है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य भी हो सकता है, । इसे दूर करने के लिए, पीएसबी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के नए तरीके अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम में उनकी हिस्सेदारी पीवीबी की तुलना में दोगुनी से अधिक है (चार्ट 2ए)। ग्रामीण और वित्तीय रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पीएसबी द्वारा एक अन्य चैनल का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, वह व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का उपयोग है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी आउटलेट्स में पीएसबी की हिस्सेदारी इन वर्षों में लगातार 60 प्रतिशत से ऊपर रही है, जो बैंक समूहों में सबसे अधिक है (चार्ट 2बी)। दूसरी ओर पीवीबी ने शहरी बीसी मॉडल को अपनाया है।

चार्ट 1ए: शाखाओं का भौगोलिक वितरण (मार्च 2021 के अंत में)

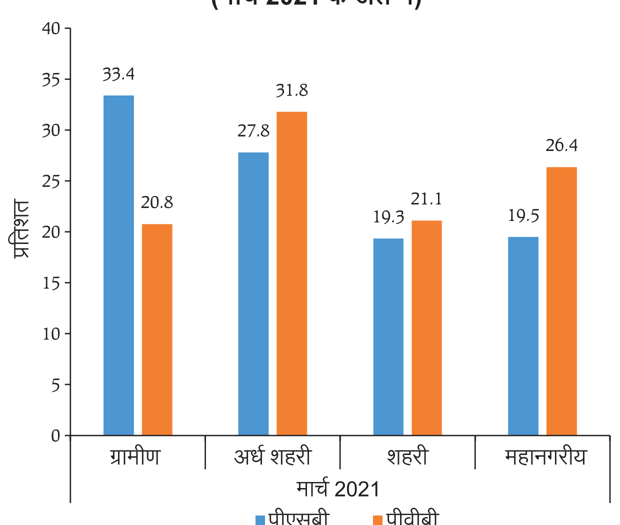

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 1बी: ग्रामीण ऋण में बैंक समूहों का हिस्सा

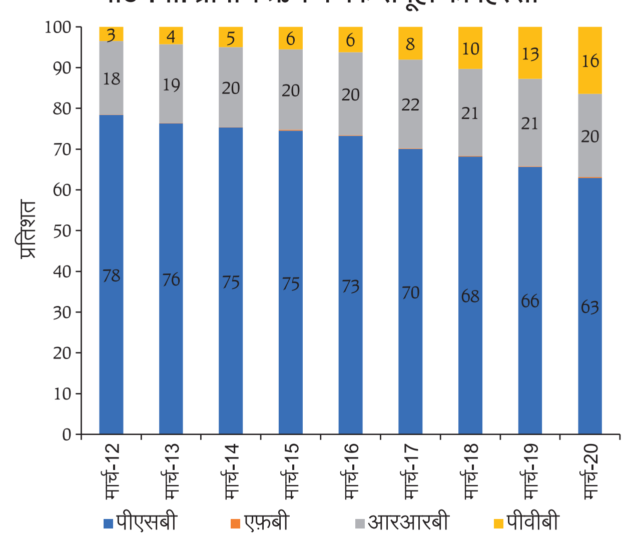

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा और क्रेडिट पर त्रैमासिक आंकड़े, आरबीआई।

चार्ट 2ए: मार्च 2021 के अंत में एटीएम का भौगोलिक वितरण

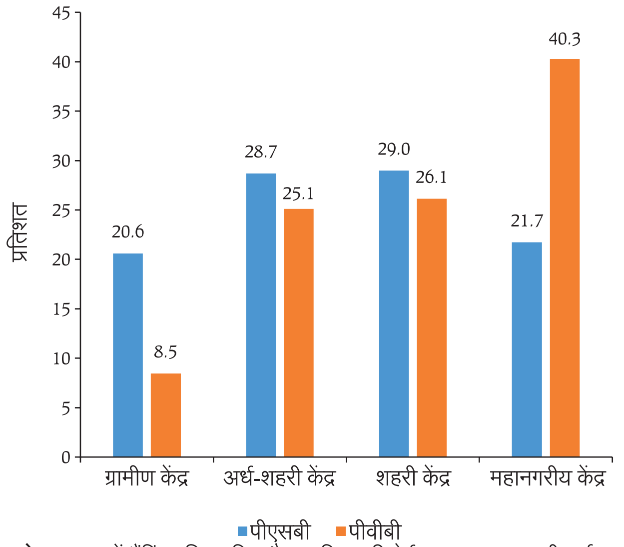

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21, आरबीआई।

चार्ट 2बी: गांवों में बीसी आउटलेट - बैंक समूहवार

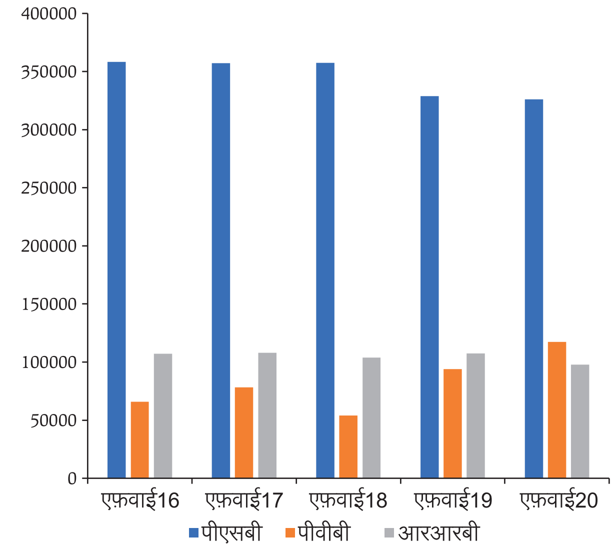

स्रोत: फुकन एवं अन्य (2021)

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करती है। जुलाई 2022 तक, 45 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाए गए और इनमें से 78 प्रतिशत खाते पीएसबी में थे (सारणी 1)। इसके अलावा, पीएसबी में खोले गए 60 प्रतिशत से अधिक पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे।

सारणी 1: बैंक-समूह स्तर पर पीएमजेडीवाई लाभार्थियों का वितरण

(लाभार्थियों की संख्या करोड़ में)

बैंक का प्रकार	ग्रामीण/अर्ध-शहरी केंद्र की बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	शहरी मेट्रो केंद्र की बैंक शाखाओं में लाभार्थियों की संख्या	ग्रामीण-शहरी महिला लाभार्थियों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	22.66	13.54	19.96	36.2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7.31	1.14	4.88	8.45
निजी क्षेत्र के बैंक	0.7	0.6	0.71	1.3
कुल	**30.67**	**15.28**	**25.55**	**45.95**

टिप्पणी: डेटा 6 जुलाई, 2022 तक का है।
स्रोत: प्रधानमंत्री जन धन योजना, भारत सरकार।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पीवीबी 40 प्रतिशत के अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा करते हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेशन की दिशा में योगदान करते हैं। विस्तृत आंकड़े हालांकि दिखाते हैं कि पीवीबी ने अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लक्ष्यों को मूलभूत उधार के माध्यम से नहीं बल्कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) में निवेश के माध्यम से पूरा किया है, विशेष रूप से कृषि और छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणियों[1] में। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की ये श्रेणियां विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हैं और उच्च प्रीमियम को आकर्षित करती हैं। पीवीबी ने ऐसे ऋण देने में कौशल और विशेषज्ञता विकसित करने के बजाय अपने पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करने की इच्छा जताई है।

III. पीएसबी की दक्षता

हम 2010-2022 में भारत में बैंकों के दक्षता स्तरों की जांच करने के लिए डीईए फ्रेमवर्क में इनपुट और आउटपुट के विभिन्न

[1] यद्यपि पीवीबी के पास सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में अधिशेष उधार है, जिसका वे पीएसएलसी के माध्यम से व्यापार करते हैं, यह छोटे और सीमांत किसानों के मामले में लगभग 30 प्रतिशत के लक्ष्य घाटे की तुलना में बहुत कम है और कृषि में लक्ष्य घाटे के करीब 20 प्रतिशत के करीब है।

चार्ट 3: पीएसएल जैविक और व्यापारिक पीएसएलसी

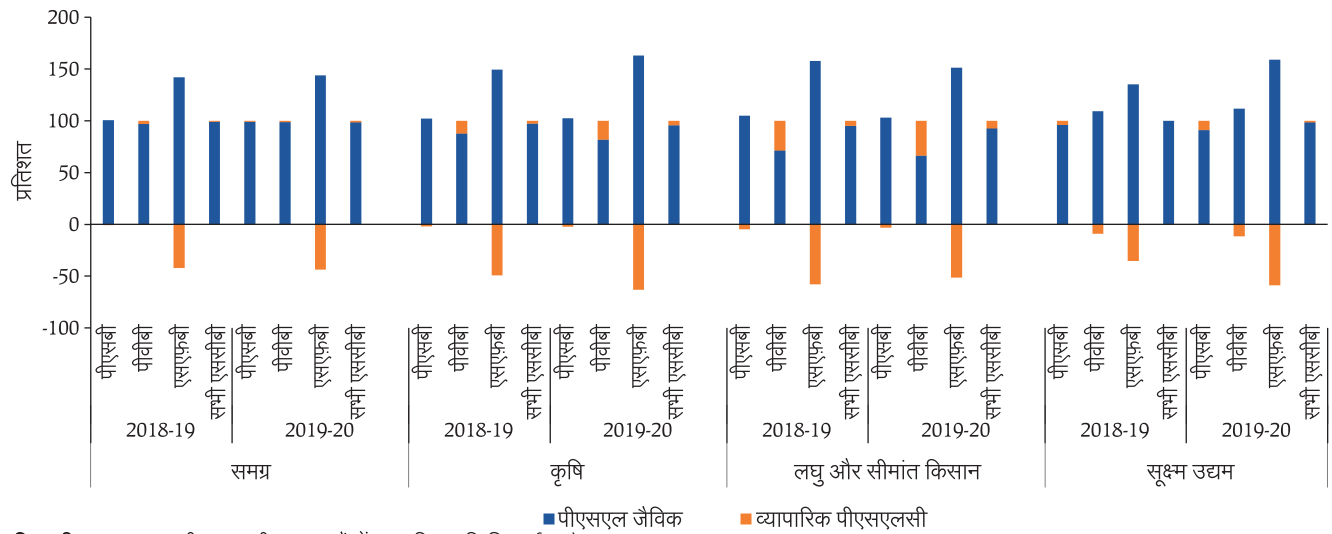

टिप्पणी: नकारात्मक पीएसएलसी व्यापार बैंकों द्वारा निवल बिक्री दर्शाता है।
स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21, आरबीआई।

संयोजनों का उपयोग करते हैं। डीईए एक रैखीय-कार्यक्रम-आधारित पद्धति है जो सजातीय संगठनों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए देखे गए इनपुट-आउटपुट अनुपातों की सीमा का निर्माण करती है और बैंकिंग में ज़्यादातर उपयोग की जा रही है (फेयर, ग्रॉसकोफ और लोवेल, 1985)। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाई की दक्षता का एक सारांश माप निकाला जाता है और प्रत्येक निर्णय लेने वाली इकाई (डीएमयू) के प्रदर्शन को इस मानदंड के आधार पर मापा जाता है ताकि यह संकेत मिल सके कि प्रत्येक डीएमयू कितना कुशल या अक्षम है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पीएसबी में कर्मचारी उतने सक्षम नहीं हैं (गुप्ता और पनगढ़िया, 2022)। इस दावे का अनुभवजन्य रूप से मूल्यांकन करने के लिए लागत न्यूनीकरण डीईए फ्रेमवर्क को नियोजित किया गया है। विशेष रूप से, पीवीबी की तुलना में पीएसबी की औसत श्रम लागत दक्षता की तुलना की जाती है। डीईए के इस विशेष रूप में, इनपुट के दिए गए स्तरों, इसकी कीमतों और प्रत्येक इकाई के आउटपुट के लिए, मॉडल सबसे अधिक श्रम लागत-कुशल इकाई की तुलना में प्रत्येक इकाई के दक्षता स्कोर का अनुमान लगाता है। लागत दक्षता को इस रूप में परिभाषित किया गया है, "दक्षता जो एक माप देती है कि एक बैंक की लागत कितनी करीब है इसके कि समान परिस्थितियों में उत्पादन के समान बंडल का उत्पादन करने के लिए एक सर्वोत्तम अभ्यास बैंक की लागत क्या होगी (कोकिसोवा, 2014)।

कुल जमा, सकल उधार और अग्रिम, कुल निवेश (एसएलआर + गैर एसएलआर) और गैर-ब्याज आय पर डेटा को आउटपुट के रूप में लिया गया जबकि कुल स्टाफ और अचल आस्ति (निवल) को इनपुट के रूप में लिया गया। औसत स्टाफ लागत (कुल स्टाफ लागत/कुल स्टाफ) और किराया, कर, प्रकाश व्यवस्था, बीमा और अचल आस्तियों की प्रति इकाई पर अन्य प्रशासनिक लागत (अन्य परिचालन व्यय/शुद्ध अचल आस्ति) को विश्लेषण के लिए इनपुट कीमतों के रूप में लिया गया। हमारे अध्ययन में बैंकों की संख्या 2010 में 49 और 2022 में 33 के बीच थी। डेटा रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों के विभिन्न प्रकाशनों से प्राप्त किया गया था।

चार्ट 4: पीएसबी और पीवीबी का दक्षता स्कोर: डीईए विश्लेषण

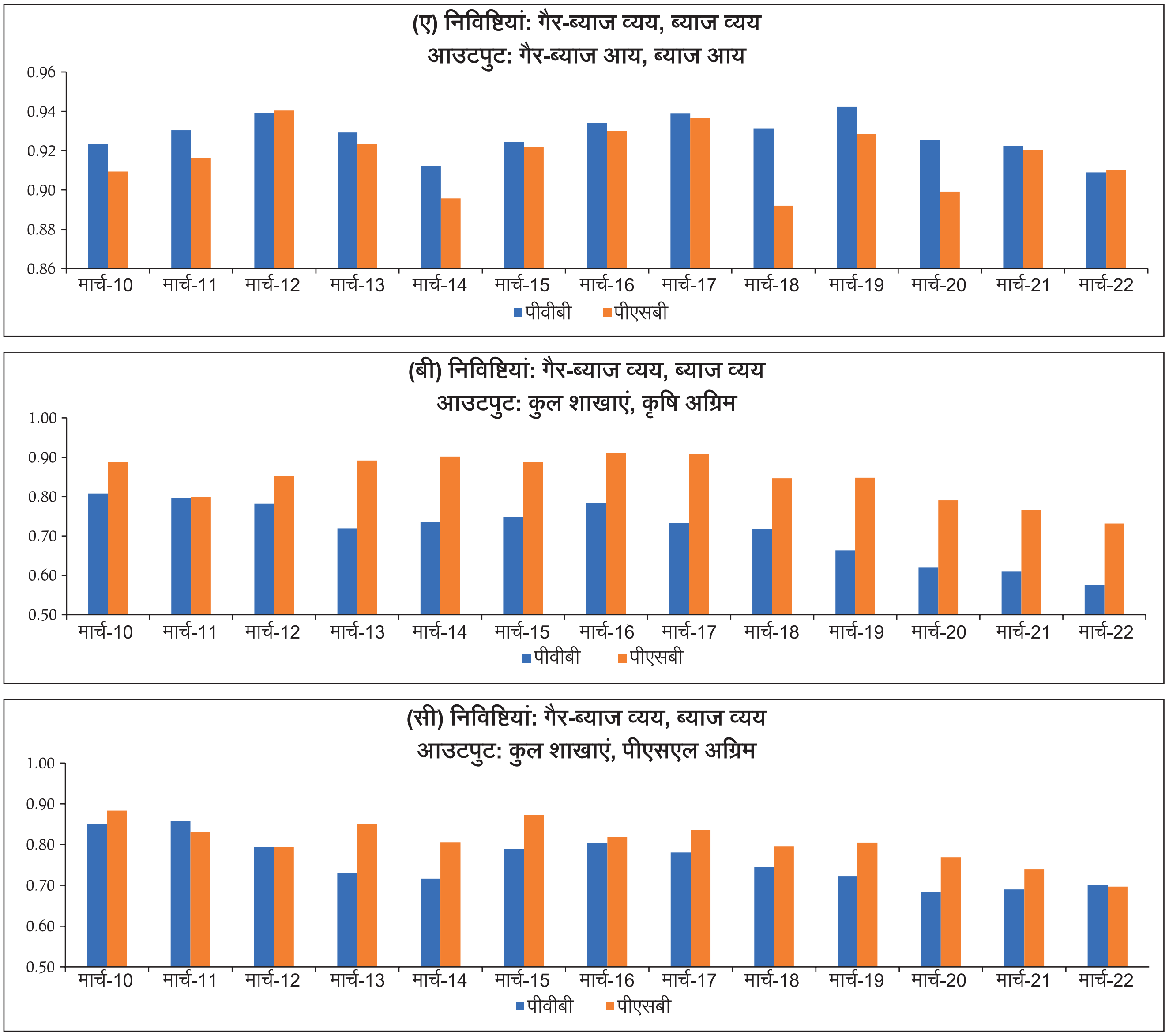

स्रोत: पर्यवेक्षी डेटा के आधार पर लेखकों की गणना।

विश्लेषण से पता चला है कि पीएसबी की श्रम लागत दक्षता 2016 को छोड़कर अधिकांश वर्षों में पीवीबी से अधिक रही है (चार्ट 5)। इसका तात्पर्य यह है कि श्रम पर कम लागत खर्च करके, पीएसबी उच्च स्तर का उत्पादन उत्पन्न कर सकते हैं। यह खोज पहले के शोध (हेरवाडकर एवं अन्य 2019) के अनुरूप है। बैंकिंग बीसी मॉडल का प्रभावी उपयोग, अन्य लागत-कुशल तकनीकों के कार्यान्वयन के साथ-साथ पीएसबी की उच्च लागत दक्षता के कारण हो सकते हैं।

चार्ट 5: बैंकों की औसत श्रम लागत दक्षता: पीवीबी की तुलना में पीएसबी (मार्च के अंत में)

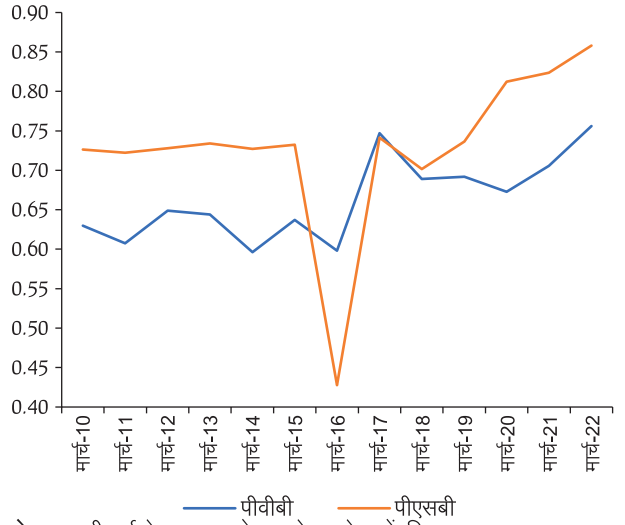

स्रोत: आरबीआई डेटा का उपयोग करते हुए लेखकों की गणना।

IV: पीएसबी की प्रतिचक्रीय भूमिका

पीवीबी की तुलना में पीएसबी ने लगातार कृषि और उद्योग को अपने कुल ऋण का एक बड़ा हिस्सा आबंटित किया है (चार्ट 6)। कृषि ऋण एक प्राथमिकता है, साथ ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी है। समय के साथ, कृषि ऋण देने में सहकारी बैंकों और आरआरबी की हिस्सेदारी कम हो गई है, जबकि पीएसबी की हिस्सेदारी[2] बढ़ गई है, यह दर्शाता है कि बाद वाले ने जरूरतमंद क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चूंकि भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार गहरे और जीवंत नहीं हैं, इसलिए उद्योगों के पास संसाधनों को जुटाने के लिए बैंकों की तुलना में कम अन्य रास्ते थे। पहले के शोध से यह भी पता चला है कि बड़े और मजबूत उद्योग इक्विटी बाजार तक आसानी से पहुंच सकते हैं लेकिन यह विकल्प छोटी संस्थाओं के लिए मुश्किल से उपलब्ध है (गांगुली, 2019)। यह 2017-18 से भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू हुए चक्रीय मंदी के दौरान विशेष रूप से सत्य था। औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करके, पीएसबी ने प्रतिचक्रीय भूमिका निभाई है।

अवसंरचना वित्त देश की संवृद्धि और विकास में एक बाधा रहा है। इन ऋणों में पीएसबी की बड़ी हिस्सेदारी है और उनकी भूमिका पूर्ववर्ती विकास वित्त संस्थानों के खत्म होने के समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है (चार्ट 7)।

चार्ट 6: क्रेडिट का क्षेत्रवार हिस्सा

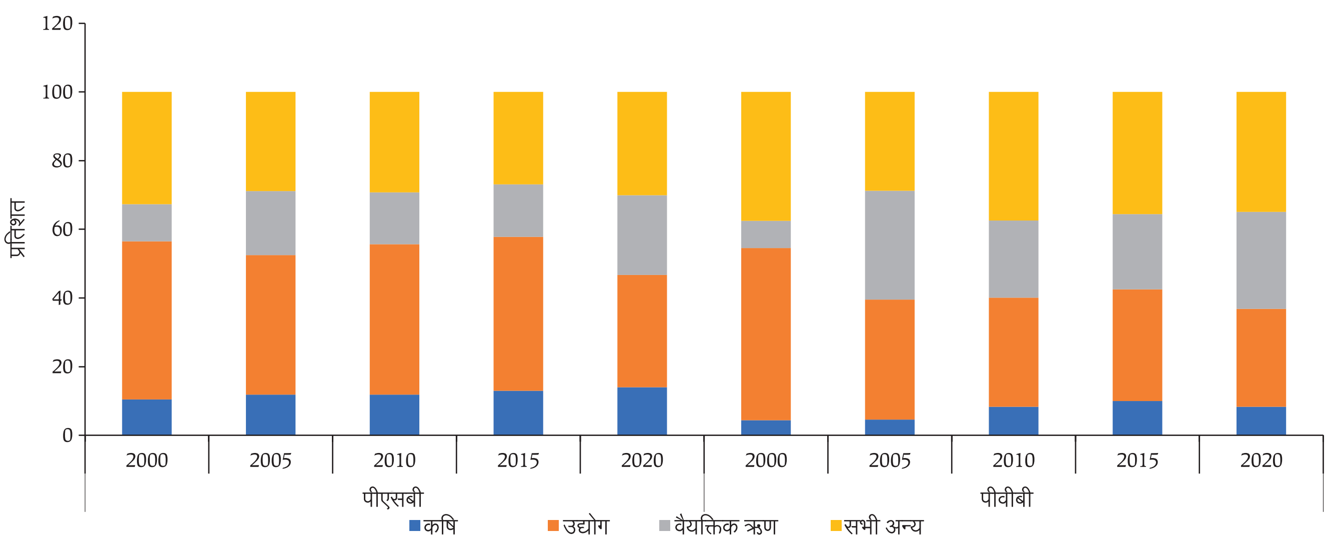

टिप्पणी: अन्य सभी में परिवहन परिचालक, पेशेवर और अन्य सेवाएं, व्यापार, वित्त और अन्य शामिल हैं।

स्रोत: मूलभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-1 (वार्षिक) - एससीबी, आरबीआई द्वारा क्रेडिट।

[2] पीवीबी की कृषि उधार में हिस्सेदारी भी कुछ हद तक बढ़ी है लेकिन प्रगति सुसंगत नहीं है।

चार्ट 7: अवसंरचना उधार में हिस्सेदारी

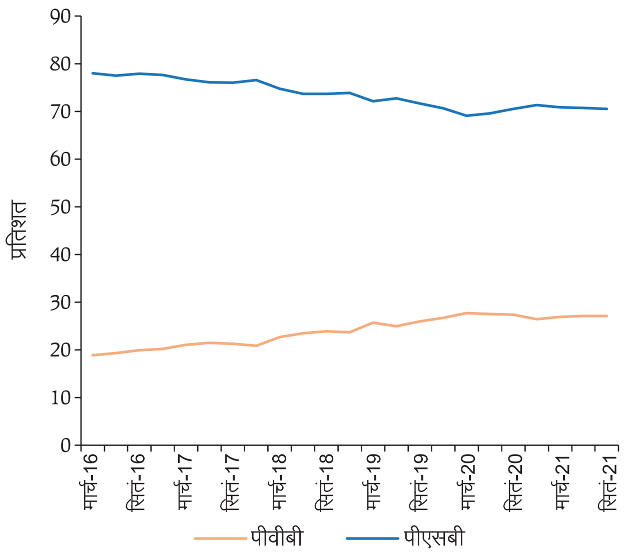

स्रोत: आरबीआई।

पीएसबी मौद्रिक नीति संचरण में भी अधिक प्रभावी हैं, प्रतिचक्रीय मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को कर्षण प्राप्त करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले सहजता चक्र के दौरान, उधार दरों में उनकी कमी पीवीबी की तुलना में काफी अधिक थी (चार्ट 8ए)। साथ ही, पीवीबी की तुलना में उनकी जमा दरें अपेक्षाकृत स्थिर थीं। पीवीबी के परिणामी उच्च एनआईएम उनके लाभ अधिकतमकरण उद्देश्य का संकेत है (चार्ट 8बी)। दूसरी ओर, मौद्रिक संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, पीएसबी ने बड़े सामाजिक लक्ष्यों में योगदान दिया है।

साहित्य सबूतों से भरा पड़ा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंक उधार देने में अधिक अनुचक्रीय हैं (मार्शल और रोचॉन 2019)। निजी बैंकों द्वारा अनुचक्रीय ऋण प्रतिचक्रीय व्यापक आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है, जबकि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रतिचक्रीय ऋण विशेष रूप से ईएमई में व्यापार चक्र को सुचारू बनाने में उपयोगी हो सकता है, (माइको और पनिज़ा, 2006, विश्व बैंक 2012; ब्रेई और श्लेरेक 2013)। यह जांचने के लिए कि क्या भारत में पीएसबी का उधार अधिक प्रतिचक्रीय (या, विपरीत रूप से, अनुचक्रीय) है, हमने एक निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन मॉडल (तालिका 2) में मार्च 2005 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 30 बैंकों के तिमाही डेटा का मूल्यांकन किया। आश्रित चर अर्थात ऋण वृद्धि को आस्तियों के मामले में बैंक के अपने अंतराल और आकार द्वारा समझाया गया है। पीवीबी डमी (पीवीबी = 1) को जीडीपी वृद्धि/जीडीपी वृद्धि के अंतराल के साथ मिलाया जाता है ताकि पीवीबी बनाम पीएसबी के अनुचक्रीय उधार के बीच अंतर का पता लगाया

चार्ट 8: उधार दर, जमा दर और एनआईएम

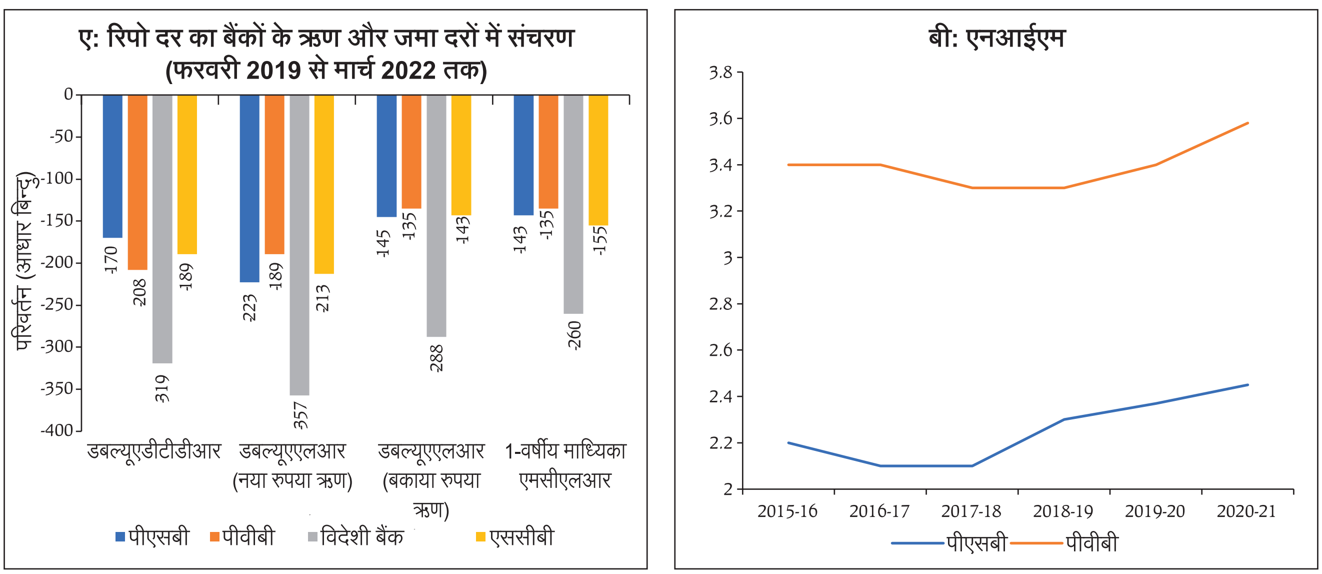

स्रोत: मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2022 और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2020-21।

जा सके। पीवीबी*जीडीपी वृद्धि और पीवीबी*जीडीपी वृद्धि टी-1 के सकारात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक यह संकेत देते हैं कि पीवीबी ऋण उनके सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अधिक अनुचक्रीय है। इसके अलावा, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के नियंत्रण के बाद भी निष्कर्ष मजबूत बने हुए हैं।

V: बाजार विश्वास

वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत में जमा पीवीबी से पीएसबी में चले गए। एक दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि यह पुनर्आवंटन उस बैंक के बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत नहीं था, जिससे जमाराशियां गई, बल्कि उनमें निहित सरकारी गारंटी का संकेत दिया था। शोधकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इसका निजी क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिकूल और अस्थिर प्रभाव पड़ा है, जहां से उनके बेहतर स्वास्थ्य के बावजूद जमा राशि निकाली गई थी (आइचेनग्रीन और गुप्ता, 2013)।

यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के स्वास्थ्य को लेकर जमाकर्ताओं की चिंताओं के मद्देनज़र 2020 की शुरुआत में जमा निकासी की कड़ी के लिए रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध पर्यवेक्षी डेटा का विश्लेषण- हालांकि अन्यथा सुझाव देता है। इस प्रकरण के दौरान जमा निकासी केवल छोटे निजी बैंकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाले कुछ पीएसबी को भी इसका सामना करना पड़ा। इन बैंकों द्वारा दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरों की पेशकश के बावजूद बहिर्वाह हुआ। जमा आम तौर पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मजबूत बैंकों के पास गए। इससे पता चलता है कि निवेशक और जमाकर्ता अपने विश्वास के मामले में निहित सरकारी गारंटी की तुलना में बैंकों के स्वास्थ्य को अधिक महत्व देते हैं। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे दबाव की अवधि के दौरान, यदि मजबूत पीएसबी मौजूद नहीं होते, तो बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर अस्थिरता का प्रभाव बहुत अधिक होता। इस तरह के प्रकरणों से बैंकों पर आसानी से दबाव पड़ सकता था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विकेंद्रीकरण हो सकता था। इस लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जनता के विश्वास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

सारणी 2: ऋण वृद्धि का निश्चित प्रभाव पैनल प्रतिगमन

	(1)	(2)	(3)	(4)
चर	ऋण वृद्धि	ऋण वृद्धि	ऋण वृद्धि	ऋण वृद्धि
(ऋण वृद्धि)$_{टी-1}$	0.858***	0.857***	0.853***	0.854***
	(0.0189)	(0.0193)	(0.0206)	(0.0203)
लॉग(कुल आस्तियां)	-1.358***	-1.366***	-1.365***	-1.358***
	(0.246)	(0.243)	(0.250)	(0.253)
पीवीबी*(जीडीपी वृद्धि)$_{टी}$	**0.130*** **			**0.131*** **
	(0.0347)			**(0.0351)**
पीवीबी*(जीडीपी वृद्धि)$_{टी-1}$		**0.133*** **	**0.134*** **	
		(0.0402)	**(0.0405)**	
पीसीए डमी			-1.109**	-1.077**
			(0.520)	(0.517)
स्थिर	17.12***	17.21***	17.33***	17.24***
	(3.114)	(3.061)	(3.174)	(3.226)
बैंक के निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes	Yes
अवलोकन	2,036	2,036	2,036	2,036
आर-वर्गित	0.819	0.819	0.819	0.819
बैंकों की संख्या	30	30	30	30

सारणी 3: बैंकों द्वारा निजी आबंटन के माध्यम से जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ करोड़ में)

	2019-20		2020-21		2021-22	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गयी राशि
पीएसबी	20	29,573	36	58,697	29	50,719
पीवीबी	8	23,121	4	33,878	12	35,682

टिप्पणी: कर्ज का निजी आबंटन और योग्य संस्थागत आबंटन शामिल है।
स्रोत: बीएसई, एनएसई और मर्चेंट बैंकर्स।

VI. निष्कर्ष

निजीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है, और इसके पक्ष और विपक्ष सर्वविदित हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से कि निजीकरण सभी बीमारियों के लिए रामबाण है, आर्थिक सोच यह स्वीकार करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुकी है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह आलेख साक्ष्य के साथ एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूरी तरह से केवल लाभ अधिकतमकरण लक्ष्य द्वारा

निर्देशित नहीं होते हैं और उन्होंने पीवीबी के विपरीत अपने उद्देश्य कार्य में वांछनीय वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को एकीकृत किया है। हमारे परिणाम पीएसबी ऋण देने की प्रतिचक्रीय भूमिका को भी इंगित करते हैं। हाल के वर्षों में, इन बैंकों ने बाजार का अधिक विश्वास भी प्राप्त किया है। कमजोर तुलन पत्र की आलोचना के बावजूद, आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के झटकों का उल्लेखनीय ढंग से सामना किया। पीएसबी के हाल के वृहत विलय के परिणामस्वरूप क्षेत्र का समेकन हुआ है, जिससे मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बैंक बन गए हैं। राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना से उनके तुलन पत्र से खराब ऋणों के पुराने बोझ को हटाने में मदद मिलेगी। हाल ही में गठित अवसंरचना और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक (एनएबीएफ़आईडी) अवसंरचना वित्त के लिए एक वैकल्पिक चैनल प्रदान करेगा, इस प्रकार पीएसबी की आस्ति देयता बेमेल चिंताओं को कम करेगा। कुल मिलाकर, इन सुधारों से पीएसबी को और मजबूत करने में मदद मिलने की संभावना है। इन निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में, इन बैंकों के निजीकरण का एक बड़े धमाके का दृष्टिकोण अच्छे से अधिक नुकसान कर सकता है। सरकार पहले ही दो बैंकों के निजीकरण के इरादे की घोषणा कर चुकी है। इस तरह के क्रमिक दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि बड़े पैमाने पर निजीकरण वित्तीय समावेशन और मौद्रिक संचरण के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में एक अंतराल पैदा नहीं करता है।

संदर्भ:

Atkinson, A. B., and Joseph E. Stiglitz, (1980), Lectures on Public Economics, London, Mc-Graw Hill

Cull, R., Peria, M. S., & Verrier, J. (2018). Bank Ownership: Trends and Implications. *World Bank Policy Research Working Paper.*

Brei, M., & Schclarek, A. (2013). Public Bank Lending in Times of Crisis. *Journal of Financial Stability.*

Eichengreen, B., & Gupta, P. (2013). The financial crisis and Indian banks: Survival of the fittest? *Journal of International Money and Finance.*

Estrin, S., & Pelletier, A. (2018). Privatization in Developing Countries: What Are the Lessons of Recent Experience? *World Bank Economic Review.*

Fare, R., Grosskopf, S., & Lovell, C. (1985). The Measurement of Efficiency of Production.

Foray, D., Mowery, D., & Nelson, R. R. (2012). Public R & D and social challenges: what lessons from mission R & D programs.

Ganguly, S. (2019). India's Corporate Bond market: Issues in Market microstructure. *RBI Bulletin, Jaunuary.*

Gupta, P., & Panagariya, A. (2022). Privatization of public sector banks in India- Why, How and How far? *India Policy Forum.*

Herwadkar, S., Neelima, K. M., Verma, R., & Asthana, P. (2019). Labour Cost Efficiency of Indian banks: A Non Parametric Analysis. *RBI Bulletin.*

Kocisova, K. (2014). Application of Data Envelopment Analysis to Measure Cost, Revenue and Profit Efficiency. *Statistika, 94(3).*

Marois, T. (2021). A Dynamic Theory of Public Banks (And Why It Matters). *Review of Political Economy.*

Marshall, W., & Rochon, L. (2019). Public Banking and Post-Keynesian Economic Theory. *International Journal of Political Economy.*

Mazzucato, M., & Penna, C. (2016). Beyond market failures: the market creating and shaping roles of state investment banks. *Journal of Economic Policy Reforms.*

Micco, A., & Panizza, U. (2006). Bank Ownership and Lending Behaviour. *Economics Letters.*

Panizza, U. (2022). State-owned commercial banks. *Journal of Economic Policy Reform.*

Phukan, S., Punnoose, S. T., Kumar, A., S, D., & Kumar, A. (2021). Financial Inclusion Plans - Reflecting the Growth Trajectory. *RBI Bulletin.*

Schapiro, M. (2012). Rediscovering the developmental path? Development bank, law, and innovation financing in Brazilian economy.

Stiglitz, J. E. (1993). The role of state in finnacial markets. *The World Bank Economic Review.*

World, B. (2012). Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance. *World Bank.*

*तूफानी समुद्र में एक स्थिर जहाज: हाल के दिनों में एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण**

एनबीएफसी क्षेत्र के समेकित तुलन पत्र में दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई, जो अर्थव्यवस्था में तेजी को प्रदर्शित करता है। इसी अवधि में ऋण वितरण में मजबूत दर से वृद्धि हुई। एनबीएफसी ने अपनी विकास दर के अनुसार निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जो 2021-22 के दौरान अब तक सभी तिमाहियों में ऋण वृद्धि से अधिक है। दिसंबर 2021 के अंत में एनबीएफसी के लाभप्रदता संकेतकों में सुधार महामारी के घटते प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, 2020-21 की इसी तिमाही की तुलना में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई है। आने वाले समय में, हालिया नियामक पहलों से एनबीएफसी क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

I. परिचय

वैश्विक वित्तीय प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ है, जो अंतर विनियमन, तकनीकी और वित्तीय प्रगति तथा अभिनव व्यापार मॉडल से प्रेरित है। इस परिवेश में, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों (एनबीएफसी)[1] की पहुँच में काफी विस्तार हुआ है, जो 2020 (एफएसबी, 2021) में वैश्विक वित्तीय आस्तियों का लगभग आधा हिस्सा है। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, गैर-बैंकों ने खुद को वित्तीय परिदृश्य के एक अभिन्न और अनिवार्य हिस्से के रूप में स्थापित किया है। वे मुख्यधारा की बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं। वे अपने ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों को समझने में निपुण हैं और तदनुसार वित्तीय उत्पाद और समाधान (आरबीआई, 2021) प्रदान करते हैं। गैर-बैंकों ने भी 'डिजिटल बैंडवेगन' का सहारा लिया है, जो भारत के वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर कोविड-19 महामारी के बाद के काल से बदल रहा है। बैंकों की तुलना में सहज और अंतर विनियमन से लाभान्वित होने के बाद, गैर-बैंक नवाचार को अपनाते हैं और वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हैं।

स्वतंत्रता से पहले की अवधि से भारत में मौजूद रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रोत्साहन मिला, जिसके बाद बैंकों ने विकासात्मक उद्देश्यों को उच्च प्राथमिकता दी। खुदरा वित्तीय और निवेश गतिविधियों को पूरा करने के लिए इसे निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया था और एनबीएफसी ने इस शून्य को भर दिया (आईएमएफ, 1998)। हाल के दिनों में भारत में एनबीएफसी[2] क्षेत्र के तेजी से विकास का वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। वित्तीय प्रणाली के सबसे बड़े उधारकर्ताओं के रूप में, एनबीएफसी क्षेत्र, बैंकों, पूंजी बाजारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफएसआर, 2021) के साथ अंतर-संबंधों के जाल में फंस गया है। इस बढ़ते परस्पर संबंध को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया था। रिज़र्व बैंक अक्तूबर 2022 से एनबीएफसी के लिए आकार आधारित विनियमन (एसबीआर) और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क लागू करने के लिए तैयार है। इन विनियमों का उद्देश्य एनबीएफसी की विविधता और लोचनीयता को संरक्षित करते हुए एक सशक्त और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली बनाना है।

भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एनबीएफसी क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, यह लेख एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म[3] पर एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त पर्यवेक्षी विवरणियों का उपयोग करके महामारी की दूसरी लहर के बाद दिसंबर 2021 तक 2021-22 में चुनिंदा एनबीएफसी के प्रदर्शन पर अध्ययन प्रस्तुत करता है।

---

* यह लेख श्री अशोक साहू, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के गैर-बैंकिंग वित्तीय अध्ययन प्रभाग में रजनीश कुमार चंद्रा, नंदिनी जयकुमार, अभ्युदय हर्ष, के एम नीलिमा और बृजेश पी द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एनबीएफसी क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित करता है जिसमें ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों को शामिल किया जाता है जो केंद्रीय बैंक, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए, इसमें संस्थानों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, मुद्रा बाजार निधि (एमएमएफ), हेज निधि और वित्त कंपनियां शामिल हैं।

[2] इस लेख में एनबीएफसी का तात्पर्य आरबीआई द्वारा विनियमित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत परिभाषित गैर-बैंक है।

[3] एनबीएफसी पर महामारी की पहली लहर के प्रभाव पर विस्तृत विवरण के लिए, कृपया भारत की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट (2019-20) के अध्याय 6 - गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान और महामारी के दौरान एनबीएफसी का कार्य-निष्पादन: एक संक्षिप्त विवरण, आरबीआई बुलेटिन, मई 2021 देखें।

शेष लेख निम्नलिखित भागों में विभाजित है। खंड II एनबीएफसी पर एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और वैश्विक एनबीएफसी क्षेत्र में भारत के स्थान पर चर्चा करता है। खंड III भारत में एनबीएफसी क्षेत्र का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करता है। खंड IV और V क्रमशः एनबीएफसी क्षेत्र के तुलन पत्र और तुलन पत्र से इतर मदों का आकलन प्रस्तुत करते हैं। खंड VI क्षेत्र के वित्तीय प्रदर्शन, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करता है। खंड VII ऋणों का क्षेत्रवार आबंटन और उसमें चूक की गंभीरता पूर्वक जांच करता है। खंड VIII इस क्षेत्र में भविष्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है और उनके मुख्य बिन्दुओं को उजागर करता है।

II. गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

भारी वित्तीय संकट (जीएफसी) ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में निहित त्रुटियों, विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में और उनके जोखिमों और कमजोरियों के आकलन में (क्लेसेन्स, डेल'एरिकिया, इगन, और लेवेन, 2010), को उजागर किया । इसलिए, जी -20 समूह ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विनियमन और निरीक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने निर्णय लेना पड़ा। प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों में से एक एनबीएफसी के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिसके तहत एफएसबी एनबीएफसी में प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण की पहचान करने और आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक वार्षिक निगरानी अभ्यास करता है।

जीएफसी के बाद, जब बैंकों ने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और यूरोप में अपने तुलन पत्र से लीवरेज को कम करना और अशोध्य ऋणों को हटाना शुरू कर दिया, एनबीएफसी ने बैंकों द्वारा खाली किए गए स्थान (सीजीएफएस, 2018) को हासिल कर लिया। इसके परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर, इस क्षेत्र में विस्तार देखा गया, जो 2002 में 58 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2020[4] में 226 ट्रिलियन हो गया, जो

चार्ट 1: वैश्विक वित्तीय आस्तियों में हिस्सेदारी

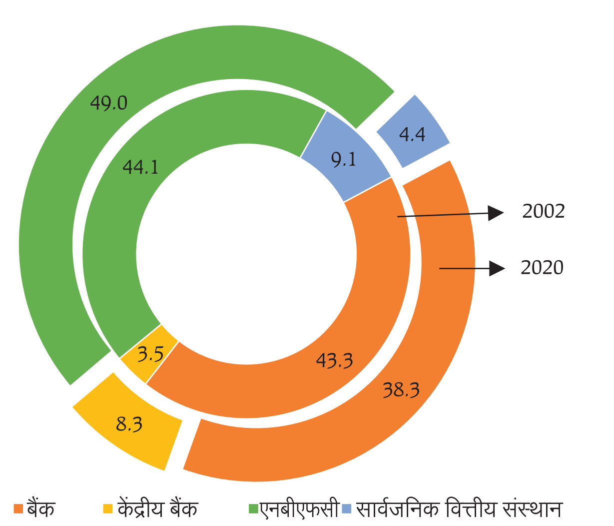

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता, एफएसबी, 2021 पर जारी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट से गणना की गई।

बैंक वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करता है। वैश्विक वित्तीय आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी 2002 में 44 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 49 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1)।

वैश्विक एनबीएफसी आस्तियों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) का बड़ा हिस्सा है। जीएफसी (कोडरेस, 2012) तक अमेरिका में सबसे बड़ा एनबीएफसी क्षेत्र था, जिसके बाद वैश्विक एनबीएफसी में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई और अन्य एई में वृद्धि हुई। फिर भी, यह 2020 में कुल एनबीएफसी आस्तियों का एक तिहाई से अधिक है। दूसरी ओर, ईएमई की हिस्सेदारी 2002 और 2020 के बीच 0.8 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 11 प्रतिशत हो गई। यह मुख्य रूप से चीन द्वारा संचालित था, जहां जीएफसी (बोमन एवं अन्य, 2018) की प्रतिक्रिया के रूप में पारंपरिक बैंकिंग पर विनियामकीय सीमाओं को लागू करने के बाद छाया बैंकिंग गतिविधियां बढ़ीं।

भारत वैश्विक स्तर पर एक छोटा भागीदार है, जिसमें 2020 में इसका हिस्सा वैश्विक एनबीएफसी आस्तियों का 0.7 प्रतिशत है (चार्ट 2)। हालांकि, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में एनबीएफआई क्षेत्र का आकार 2002 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 60 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो भारत के

[4] इसमें 29 व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार शामिल हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80 प्रतिशत है।

चार्ट 2: वैश्विक एनबीएफसी आस्तियों में हिस्सेदारी

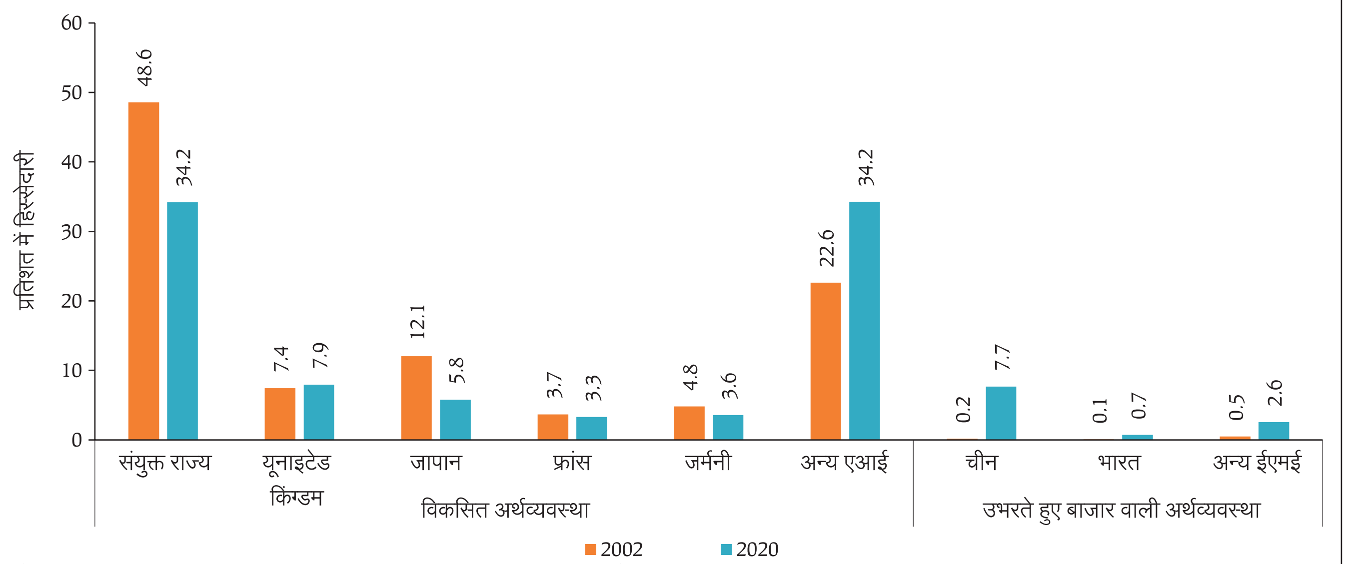

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता, एफएसबी, 2021 पर जारी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट से गणना की गई।

वित्तीय परिदृश्य में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है (चार्ट 3)।

एनबीएफसी किस सीमा तक बैंक जैसे वित्तीय स्थिरता जोखिम पैदा करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए, एफएसबी ने एक "नैरो माप" विकसित किया है, जो एनबीएफसी को पांच

चार्ट 3: भारतीय एनबीएफसी क्षेत्र का आकार (जीडीपी के हिस्सेदारी के रुप में), 2002-20

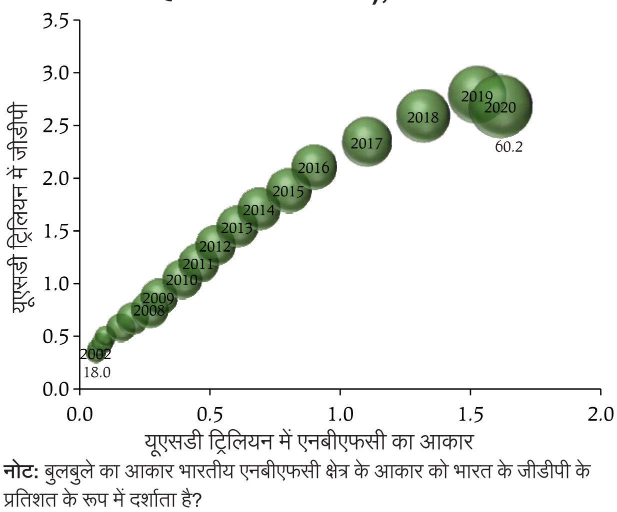

नोट: बुलबुले का आकार भारतीय एनबीएफसी क्षेत्र के आकार को भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है?

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता, एसएफबी, 2021 पर जारी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट से गणना की गई।

आर्थिक कार्यों (ईएफ) या गतिविधियों[5] में वर्गीकृत करता है। वैश्विक स्तर पर, नैरो माप, जहाँ एनबीएफआई आस्तियों का लगभग 28 प्रतिशत है, तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में यह लगभग 45 प्रतिशत है (सारणी 1)।

वैश्विक स्तर पर, नैरो माप में ईएफ 1 का हिस्सा 2006 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 75 प्रतिशत से अधिक हो गया और इसी अवधि के दौरान अनाबंटित श्रेणी को छोड़कर अन्य गतिविधियों में गिरावट आई (चार्ट 4 ए)। 2006 और 2020 के बीच 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ, ईएफ 1 ने नैरो माप की वृद्धि को, विशेषकर जीएफसी के पश्चात, बढ़ावा दिया। इसके विपरीत, ईएफ 2 भारत में सबसे बड़ी इकाई प्रकार बना रहा, इसके बाद ईएफ 1, जहाँ 2006-20 के दौरान ईएफ़2 17.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा था। भारत के नैरो माप में ईएफ़1 और ईएफ़2 की हिस्सेदारी काफी हद तक स्थिर रहे हैं (चार्ट 4बी)। ईएफ 2 संस्थाओं में बड़े पैमाने पर वित्त कंपनियां शामिल हैं, जो ऋण मध्यस्थता का कार्य करती हैं और ऋण प्रावधान के लिए अल्पकालिक वित्त पोषण पर भरोसा करती हैं। वे बैंक ऋण के पूरक हैं और संबन्धित अन्य क्षेत्रों को वित्तपोषण

[5] ये संस्थाएं उन गतिविधियों में शामिल हैं जिनमें परिपक्वता / चलनिधि परिवर्तन, लीवरेज या अपूर्ण ऋण जोखिम हस्तांतरण और / या नियामक मध्यस्थता शामिल है।

सारणी 1: संस्था और गतिविधि-वार नैरो मेज़र का वर्गीकरण, 2020

आर्थिक कार्य / गतिविधि	संस्था का प्रकार	आर्थिक कार्य के अनुसार नैरो मेजर में हिस्सेदारी: वैश्विक	आर्थिक कार्य के अनुसार नैरो मेजर में हिस्सेदारी: भारत
ईएफ़1	एमएमएफ, नियत आय निधि, मिश्रित निधि, ऋण हेज निधि, स्थावर संपदा निधि	75.1	22.5
ईएफ़2	वित्त कंपनियां, लीजिंग / फैक्टरिंग कंपनियां, उपभोक्ता ऋण कंपनियां	6.7	76.7
ईएफ़3	ब्रोकर-डीलर, कस्टोडियल खाते, प्रतिभूति वित्त कंपनियां	7.8	0.4
ईएफ़4	ऋण बीमा कंपनियां, वित्तीय गारंटर, मोनोलाइन बीमाकर्ता	0.3	0.0
ईएफ़5	प्रतिभूतिकरण माध्यम, संरचित वित्त माध्यम, आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां	7.5	0.4
अनाबंटित	ऐसे एनबीएफसी जिन्हें संबंधित अधिकारियों ने बैंक की तरह वित्तीय स्थिरता जोखिम में शामिल करने का आकलन किया लेकिन एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं जा सका।	2.6	0.0
कुल एनबीएफ़सी क्षेत्र के हिस्से के रूप में नैरो मेज़र अर्थात, ईएफ़1 + ईएफ़2 + ईएफ़3 + ईएफ़4 + ईएफ़5 + अनाबंटित।		**27.9**	**44.5**

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता, एफएसबी, 2021 पर जारी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट से गणना की गई।

प्रदान करते हैं, जहां बैंक सक्रिय भागीदार नहीं हैं (एफएसबी, 2021)। भारत में एनबीएफसी बड़े पैमाने पर ईएफ 2 का एक हिस्सा हैं और आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत विनियमित हैं तथा इस लेख की विषय वस्तु हैं।

चार्ट 4: नैरो मेज़र संरचना, 2006-20

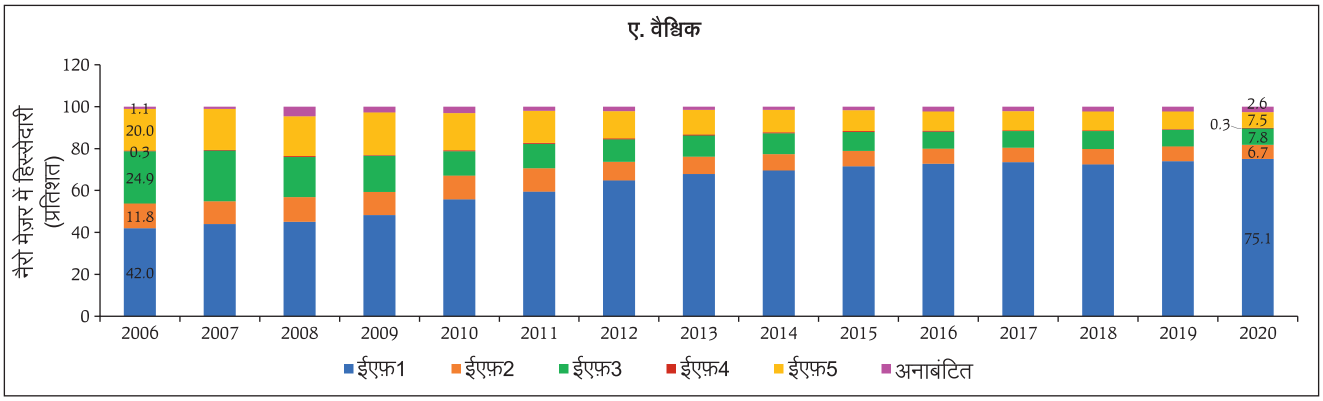

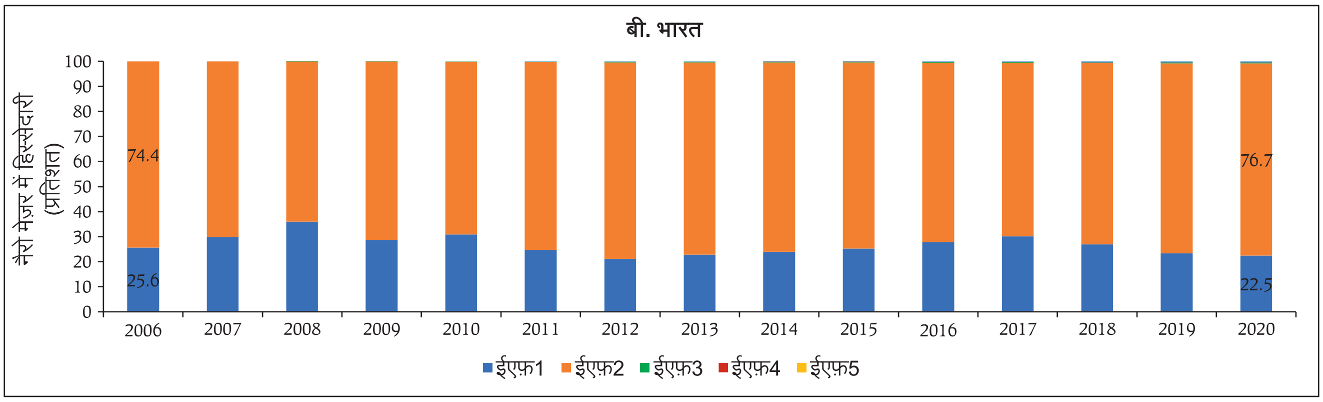

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता, एफएसबी, 2021 पर जारी वैश्विक निगरानी रिपोर्ट से गणना की गई।

सारणी 2: गतिविधि द्वारा एनबीएफसी क्षेत्र का वर्गीकरण

एनबीएफसी का प्रकार	गतिविधि की प्रकृति / मुख्य व्यवसाय
निवेश और ऋण कंपनी (आईसीसी)	उधार और निवेश।
अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी)	बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण प्रदान करना।
अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ)	अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधिक ऋण प्रवाह को सुगम बनाना।
मूल निवेश कंपनी (सीआईसी)	इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, ऋण, या समूह कंपनियों के ऋणों में निवेश।
एनबीएफसी- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई)	छोटे कर्जदारों को संपार्श्विक मुक्त ऋण और अग्रिम।
एनबीएफसी – फैक्टर	फैक्टरिंग व्यवसाय अर्थात प्राप्तियों का वित्तपोषण।
गैर-परिचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)	प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के माध्यम से निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना हेतु।
बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी)	ऋण के लिए बंधक गारंटी प्रदान करना।
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)	बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बेची गई वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण और व्यापार।
पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (पी2पी)	धन जुटाने में मदद करने के लिए उधारदाताओं और उधारकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना।
अकाउंट एग्रीगेटर (एए)	ग्राहक या अन्य को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट एक समेकित, संगठित और पुनर्प्राप्ति योग्य तरीके से जानकारी एकत्र करना और प्रदान करना।
आवास वित्त कंपनी (एचएफ़सी)	आवास के लिए वित्तपोषण।

स्रोत: आरबीआई।

III. एनबीएफसी क्षेत्र का सामान्य अवलोकन

31 जनवरी, 2022 तक रिज़र्व बैंक के साथ 9,495[6] एनबीएफसी पंजीकृत थीं। देयता संरचना के आधार पर, एनबीएफसी को जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) में, जिन्हें सावधि जमा जुटाने की अनुमति है और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एनबीएफसी-एनडी को आगे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी आस्तियों का आकार 500 करोड़ रुपये से अधिक है। उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधि के आधार पर, एनबीएफसी को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (सारणी 2)।

कंपनियों की संख्या के दृष्टिकोण से, एनबीएफसी-एनडी, जिनकी आस्तियों का आकार 500 करोड़ रुपये से कम है, का

चार्ट 5: एनबीएफसी का विभाजन

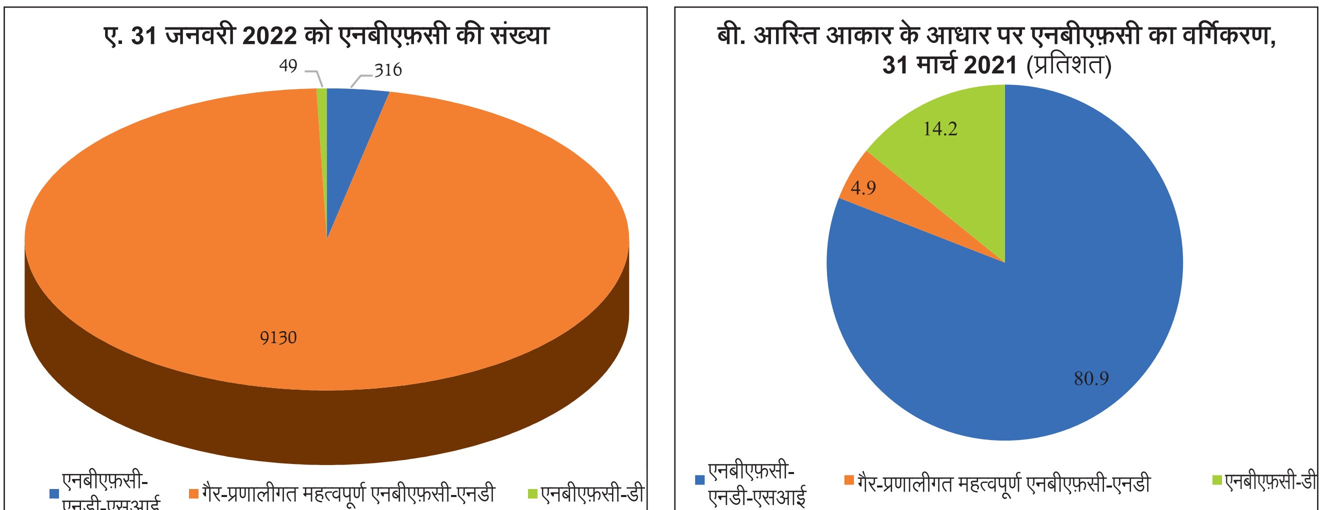

नोट: 1.सीआईसी सहित
2. आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

नोट: 1. नियमित आधार पर विवरणी भरने वाले एनबीएफ़सी (सीआईसी को छोड़कर) पर आधारित।
2. आंकड़े अनंतिम हैं। **स्रोत:** पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

[6] एचएफसी और एआरसी को छोड़कर।

सबसे बड़ा हिस्सा है (चार्ट 5 ए)। एनबीएफसी-डी की संख्या जनवरी 2021 में 64 से घटकर जनवरी 2022 में 49 हो गई है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई कंपनियों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी लगभग 81 प्रतिशत है (चार्ट 5 बी)। मार्च 2021 तक, एनबीएफसी-डी का हिस्सा लगभग 14 प्रतिशत और गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी था, जो इस क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 5 प्रतिशत था।

निरंतरता बनाए रखने के लिए, हमारे नमूने में 278 एनबीएफसी शामिल हैं, जिन्होंने दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021 तक नियमित रूप से सभी तिमाहियों में विवरणियां भरी हैं। हमारा नमूना दिसंबर 2021[7] की स्थिति के अनुसार वैश्विक एनबीएफसी की आस्तियों का लगभग 85 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इस नमूने में, एनबीएफसी-आईसीसी सबसे बड़ा (52.8 प्रतिशत) है, इसके बाद आईएफ़सी (43.7 प्रतिशत) हैं, जिसमें मुख्य रूप से बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी शामिल हैं। एनबीएफ़सी-एमएफ़आई, एनबीएफ़सी-आईडीएफ़ और एनबीएफसी -फैक्टर को मिलाकर यह हमारे नमूने का शेष 3.5 प्रतिशत हिस्सा होता है।

IV. एनबीएफसी का तुलन पत्र-आधारित विश्लेषण

एनबीएफसी की समेकित तुलन पत्र में दिसंबर 2020 की तुलना में दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि हुई (सारणी 3)। महामारी की दूसरी लहर के बाद, अर्थव्यवस्था में तेजी, दबी हुई मांग के पुनः शुरू होने, पर्याप्त प्रावधानों की उपलब्धता और पूंजी की स्थिति में सुधार से वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी के विश्लेषण से भी उनके तुलन पत्र में विस्तार का पता चलता है।

IV.1. एनबीएफसी की देयताओं की संरचना

उधारी, आरक्षित निधि और अधिशेष कुल मिलाकर तुलन पत्र की देयता पक्ष का लगभग 88 प्रतिशत है। दिसंबर 2021 के अंत में, एनबीएफसी द्वारा पुनः लाभ अर्जित किए जाने के कारण आरक्षित निधि और अधिशेष में तेज गति से वृद्धि हुई, जिससे उनका तुलन पत्र सुदृढ़ हुआ। सार्वजनिक जमाराशि तक पहुँच वाली एनबीएफसी-डी को छोड़कर, अन्य एनबीएफसी अपनी निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक और बाजार उधार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

[7] एनबीएफसी ब्रह्मांड में एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई (सीआईसी और पीडी को छोड़कर) शामिल हैं।

सारणी 3: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

	के अंत में बकाया राशि			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	
	दिसं-20	मार्च-21	दिसं-21	दिसं 19 की तुलना में दिसं 20 में	दिसं 20 की तुलना में दिसं 21 में
1. शेयर पूंजी	87,877	91,392	92,902	14.1	5.7
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	4,36,427	4,63,942	5,18,518	13.5	18.8
3. सार्वजनिक जमा	52,524	56,426	63,510	27.4	20.9
4. कुल उधार	19,63,017	21,01,027	22,08,431	10.9	12.5
5. वर्तमान देयताएं और प्रावधान	1,71,847	1,72,047	1,73,283	12.4	0.8
6. अन्य देयताएं	26,100	33,903	52,619	3.9	101.6
कुल देयताएं / आस्तियां	**27,37,792**	**29,18,738**	**31,09,263**	**11.7**	**13.6**
1. ऋण और अग्रिम	22,52,413	23,93,871	25,02,575	17.7	11.1
2. निवेश	2,32,851	2,41,748	2,80,547	18.1	20.5
3. नकद और बैंक शेष	1,16,197	1,31,857	1,40,814	47.7	21.2
4. अन्य वर्तमान आस्तियां	78,129	74,707	80,916	2.5	3.6
5. अन्य आस्तियां	58,203	76,555	1,04,411	-68.4	79.4

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. संख्याओं का योग नहीं हो सकता है क्योंकि सभी घटकों को यहां रिपोर्ट नहीं किया गया है।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

एनबीएफसी के पास जमानती और गैर-जमानती दोनों तरह की उधारी है। दिसंबर 2021 के अंत में कुल उधारियों में जमानती उधारियों का हिस्सा आधे से अधिक था (चार्ट 6 ए)। दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में बाजार उधारी की तुलना में बैंक उधारी में उच्च गति से वृद्धि हुई (चार्ट 6 बी)।

डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) दोनों बाजार उधार में शामिल हैं। बैंकों द्वारा एनबीएफसी के डिबेंचर की ख़रीदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जो मार्च 2021 और दिसंबर 2021 के बीच मामूली रूप से बढ़ी है (चार्ट 7 ए)। दिसंबर 2021 के अंत में एनबीएफसी के सीपी ख़रीदारी में म्यूचुअल फंड अग्रणी रहा है, जिसके पश्चात बैंकों का योगदान रहा है, जिसमें इन दोनों का हिस्सा एनबीएफसी के कुल सीपी का 86.8 प्रतिशत था (चार्ट 7बी)।

चार्ट 6: एनबीएफसी का उधारी प्रोफाइल

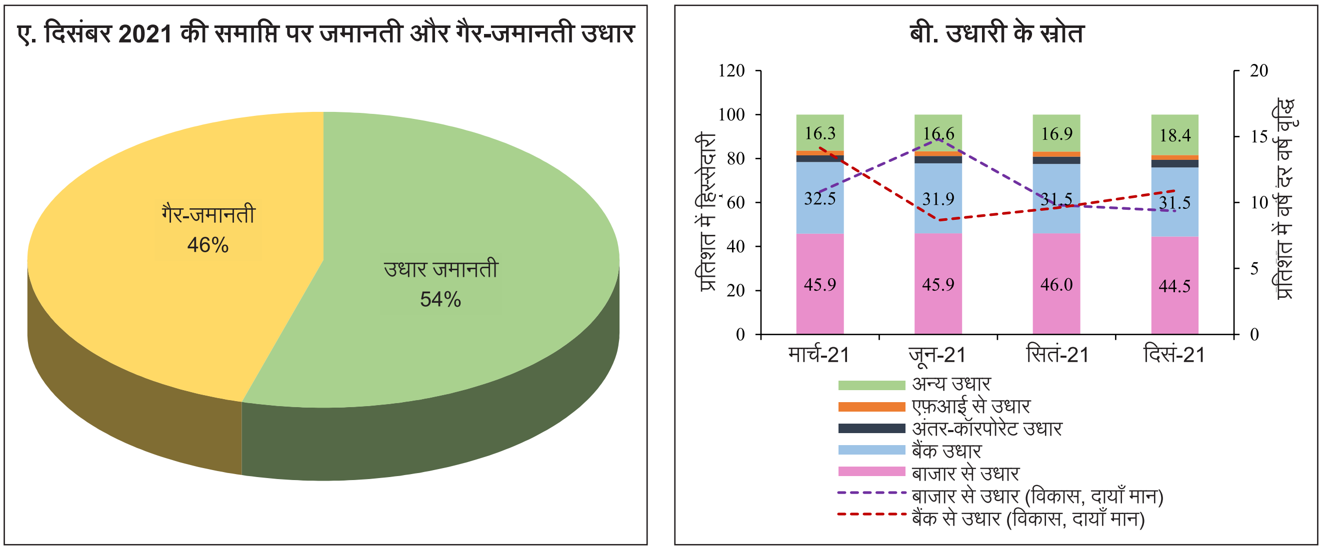

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

बैंक उधारी में सावधि ऋण, कार्यकारी पूंजीगत ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। आईएलऐंडएफएस प्रकरण के बाद एनबीएफसी की उधारी में धीरे-धीरे बदलाव आया है और लंबी अवधि की उधारी पर निर्भरता बढ़ रही है। इसलिए, एनबीएफसी द्वारा बैंकों से उधार लेने में सावधि ऋण का मुख्य हिस्सा होता है। सावधि ऋणों में निरंतर वृद्धि आर्थिक रिकवरी के गति पकड़ने का संकेत है। दूसरी ओर, कार्यशील पूंजी ऋण की वृद्धि दर कम रही (चार्ट 8)।

चार्ट 7: एनबीएफसी के ऋण लिखतों के अभिदानकर्ताओं का संस्था वार विवरण

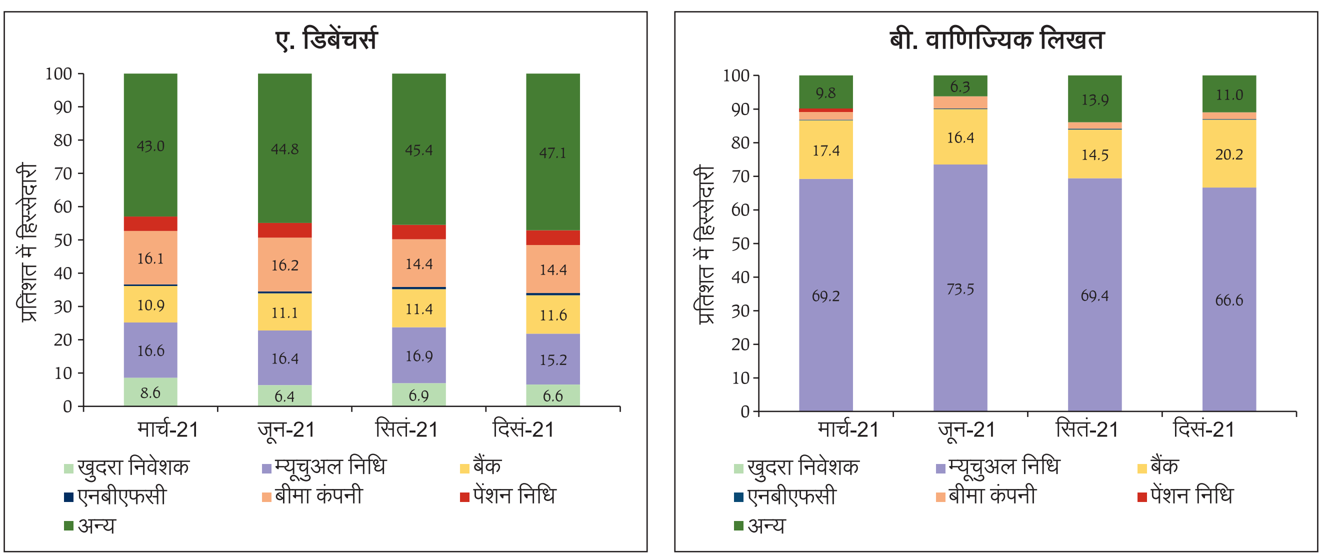

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 8: एनबीएफसी के बैंक ऋणों का गठन

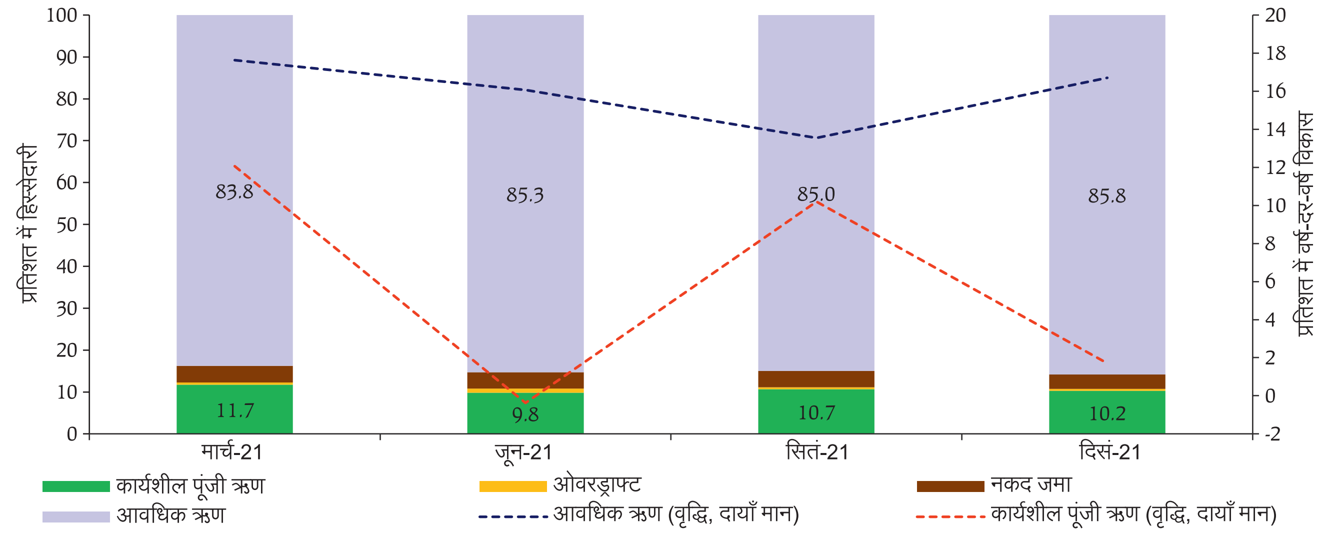

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

2020 में राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद की तिमाही (2020-21 की पहली तिमाही) में, जोखिम से बचने, वित्तीय बाजारों में बिकवाली और म्यूचुअल फंडों द्वारा कुछ योजनाओं को अचानक बंद करने सहित कई कारकों के संयोजन के कारण, एनबीएफसी के बॉण्ड पर प्रतिफल में वृद्धि हुई। निम्नलिखित तिमाहियों में प्रसार कम हो गया, लेकिन एएए और एए-रेटेड एनबीएफसी के बीच अंतर बना रहा। हालांकि, जनवरी 2021 के बाद से, अंतर कम होना शुरू हो गया। एए रेटिंग वाली एनबीएफसी के तीन साल के बॉण्ड और समान परिपक्वता वाले एएए रेटेड एनबीएफसी के बॉण्ड के बीच का अंतर जनवरी 2021 में 145 आधार अंक (बीपीएस) के शिखर से गिरकर दिसंबर 2021 में 74 बीपीएस हो गया, और इस प्रकार, कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच गया। यह बाजार में जोखिम से बचने में धीरे-धीरे कमी को दर्शाता था (चार्ट 9 ए)। अप्रैल 2020 में कोविड-19 की पहली लहर के बाद ट्रेजरी बिलों पर सीपी का प्रसार चरम पर था और दूसरी लहर के दौरान मार्च 2021 में यह फिर से बढ़ गया। बाद में यह धीरे-धीरे इसमें कमी आई, लेकिन प्राथमिक बाजार गतिविधि (आरबीआई, 2022) (चार्ट 9 बी) के कारण पिछली तिमाहियों की तुलना में दिसंबर 2021 में इसमें तेजी आई।

सीपी बाज़ार में एनबीएफसी और कॉरपोरेट सबसे बड़े भागीदार हैं। 2020-21 की तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद 2021-22 की तीसरी तिमाही में कुल सीपी निर्गम में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि एनबीएफसी द्वारा संचालित की गई थी, जिसने 2021-22 की तीसरी तिमाही में सीपी के माध्यम से 3,12,530 करोड़ रुपये जुटाए, जो कुल निर्गम का 48.2 प्रतिशत था। ऐसा प्रतीत होता है कि कम ब्याज दर के माहौल ने एनबीएफसी को इस चैनल के माध्यम से अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित किया हो (चार्ट 10)।

IV.2 एनबीएफसी की आस्ति संरचना

निवेश के बाद ऋण और अग्रिम एनबीएफसी के तुलन पत्र के आस्ति पक्ष के लिए सबसे बड़े घटक हैं। एनबीएफसी गैर-जमानती ऋणों की तुलना में जमानती ऋण अधिक प्रदान करते हैं। एनबीएफसी अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों, इक्विटी, डिबेंचर, बॉण्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती हैं।

एनबीएफसी ऋण में दिसंबर 2020 में 17.7 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2021 के अंत में 11.1 प्रतिशत की वृद्धिशील वृद्धि दिखाई दी, जो अनुकूल आधार प्रभाव के कारण थी। एनबीएफसी ने निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करना जारी रखा,

चार्ट 9: एनबीएफसी के बाजार लिखतों का स्प्रेड

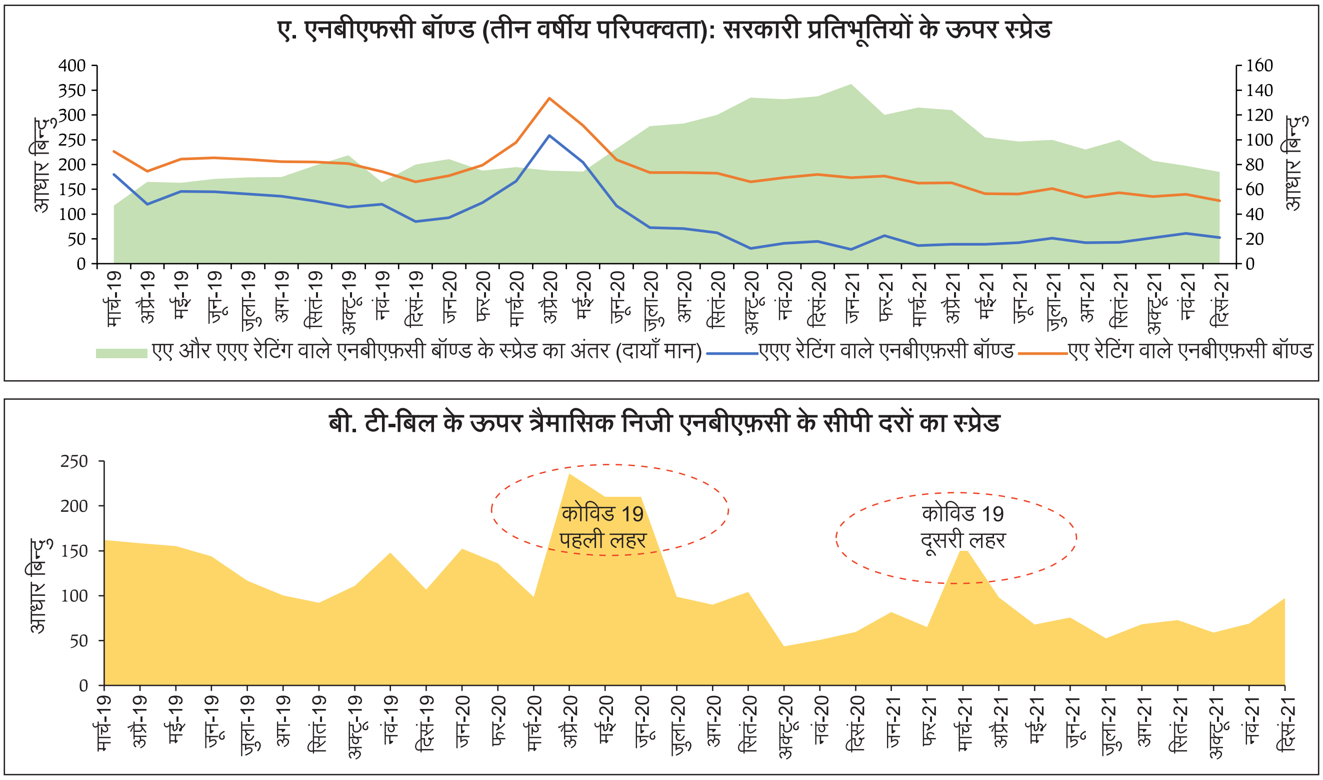

स्रोत: 1. ब्लूमबर्ग
2. आरबीआई

जैसा कि 2021-22 के दौरान अब तक सभी तिमाहियों में ऋण में वृद्धि से अधिक उनकी वृद्धि दर से संकेत मिलता है। एनबीएफसी ने पिछली अवधि में नकदी को संरक्षित किया था, इसलिए दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में नकदी और बैंक जमाराशि की वृद्धिशील वृद्धि में गिरावट आई। यह उनके तुलन पत्र में एनबीएफसी की संतोषजनक चलनिधि की स्थिति का संकेत है, जिसे

चार्ट 10: सीपी निर्गम का गठन

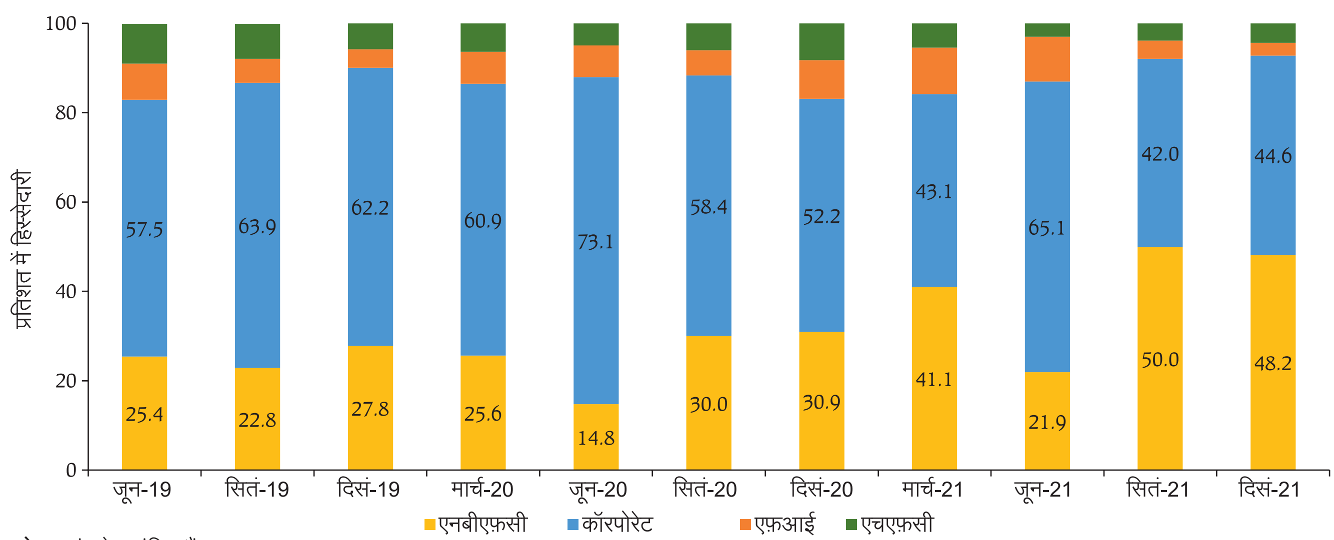

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 11: एनबीएफसी आस्तियों के घटक

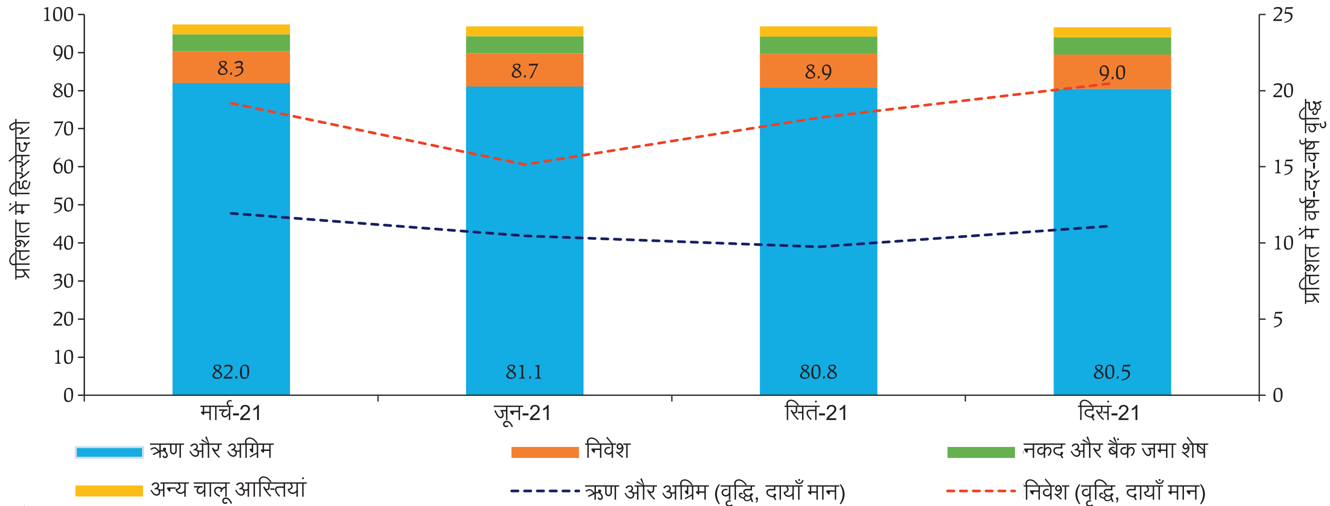

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

प्रणालीगत अधिशेष चलनिधि (चार्ट 11) द्वारा और अधिक सहायता प्राप्त होती है।

कोविड-19 के कम खतरे के साथ-साथ टीकाकरण में प्रगति के कारण दिसंबर 2021 के अंत तक एनबीएफसी की ऋण वृद्धि में मामूली वृद्धि देखी गई, जिससे उच्च गतिशीलता हुई। त्योहारों के मौसम के आगमन ने भी इस संबंध में मदद की। अधिकांश उपभोक्ता ऋण प्रदान करने वाले आईसीसी ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी दिखाई। महामारी की दूसरी लहर के कारण आईएफसी की ऋण वृद्धि में थोड़ी कमी आई है, लेकिन बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर सरकार के ध्यान के बाद, निकट भविष्य में बुनियादी ढांचा ऋण की मांग में सुधार होने की संभावना है। एनबीएफसी-एमएफआई ने महामारी (चार्ट 12 ए) से हुए झटके को धता बताते हुए तेज गति से विकास किया। इस अवधि के दौरान एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण

चार्ट 12: एनबीएफसी का वर्गीकरण-वार ऋण

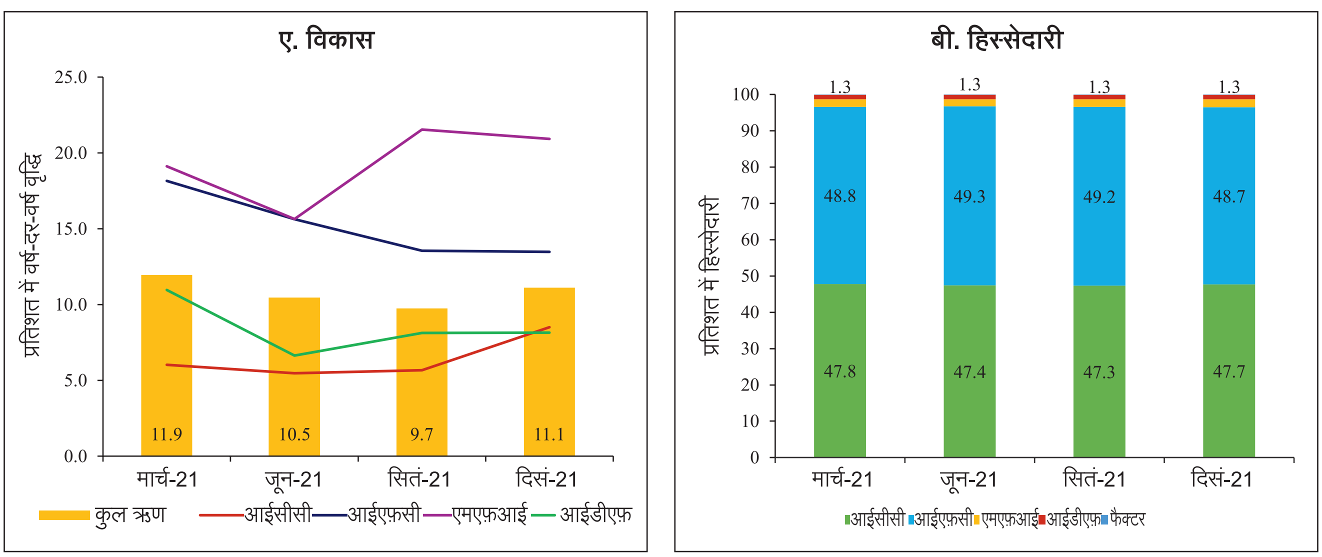

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

चार्ट 13: एनबीएफसी का निवेश प्रोफाइल

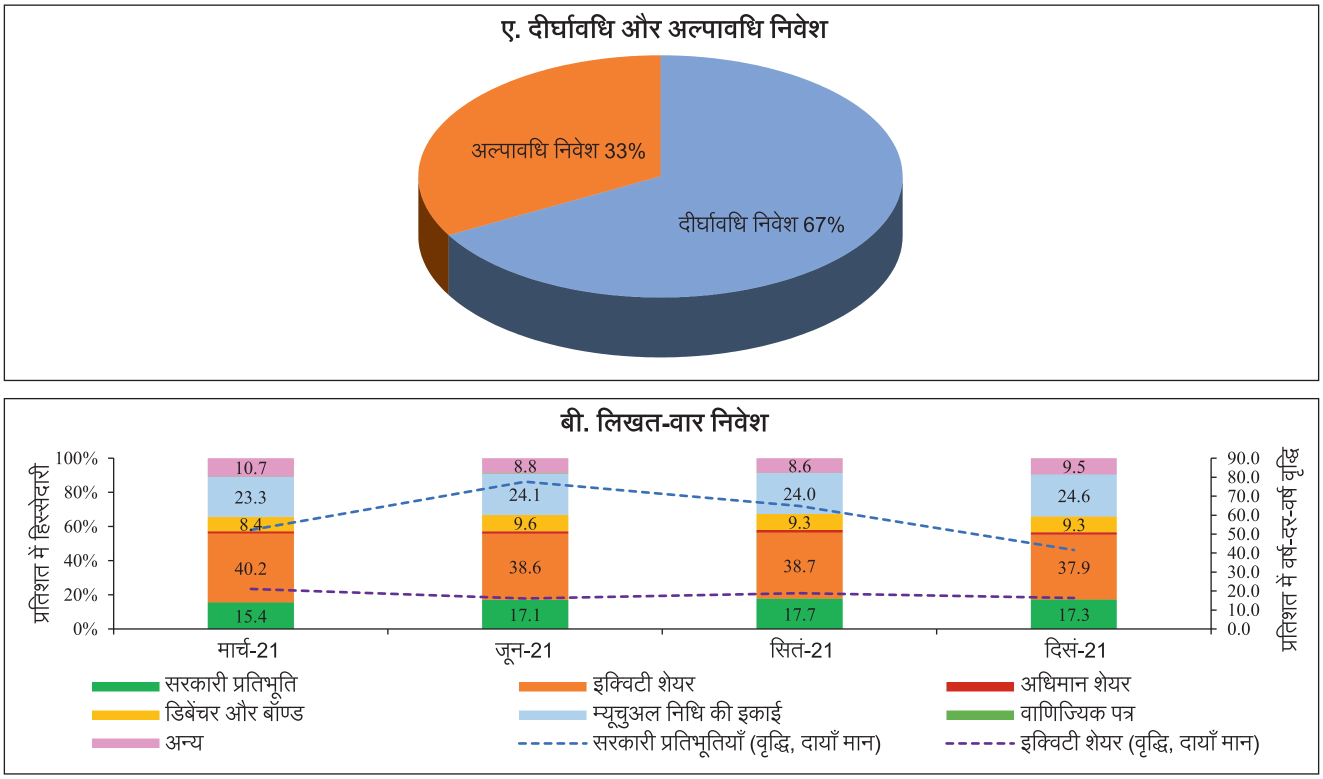

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

में आईसीसी और आईएफसी का योगदान लगभग 96 प्रतिशत था (चार्ट 12 बी)।

दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में दीर्घकालिक निवेश कुल निवेश पर हावी रहा (चार्ट 13 ए)। इस अवधि में, शेयर बाजार में तेजी और अपने उधार व्यवसाय से कम ब्याज आय को देखते हुए, एनबीएफसी ने इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों में अपना निवेश जारी रखा। दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 41.6 प्रतिशत बढ़ा। इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों में एनबीएफसी का निवेश कुल निवेश का आधे से अधिक हिस्सा है (चार्ट 13 बी)।

V. एनबीएफसी का तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर

तुलन-पत्र से इतर (ओबीएस) एक्सपोजर उन गतिविधियों को संदर्भित करता है, जिनमें ऐसे आकस्मिक वचनबद्धताएं या अनुबंध शामिल होते हैं, जो कंपनी के लिए शुल्क-आधारित आय प्रदान करते हैं, किन्तु पारंपरिक लेखा प्रक्रिया (घोष और नाचने, 2002) के तहत आस्ति या देयताओं के रूप में कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाये नहीं जाते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गारंटी, वचनबद्धताएं, ब्याज दर और विनिमय दर संविदाएं, आपाती सुविधाएं और ऋण व्यवस्थाएँ शामिल हैं। ओबीसी गतिविधियां एनबीएफसी को उनकी गैर-ब्याज आय को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक स्रोत प्रदान करती हैं। हालांकि, वे तुलन पत्र गतिविधियों (बीसीबीएस, 1986) के समान चलनिधि जोखिम, ऋण जोखिम और बाजार जोखिम भी पैदा करते हैं। 2018 से चरणबद्ध तरीके से एनबीएफसी पर लागू किया गया इंड-एएस फ्रेमवर्क इन जोखिमों पर विचार करता है और एनबीएफसी के लिए उचित प्रावधान की आवश्यकता निर्धारित करता है।

एनबीएफसी क्षेत्र में, महामारी से संबंधित वित्तीय अनिश्चितताओं के कारण कुल जोखिम-समायोजित गैर-वित्त पोषित एक्सपोजर में वित्तीय और अन्य गारंटी का हिस्सा दिसंबर 2020 में 19.1 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2021 में 38.7 प्रतिशत हो गया। दिसंबर 2021 के अंत तक सभी एनबीएफसी के कुल

चार्ट 14: एनबीएफसी क्षेत्र का गैर-निधिक एक्सपोजर/तुलन पत्र से इतर मदें

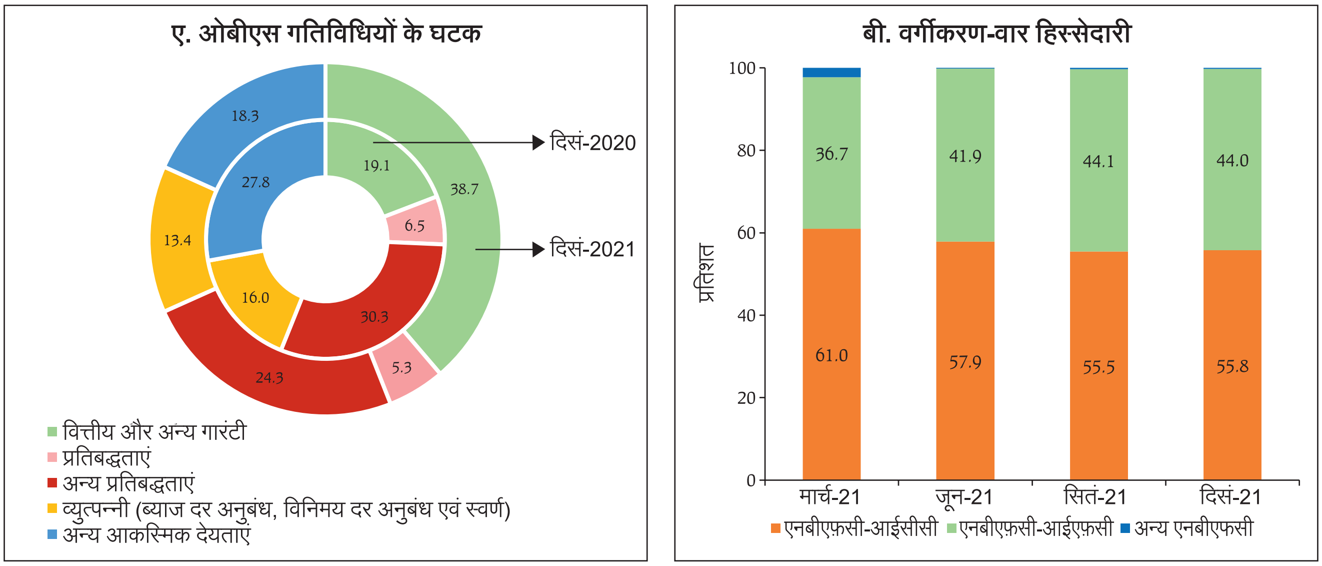

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

जोखिम-समायोजित गैर-वित्त पोषित एक्सपोजर का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा आईसीसी और आईएफसी का रहा (चार्ट 14)।

VI. वित्तीय प्रदर्शन, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता

एनबीएफसी क्षेत्र की लाभप्रदता में 2020-21 की इसी तिमाही की तुलना में 2021-22 की तीसरी तिमाही में सुधार हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत कम परिचालन व्यवधानों के साथ दूसरी लहर के प्रभाव को दूर कर दिया (चार्ट 15)। एनबीएफसी क्षेत्र का सबसे बड़ा खंड, एनबीएफसी-एनडी-एसआई ने निधि और शुल्क-आधारित आय में मजबूत वृद्धि दर्ज किया, जिसने उनकी लाभप्रदता को बढ़ा दिया। दूसरी ओर, एनबीएफसी-डी की आय में केवल मामूली वृद्धि हुई, लेकिन ब्याज व्यय में गिरावट के कारण लाभ में वृद्धि हुई।

एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता, जो महामारी की दूसरी लहर के कारण खराब हो गई थी, 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान स्थिर हो गई। हालांकि, जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात में 2021-22 की तीसरी तिमाही में तेजी देखी गई क्योंकि एनबीएफसी ने संशोधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंड[8] के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया। आस्ति गुणवत्ता में गिरावट संभवतः समाधान ढांचा 2.0 के तहत व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान की गई नियामकीय सहिष्णुता को वापस लेने के लिए भी जिम्मेदार थी, जिसमें एनबीएफसी को निर्देश दिया

चार्ट 15: एनबीएफसी का लाभप्रदता सूचकांक

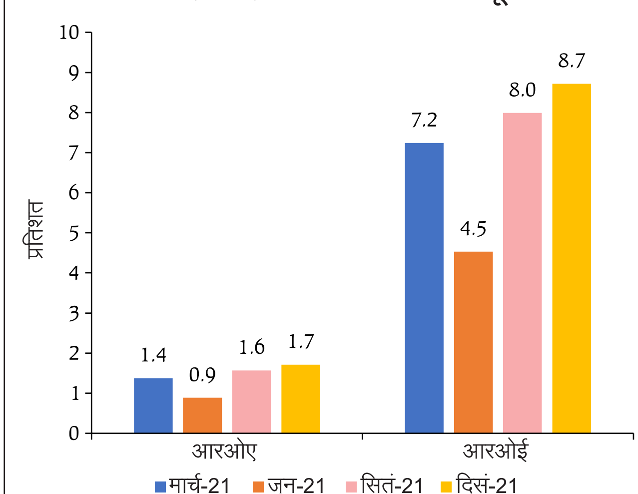

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. आरओए- आस्तियों से आय
3. आरओई – इक्विटी से आय

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

8 https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12194&Mode=0
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12230&Mode=0

गया था कि वे इसे केवल उन उधारकर्ताओं के लिए लागू करें जो कोविड-19 (सितंबर 2021 से लागू) [9] (चार्ट 16) के कारण दबाव में हैं। उम्मीद है कि ये उपाय लंबे समय में फायदेमंद होंगे क्योंकि एनबीएफसी बेहतर वसूली प्रक्रियाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बैंकों और एनबीएफसी के बीच नियामकीय अंतर को पाटने के दौरान अपने उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को प्रोत्साहित करेंगे।

मौजूदा विनियमों के अनुसार, प्रत्येक एनबीएफसी को अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों (तुलन पत्र और तुलन पत्र से इतर मदों सहित) के 15 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। एनबीएफसी की पूंजी की स्थिति को और मजबूत करने के लिए उनके लिए पीसीए ढांचे को 1 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी बनाया जाएगा। जोखिम सीमा का उल्लंघन करने वाली किसी भी एनबीएफसी (तीन मापदंडों, अर्थात् सीआरएआर, टियर -1 अनुपात और एनपीए) द्वारा परिभाषित) को पीसीए के तहत रखा जाएगा। वर्तमान में, एनबीएफसी क्षेत्र दिसंबर 2021 के अंत में 27.5 प्रतिशत के समग्र सीआरएआर के साथ इन नए नियमों का पालन करने के लिए सहज तरीके से तैयार है (चार्ट 17)।

चार्ट 16: एनबीएफसी की आस्तियों की गुणवत्ता

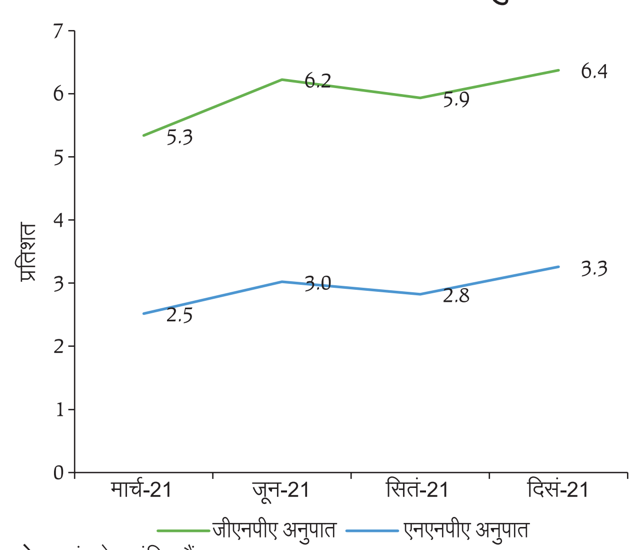

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

चार्ट 17: एनबीएफसी की पूंजीगत स्थिति

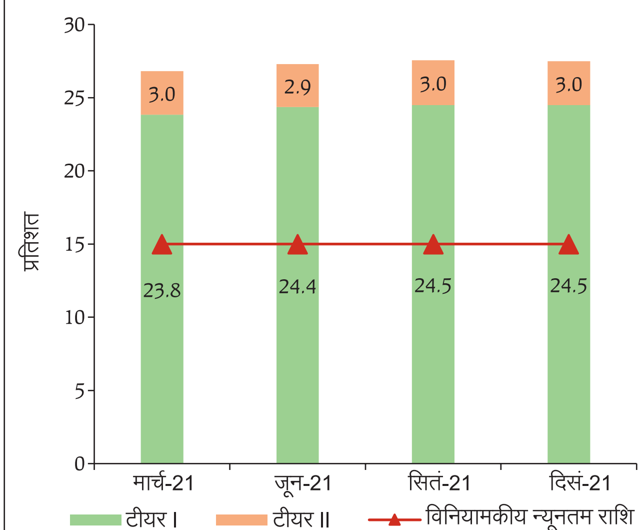

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

VII. एनबीएफसी के ऋण और एनपीए का क्षेत्रवार वितरण

एनबीएफसी ने खुदरा, सेवाओं और कृषि के बाद औद्योगिक क्षेत्र में अपने तुलन पत्र से सबसे बड़ी मात्रा में ऋण का उपयोग करना जारी रखा। दिसंबर 2020 के अंत (चार्ट 18 ए) की तुलना में 2021-22 (दिसंबर 2021 के अंत तक) में क्षेत्रवार ऋण वितरण काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। महामारी की दूसरी लहर के थमने के बाद आधार प्रभाव और आर्थिक गतिविधियों की बहाली के कारण सभी क्षेत्रों में उच्च विकास दर देखी गई। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित रहे सूक्ष्म और लघु तथा बड़े उद्योग में पुनरुद्धार के संकेत दिखाई दिए। सेवा क्षेत्र ने पिछली तीन तिमाहियों से ऋण वृद्धि में लगातार सुधार दिखाया है। सेवा क्षेत्र के भीतर, परिवहन परिचालकों, व्यापार और वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) में एक मजबूत गति से वृद्धि हुई। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण ने दिसंबर 2020 की तुलना में दिसंबर 2021 में 13.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन जारी रखा (चार्ट 18 बी)।

[9] 5 मई, 2021 को, रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए, जिसने एनबीएफसी को समाधान ढांचा 2.0 के तहत उधारकर्ताओं के लिए समाधान प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीतियां बनाने का निर्देश दिया।

चार्ट 18: एनबीएफसी का क्षेत्र वार ऋण

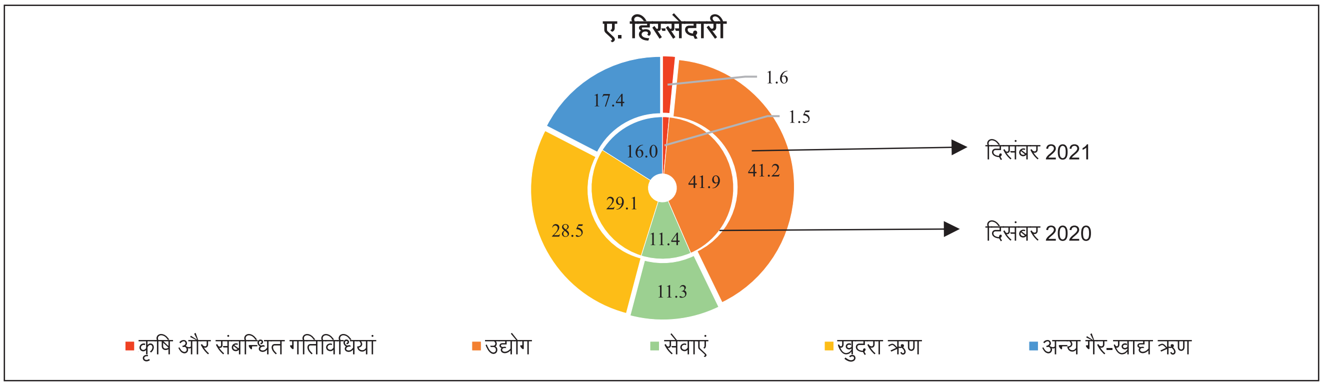

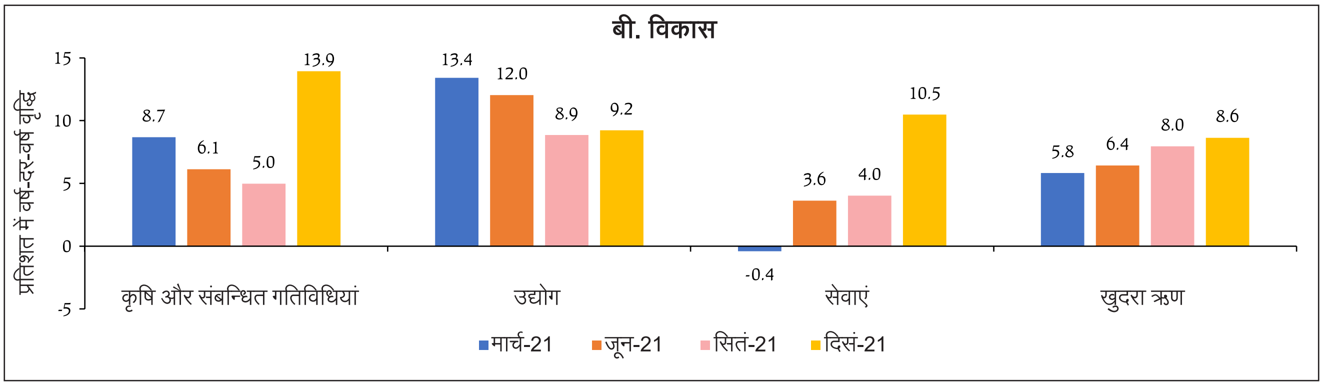

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं ।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

VII.1 उप-क्षेत्रवार ऋण और आस्ति गुणवत्ता

उद्योग के अंतर्गत, एनबीएफसी से सबसे बड़ा ऋण प्राप्त कर्ता था ऊर्जा[10], क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाली कई बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी की उपस्थिति थी। दिसंबर 2021 के अंत तक एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण में इसकी हिस्सेदारी 33.7 प्रतिशत थी। खुदरा क्षेत्र में, एनबीएफसी बड़े पैमाने पर वाहन ऋण उप-क्षेत्र में काम करती हैं, इसके बाद स्वर्ण ऋण उप-खंड है। सेवा क्षेत्र के तहत परिवहन परिचालन और सीआरई प्रमुख उप-खंड हैं। महामारी के दौरान आर्थिक मंदी ने सीआरई व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कंपनियों द्वारा घर से काम नीति पर निरंतर निर्भरता ने सीआरई उप-खंड (चार्ट 19 ए) की संभावनाओं को भी कम कर दिया।

दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में एनपीए में औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, इसके बाद क्रमशः खुदरा ऋण, सेवा और कृषि का स्थान रहा। उद्योग के अंतर्गत, दिसंबर 2021 के अंत में एनबीएफसी की कुल अशोध्य आस्तियों में विद्युत क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था, जो कुल एनबीएफसी एनपीए का 30 प्रतिशत था। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति[11] की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत क्षेत्र में एनपीए, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च ब्याज लागत, न्यायालयी मामलों, उधार देने वाले कंसोर्टियम द्वारा निर्णय में विलंब और कार्यशील पूंजी की कमी जैसे बाहरी कारणों से लागत में वृद्धि के कारण हैं। 2021-22 की तीसरी तिमाही के अंत में एनबीएफसी क्षेत्र के एनपीए में खुदरा क्षेत्र की हिस्सेदारी 31.3 प्रतिशत थी। खुदरा क्षेत्र में, वाहन ऋण ने ऋण में अपने हिस्से के सापेक्ष इस क्षेत्र में अधिक ह्रासित आस्तियों को जोड़ा,

[10] एनबीएफसी के पर्यवेक्षी विवरणी के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और सौर नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।

[11] ऊर्जा पर स्थायी समिति (2020-2021)।

चार्ट 19: एनबीएफसी के क्षेत्र वार ऋण का वितरण और एनपीए (दिसंबर 2021 के अंत में)

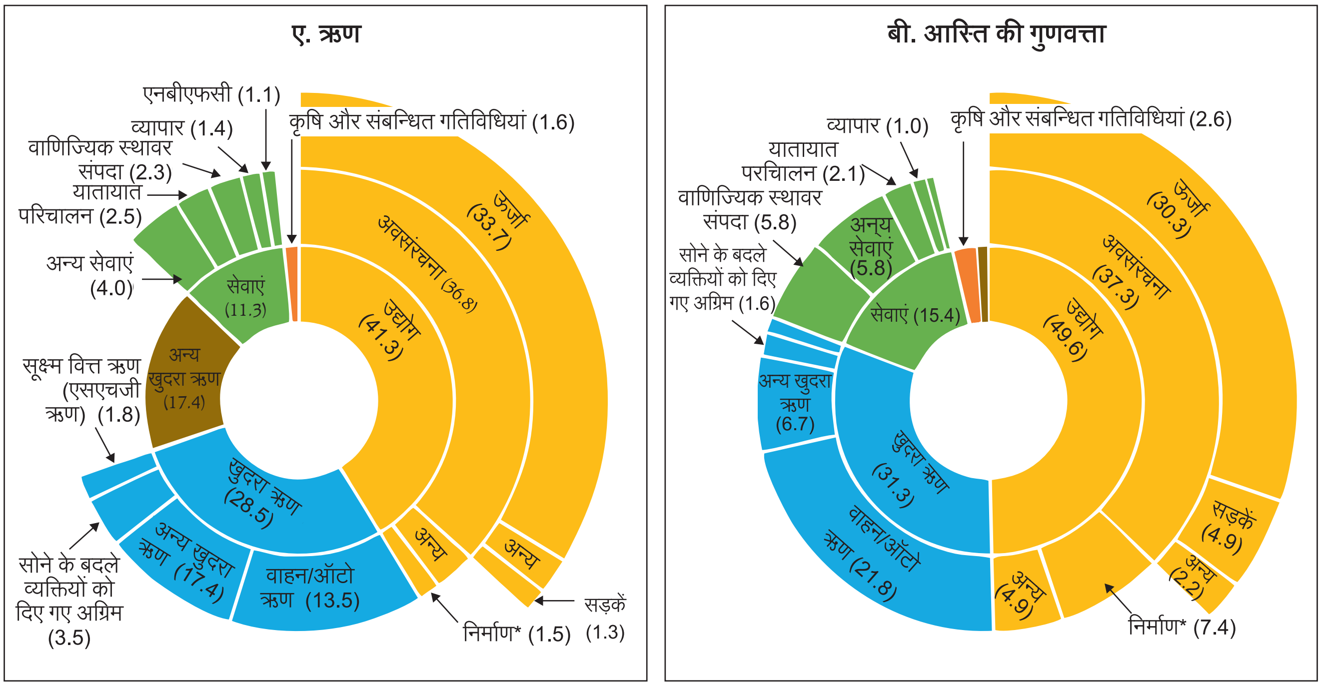

नोट: 1. सनबर्स्ट चार्ट उन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एनबीएफसी उधार देती हैं। प्रत्येक चार्ट खंड का आकार क्षेत्र के कुल ऋण/एनपीए में उसके हिस्से (कोष्ठक में उल्लिखित) के समानुपाती होता है।
*निर्माण में खनन और उत्खनन, बुनियादी धातु और धातु उत्पाद, सभी इंजीनियरिंग, वाहन और वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण शामिल हैं.
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

क्योंकि कम माल ढुलाई दरों और बढ़ती ईंधन लागत (मूडीज, 2021) से वाहन ऋण की कमाई क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सेवा क्षेत्र में, एनपीए में सबसे बड़ा हिस्सा सीआरई का था। अप्रैल 2020 में, रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए, जिसने एनबीएफसी को ऐसे सीआरई परियोजनाओं का पुनर्रचना की अनुमति दी गई, जिन्हें प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे कारणों से एक वर्ष की देरी का सामना करना पड़ा। इसके बाद, नियामकीय सहिष्णुता समाप्त होने के बाद सीआरई उप-क्षेत्र के एनपीए में 2021-22 की पहली तिमाही में काफी वृद्धि हुई और यह 2021-22 की तीसरी तिमाही (चार्ट 19 बी) तक अधिक बना रहा। नवंबर 2021 में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी के लिए नए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के साथ-साथ कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए नीतिगत उपायों को लागू करने से दिसंबर 2021 में सभी क्षेत्रों में एनपीए की बेहतर पहचान हुई।

VIII. निष्कर्ष

हालांकि वैश्विक एनबीएफसी आस्तियों में भारत का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एनबीएफसी क्षेत्र की हिस्सेदारी समय के साथ लगातार बढ़ी है। भारत में एनबीएफसी क्षेत्र (आस्ति आकार के संदर्भ में) की लगभग 45 प्रतिशत संस्थाएं ऐसी हैं, जो परिपक्वता और चलनिधि परिवर्तन से जुड़े ऋण मध्यस्थता में संलग्न हैं और इसलिए, वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर, दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में, एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तेज गति से बढ़ी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कम होने के साथ 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में एनबीएफसी क्षेत्र की आधारभूत स्थिति में भी सुधार हुआ है। दूसरी ओर, 2021-22 की तीसरी तिमाही में इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिसके लिए आंशिक रूप से एनबीएफसी को आईआरएसीपी

मानदंडों में बदलाव के साथ-साथ व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए समाधान ढांचा - 2.0 के तहत नियामकीय छुट को लागू करने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

मजबूत पूंजी बफर, पर्याप्त प्रावधान और उनके बही-खातों में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के साथ, एनबीएफसी विस्तार के लिए तैयार हैं। फिर भी, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, एनबीएफसी को मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के कारण बढ़ती उधार लागत से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जबकि एनबीएफसी ने अपनी पहुंच और नए ग्राहकों के अधिग्रहण में सुधार के लिए डिजिटल चैनलों का लाभ उठाकर अपने व्यापार मॉडल को बड़े पैमाने पर संरेखित किया है, यह छोटे एनबीएफसी के लिए एक चुनौती का कार्य हो सकता है, जिन्हें अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। एनबीएफसी को साइबर अपराधों के बारे में अधिक सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। एक अन्य चुनौती हितधारकों का विश्वास हासिल करने के लिए मजबूत अभिशासन और जोखिम प्रबंधन मानकों का निर्माण करना है।

नियामकीय मोर्चे पर एनबीएफसी के परिचालन के बढ़ते पैमाने और जटिलता के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली में अन्य संस्थाओं के साथ उनके बढ़ते अंतर-संबंध को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने एसबीआर की परिकल्पना की है। इन नियमों के तहत, आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करते हुए, जोखिम और संचालन के पैमाने के आधार पर एक गतिविधि-आधारित विनियमन से ध्यान स्थानांतरित कर दिया गया है। पीसीए और आईआरएसीपी मानदंडों जैसी बैंक की तरह नियामकीय पहल से बैंकों की तुलना में एनबीएफसी के विनियमन में अंतर को और कम करेगी। इन विनियमों से आने वाले समय में एनबीएफसी क्षेत्र के मजबूत होने की उम्मीद है।

References

BCBS. (1986). *The management of banks' off-balance-sheet exposures: a supervisory perspective.* Retrieved from Bank for International Settlements: https://www.bis.org/publ/bcbsc134.htm

Bowman, J., Hack, M., & Waring, M. (2018). *Non-bank Financing in China, Bulletin March 2018.* Retrieved from Reserve Bank of Australia: https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2018/mar/pdf/non-bank-financing-in-china.pdf

CGFS. (2018). *Structural changes in banking after the crisis.* Committee on the Global Financial System, BIS.

Claessens, S., Dell'Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L. (2010, February). *Lessons and Policy Implications from the Global Financial Crisis.* Retrieved from International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1044.pdf

FSB. (2021). *Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation.* Financial Stability Board (FSB).

FSR. (2021). *Financial Stability Report, December 2021.* Reserve Bank of India. Retrieved from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs//PublicationReport/Pdfs/FSRDEC2021_FULL2D99E6548CD0478CA90EE717F2B85D45.PDF

Ghosh, S., & Nachane, D. (2002). Off-balance sheet activities in banking: Theory and Indian experience. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA).*

IMF. (1998). *IMF Staff Country Report No. 98/112.* Washington D.C.: International Monetary Fund.

Kannan, R., Shanmugam, K., & Bhaduri, S. (2019). *Non-Banking Financial Companies Role in India's Development: A Way Forward.* Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Kodres, L. (2012). *Economic Premise, September 2012.* Retrieved from International Monetary Fund (IMF): https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/52-shadow-banking.htm

Moody's. (2021). *Auto ABS – India: Coronavirus resurgence will hurt performance.*

RBI. (2019-20). *Report on Trend and Progress of Banking in India.*

RBI. (2021). *Chasing the Horizon, November 2021.* Retrieved from Bulletin: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20626

RBI. (2022). *State of the Economy, January 2022.* Retrieved from Bulletin: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=20749

*भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्काल निगरानी**

आलेख कम से कम संभव अंतराल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीनतम विकास का पता लगाने के लिए साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक प्रस्तुत करता है। दैनिक/साप्ताहिक संकेतकों का उपयोग करते हुए दो अलग-अलग साप्ताहिक सूचकांक विकसित किए गए हैं - (i) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन को दर्शाने वाले गतिकी कारक मॉडल का उपयोग करते हुए एक 7-संकेतक साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक (डब्ल्यूएआई); (ii) एक 15-संकेतक साप्ताहिक प्रसार सूचकांक (डबल्यूडीआई) एक क्रमिक आधार पर दिशात्मक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो मॉडल-आधारित डबल्यूएआई की सहायता करता है। डबल्यूएआई ने फरवरी 2022 से रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण हुए हालिया व्यवधानों के बाद महामारी के वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव का पता लगाया।

I. भूमिका

कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने आजीविका की सुरक्षा के लिए त्वरित नीतिगत कार्रवाइयों का आह्वान किया और तेजी से सुधार में मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था का समय पर मूल्यांकन किया। महामारी के कारण तेजी से नवाचार और उत्पादन प्रक्रियाओं के पुनर्गठन के साथ, मौजूदा आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। इसलिए इसके पूरक अधिमानतः कम समय अंतराल के साथ वाले अतिरिक्त डेटा की ज़रूरत पड़ी।

केंद्रीय बैंकों के लिए, विशेष रूप से मौद्रिक नीति निर्णयों में सटीक निर्णय लेने के लिए आर्थिक गतिविधि पर समय पर जानकारी महत्वपूर्ण है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति के प्रत्येक दौर के दौरान, निर्णय लेने के लिए निर्धारित उपलब्ध सूचना अत्यधिक अतुल्यकालिक पाई गई है। द्वैमासिक नीति के आंकड़ों के संदर्भ में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तिमाही और पारंपरिक उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) मासिक आधार पर एक या दो महीने के अंतराल के साथ उपलब्ध है (सारणी 1)। नीति के अगस्त और फरवरी दौर के दौरान, सूचना अंतर विशेष रूप से बड़ा है क्योंकि नवीनतम उपलब्ध आधिकारिक जीडीपी डेटा दो तिमाहियों[1] से पिछड़ जाएगा। इसके अलावा, पूर्ववर्ती तिमाही के लिए निर्धारित एचएफआई पूरी तरह से पूर्ण नहीं है और संदर्भ तिमाही के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

डिजिटलीकरण और स्वचालन में प्रगति का लाभ उठाते हुए, मंत्रालय, नियामक निकाय और अन्य निजी एजेंसियां उच्च आवृत्ति पर अतिरिक्त आर्थिक डेटा प्रकाशित कर रही हैं। लगभग वास्तविक समय में उपलब्ध ऐसे दैनिक/साप्ताहिक संकेतक, नीति

सारणी 1: मौद्रिक नीति के लिए सूचना उपलब्धता

दौर	संदर्भ तिमाही	संकेतक उपलब्धता				साप्ताहिक सूचकांक (तक संपूर्ण)
		जीडीपी	मासिक एचएफ़आई			
			संपूर्ण	आंशिक	अल्प	
अप्रैल (टी)	ति1 (टी)	ति 3 (टी-1)	जनवरी	फरवरी	मार्च	मार्च
जून (टी)	ति 1 (टी)	ति 4 (टी-1)	-	अप्रैल	मई	मई
अगस्त (टी)	ति 2 (टी)	ति 4 (टी-1)	अप्रैल, मई	जून	जुलाई	जुलाई
अक्टूबर (टी)	ति3 (टी)	ति 1 (टी)	जुलाई	अगस्त	सितंबर	सितंबर
दिसंबर (टी)	ति3 (टी)	ति 2 (टी)	-	अक्टूबर	नवंबर	नवंबर
फरवरी (टी)	ति4 (टी)	ति 2 (टी)	अक्टूबर , नवंबर	दिसंबर	जनवरी	जनवरी

टिप्पणी: 1. टी चालू वित्त वर्ष को दर्शाता है।
2. लेखकों का संकलन।

* यह आलेख राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुपम प्रकाश, चैताली भौमिक और ईशु ठाकुर द्वारा तैयार किया गया है। श्री संजय हांसदा, परामर्शदाता, को उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया जाता है। अमित कुमार द्वारा प्रदान किए गए डेटा समर्थन की भी सराहना की जाती है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] अप्रैल एमपीसी दौर के दौरान, नवीनतम जीडीपी अनुमान दो तिमाहियों के अंतराल यानी क्यू3 (टी-1) तक उपलब्ध हैं। हालांकि, पिछले पूर्ण वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों का उपयोग करके अनुमानित क्यू4 (टी-1) के लिए अनुमानित डेटा की उपलब्धता अंतराल को एक तिमाही तक कम कर देती है।

से पहले के सप्ताह तक सूचना की आपूर्ति करके मौद्रिक नीति दौर के दौरान सूचना अंतर को पाटने की क्षमता रखते हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आलेख कम से कम संभावित अंतराल के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीनतम विकास का पता करने के लिए साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक प्रस्तुत करता है। दैनिक/साप्ताहिक संकेतकों का उपयोग करते हुए दो अलग-अलग साप्ताहिक सूचकांक विकसित किए गए हैं - (i) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन को दर्शाने वाले गतिकी कारक मॉडल का उपयोग करते हुए एक 7-संकेतक साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक (डब्ल्यूएआई); (ii) एक 15-संकेतक साप्ताहिक प्रसार सूचकांक (डबल्यूडीआई) एक क्रमिक आधार पर दिशात्मक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो मॉडल-आधारित डबल्यूएआई की सहायता करता है। डब्ल्यूडीआई प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव की दिशा पर एक समग्र तस्वीर पेश करने के लिए गतिविधि में अनुक्रमिक आंदोलन प्रस्तुत करता है। ये सूचकांक आर्थिक चर के चयनित सेट के लिए साप्ताहिक प्रक्षेपवक्र प्रदान करने के अलावा तिमाही जीडीपी के एक मजबूत संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं।

शेष आलेख इस प्रकार संरचित है - खंड II अन्य केंद्रीय बैंकों और निजी संगठनों द्वारा विकसित मौजूदा साप्ताहिक सूचकांकों का अवलोकन प्रदान करता है, इसके बाद खंड III में घटक संकेतकों का विवरण दिया गया है। खंड IV साप्ताहिक सूचकांकों के निर्माण में प्रयुक्त कार्य-प्रणाली पर चर्चा करता है। खंड V सूचकांकों के प्रक्षेपवक्र और महत्वपूर्ण समष्टिआर्थिक संकेतकों, जैसे जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के साथ उनके संबंध को प्रस्तुत करता है। खंड VI उपयोगिता, मौजूदा सीमाओं और भविष्य के संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

II. केंद्रीय बैंकों में साप्ताहिक ट्रैकिंग

केंद्रीय बैंक, थिंक टैंक और अन्य स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने महामारी से पहले ही उपलब्ध एचएफआई के साथ आर्थिक गतिविधि का अनुमान/पूर्वानुमान लगाने के लिए सूचकांक बनाने के अभ्यास में खुद को लगा लिया। हालाँकि, महामारी के प्रकोप के दौरान अचानक आर्थिक विकास के मद्देनजर एक उपयुक्त सूचकांक की खोज तेज हो गई। अमेरिका में, फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क ने एक साप्ताहिक आर्थिक सूचकांक (डबल्यूईआई) विकसित किया, जिसमें 10 एचएफ़आई का एक सेट शामिल था (लुईस और अन्य, 2020)। डबल्यूईआई को प्रत्येक गुरुवार को पूर्ववर्ती सप्ताह तक के डेटा के साथ अपडेट किया जाता है, जबकि पहले के सप्ताहों के लिए संशोधन, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाता है। एनवाई फेड का डब्ल्यूईआई मुख्य रूप से एक निश्चित विंटेज पर नवीनतम उपलब्ध डेटासेट के आधार पर वास्तविक आर्थिक गतिविधि की एक साप्ताहिक तस्वीर देता है, जिसे तिमाही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए भी उपयोग किया जाता है।

ड्यूश बुंडेसबैंक द्वारा जर्मनी के लिए बनाया गया एक अपरंपरागत साप्ताहिक आर्थिक गतिविधि सूचकांक तिमाही जीडीपी (एरास्लान और गोट्ज़, 2020) का पता लगाने के लिए उच्च आवृत्ति चर का उपयोग करता है। इसने मिश्रित आवृत्ति डेटासेट का उपयोग किया जिसमें मासिक औद्योगिक उत्पादन और नवीनतम जीडीपी अनुमान के साथ आसानी से उपलब्ध उच्च आवृत्ति चर शामिल थे। उच्च आवृत्ति संकेतकों की 13-सप्ताह की वृद्धि दर की गणना की जाती है और मिश्रित-आवृत्ति डेटासेट के भीतर एक सामान्य कारक की गणना प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) का उपयोग करके की जाती है। सूचकांक को 13-सप्ताह की वृद्धि दर के रूप में देखा जाता है और किसी दिए गए तिमाही के अंत में, सूचकांक के मूल्यों को परिवर्तन की तिमाही-दर-तिमाही दर के रूप में (अनुमानित रूप में) व्याख्या की जा सकती है।

यूरोज़ोन की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं फ़्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और स्पेन (यूरोज़ोन आउटपुट का 83 प्रतिशत शामिल) के आंकड़ों के आधार पर, आईएनजी साप्ताहिक आर्थिक गतिविधि सूचकांक (आईएनजी-डब्ल्यूएआई) का निर्माण आईएनजी द्वारा यूरोज़ोन की आर्थिक गतिविधि का पता करने के लिए किया गया है। गूगल खोज, गूगल गतिशीलता, उत्सर्जन, ऊर्जा खपत और ट्रकिंग माइलेज पर ओपन एक्सेस डेटा और एनवाई फेड और बुंडेसबैंक के समान एक कार्य-प्रणाली का उपयोग करते हुए, सूचकांक पिछले सप्ताह की आर्थिक गतिविधि को पूरे डेटा श्रृंखला के औसत की तुलना में दिखाता है।

ओईसीडी तीन साप्ताहिक ट्रैकर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से 46 देशों (भारत सहित) की आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक

समय पर नज़र रखने में भी संलग्न है, जिनमें से एक को 2021[2] के अंत में बंद कर दिया गया था जबकि अन्य दो को अपडेट किया जाना जारी है। दो सक्रिय ट्रैकर्स में से एक, पिछले वर्ष के समान सप्ताह के सापेक्ष साप्ताहिक जीडीपी का अनुमान प्रदान करता है। दूसरा, दो साल पहले के समान सप्ताह के सापेक्ष साप्ताहिक जीडीपी का अनुमान प्रदान करता है, यानी 104-सप्ताह का अंतर। ट्रैकर्स की गणना गूगल ट्रेंड्स डेटा के एक पैनल में मशीन लर्निंग तकनीक को लागू करके और खोज व्यवहार पर जानकारी एकत्र करके की जाती है। एल्गोरिथ्म गूगल खोज श्रेणियों और संबंधित कीवर्ड के संग्रह के आधार पर विभिन्न चर के लिए जानकारी निकालता और संकलित करता है और उनका विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत समूहीकरण करता है जैसे खपत (जैसे, "खाना और पीना", "ऑटो और वाहन", "घरेलू उपकरण"), श्रम बाजार (जैसे "बेरोजगारी", "बेरोजगारी लाभ", "नौकरियां"), आवास ("अचल आस्ति एजेंसी", "बंधक"), व्यापार सेवाएं (जैसे, "उद्यम पूंजी"), दिवालियापन (जैसे, "दिवालियापन"), औद्योगिक गतिविधि (जैसे, "समुद्री परिवहन", "कृषि उपकरण"), व्यापार (जैसे, "निर्यात", "माल") के साथ-साथ आर्थिक भावना (जैसे, "मंदी") और गरीबी (जैसे, "खाद्य बैंक")

भारत में, सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आपातकालीन नीति कार्यों के तहत आर्थिक गतिविधि में प्रगति का पता करने के लिए महामारी के दौरान एचएफ़आई की निगरानी की। कुछ नाम हैं, सिटी बैंक द्वारा संकीर्ण सुधार सूचकांक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा व्यापार गतिविधि सूचकांक और नोमुरा इंडिया व्यापार मोचन सूचकांक (निबरी), महामारी के दौरान लोकप्रिय हुए। फरवरी 2020 के स्तर (100 के रूप में माना जाता है) की तुलना में, निबरी ने कार्यस्थल और खुदरा और मनोरंजन स्थलों के आसपास गतिशीलता पर गूगल के दैनिक सामुदायिक डेटा का उपयोग करके गतिविधि की स्थिति, ड्राइविंग गतिशीलता के लिए एप्पल मैप का सूचकांक, श्रम भागीदारी दर पर साप्ताहिक सर्वेक्षण और साप्ताहिक बिजली की मांग में मौसमी रूप से समायोजित रुझान दिखाया। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रेरित प्रतिबंधों के कारण, यह पाया गया कि अप्रैल 2020 के अंत तक गतिविधि लगभग 56 प्रतिशत अंक गिरकर 44.4 के निचले स्तर पर आ गई।

[2] ओईसीडी ने एक प्रतितथ्यात्मक ट्रैकर बनाया, जो साप्ताहिक जीडीपी और संकट-पूर्व जीडीपी प्रवृत्ति के बीच प्रतिशत अंतर को प्रस्तुत करता है। संकट-पूर्व जीडीपी प्रक्षेपवक्र नवंबर 2019 में किए गए ओईसीडी पूर्वानुमानों द्वारा अनुमानित है और 2021 के अंत तक उपलब्ध है।

III. डेटा विवरण

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कुल 17 संकेतकों पर विचार किया गया है, जिन्हें मोटे तौर पर पांच बकेट में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि सॉफ्ट, श्रम बाजार, मांग/बिक्री, गतिशीलता और भुगतान (सारणी 2)।

सारणी 2 : उच्च आवृति संकेतक

क्रम सं.	श्रेणी	संकेतक	आवृत्ति	स्रोत
1	नरम	गूगल रुझान	दैनिक	गूगल
2		उपभोक्ता भावना सूचकांक	साप्ताहिक	सीएमआईई
3		उपभोक्ता अपेक्षा सूचकांक	साप्ताहिक	
4		वर्तमान आर्थिक स्थिति सूचकांक	साप्ताहिक	
5	श्रम	बेरोजगारी दर (%)	साप्ताहिक	
6		श्रम भागीदारी दर (%)	साप्ताहिक	
7	मांग/बिक्री	विद्युत उत्पादन	दैनिक	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पोसोको)
8		मोटर वाहन पंजीकरण	साप्ताहिक	वाहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
9		रेलवे माल लदान	दैनिक	रेल मंत्रालय
10		हवाई माल यातायात	दैनिक	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
11	गतिशीलता	रेल यात्री	दैनिक	रेल मंत्रालय
12		गतिशीलता (खुदरा, किराना, उद्यान, पारगमन और कार्यस्थल)	दैनिक	गूगल
13		विमान यातायात	दैनिक	एएआई
14		विमान पत्तन पर आने वालों की संख्या	दैनिक	एएआई
15	भुगतान	आरटीजीएस	दैनिक	आरबीआई
16		खुदरा भुगतान	दैनिक	
17		एटीएम और एईपीएस आहरण	दैनिक	

टिप्पणी: खुदरा भुगतान में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) भुगतान शामिल हैं।।

चार्ट 1: गूगल रुझान

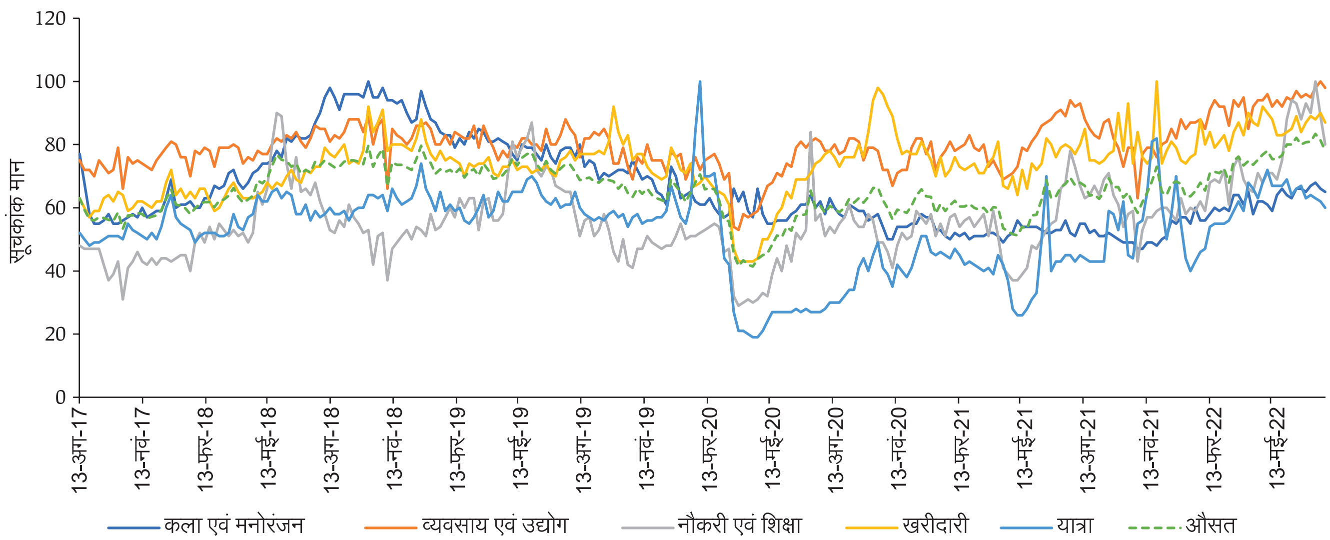

स्रोत: गूगल।

17 संकेतकों की प्रारंभिक सूची में, कई संकेतकों के बीच वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए लंबी अवधि की श्रृंखला उपलब्ध नहीं थी क्योंकि कई संकेतक महामारी के प्रकोप के दौरान या बाद में पहली बार जारी किए गए थे। तदनुसार, सूचकांकों के लिए गए संकेतक सारणी 2 में प्रस्तुत सूची का एक उपसमुच्चय हैं। सॉफ्ट संकेतक जैसे, गूगल रुझान डेटा और सीएमआईई भावना सूचकांक (उपभोक्ता भावना, वर्तमान आर्थिक स्थिति और उपभोक्ता अपेक्षाएं) दोनों 2017 के बाद से (चार्ट 1 और 2) उपलब्ध हैं, उनमें पहले लॉकडाउन (मार्च-अप्रैल 2020) के दौरान तेज गिरावट देखी गई। भावना सूचकांक ने विशेष रूप से लगभग 60 सूचकांक बिंदु की भारी गिरावट देखी। भावना में सुधार, जो हालांकि ऊपर की ओर है, अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से काफी नीचे है।

चार्ट 2: सीएमआईई भावना सूचकांक

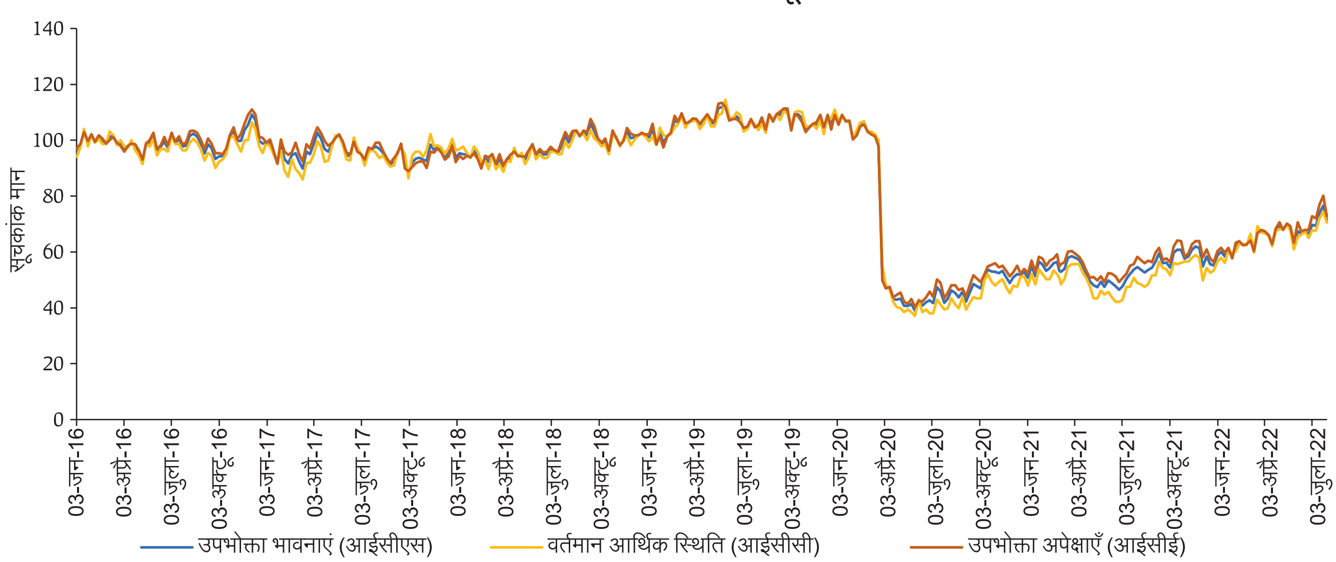

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट 3: सीएमआईई श्रम बाज़ार

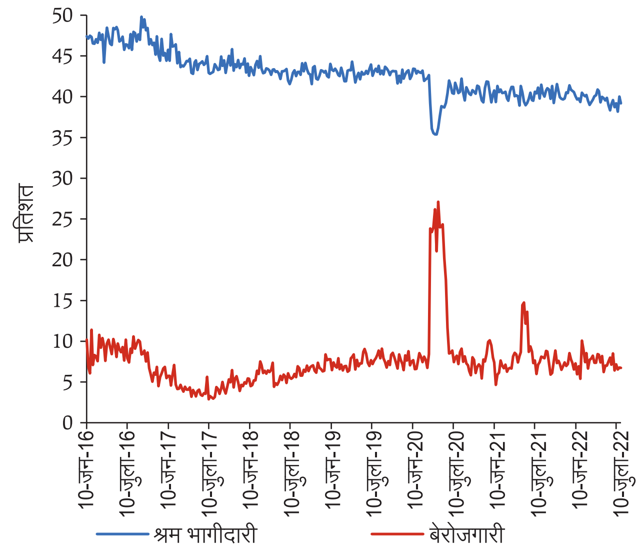

स्रोत: सीएमआईई।

चार्ट 4: रेल यात्री एवं मालभाड़ा

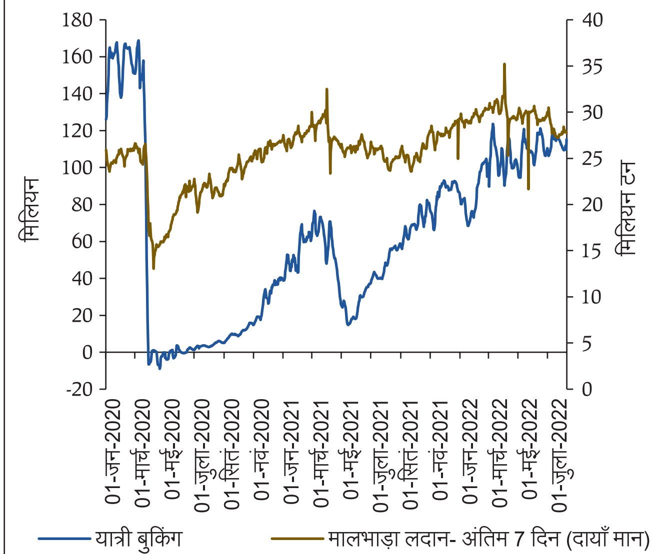

स्रोत: रेल मंत्रालय; और सीईआईसी।

श्रम बाजार की स्थितियों का दो संकेतकों के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है - बेरोजगारी दर और श्रम भागीदारी दर। हालांकि पहली और दूसरी लहर के दौरान अल्पकालिक बढ़ोतरी के अलावा बेरोजगारी दर में कोई दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही है, हाल के दिनों में श्रम भागीदारी में धीरे-धीरे गिरावट आई है (चार्ट 3)। मॉडल के लिए, बेरोज़गारी दर के पारस्परिक को बेरोज़गारी और उत्पादन के बीच के व्युत्क्रम संबंध को नियंत्रित करने के लिए माना गया है। महामारी और संबंधित अनिश्चितता के कारण परिवहन क्षेत्र में, भारतीय रेलवे की यात्री बुकिंग और माल ढुलाई में भी भारी गिरावट आई है। माल ढुलाई ने हालांकि तेजी से सुधार दर्ज किया (चार्ट 4)।

वाहन पंजीकरण और विद्युत उत्पादन खपत मांग के दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जबकि पूर्व प्रत्येक वर्ष त्योहारी मौसम (विशेष रूप से अक्टूबर-नवंबर के दौरान) में चरम पर होता है, विद्युत उत्पादन पिछले वर्षों में ऊपर की ओर बढ़ने के अलावा, उच्च मांग को पूरा करने के लिए हर गर्मियों के दौरान बढ़ता है (चार्ट 5 और 6)।

एक बाजार अर्थव्यवस्था में लेनदेन करने और निपटान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भुगतान डेटा अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि का पता लगाने के एक अपरंपरागत स्रोत का काम करता है (आरबीआई, 2021)। आरटीजीएस लेन-देन

चार्ट 5: पंजीकृत मोटर वाहन

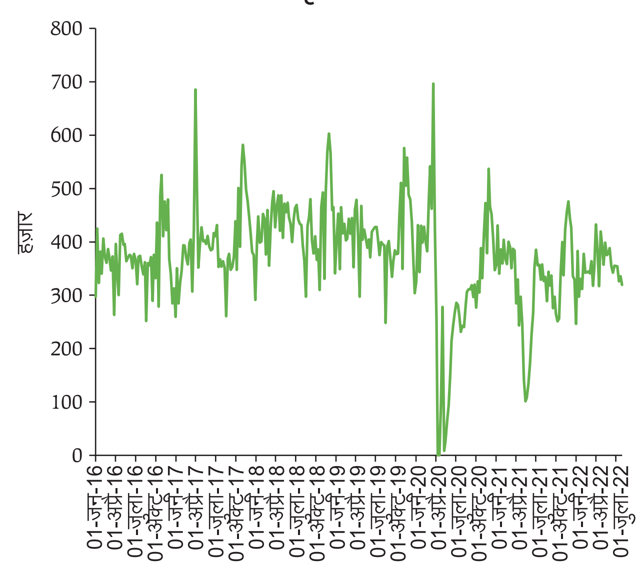

स्रोत: वाहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

चार्ट 6: विद्युत उत्पादन

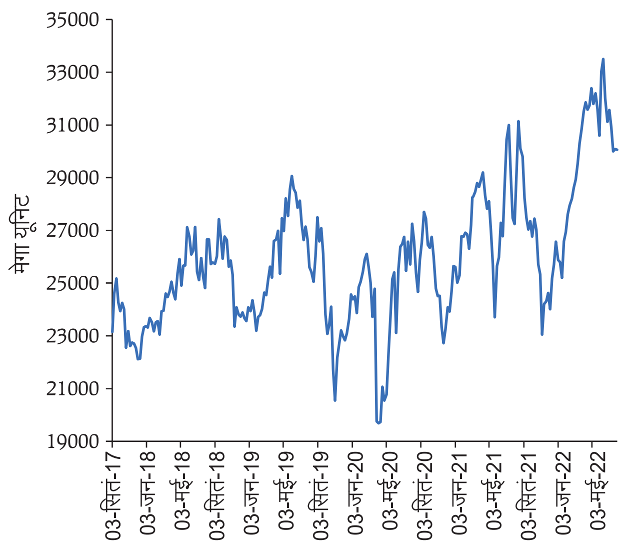

स्रोत: पोसोको; और सीईआईसी।

चार्ट 8: खुदरा भुगतान

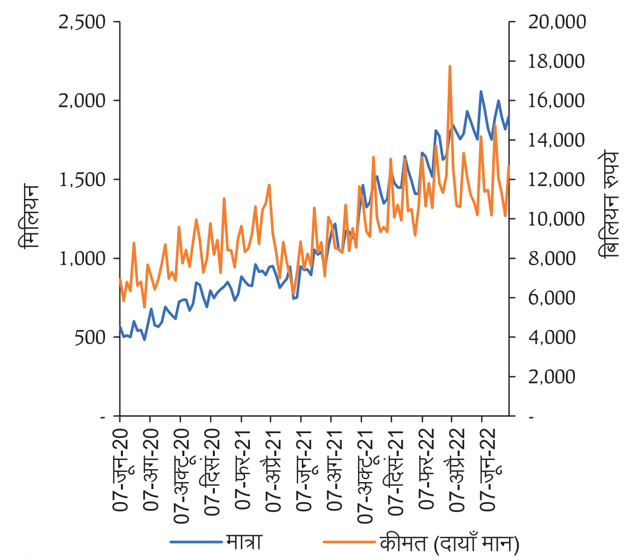

स्रोत: आरबीआई।

(ग्राहक और इंटरबैंक), जो डिजिटलीकरण में वृद्धि के कारण ऊपर की ओर रुझान दिखा रहा है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक मौसमी वृद्धि दिखाता है (चार्ट 7)। खुदरा भुगतान (मूल्य और मात्रा) डेटा जिसे आरबीआई ने जून 2020 से प्रकाशित करना शुरू किया था, वह भी इसी तरह की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। महीने के अंत में अधिकांश भुगतान किए जाने के साथ, हर महीने के अंत में खुदरा भुगतान के मूल्य और मात्रा दोनों में उछाल देखा जा सकता है (चार्ट 8)। महामारी के दौरान आघात झेलने के बावजूद, दोनों डेटा श्रृंखलाओं ने अच्छी तरह से वापसी की है। 2021-22 की पहली तिमाही में गिरावट के बाद एटीएम से नकद निकासी में अच्छा सुधार हुआ (चार्ट 9)।

जून 2021 के बाद से एयर कार्गो, विमान उड़ान और हवाई अड्डे पर आने वालों की संख्या के आंकड़े दैनिक आधार पर

चार्ट 7: आरटीजीएस
(ग्राहक और इंटरबैंक)

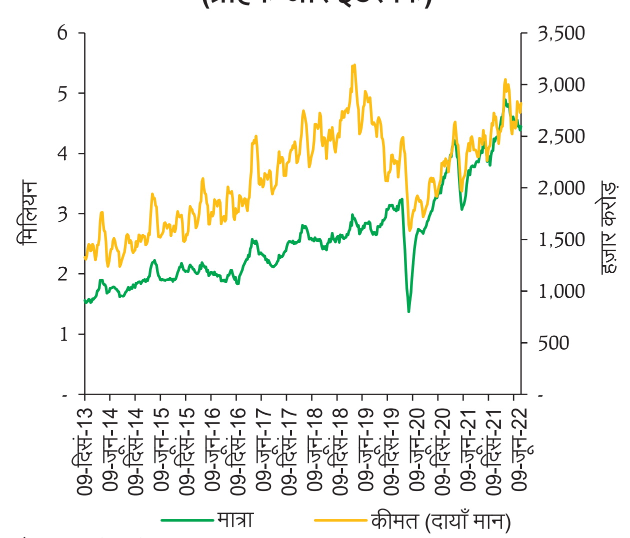

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 9: नकद आहरण

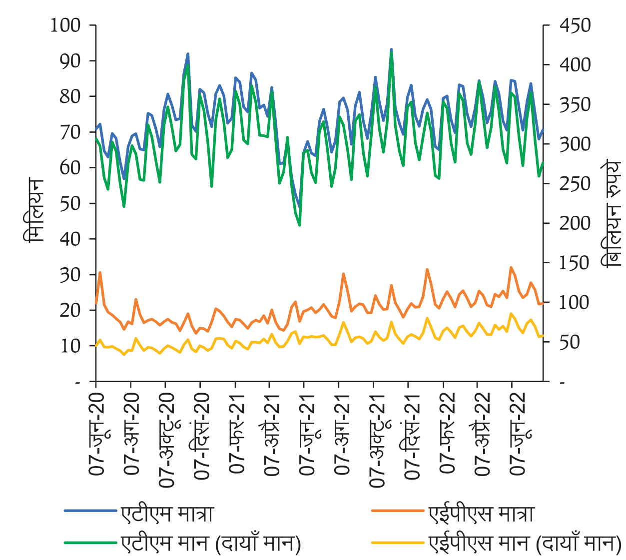

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 10: हवाई यातायात

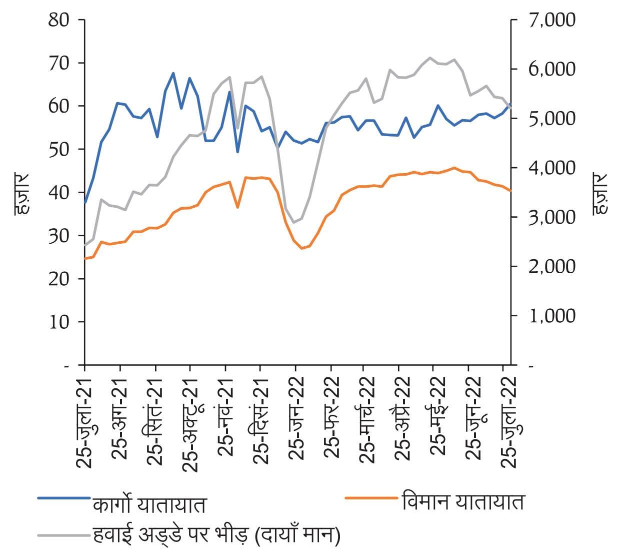

स्रोत : एएआई; और सीईआईसी।

उपलब्ध हैं (चार्ट 10)। चूंकि गतिक कारक मॉडल (डीएफ़एम) के लिए अवधि बहुत कम है, इसलिए इन डेटा श्रृंखलाओं का उपयोग केवल प्रसार सूचकांक में किया गया है। नियत समय में अधिक डेटा बिंदुओं को एकत्र करने के साथ, हवाई यातायात डेटा का उपयोग डबल्यूएआई के लिए डीएफ़एम में भी किया जा सकता है।

संकेतकों के स्थिरता गुणों के परीक्षण से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश पहले अंतर पर स्थिर हैं (सारणी 3)।

वर्ष-दर-वर्ष वास्तविक जीडीपी और आईआईपी वृद्धि के साथ मासिक और तिमाही आवृत्ति पर एकत्रित संकेतकों की वृद्धि दर के बीच सहसंबंध गुणांक की जांच मॉडल में शामिल करने से पहले की गई है। लगभग सभी संकेतकों ने अपेक्षित संकेतों के साथ लक्ष्य चरों के साथ मजबूत सहसंबंध प्रदर्शित किया। आरटीजीएस भुगतान, विद्युत उत्पादन, गूगल ट्रेंड और वाहन पंजीकरण के मामले में सहसंबंध का परिमाण विशेष रूप से मजबूत है (सारणी 4ए और 4बी) ।

सारणी 3: चयनित संकेतकों की स्थिरता

क्र. सं.	संकेतक	प्रसार सूचकांक	डीएफ़एम-7	चर परिवर्तन
1	गूगल रुझान		√	पहला अंतर
2	उपभोक्ता भावना सूचकांक (सीएसईएनटी)	√	√	स्तर
3	बेरोजगारी दर (अन रेट)	√	√	स्तर
4	श्रम बल भागीदारी दर (एलएफ़पीआर)	√	√	स्तर
5	विद्युत उत्पादन (इलेक्जेन)	√	√	पहला अंतर
6	मोटर वाहन पंजीकरण (एमवीआरईजी)	√	√	पहला अंतर
7	रेलवे माल लदान	√		पहला अंतर
8	एयर कार्गो ट्रैफिक	√		पहला अंतर
9	रेल यात्री	√		पहला अंतर
10	गतिशीलता (खुदरा, किराना, पार्क, पारगमन और कार्यस्थल)			स्तर
11	विमान यातायात	√		पहला अंतर
12	हवाई अड्डे पर भीड़	√		पहला अंतर
13	आरटीजीएस	√	√	पहला अंतर
14	खुदरा भुगतान	√		पहला अंतर
15	एटीएम और एईपीएस निकासी	√		पहला अंतर

टिप्पणी: 1. कोविड-19 की विभिन्न लहरों को प्रदर्शित करने के लिए गूगल गतिशीलता संकेतक स्तरों में केवल साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक में शामिल किए गए हैं और खंड 5 के चार्ट 12 में गतिविधियों में बाद की बहाली दर्शायी गई है।
2. डीएफ़एम के लिए चरों के प्रथम अंतर रूपांतरण वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर और प्रसार सूचकांक के लिए सप्ताह-दर-सप्ताह (डब्ल्यू-ओ-डब्ल्यू) आधार पर किया जाता है।

सारणी 4ए: तिमाही जीडीपी वृद्धि के साथ सहसंबंध मैट्रिक्स

	सीएसईएनटी	एलएफ़पीआर	अन रेट	इलेक्जेन	एमवीपंज	आरटीजीएस	गूगल रुझान
सीएसईएनटी	1.00						
एलएफ़पीआर	0.82***	1.00					
अन रेट	0.33	0.37	1.00				
इलेक्जेन	0.46*	0.61**	0.49*	1.00			
एमवीपंजीकरण	0.21	0.55**	-0.29	0.46*	1.00		
आरटीजीएस	0.55**	0.75*	0.30	0.83***	0.64**	1.00	
गूगल रुझान	0.70***	0.56**	0.54**	0.80***	0.24	0.60**	1.00
जीडीपी	**0.78*** **	**0.90*** **	**0.55** **	**0.86*** **	**0.48* **	**0.86*** **	**0.81*** **

टिप्पणी: ***पी< ; **पी<; *पी <.

सारणी 4बी: आईआईपी वृद्धि के साथ सहसंबंध मैट्रिक्स

	सीएसईएनटी	एलएफ़पीआर	अन रेट	इलेक्जेन	एमवीपंज	आरटीजीएस	गूगल रुझान
सीएसईएनटी	1.00						
एलएफ़पीआर	0.74***	1.00					
अन रेट	0.33**	0.40***	1.00				
इलेक्जेन	0.40***	0.66***	0.51***	1.00			
एमवीपंजीकरण	0.13	0.53***	-0.01	0.56***	1.00		
आरटीजीएस	0.51***	0.68***	0.28*	0.72***	0.36**	1.00	
गूगल रुझान	0.67***	0.57***	0.54***	0.76***	0.25*	0.53***	1.00
आईआईपी	**0.40*** **	**0.79*** **	**0.34** **	**0.87*** **	**0.83*** **	**0.69*** **	**0.59*** **

टिप्पणी: ***पी< ; **पी<; *पी <.

IV. कार्य-प्रणाली

सूचकांकों से दो अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करने की उम्मीद की जाती है (i) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वास्तविक अर्थव्यवस्था में विकास पर नज़र रखना (डबल्यूएआई), और (ii) अनुक्रमिक गतिशीलता (डबल्यूडीआई) को दर्शाना। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, मॉडल-आधारित और सरल एकत्रीकरण दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है, जो कुछ संवेदनशीलता और मजबूती विश्लेषण द्वारा समर्थित हैं। पूर्व-महामारी के समय के सापेक्ष स्तर के संदर्भ में आर्थिक सुधार की निगरानी के लिए, डबल्यूएआई का एक और संस्करण भी विकसित किया गया है। यह उस अवधि के दौरान प्रासंगिक है जब भारी आधार प्रभाव होता है और सुधार की गति को समझने के लिए संवेग एक उपयुक्त मानदंड के रूप में काम करता है, जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। पिछले वर्ष की तुलना में गतिविधि में सुधार हो सकता है, लेकिन यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या यह तात्कालिक पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में बढ़ रहा है, या यह आघात से पहले मौजूद स्तर पर वापस आ गया है, या क्या यह सुधार को बनाए रखने में सक्षम है।

गेवेके (1977) और सार्जेंट एंड सिम्स (1977) द्वारा विकसित डीएफ़एम, कई समय श्रृंखला से एक समग्र सूचकांक के निर्माण के लिए अग्रणी फ्रेमवर्क हैं। आयाम के अभिशाप से निपटने के दौरान कारक मॉडल चर के बड़े सेट सहित एक समृद्ध डेटासेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। डीएफएम का सार अवलोकित घटक संकेतकों के सह-गति को समाहित करते हुए कम संख्या में अनदेखे या अव्यक्त श्रृंखला का उत्पादन करना है। गणितीय रूप से, डीएफएम प्रेक्षित श्रृंखला को सामान्य कारकों के सदिश और विशेष स्वभाव की गड़बड़ी के योग के रूप में प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में, जियानोन एवं अन्य (2008) और बनबुरा एवं अन्य (2011) में निर्दिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर, मासिक इनपुट चर द्वारा दर्शाए गए आर्थिक चक्र के अनुमान के आधार पर तिमाही आवृत्ति पर प्रकाशित वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए डीएफ़एम का उपयोग किया जाता है।

चूंकि कई संकेतकों की एक छोटी समय श्रृंखला होती है, संकेतकों के दो सेटों का उपयोग करके सूचकांकों का निर्माण किया गया है। लंबी अवधि के लिए उपलब्ध संकेतकों का छोटा सेट वर्ष-दर-वर्ष आधार पर परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी होता है, और तिमाही जीडीपी के साथ इसकी अनुरूपता की जांच करने का अवसर भी प्रदान करता है। उपयुक्त परिवर्तनों के बाद स्थिर मासिक इनपुट चर के वेक्टर को $x^M_t = (x_1{}^M{}_t, x_2{}^M{}_t, \ldots\ldots, x_n{}^M{}_t)$ के रूप में निरूपित किया जाता है जिसमें लापता संप्रेक्षण भी शामिल हैं। इनपुट चर $x^M{}_t$ को निम्नलिखित कारक संरचना प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है:

$$x^M{}_t = \mu + \Lambda^M F_t + \epsilon^M{}_t \qquad \ldots(1)$$

जहां F_t मासिक आवृत्ति के असंप्रेक्षित कारकों का एक $r \times 1$ वेक्टर है, Λ^M मासिक चर के कारक लोडिंग को दर्शाता है और ϵ_t विलक्षण त्रुटि घटक का वेक्टर है एआर (1) प्रक्रिया के बाद $\epsilon^M{}_{i,t} = \alpha_i \epsilon^M{}_{i,t-1} + e_{i,t}$ जहां $e_{i,t} \sim$ i.i.d. $N(0, \sigma^2_i)$ और $E[e_{i,t}, e_{j,s}] = 0$ for $i \neq j$. कारकों को क्रम p: की वीएआर प्रक्रिया का पालन करने की अनुमति है।

$$F_t = A_1 F_{t-1} + \ldots. + A_p F_{t-p} + v_t \text{ , } v_t \sim \text{i.i.d } N(0,Q) \qquad \ldots(2)$$

जहां v_t सामान्य आघात हैं और $A_1, \ldots\ldots, A_p$ वीएआर गुणांक के $r \times r$ मैट्रिक्स हैं।

सही और सटीक बिंदुओं वाले डेटा सेट की उपलब्धता में, कारकों के बीच गतिक संबंध विशेष अंश की जानकारी और दुर्लभ जानकारी के साथ हाल की अवधि के अनुमान की सटीकता को बढ़ाकर एक स्थिर कारक मॉडल पर बढ़त प्रदान करता है। असंप्रेक्षित कारक एफ़$_{टी}$ का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि स्टेट स्पेस फ्रेमवर्क के तहत अपेक्षा-अधिकतमकरण (ईएम) एल्गोरिथ्म है, जहां कलमन फ़िल्टर का उपयोग करके कारक का अनुमान लगाया जाता है। डीएफएम इस उद्देश्य के लिए उपयोगी है क्योंकि एकल मॉडल स्वचालित रूप से नए डेटा को अपनाता है क्योंकि यह ब्याज[3] के चर का अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध हो जाता है। वास्तविक समय की निगरानी के लिए एचएफआई का उपयोग करने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण विशिष्ट आर्थिक चर का पूर्वानुमान लगाना और नए डेटा आने पर पूर्वानुमानों के मॉडल-आधारित अपडेट प्रदान करना हो सकता है।

घटक श्रृंखला के आधार पर डब्ल्यूएआई का अनुमान लगाने के बाद, तिमाही वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पता लगाने के लिए इसे फिर से गठित किया जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वृहत-संकेतक होने के अलावा, व-द-व सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि भी साप्ताहिक मौसमी समायोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले 52-सप्ताह के प्रतिशत परिवर्तन के साथ संरेखित होती है। निम्नलिखित प्रतिगमन का उपयोग करके परिमाण और विस्थापन मापदंड का अनुमान लगाया गया है।

$$GDP^q\ growth = \alpha + \beta WAI^q\ growth + \varepsilon^q \qquad ...(3)$$

जहां, जीडीपी$^{क्यू}$ वृद्धि वास्तविक जीडीपी में व-द-व वृद्धि है

डब्ल्यूएआई$^{क्यू}$ वृद्धि डब्ल्यूएआई में 52-सप्ताह की वृद्धि दर का तिमाही औसत है और

$\varepsilon^q \sim \text{i.i.d. } N(0, \sigma^2)$

इस प्रकार, अनुमानित गुणांक $\hat{\alpha}$ और $\hat{\beta}$ पर आधारित समीकरण (3) से अनुमानित y-चर हमें पुनर्वर्धित डब्ल्यूएआई प्रदान करता है जो तिमाही जीडीपी वृद्धि के साथ तुलनीय है। वर्धित डब्ल्यूएआई के 13-साप्ताहिक गतिशील औसत (एमए) को तिमाही जीडीपी का पता लगाने वाले संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और तिमाही के अंतिम सप्ताह में डब्ल्यूएआई का 13-साप्ताहिक एमए उस तिमाही के औसत को दर्शाता है।

[3] तात्कालिक पूर्वानुमान में गतिक कारक मॉडल के अनुप्रयोग के लिए, जियानोन, रीचलिन एंड स्मॉल (2008) और ऑरोबा, डाइबोल्ड और स्कॉटी (2009) देखें।

साप्ताहिक प्रसार सूचकांक

विभिन्न संकेतकों से जानकारी का उपयोग करते हुए एक समेकित प्रसार सूचकांक के संदर्भ में गतिविधि में साप्ताहिक क्रमिक उतार-चढ़ाव प्रस्तुत किया गया है। डब्ल्यूडीआई, निर्माण द्वारा, केवल गतिविधि में गति की दिशा प्रस्तुत करता है और परिमाण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। डब्ल्यूडीआई का निर्माण अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली साप्ताहिक आवृत्ति पर 15 संकेतकों के एक सेट का उपयोग करके किया गया है। सूचकांक का निर्माण सम्मेलन बोर्ड[4] की कार्यप्रणाली के अनुसार किया गया है, जो कई समय श्रृंखलाओं की सहगति को दर्शाता है। यह 0 और 100 के बीच होता है और चयनित चर के अनुपात को मापता है जो सूचकांक में सकारात्मक योगदान देता है। उदाहरण के लिए, 65 के सूचकांक मूल्य की व्याख्या सप्ताह दर सप्ताह (स-द-स) त्वरण दर्ज करने वाले संकेतकों के 65 प्रतिशत के रूप में की जाती है, जबकि 50 के सूचकांक मूल्य का तात्पर्य कुल संकेतकों के 50 प्रतिशत में स-द-स त्वरण से है। निर्माण प्रत्येक संकेतक के लिए स-द-स वृद्धि दर की गणना के साथ शुरू होता है। संकेतक जो 0.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ते हैं, उन्हें 1 का मान दिया जाता है, जो घटक 0.5 प्रतिशत से अधिक घटते हैं उन्हें 0 का मान दिया जाता है, और 0.5 से (-) 0.5 प्रति वृद्धि दर वाले घटक जो होते हैं उन्हें 0.5 का मान दिया जाता है। 0 से 100 के बीच एक सूचकांक मूल्य प्राप्त करने के लिए घटक श्रृंखला के मूल्यों को एकत्रित किया जाता है।

V. डब्ल्यूएआई का प्रक्षेपवक्र

पहले कोविड लहर प्रेरित लॉकडाउन का प्रभाव डब्ल्यूएआई के प्रक्षेपवक्र में गहरी गिरावट से स्पष्ट है (चार्ट 11)। जीडीपी के नुकसान के संदर्भ में दूसरी लहर का हल्का प्रभाव जो लगभग एक-तिहाई होने का अनुमान है, की भी डब्ल्यूएआई स्तरों में गिरावट से पुष्टि हुई थी (आरबीआई, 2022)। फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 के महीने में डब्ल्यूएआई द्वारा प्रदर्शित, सुधार में देर के अलावा, कोविड की तीसरी लहर का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं था। डब्ल्यूएआई के 13-सप्ताह के एमए का मूल्य एक संदर्भ तिमाही के अंतिम सप्ताह में जीडीपी (13-सप्ताह एमए) तक बढ़ा, यह उस तिमाही के दौरान गतिविधि को भी शामिल करता है और इसलिए,

[4] https://conference-board.org/data/bci/index.cfm?id=2180

चार्ट 11: साप्ताहिक गतिविधि सूचकांक

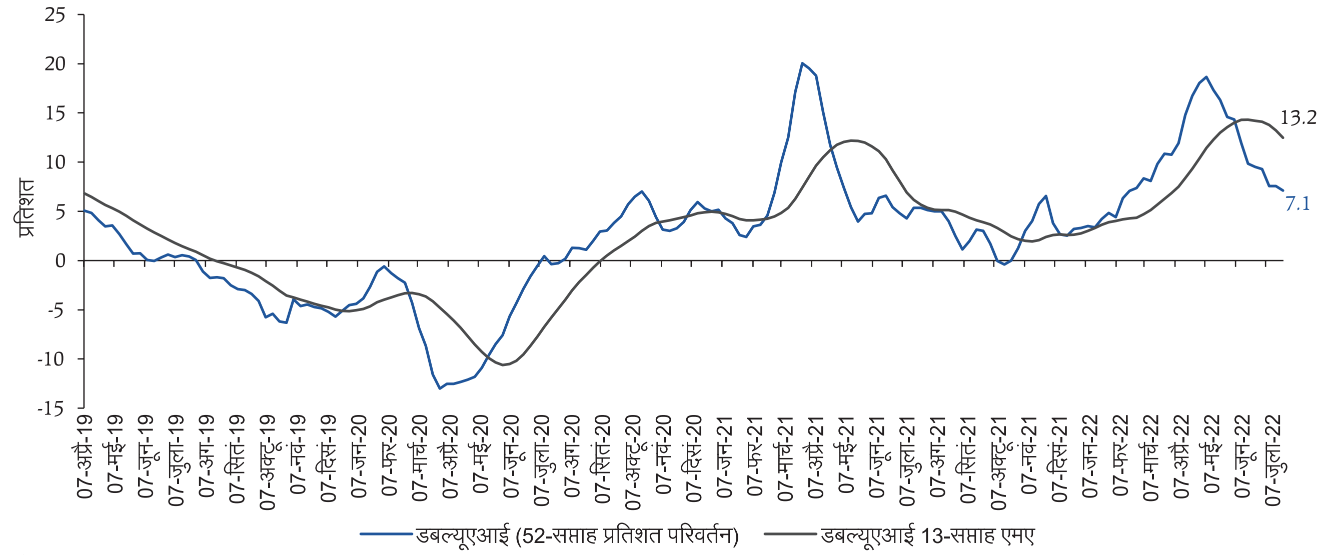

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

उस तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का एक मोटा अनुमान है।

महामारी के दौरान सूचकांकों के प्रदर्शन का वर्णन

महामारी के प्रकोप के बाद से दो वर्षों के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं के संयोजन के साथ डबल्यूएआई प्रक्षेपवक्र का खुलासा देखा जा सकता है। 11 मार्च, 2020 को डबल्यूएचओ ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया और 30 जनवरी, 2020 को केरल में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया। तब से, भारत ने महामारी की तीन लहरों का अनुभव किया है, जो मामलों की संख्या में इसे दुनिया में दूसरे स्थान पर ले गया है। भारत ने 24 मार्च को घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण के साथ पहली लहर के दौरान संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया में सबसे कड़े प्रतिबंधों में से एक को मई 2020 के अंत तक जारी रखा। तदनुसार, डब्ल्यूएआई 29 मार्च, 2020 को समाप्त सप्ताह में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.6 प्रतिशत कम रहा, इसके बाद अप्रैल और मई में क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ। डबल्यूएआई में संकुचन को लगभग सभी घटक संकेतकों जैसे उपभोक्ता भावनाओं, विद्युत उत्पादन, वाहन पंजीकरण, गूगल प्रवृत्ति की विभिन्न खोज श्रेणियों, आरटीजीएस भुगतान और आसमान छूती बेरोजगारी दर में व्यापक-आधारित गिरावट से रेखांकित किया गया था।

प्रतिबंधों में धीरे-धीरे छूट के साथ, जून 2020 से 6 चरणों में प्रतिबंध हटने शुरू हुए - अनलॉक 1.0 से अनलॉक 6.0। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति परिवार के सदस्यों को मुफ्त राशन जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य नौकरियों की रक्षा करना, वित्तीय सहायता के साथ-साथ विनियामक छूट, विस्तार और गारंटी योजनाएं प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, आरटीजीएस लेनदेन, विद्युत उत्पादन, बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर जैसे कुछ संकेतकों में वी-आकार की रिकवरी दिखाई दे रही थी। उपभोक्ता भावनाओं, रेलवे, हवाई यात्रा, वाहन पंजीकरण में हालांकि धीमी गति से सुधार हुआ। संकेतकों में सुधार के साथ, डब्ल्यूएआई में संकुचन भी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई 2020 के दूसरे सप्ताह तक लगातार 12 सप्ताह लगातार कम हुआ। क्रमिक अनलॉकिंग के साथ प्रत्येक बाद के महीने में संकुचन में कमी के साथ, सितंबर 2020 में महामारी के अपने चरम से घटने के बाद अक्टूबर 2020 के दूसरे सप्ताह में डब्ल्यूएआई सकारात्मक हो गया। डबल्यूएआई, जो एक संदर्भ तिमाही के अंत के एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध है और जीडीपी डेटा की आधिकारिक रिलीज

से लगभग दो महीने पहले के योग नें, 2020-21 में तिमाही जीडीपी वृद्धि को यथोचित रूप से ट्रैक किया। इसलिए, तिमाही जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्ति के बाद, डब्ल्यूएआई ने दो तिमाहियों के संकुचन के बाद, तीसरी तिमाही में सकारात्मक क्षेत्र में वापसी की और 2020-21 की चौथी तिमाही में और मजबूत हुई।

डब्ल्यूएआई के अनुमानित व-द-व परिवर्तन 2020-21 में तेज संकुचन से उत्पन्न 2021-22 में आधार प्रभावों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसलिए, 2021-22 में कोविड-19 लहरों के बाद के प्रभाव को कम कर दिया। इस मुद्दे को हल करने के लिए, एक साप्ताहिक सुधार सूचकांक (डबल्यूआरआई) विकसित किया गया है, जो केवल स्तरों पर डबल्यूएआई है, विशेष रूप से महामारी की विभिन्न लहरों के आर्थिक प्रभाव की तुलना में पूर्व-महामारी स्तर के लिए बनाया किया गया है (चार्ट 12)। डबल्यूआरआई ने दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह से अपने पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर लिया। टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी, 2021 से हुई, आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आई, जो लगातार पंद्रह हफ्तों अप्रैल 2021 के दूसरे हफ्ते जब दूसरी लहर तेज हुई तक सूचकांक में निरंतर सकारात्मक गति में परिलक्षित होता है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव मध्यम था। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन के सुदृढ़ीकरण ने आर्थिक सुधार को विफल कर दिया क्योंकि डबल्यूआरआई मई और जून, 2021 में पूर्व-महामारी स्तर से नीचे गिर गया। डबल्यूआरआई ने दूसरी लहर में कमी के साथ जुलाई के पहले सप्ताह में वापसी की, प्रतिबंधात्मक उपायों को हटाने और सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान में तेजी लाना और सितंबर तक स्थिर गति बनाए रखना। कोयले के संकट के कारण व्यवधान, दुनिया भर में सेमी-कंडक्टर चिप की कमी ने गतिविधि पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया जैसा कि अक्टूबर के अंत और नवंबर 2021 से रिकवरी वक्र में नीचे की ओर प्रक्षेपवक्र में परिलक्षित हुआ था। कोविड-19 की पहली दो लहरों के विपरीत, ओमिक्रॉन लहर का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि डबल्यूआरआई द्वारा परिलक्षित होता है जो दिसंबर और जनवरी 2022 में पूर्व-महामारी स्तर से ऊपर रहा और उसके बाद तेजी से सुधार हुआ।

हालिया प्रक्षेपवक्र: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से

ओमिक्रॉन लहर के कारण जनवरी के दौरान मंदी के बाद डब्ल्यूएआई में सुधार हुआ। डब्ल्यूएआई ने अप्रैल और मई 2022 के महीने में औसतन दो अंकों की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, इन दो महीनों में देखी गई तेज वृद्धि आंशिक रूप से दूसरी लहर से निकलने वाले आधार प्रभाव के कारण थी। डब्ल्यूएआई में जून में

चार्ट 12 : साप्ताहिक रिकवरी सूचकांक
(फरवरी 2, 2020=100)

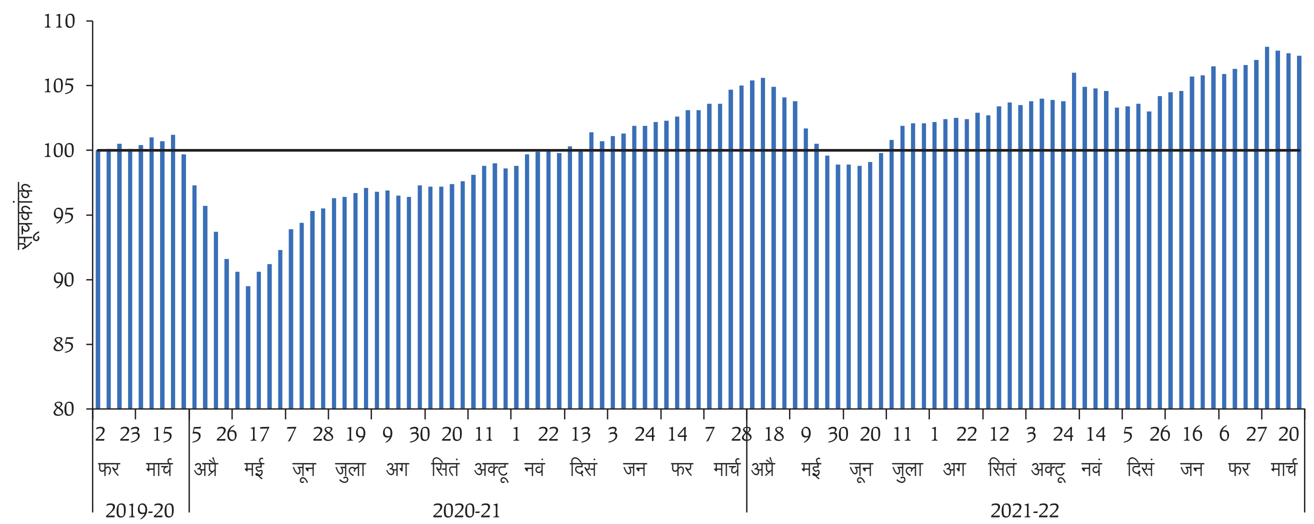

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 13: साप्ताहिक प्रसार सूचकांक (डबल्यूडीआई)

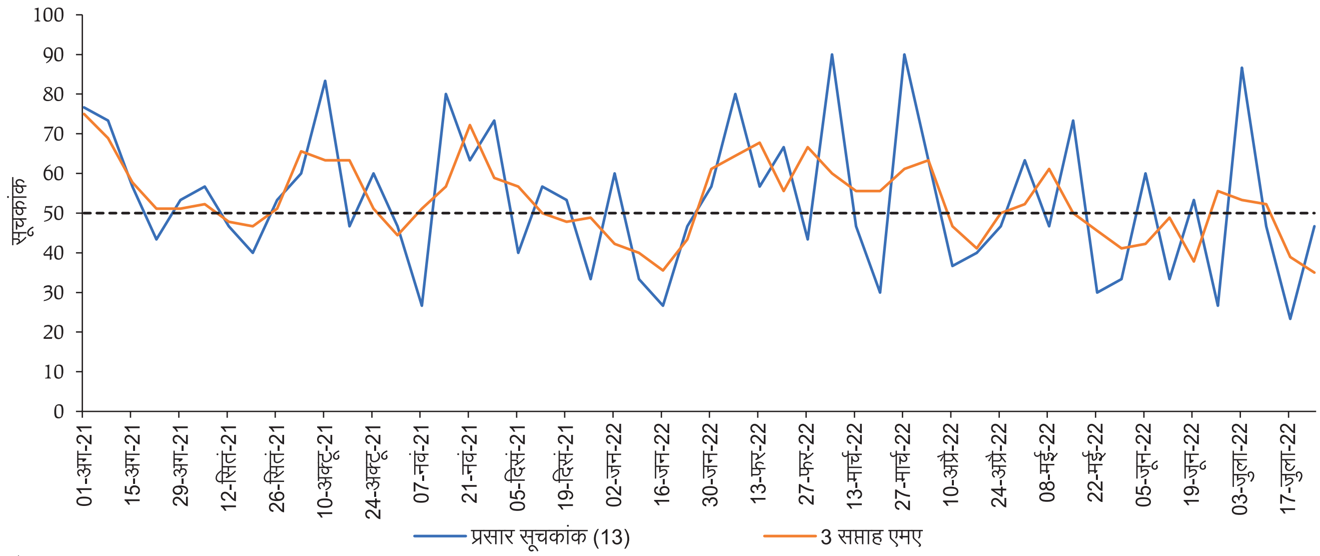

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

कमी आई और जुलाई 2022 में नीचे की ओर जारी रहा। साप्ताहिक प्रसार सूचकांक (डबल्यूडीआई) से स्पष्ट अनुक्रमिक गति मार्च 2022 से गति में निरंतर कमी का सुझाव देता है। डबल्यूडीआई का फरवरी और मार्च 2020 के महीने में 3 महीने का एमए औसत 61.1 रहा, लेकिन उसके बाद चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न होने वाली कई विपरीत परिस्थितियों के बीच काफी हद तक कम हो गया (चार्ट 13)। अप्रैल के पहले सप्ताह से लेकर 24 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक के 17 हफ्तों में से डब्ल्यूडीआई नौ मौकों पर 50 से नीचे रहा। मई में 50 को छूने के बाद, डबल्यूडीआई का 3 महीने का एमए जून में 46.1 तक गिर गया और जुलाई 2022 में और घटकर 44.9 हो गया।

अक्टूबर 2020 से प्रस्तुत डबल्यूडीआई ने अप्रैल 2021 के सप्ताहों के दौरान गति में तेज गिरावट प्रदर्शित की जब कोविड की दूसरी लहर तेज हो गई। बाद के महीनों में सूचकांक में तेजी से वापसी हुई और आधे से अधिक घटक संकेतकों ने सकारात्मक गति दिखाई। सूचकांक दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में मुख्य रूप से रोजगार दर में गिरावट और महामारी की तीसरी लहर के कारण नीचे की ओर चला गया। फरवरी में सूचकांक में तेजी से वापसी हुई और मार्च और अप्रैल में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति में रुकावट के बावजूद मार्च और अप्रैल में लचीला बना रहा।

समष्टि-संकलित राशियों के साथ संबंध

डब्ल्यूएआई और आउटपुट उपायों के दो प्राथमिक समष्टि संकेतकों के बीच अनुमानित संबंध - वास्तविक जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन का भी पता लगाया गया है (चार्ट 14 और चार्ट 15)। वास्तविक जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर के साथ डब्ल्यूएआई का तिमाही औसत समय के साथ मजबूत सह-गति प्रदर्शित करता है। दो श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध गुणांक भी उच्च स्तर पर 0.79 रहा। आधिकारिक जीडीपी डेटा जारी करने में दो महीने का अंतराल डबल्यूएआई में समय पर हुए विकास को देखना और भी महत्वपूर्ण बनाता है। डब्ल्यूएआई का तिमाही योग सकल घरेलू उत्पाद तक बढ़ा कर तिमाही के अंत से एक सप्ताह के भीतर सकल घरेलू उत्पाद का एक तात्कालिक अनुमान प्रदान किया जा सकता है। डब्ल्यूएआई का मासिक औसत 0.66 के रूप में दो श्रृंखलाओं के बीच सहसंबंध गुणांक के साथ आईआईपी में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का अच्छी तरह से पता करता है। किसी विशेष महीने के लिए आईआईपी पैंतालीस दिनों के अंतराल के साथ जारी होता है। डबल्यूएआई का चार-सप्ताह का औसत, जो एक

चार्ट 14: जीडीपी के साथ संबंध

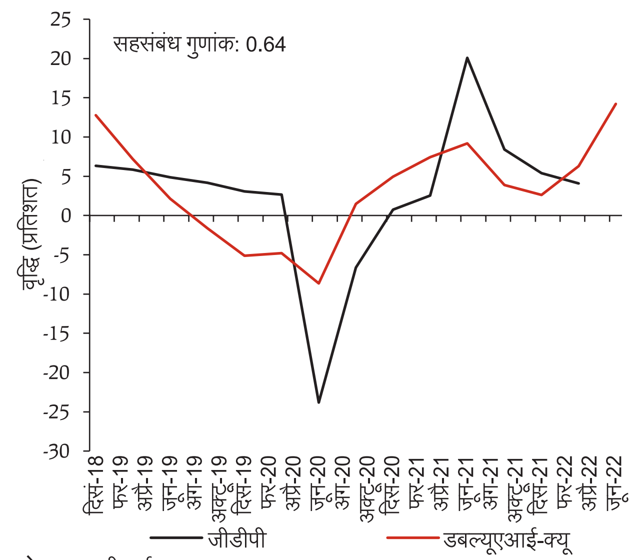

स्रोत : आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 15: आईआईपी के साथ संबंध

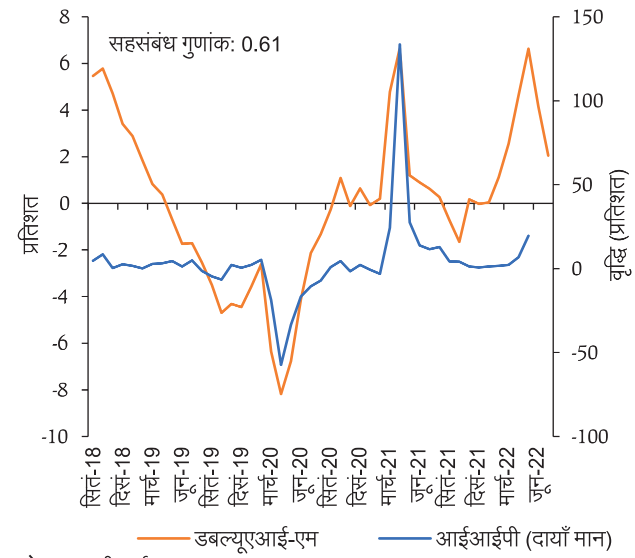

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

महीने का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी ओर, महीने के अंत से पांच दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाता है। कम आवृत्ति उपायों के साथ मजबूत संबंध इंगित करता है कि कच्चे उच्च-आवृत्ति डेटा में निहित कोलाहल के बावजूद, संकेतकों को एक साप्ताहिक सूचकांक में संयोजित करने से वास्तविक आर्थिक गतिविधि का सूचनात्मक और समय पर संकेत मिलता है।

पूर्वानुमान डबल्यूएआई का स्वाभाविक अनुप्रयोग है, हम आगे डबल्यूएआई और निम्न-आवृत्ति वास्तविक गतिविधि उपायों के बीच पूर्वानुमान संबंधों का पता लगाते हैं। हम तिमाही के पहले महीने के लिए डब्ल्यूएआई से शुरू करते हुए, डब्ल्यूएआई से सूचना के प्रवाह को कम करके लक्ष्य चर जीडीपी का तात्कालिक अनुमान[5] लगाने का प्रयास करते हैं (सारणी 5ए)।

$$GDP^q\ growth = c + \sum_{i=1}^{mi} \beta_i\, WAI_q^{mi}\,\text{growth} + e_q;\ mi = 1,2,3;\ \ldots(4)$$

$$IIP^m\ growth = c + \sum_{i=1}^{wi} \beta_i\, WAI_m^{wi}\,\text{growth} + e_m;\ wi = 1,2,3,4;\ \ldots(5)$$

समान रूप से, आईआईपी महीने के पहले सप्ताह के लिए डबल्यूएआई से शुरू होकर कम हो गया है और प्रत्येक बाद के सप्ताह से निकलने वाली अतिरिक्त जानकारी के साथ आगे बढ़ा है (सारणी 5b)। इन तात्कालिक अनुमान का लक्ष्य केवल लक्ष्य चर

सारणी 5ए: मासिक सूचना प्रवाह

	डबल्यूएआई माह 1	डबल्यूएआई माह 2	डबल्यूएआई माह 3
गुणांक	0.952***	1.034***	0.990***
मानक त्रुटि	0.164	0.195	0.235
समायोजित आर -वर्ग	0.685964	0.64311	0.52790
एफ़ सांख्यिकी	33.7652***	28.0304***	17.7730***
अवलोकन की संख्या	16	16	16
थिल यू	**0.74136**		

टिप्पणी: ***पी; **पी; *पी <।

सारणी 5बी: मासिक सूचना प्रवाह

	डबल्यूएआई माह 1	डबल्यूएआई माह 2	डबल्यूएआई माह 3	डबल्यूएआई माह 4
गुणांक	2.2845***	2.3015***	2.2548***	2.1884***
मानक त्रुटि	0.3448	0.3425	0.3485	0.3576
समायोजित आर -वर्ग	0.4772	0.4844	0.4651	0.4368
एफ़ सांख्यिकी	43.9043	45.1635	41.8636	37.4588
अवलोकन की संख्या	48	48	48	48
थिल यू	**0.91980**			

टिप्पणी: ***पी; **पी; *पी <।

[5] मानक तात्कालिक पूर्वानुमान (न्यूयॉर्क, अटलांटा और सेंट लुइस के फेडरल रिज़र्व बैंकों सहित) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जैसे निम्न आवृत्ति लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत जानकारीपूर्ण हैं। लेकिन, चूंकि सकल घरेलू उत्पाद एक तिमाही चर है, ऐसे मॉडल एक सप्ताह से अगले सप्ताह तक भिन्नता को उजागर करने के लिए सक्षम नहीं हैं।

की आवृत्ति पर लक्ष्य श्रृंखला में औसत भिन्नता का पूर्वानुमान लगाना है, जो यह अच्छा प्रदर्शन करता है। तिमाही जीडीपी के लिए, सभी तीन महीनों के लिए डब्ल्यूएआई अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, पहला महीना समायोजित आर-वर्गित के उच्चतम मूल्य के साथ सबसे मजबूत संबंध प्रस्तुत करता है जो अगले दो महीनों में थोड़ा कम हो जाता है। आईआईपी के मामले में, पहले दो हफ्तों की जानकारी ने सबसे मजबूत संबंध पेश किया, जबकि तीसरे और चौथे सप्ताह की जानकारी ने, अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने के बावजूद, पूर्वानुमान में कोई सुधार नहीं किया। इसके अलावा, आईआईपी और जीडीपी दोनों के मामले में थील का यू सांख्यिकी, जो एक सापेक्ष सटीकता माप है, जो पूर्वानुमानित परिणामों की तुलना न्यूनतम ऐतिहासिक डेटा के साथ पूर्वानुमान के परिणामों से करता है, यह दर्शाता है कि डब्ल्यूएआई सामान्य पूर्वानुमान की तुलना में बेहतर पूर्वानुमान की शक्ति रखता है।

VI. निष्कर्ष

तेजी से विकसित हो रही आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डेटा के नए स्रोत नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण के लिए एक आवश्यकता बन गए हैं। इस संबंध में, डबल्यूएआई और डबल्यूडीआई समग्र आर्थिक गतिविधि के समग्र संकेतक के रूप में काम कर सकते हैं। इस अध्ययन से पता चलता है कि डबल्यूएआई महामारी के वर्षों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में उतार-चढ़ाव बाद से फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के कारण हुए हाल के व्यवधानों का पता करता है। इसकी समय पर उपलब्धता के कारण, डबल्यूएआई में मासिक उच्च आवृत्ति संकेतकों में सूचना के अंतर को पाटने की क्षमता है - मौद्रिक नीति विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट। डब्ल्यूएआई मासिक आईआईपी और तिमाही सकल घरेलू उत्पाद जैसे समष्टिआर्थिक चर को यथोचित रूप से ट्रैक करता है। विशेष रूप से, डब्ल्यूएआई का 4-सप्ताह का एमए और 13-सप्ताह का एमए, संदर्भ माह या तिमाही के अंत के तुरंत बाद आईआईपी और जीडीपी वृद्धि की वर्तमान जानकारी प्रदान करता है।

पूर्व-महामारी के समय के सापेक्ष रिकवरी की निगरानी के लिए, डबल्यूआरआई को स्तर के संदर्भ में रिकवरी दिखाने में भी विकसित किया गया है। कोविड-19 की पहली दो लहरों के विपरीत, ओमिक्रॉन लहर का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि डबल्यूआरआई में कमी आई लेकिन दिसंबर और जनवरी 2022 में यह पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर रहा और इसके बाद तेजी से ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र में गया। एक सप्ताह के लिए डब्ल्यूडीआई समग्र दिशा को प्रदर्शित करके आर्थिक गतिविधि में गति प्रस्तुत करता है जहां अर्थव्यवस्था एकल सूचकांक मूल्य के संदर्भ में (ऊपर या नीचे) बढ़ रही है। डबल्यूडीआई आर्थिक गतिविधि में गति को ट्रैक करने में उपयोगी पाया गया है और मॉडल-आधारित डबल्यूएआई को उपयुक्त रूप से पूरक करता है।

साप्ताहिक सूचकांक जीडीपी के अधिक परिष्कृत तात्कालिक पूर्वानुमान मॉडल के पूरक हो सकते हैं। वर्तमान में, दैनिक और साप्ताहिक उच्च आवृत्ति संकेतकों का सेट सीमित है लेकिन महामारी के प्रकोप के बाद से तेज गति से बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए, पर्याप्त डेटा बिंदुओं की उपलब्धता के साथ, वास्तविक आर्थिक गतिविधि की वास्तविक समय ट्रैकिंग को सक्षम और मजबूत करने के लिए मजबूत सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

संदर्भ:

Eraslan, S., and T. Gotz (2020), "An unconventional weekly economic activity index for Germany", Technical Paper, Deutsche Bunesbank Eurosystem.

Geweke, J. (1977), "The Dynamic Factor Analysis of Economic Time Series", in Latent Variables in Socio-Economic Models, ed. by D.J. Aigner and A.S. Goldberger, Amsterdam: North-Holland.

Giannone, D., L. Reichlin, and D. Small (2008), "Nowcasting: The Real-Time Informational Content of Macroeconomic Data", *Journal of Monetary Economics*, 55, 665-676.

Konings, Joana (2021), "Introducing the ING weekly economic activity index for the eurozone", ING, Think Economic and Financial Analysis.

Lewis, D.J., K. Mertens, and J.H. Stock (2020a), "Monitoring Real Activity in Real Time: The Weekly Economic Index", Liberty Street Economics, March

30, 2020. https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2020/03/monitoring-real-activity-in-real-time-the-weekly-economic-index/, accessed on May 22, 2022.

Lewis, D. J., K. Mertens, and J. H. Stock (2020), "U.S. Economic Activity during the Early Weeks of the SARS-Cov-2 Outbreak", Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 920, April.

Lewis, D.J., K. Mertens, and J.H. Stock (2020b), "Tracking the COVID-19 Economy with the Weekly Economic Index (WEI)", Liberty Street Economics, August 4, 2020. https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2020/08/tracking-the-covid-19-economy-with-the-weekly-economic-index-wei.html, accessed on May 23, 2022.

McCracken, M. (2020), "COVID-19: Forecasting with Slow and Fast Data", On the Economy Blog, Federal Reserve Bank of St Louis.

Reserve Bank of India (2021). Monetary Policy Report, October.

Reserve Bank of India (2022). Report on Currency and Finance, October.

Stock, J.H., and M.W. Watson (1989), "New Indexes of Coincident and Leading Economic Indicators", NBER Macroeconomics Annual 1989, 351-393.

Stock, J.H., and M.W. Watson (2002a), "Forecasting Using Principal Components from a Large Number of Predictors," *Journal of the American Statistical Association*, 97:1167-1179.

Stock, J.H., and M.W. Watson (2002b), "Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indices", *Journal of Business and Economic Statistics*, 20:147-162.

Woloszko, N. (2020), "Tracking activity in real time with Google Trends", OECD Economics Department Working Papers No. 1634.

*निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 के लिए दृष्टिकोण**

भारत में निजी निवेश गतिविधि के लिए निकट अवधि के दृष्टिकोण का अनुमान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के परियोजना निवेश प्रस्तावों से लगाया जाता है। कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद व्यावसायिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने और मांग की स्थिति में सुधार के साथ, 2021-22 के दौरान नई परियोजनाओं की घोषणा में काफी वृद्धि हुई, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की। 2021-22 के दौरान परिकल्पित कुल कैपेक्स निवेश में से एक तिहाई से अधिक 2022-23 में खर्च किए जाने की उम्मीद है।

परिचय

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश वातावरण को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए निजी निवेश दृष्टिकोण का आकलन महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट क्षेत्र के वार्षिक खातों के प्रकाशन में देरी को देखते हुए, तुलन पत्र आधारित निवेश दर अल्पकालिक निवेश दृष्टिकोण का आकलन करने में उपयोगी नहीं हो सकती है। एक विकल्प के रूप में, परिकल्पित कॉर्पोरेट निवेश योजनाओं और निवेश भावना के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सर्वेक्षण-आधारित विधियों का लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। इस तरह के सर्वेक्षणों के परिणाम वर्तमान निवेश माहौल और निवेश के इरादे दोनों के आकलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिनके लघु से मध्यम अवधि में कार्यान्वित होने की संभावना है।

भारत में भी, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही निजी निवेश के आकलन और पूर्वानुमान/नव-कास्टिंग के लिए इस तरह के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की कैपेक्स योजनाओं का उपयोग रंगराजन (1970) [1] द्वारा कैपेक्स के समय चरणबद्ध तरीके से अपनाई गई पद्धति के आधार पर निवेश पर एक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए किया गया है । इस तरह के लेख शुरू में आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक और बाद में 1989 से आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किए गए थे।

यह लेख पांच खंडों में सृजित किया गया है। खंड II कार्यप्रणाली और इसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। समीक्षा की अवधि के दौरान स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएँ, उनका वित्तपोषण, और क्षेत्रों और उद्योगों के संदर्भ में वितरण संबंधी पहलुओं को खंड III में प्रस्तुत किया गया है । खंड IV स्वीकृत/अनुबंधित ऋण/वित्तपोषण के चरणबद्ध प्रोफाइल से संबंधित है और कॉर्पोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है। खंड V अध्ययन का समापन करता है।

II. कार्यप्रणाली और सीमाएं

यह लेख निजी कॉर्पोरेट की निवेश गतिविधि के निकट अवधि के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए रंगराजन (1970) का अनुसरण करता है। इस उद्देश्य के लिए, निवेश के इरादे पर डेटा तीन अलग-अलग स्रोतों के माध्यम से एकत्र किया गया था, अर्थात, i) बैंक और वित्तीय संस्थाएं (एफआई) [2] जो निजी कंपनियों को परियोजना वित्त के कारोबार में शामिल हैं, (ii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), रुपये में मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) जारी करने सहित बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के माध्यम से पूंजीगत व्यय उद्देश्य के लिए उठाए गए वित्त, और (iii) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और एक वर्ष के दौरान राइट्स इश्यू।

* यह लेख सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग में राजेंद्र एन चौहान और राजेश बी कावेड़िया द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। “निजी कॉर्पोरेट निवेश: 2020-21 में वृद्धि और 2021-22 के लिए आउटलुक” श्रृंखला में पिछला लेख भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के सितंबर 2021 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

[1] यह पद्धति 19 दिसंबर, 1970 को डॉ. सी. रंगराजन द्वारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में लिखे गए लेख “कॉर्पोरेट क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का पूर्वानुमान” में प्रकाशित हुई थी।

[2] में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो परियोजना वित्तपोषण में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आरईसी) और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम)।

पूंजी निवेश की दोहरी गणना और परिणामस्वरूप अतिवृद्धि से बचने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है कि प्रत्येक पूंजीगत व्यय परियोजना केवल एक बार निर्धारित जानकारी में प्रवेश करती है, भले ही इसे आरबीआई के आंतरिक डेटाबेस के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके कई स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया हो। इस अध्ययन में केवल उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जो ऊपर उल्लिखित किसी भी स्रोत के माध्यम से वित्तपोषित हैं, जिनकी परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है और निजी स्वामित्व 51 प्रतिशत से ऊपर है। केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

अनुमान इस धारणा के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनियां अपनी प्रत्याशित पूंजीगत व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में उपलब्ध कॉर्पोरेट निश्चित निवेश के पूर्व-पश्च अनुमानों से अलग हो सकते हैं। यह इस संभावना के मद्देनजर है कि कुछ प्रत्याशित लक्ष्य उनकी राशि और निवेश के समय के संदर्भ में वास्तविक निवेश में फलीभूत नहीं हो सकते हैं और कुछ परियोजनाएं स्व-वित्तपोषित हो सकती हैं।

III. स्वीकृत/अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएं

नई परियोजना घोषणाओं की संख्या के संदर्भ में निवेश का माहौल 2019-20 के दौरान कमजोर रहा और 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण और बिगड़ गया। इसके बाद, व्यावसायिक गतिविधियों की बहाली और मांग की भावना में सुधार के साथ, नई कैपेक्स परियोजना घोषणाओं ने पुनरुद्धार के कुछ संकेत दिखाए। 2021-22 के दौरान, 28 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, जो परियोजना वित्त में सक्रिय रूप से शामिल थे, ने 403 परियोजनाओं की सूचना दी, जो 2020-21 के दौरान रिपोर्ट की गई 220 परियोजनाओं की रिपोर्ट के साथ-साथ 2019-20 के दौरान रिपोर्ट की गई 320 परियोजनाओं से काफी अधिक थी, मुख्य रूप से छोटी टिकट परियोजनाओं में वृद्धि के कारण . हालांकि, कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन और संबंधित प्रतिबंधों के कारण 2020-21 में ₹75,558 करोड़ के रिकॉर्ड निचले स्तर की तुलना में ₹1,43,314 करोड़ की कुल परियोजना लागत लगभग दोगुनी हो गई थी, लेकिन यह पूर्व-कोविड स्तरों से कम रही (संलग्नक: सारणी ए1)।

कुल 361 कंपनियों ने, जिन्होंने पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तपोषण नहीं लिया, ने ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से 47,824 करोड़ रुपये की राशि जुटाई और 27 अन्य कंपनियों ने आईपीओ मार्ग के तहत घरेलू इक्विटी निर्गम के माध्यम से अपनी पूंजीगत खर्च जरूरतों के लिए 3,410 करोड़ रुपये जुटाए। कुल मिलाकर, 2021-22 के दौरान 791 परियोजनाओं की निवेश योजना बनाई गई, जो 2020-21 में 576 परियोजनाओं के मुकाबले ₹1,16,603 करोड़ के निवेश के इरादे से ₹1,94,548 करोड़ थी, जो कि 2016-17 के बाद से देखे गए स्तरों से तुलनात्मक रूप से कम रही। (अनुलग्नक: सारणी ए1-ए 4)।

(i) आकार के अनुसार

2020-21 और 2021-22 के दौरान कुल परियोजना लागत में मेगा परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी (₹5,000 करोड़ और अधिक) में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। बड़ी परियोजनाओं (परियोजना लागत: ₹1,000 करोड़ - ₹5,000 करोड़) ने 2021-22 के दौरान स्वीकृत परियोजना लागत में काफी अधिक हिस्सेदारी (47 प्रतिशत) का योगदान दिया। हालांकि 2021-22 के दौरान बड़ी परियोजनाओं की संख्या पिछले वर्ष के दौरान 24 परियोजनाओं से बढ़कर 36 हो गई, लेकिन परियोजनाओं की कुल लागत में उनकी हिस्सेदारी 2021-22 के दौरान कम हो गई (संलग्नक: सारणी ए5)।

(ii) उद्देश्य-वार

2021-22 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई कुल परियोजना लागत में ग्रीनफील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का प्रमुख हिस्सा (89 प्रतिशत) रहा, जो अतीत में देखे गए रुझान से तुलनीय है। परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान काफी वृद्धि हुई है, जो 2019-20 के दौरान घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं से भी अधिक है। कुल परियोजना लागत का 11 प्रतिशत मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए निर्देशित किया गया था (अनुलग्नक: सारणी ए6)।

(iii) उद्योग-वार

2020-21 से 2021-22 में कुल परियोजना लागत में वृद्धि हुई है, जिसमें कई उद्योगों ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। उदाहरण

चार्ट 1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा

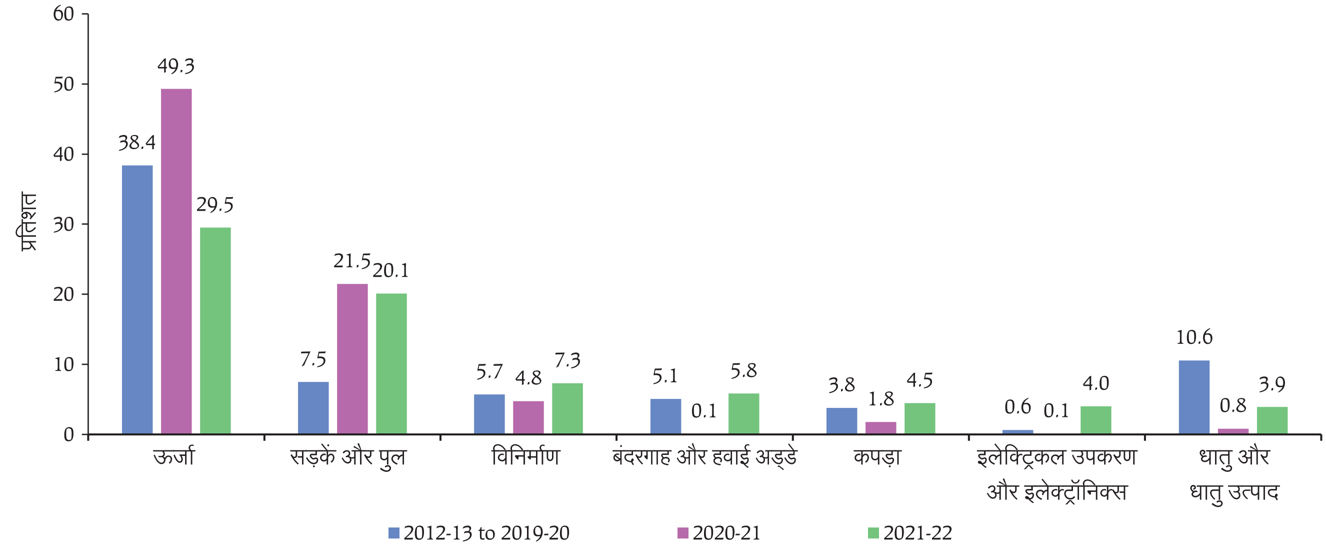

स्रोत: बैंकों/वित्तीय संस्थानों और लेखक की गणना से परियोजना वित्त पर डेटा एकत्र किया गया।

के लिए, इस अवधि के दौरान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल लागत 56,103 करोड़ रुपये से बढ़कर 81,221 करोड़ रुपये हो गई। गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र में, निर्माण, कपड़ा, विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु और धातु उत्पादों जैसे उद्योगों ने 2021-22 में परिकल्पित परियोजनाओं की कुल लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की (अनुबंध: सारणी ए 7)।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र, जिसमें (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (iv) भंडारण और जल प्रबंधन, (v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क, और (vi) सड़कें और पुल शामिल हैं, 2021-22 के दौरान कुल परियोजना लागत के आधे से अधिक के लिए प्रमुख क्षेत्र बने रहे। हालांकि, इसी अवधि के दौरान परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद कुल परियोजना लागत में इसकी हिस्सेदारी 2020-21 में 74.3 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 56.7 प्रतिशत हो गई है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की हिस्सेदारी में गिरावट मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी से प्रेरित थी, भले ही इसने बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। इसके अलावा, 2012-13 से 2019-20 की तुलना में हाल के वर्षों में 'सड़क और पुलों' में निवेश की हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है। इसके विपरीत, 'धातु और धातु उत्पादों' में निवेश का हिस्सा 2012-13 से 2019-20 के दौरान अपने हिस्से की तुलना में काफी कम रहा, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में इसमें सुधार हुआ (चार्ट 1)।

बिजली क्षेत्र के भीतर, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में परियोजना घोषणाएं 2021-22 के दौरान प्रमुख रहीं, जो अक्षय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलों को दर्शाती हैं (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: अक्षय ऊर्जा पर जोर

पर्यावरण और समग्र अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, दुनिया भर के अधिकांश देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से गैर-पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में स्थानांतरित करने के अपने प्रयास कर रहे हैं। कई विकसित और विकासशील देशों ने समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पेरिस में पार्टियों के वार्षिक सम्मेलन (सीओपी)-21 के दौरान, भारत ने भी प्रतिबद्धता जताई कि वह 2030

(Contd.)

तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत हासिल कर लेगा । इसके अलावा, ग्लासगो, यूके में सीओपी-26 में, माननीय भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने पांच महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की जिसमें शामिल हैं (i) भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 जीडबल्यू तक पहुंचाना और, (ii) भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत पूरा करेगा।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के अंतर्गत नवीकरणीय पुनर्खरीद दायित्व (आरपीओ) का प्रावधान, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास, उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण और सौर पैनलों के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से विद्युत पारेषण नेटवर्क का विकास, बैंकों द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋण के भाग के रूप में सौर रूफ टॉप को अनिवार्य बनाना शामिल है। अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों में छूट, नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास का समर्थन करना, स्वचालित मार्ग [3] के माध्यम से इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना।

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, भारत ने नवंबर 2021 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल किया है - प्रतिबद्ध समय सीमा से नौ साल पहले अपने एनडीसी को हासिल करने वाला पहला देश। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, मार्च 2022 तक, अक्षय ऊर्जा (परमाणु आधारित सहित) की स्थापित क्षमता लगभग 163 गीगावॉट है, जो कुल स्थापित क्षमता का 41 प्रतिशत है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति

2014 के बाद से कुल स्थापित क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 में 75.5 गीगावॉट से बढ़कर मार्च 2022 तक 156.6 गीगावॉट हो गई। महामारी के कारण आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद, जो रूस-यूक्रेन युद्ध और पवन और सौर ऊर्जा घटकों की कीमतों में वृद्धि से और बढ़ गया था, भारत 2021-22 के दौरान लगभग 15 गीगावॉट क्षमता जोड़ने में सक्षम था, जिससे मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 के अंत तक कुल स्थापित क्षमता में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आरईएन 214 की 'रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट' के अनुसार, दिसंबर 2021 के अंत में संचयी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर रहा। साथ ही, नई क्षमता वृद्धि के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा।

कुल स्थापित क्षमता में स्थापित सौर क्षमता का हिस्सा मार्च 2014 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 में 28.5 प्रतिशत और मार्च 2022 में 34.5 प्रतिशत हो गया। औसतन, 2014-2022 के दौरान अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में बड़े जल विद्युत संयंत्रों और पवन ऊर्जा का हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत और 29 प्रतिशत था (चार्ट 2)।

राज्यों में, अप्रैल 2022 तक, राजस्थान ने कुल स्थापित क्षमता में 15.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। कुल स्थापित क्षमता में, शीर्ष 5 राज्यों, अर्थात् राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की कुल हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है।

चार्ट 2: अक्षय ऊर्जा : स्थापित क्षमता (मार्च -अंत)

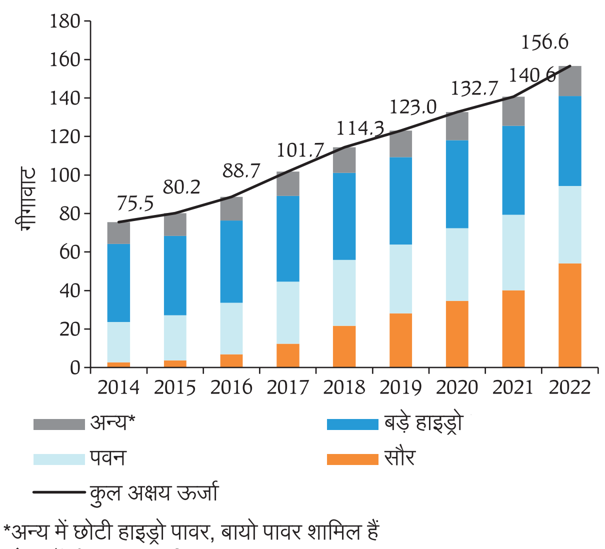

*अन्य में छोटी हाइड्रो पावर, बायो पावर शामिल हैं
स्रोत: केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण

(Contd.)

[3] https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177515

[4] आरईएन 21 वैश्विक अक्षय ऊर्जा समुदाय है, जिसे 2004 में अक्षय ऊर्जा पर बॉन 2004 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामस्वरूप बनाया गया था। इसका अधिदेश वास्तविक समय के आधार पर स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेटा के एक विशाल निकाय को एकत्र करना, समेकित करना और संश्लेषित करना है।

चार्ट 3: अपरंपरागत ऊर्जा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह

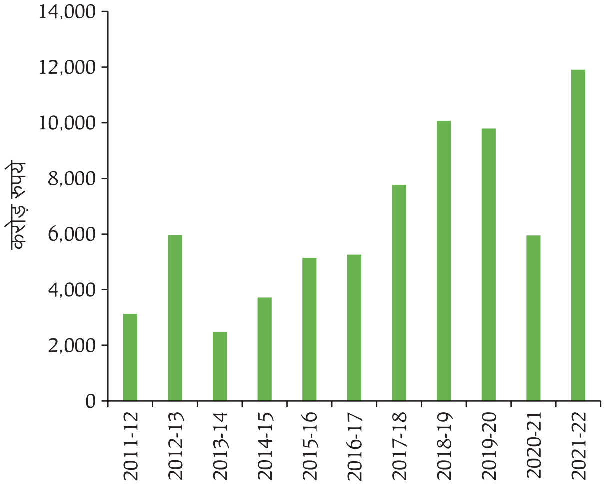

स्रोत: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

अप्रैल 2000 से मार्च 2022 के दौरान, गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र को 75,000 करोड़ रुपये का एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 2 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में गैर-पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है। 2021-22 में, इस क्षेत्र ने 11,905 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च एफडीआई इक्विटी प्रवाह पर कब्जा कर लिया (चार्ट 3)।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, अधिकांश ऊर्जा मांग अभी भी जीवाश्म ईंधन स्रोतों के माध्यम से पूरी की जाती है। इस क्षेत्र में निवेश के इरादों को मूर्त रूप देने, जैसा कि शीर्ष कंपनियों ने अपनी नवीनतम वार्षिक निवेशक बैठक में घोषणा की थी, सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों के साथ संभवतः अक्षय क्षेत्र में पर्याप्त निवेश में बदल सकता है।

(iv) राज्यवार

राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 के दौरान, आधे से अधिक (56.4 प्रतिशत) परियोजनाएं पांच राज्यों, अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शुरू की गईं इन पांच राज्यों की हिस्सेदारी 2012-13 से 2019-20 के दौरान 40.7 प्रतिशत की औसत हिस्सेदारी से बढ़कर पिछले दो वर्षों के दौरान 50.0 प्रतिशत से अधिक हो गई। (चार्ट 4 और अनुलग्नक: सारणी ए 8)।

2021-22 में, राजस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में सबसे अधिक हिस्सा

चार्ट 4: बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में मुख्य राज्यों का हिस्सा

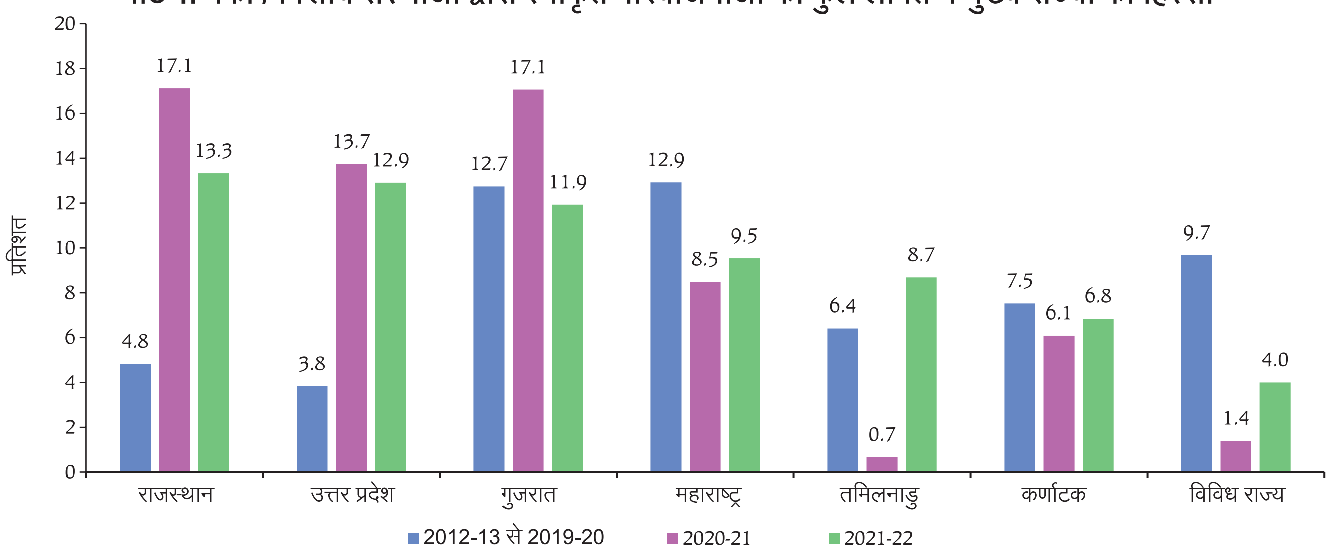

विविध राज्य: एक राज्य से अधिक राज्यों में फैली हुई परियोजनाएं
स्रोत: परियोजना वित्त से संबन्धित आंकड़े बैंकों /वित्तीय संस्थाओं एवं लेखक की स्वयं की गणना के आधार पर एकत्र किए गए हैं।

लिया, जो लगातार दो वर्षों तक शीर्ष स्थान पर बना रहा। जबकि 2021-22 के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात की हिस्सेदारी में गिरावट आई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक ने परियोजनाओं की कुल लागत में अपने हिस्से में सुधार किया (चार्ट 4 और अनुबंध: सारणी ए 8)।

4. निवेश लक्ष्यों की चरणबद्ध प्रोफाइल

विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से परिकल्पित पूंजीगत व्यय के चरणबद्ध प्रोफाइल की जानकारी पूंजीगत व्यय के अल्पकालिक (एक वर्ष आगे) पूर्वानुमान उत्पन्न करने में मदद करती है। 2021-22 में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध तरीके से संकेत मिलता है कि कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 41.8 प्रतिशत (59,897 करोड़ रुपये) उसी वर्ष खर्च होने की उम्मीद थी, जबकि 30.9 प्रतिशत (44,282 करोड़ रुपये) 2022-23 में और अन्य 17.6 प्रतिशत (25,267 करोड़ रुपये) खर्च होने की संभावना है। 2021-22 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में से 9.7 प्रतिशत 2021-22 से पहले ही खर्च किया जा चुका था। नियोजित व्यय से, बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2021-22 में परिकल्पित पूंजीगत व्यय में 3.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 2020-21 के दौरान 1,33,498 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 के दौरान 1,28,366 करोड़ रुपये हो गया (अनुबंध सारणी ए 1)।

2021-22 में ईसीबी के जरिये जुटाए गए संसाधनों से होने वाला पूंजीगत व्यय एक साल पहले के स्तर से 73.4 प्रतिशत बढ़कर 64,178 करोड़ रुपये हो गया। पूंजी बाजार (इक्विटी मार्ग) ने 2021-22 में 1,178 करोड़ रुपये के परिकल्पित पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण को सक्षम किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है (अनुबंध: सारणी ए 2, ए 3)। कुल मिलाकर, 2021-22 में निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा 1,93,722 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत व्यय निवेश किए जाने की उम्मीद थी, जो पिछले वर्ष के नियोजित चरणों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस वृद्धि को ईसीबी मार्ग के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है (अनुबंध: सारणी ए 4)।

संदर्भ वर्ष से पहले पिछले वर्षों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं [5] के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध प्रोफाइल 2021-22 में 68,469 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 71,012 करोड़ रुपये हो गया; लेकिन वित्तपोषण के सभी चैनलों के आधार पर, यह 2021-22 में 1,07,535 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 में 97,644 करोड़ रुपये पर कम रहा (अनुबंध: तालिका ए 1 और ए 4)।

V. निष्कर्ष

यह लेख निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा उनके परियोजना प्रस्तावों की चरणबद्ध योजनाओं (पूर्व-पूर्व) के आधार पर निवेश इरादों पर डेटा का उपयोग करता है ताकि कुल निवेश इरादों पर पहुंचा जा सके और निकट अवधि में निवेश गतिविधि के दृष्टिकोण का आकलन किया जा सके। महामारी की अवधि में वापस आने के बाद, 2021-22 के दौरान नई निवेश परियोजनाओं की घोषणाओं में काफी वृद्धि हुई, परियोजना की कुल लागत में 2020-21 की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे बनी हुई है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने 'बिजली' और 'सड़क और पुल' क्षेत्रों के नेतृत्व में अधिकतम पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को आकर्षित करना जारी रखा। सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों को दर्शाते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश पिछले कुछ वर्षों में आकर्षण प्राप्त कर रहा है। इससे सीओपी-26 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

आने वाले समय में निजी कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार, क्षमता उपयोग के बढ़ते स्तर, मजबूत मांग धारणा, उच्च पूंजीगत खर्च और सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलों से पूंजीगत व्यय चक्र में नई जान आने की उम्मीद है।

[5] पाइपलाइन परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो कार्यान्वयन के लिए पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। एक पाइपलाइन परियोजना से कैपेक्स किसी दिए गए वर्ष के लिए परिकल्पित राशि है, जो उस दिए गए वर्ष से पहले स्वीकृत हो गई थी।

अनुबंध

सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

स्वीकृति का वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृति के वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	रद्दीकरण के कारण परियोजना लागत - (₹ करोड़ में)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2012-13 तक				2,35,368	1,35,834	48,733	14,263	7,316	2,045						
2013-14	472	1,34,019	1,27,328 (5.0)	15,139	34,769	44,925	19,909	7,105	2,677	1,472					
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)	98	14,822	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036				
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)		3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220			
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)		1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	4,001	2,086		
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)			620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	10,202	2,342	242	
2018-19	409	1,76,581	1,59,189 (9.8)				569	6,862	11,000	59,973	47,080	21,248	9,759	2,663	35
2019-20	320	2,00,038	1,75,830 (12.1)						4,049	14,524	53,978	58,556	28,116	14,114	2,493
2020-21	220	75,558	75,558 (0.0)							2,491	3,709	29,013	26,166	9,711	4,468
2021-22	403	1,43,314									3,610	10,258	59,897	44,282	25,267
कुल और				**2,50,605**	**1,90,564**	**1,40,253**	**1,38,595**	**1,43,077**	**1,33,172**	**1,46,665**	**1,41,898**	**1,33,498**	**1,28,366**	**71,012**	**32,263**
प्रतिशत परिवर्तन					**-24.0**	**-26.4**	**-1.2**	**3.2**	**-6.9**	**10.1**	**-3.3**	**-5.9**	**-3.8**	**#**	

&: कॉलम के योग किसी विशेष वर्ष में परिकल्पित कैपेक्स को दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अनुमान पूर्व-पूर्व है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए से भिन्न हैं।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में स्वीकृत होने वाले प्रस्ताव से कैपेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

^: ब्रैकेट में आंकड़े संशोधन/रद्दीकरण का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: कैपेक्स परियोजनाओं की चरणबद्धता * ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी ** के माध्यम से वित्त पोषित**

में अनुबंधित ऋण ↓	जारी किए गए एलआरएन की संख्या	कुल अनुबंधित ऋण (₹ करोड़)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012-13 तक			53,465	22,667	6,400	1,333								
2013-14	563	80,736		56,197	20,976	3,563								
2014-15	478	57,327			36,791	16,806	3,151	575	2	2				
2015-16	314	38,885				28,998	7,311	2,572	4					
2016-17	346	22,154					14,953	6,005	1,192	2	2			
2017-18	419	37,896						17,822	13,054	6,484	529	7		
2018-19	515	72,490							46,221	17,725	1,236	5,398	1,844	66
2019-20	495	95,491								65,367	17,157	11,717	965	285
2020-21	344	40,382									18,084	21,523	642	133
2021-22	361	47,824										25,533	21,793	498
कुल और			**53,465**	**78,864**	**64,167**	**50,700**	**25,415**	**26,974**	**60,473**	**89,580**	**37,008**	**64,178**	**25,244**	**982**
प्रतिशत परिवर्तन				**47.5**	**-18.6**	**-21.0**	**-49.9**	**6.1**	**124.2**	**48.1**	**-58.7**	**73.4**	**#**	

*: वे परियोजनाएँ जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

**: 2016-17 से रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांड (आरडीबी) शामिल किए गए हैं।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में निकाले जाने वाले प्रस्तावों से कै पेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

और: अनुमान पूर्व-पूर्व है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है। वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए से भिन्न हैं।

एलआरएन : ऋण पंजीकरण संख्या

सारणी ए3: इक्विटी इश्यू के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता*

इक्विटी के दौरान जारी किया गया ↓	कंपनियों की संख्या	कैपेक्स परिकल्पित (₹ करोड़)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012-13 तक			988	494	108									
2013-14	21	454			384	70								
2014-15	24	1,078			189	557	332							
2015-16	40	4,511			11	644	2,753	849	183	71				
2016-17	29	1,159				14	471	368	163	143				
2017-18	51	1,538						419	327	787	5			
2018-19	39	609							506	90	13			
2019-20	12	53							2	49	2			
2020-21	12	663									139	421	84	19
2021-22	27	3,410									10	757	1,304	1,339
कुल और			**988**	**494**	**692**	**1,285**	**3,556**	**1,636**	**1,181**	**1,140**	**169**	**1,178**	**1,388**	**1,358**
प्रतिशत परिवर्तन				**-50.0**	**40.1**	**85.7**	**176.7**	**-54.0**	**-27.8**	**-3.5**	**-85.2**	**597.0**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में लागू होने वाले प्रस्तावों से कैपेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

और: अनुमान पूर्व-पूर्व में केवल परिकल्पित निवेश को शामिल कर रहा है, वे उनसे अलग हैं वास्तव में महसूस/उपयोग किया गया।

सारणी ए4: बैंकों/वित्तीय संस्थानों/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता*

स्वीकृति का वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या बैंक/वित्तीय संस्थान/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी/आईपीओ	परियोजना लागत (₹ करोड़)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2022-23 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012-13 तक			2,89,821	1,58,995	55,241	15,596	7,316	2,045						
2013-14	1056	2,08,518	15,139	90,966	66,285	23,542	7,105	2,677	1,472					
2014-15	828	1,45,658	98	14,822	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038				
2015-16	700	1,35,177		3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220			
2016-17	916	2,02,562		1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8,711	4,003	2,086		
2017-18	955	2,07,673			620	15,184	12,445	81,242	54,817	30,038	10,736	2,349	242	
2018-19	963	2,32,288				569	6,862	11,000	1,06,700	64,895	22,497	15,157	4,507	101
2019-20	827	2,71,374						4,049	14,526	1,19,394	75,715	39,833	15,079	2,778
2020-21	576	1,16,603							2,491	3,709	47,236	48,110	10,437	4,620
2021-22	791	1,94,548								3,610	10,268	86,187	67,379	27,104
कुल और			**3,05,058**	**2,69,922**	**2,05,112**	**1,90,580**	**1,72,048**	**1,61,782**	**2,08,319**	**2,32,618**	**1,70,675**	**1,93,722**	**97,644**	**34,603**
प्रतिशत परिवर्तन				**-11.5**	**-24.0**	**-7.1**	**-9.7**	**-6.0**	**28.8**	**11.7**	**-26.6**	**13.5**	**#**	

*: 2016-17 से रुपये में मूल्यवर्गित बांड (आरडीबी) शामिल किए गए हैं।

#: 2022-23 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2022-23 में स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों से कैपेक्स पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान पूर्व-पूर्व में केवल परिकल्पित निवेश को शामिल कर रहा है, वे उनसे अलग हैं जो वास्तव में वसूले /उपयोग किए हैं।

सारणी ए5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2012-13 से 2021-22

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	₹ 100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़	₹5000 करोड़ और ऊपर	कुल
2012-13	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	245 4.8	119 14.6	20 7.3	23 26.8	7 46.4	**414** **100 (1,89,483)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	306 8.3	115 20.0	25 13.9	21 29.1	5 28.7	**472** **100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	223 9.0	65 16.6	18 14.6	19 47.8	1 12.0	**326** **100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	214 8.6	76 20.9	34 26.0	21 38.5	1 5.9	**346** **100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	287 5.8	180 23.3	29 11.9	40 41.7	5 17.4	**541** **100 (1,79,239)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	263 5.2	149 21.0	28 10.8	42 43.8	3 19.1	**485** **100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	220 4.8	110 17.0	39 17.0	36 39.6	4 21.6	**409** **100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	150 3.3	84 11.9	45 18.6	36 37.4	5 28.8	**320** **100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	128 5.5	52 16.8	15 14.2	24 53.5	1 10.0	**220** **100 (75,558)**
2021-22	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	202 5.6	126 19.9	37 19.8	36 46.8	2 7.8	**403** **100 (1,43,314)**

टिप्पणी: i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ करोड़ में हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते हैं।

सारणी ए6: 2012-13 से 2021-22 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का प्रयोजन-वार वितरण

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	नया	विस्तार और आधुनिकीकरण	विविधता	अन्य	कुल
2012-13	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	303 84.2	107 14.7	– –	4 1.1	**414** **100 (1,89,483)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	361 65.2	95 20.1	2 –	14 14.7	**472** **100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	203 39.4	92 14.7	2 0.2	29 45.7	**326** **100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	260 73.6	64 14.3	3 0.1	19 12	**346** **100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	429 78.6	97 9.9	4 0.1	11 11.3	**541** **100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	396 89.0	80 9.5	2 0.1	7 1.5	**485** **100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	309 76.8	80 19.3	– –	20 3.9	**409** **100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	262 79.8	37 13.7	1 –	20 6.4	**320** **100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	181 94.1	38 5.9	1 –	– –	**220** **100 (75,558)**
2021-22	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत शेयर	313 89.1	89 10.8	1 0.1	– –	**403** **100 (1,43,314)**

टिप्पणी: i. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत ₹ करोड़ में हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते।

iii. -: शून्य/ नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग- वार वितरण: 2012-13 से 2021-22

उद्योग	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
आधारभूत संरचना	82	47.9	87	39.8	74	48.8	108	72.0	204	62.6	150	51.8	122	60.4	99	61.5	63	74.3	96	56.7
i) शक्ति	71	39.4	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	78	26.8	47	32.9	35	49.3	59	29.5
ii) दूरसंचार	2	5.6	1	–	1	4.9	1	0.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे	1	1.9	1	0.8	–	–	3	2.4	8	5.7	6	3.1	4	14.2	4	8.4	1	0.1	2	5.8
iv) भंडारण और जल प्रबंधन	–	–	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	13	5.7	4	0.4	5	1.2	2	0.2
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	11	3.2	8	1.3	5	2.2	3	1.1
vi) सड़कें और पुल	–	–	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	16	10.4	36	18.5	17	21.5	30	20.1
निर्माण	20	2.8	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	26	2.3	44	11.4	27	4.8	23	7.3
कपड़ा	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	27	3.4	11	0.5	15	1.8	56	4.5
विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स	10	1.9	9	2.0	7	0.2	2	0.2	9	0.2	6	0.2	1	0.1	4	–	1	0.1	5	4.0
धातु और धातु उत्पाद	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	16	3.0	14	0.8	6	0.8	27	3.9
रसायन और उर्वरक	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	19	2.9	12	1.3	9	1.6	20	3.4
सीमेंट	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	10	5.1	2	0.1	5	1.3	3	3.2
परिवहन सेवाएं	16	1.7	15	0.5	5	0.6	10	1.2	12	0.4	16	4.1	5	0.2	14	1.4	1	0.1	19	2.5
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं	17	1.4	10	0.7	2	0.1	1	–	22	1.1	18	1.8	15	2.6	12	0.7	7	0.3	19	2.3
खाद्य उत्पाद	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.4	32	1.9	20	1.5	25	1.7
दवाइयों	10	0.4	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.6	9	0.6	7	0.5	20	1.3
गैर-विद्युत मशीनरी का निर्माण	9	0.7	6	1.2	–	–	–	–	4	0.2	2	–	20	3.7	3	0.1	3	0.3	7	1.3
मुद्रण और प्रकाशन	1	–	2	4.2	1	–	1	–	3	0.1	1	0.1	–	–	1	0.6	–	–	1	1.1
कांच और मिट्टी के बर्तन	3	–	11	0.3	19	0.7	8	0.5	19	0.6	20	0.8	2	–	–	–	12	0.6	9	1.1
कोक और पेट्रोलियम उत्पाद	–	–	1	0.5	1	3.4	2	2.0	2	0.5	1	0.4	–	–	3	8.0	–	–	7	1.0
अन्य*	98	6.2	113	10.2	64	9.8	72	10.3	61	7.0	69	6.9	95	13.2	60	10.9	44	12.2	66	4.7
कुल	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**	**403**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)	**1,89,483**		**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**		**1,43,314**	

*: होटल और रेस्तरां, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, आईटी सॉफ्टवेयर, चीनी और संबद्ध उत्पाद, परिवहन उपकरण, कागज और कागज उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियां, खनन और उत्खनन, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, अन्य विनिर्माण, अन्य सेवाएं जैसे उद्योग शामिल हैं।

टिप्पणी: i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते हैं।

ii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण: 2012-13 से 2021-22

उद्योग	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
राजस्थान	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	21	7.7	23	3.8	21	17.1	33	13.3
उत्तर प्रदेश	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.5	22	3.7	30	2.4	28	4.8	24	5.6	30	13.7	33	12.9
गुजरात	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	56	11.1	47	15.1	54	17.1	83	11.9
महाराष्ट्र	67	10.7	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	34	11.5	41	6.9	13	8.5	44	9.5
तमिलनाडु	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.3	23	4.4	28	6.6	32	12.8	28	8.3	7	0.7	40	8.7
कर्णाटक	20	1.6	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	34	5.7	33	17.2	11	6.1	24	6.8
केरल	3	0.3	3	–	4	0.2	4	0.1	6	2.7	3	0.1	6	0.9	3	1.0	-	-	5	4.2
Madhya Pradesh	13	3.9	30	6.1	14	3.9	21	7.0	18	7.5	10	0.7	12	1.6	10	1.2	19	2.8	18	4.1
बिहार	7	0.1	6	0.2	4	0.1	6	0.2	4	0.2	3	0.1	6	0.4	6	3.4	1	–	5	3.3
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	10	3.8	51	5.5	17	1.9	26	9.1	12	4.0	9	1.9	15	3.0
Goa	2	0.2	-	-	-	-	1	–	3	0.6	2	1.9	3	1.8	2	0.1	-	-	3	2.9
पश्चिम बंगाल	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	13	1.1	7	0.9	3	0.4	11	2.6
आंध्र प्रदेश	35	5.7	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.1	12	4.0	7	15.0	12	2.3
ओडिशा	10	26.8	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	3.0	9	1.4	6	1.9	2	0.1	9	2.1
पंजाब	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	15	1.9	9	0.8	4	0.7	15	2.1
हरियाणा	18	1.2	15	1.1	11	1.9	16	3.6	13	1.6	21	0.5	18	1.7	20	3.4	15	7.8	14	2.0
हिमाचल प्रदेश	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	–	8	2.3	7	0.3	6	0.1	4	0.2	7	1.2
झारखंड	8	1.2	4	0.3	2	0.7	5	0.3	1	–	3	0.3	2	0.5	4	9.4	1	0.2	6	0.8
दिल्ली	4	0.6	5	0.4	2	0.1	1	0.1	5	0.3	6	1.2	8	1.3	3	0.6	2	0.1	3	0.6
छत्तीसगढ़	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.6	15	4.0	7	4.8	6	0.9	6	0.2	3	1.2	4	0.6
मल्टी-स्टेट #	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	15	9.8	8	11.7	2	1.4	7	4.0
अन्य*	26	6.8	23	5.7	12	1.3	20	1.6	28	1.3	26	5.6	29	3.0	10	0.5	12	5.2	12	0.9
कुल	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**	**403**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)	**1,89,483**		**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**		**1,43,314**	

#: कई राज्यों में परियोजनाओं का संकलन करें।

*: शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करें।

टिप्पणी: i. प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। राउंडिंग के कारण प्रतिशत कुल 100 नहीं हो सकते हैं।

ii. -: शून्य/नगण्य।

*उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर में अस्थिरता**

इस लेख में 2007 के बाद से अमेरिकी डॉलर की तुलना में चुनिंदा ईएमई की मुद्राओं की अस्थिरता की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है, जिसमें वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोज़ोन राष्ट्रीय ऋण संकट, टैपर-टंट्रम, कोविड -19 महामारी, हाल ही में रूस-यूक्रेन संघर्ष और फेड द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने जैसे उच्च अस्थिरता के प्रमुख प्रकरण शामिल हैं। यह इन प्रकरणों के दौरान भारतीय रुपये की अस्थिरता की भी जांच करता है और अत्यधिक अस्थिरता को रोकने में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का आकलन करता है। इस अध्ययन में पाया गया कि अध्ययन अवधि के दौरान आईएनआर की अस्थिरता की उम्मीदों में कमी आई है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक वैश्विक स्पिलओवर प्रेरित विनिमय बाजार दबाव के लगातार उच्च अस्थिरता प्रकरणों पर अपने हस्तक्षेप उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

परिचय

मुद्रा अस्थिरता किसी दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की आवृत्ति और सीमा का एक माप है। यह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक मानक विचलन के संदर्भ में व्यक्त किए गए माध्य के आसपास के परिवर्तनों की गणना करके मापा जाता है। इसमें संख्या जितनी बड़ी होगी, एक अवधि में अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी। एक ऐसी दुनिया में जहां बाजार-निर्धारित विनिमय दरों[1] पर मुद्राओं में बड़े पैमाने पर ट्रेड होते हैं, मुद्रा अस्थिरता में वृद्धि बहुत आम हैं। जबकि प्रमुख मुद्रा (यूएसडी, यूरो, पाउंड, येन, कनाडाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और स्विस फ्रैंक) जोड़े की अस्थिरता आमतौर पर कम होती है, वहीं उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) मुद्राओं (कभी-कभी व्यापारियों द्वारा एक्जोटिक मुद्राओं के रूप में संदर्भित) की यह अपेक्षाकृत अधिक होती है।

एक विशिष्ट मुद्रा की अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, चालू खाता घाटा, राजनीतिक स्थिरता, पण्य पर निर्भरता के साथ-साथ भू-राजनीतिक घटनाएं हैं। इसके अलावा, मुद्रा की समग्र चलनिधि भी मायने रखती है, जो इस तथ्य के अनुरूप है कि प्रमुख मुद्राओं में तथाकथित एक्जोटिक मुद्राओं की तुलना में कम अस्थिरता होती है, जिसमें प्रमुख मुद्राओं का कारोबार[2] लगभग 85 प्रतिशत होता है।

पूंजी प्रवाह और संबंधित विनिमय दर में उतार-चढ़ाव तीन मुख्य चैनलों के माध्यम से ईएमई में समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं: (i) विनिमय दर मुद्रास्फीति के माध्यम से; (ii) निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता; और (iii) घरेलू वित्तीय स्थिति। उनकी आर्थिक और वित्तीय संरचनाओं (बीआईएस, 2019) के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ईएमई में प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, ईएमई में विनिमय दर की अस्थिरता का अध्ययन सर्वोपरि महत्व का है। इस पृष्ठभूमि के साथ, यह लेख 2007 के बाद से अमेरिकी डॉलर की तुलना में चुनिंदा ईएमई की मुद्राओं की अस्थिरता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। खंड 2 में भारतीय रुपये, इंडोनेशियाई रुपिया, तुर्की लीरा, ब्राजील रियल, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, दक्षिण कोरियाई वॉन, फिलीपींस पेसो और थाई बहत के उतार-चढ़ाव के रुझान शामिल हैं (पहले पांच को टेपर टैंट्रम के दौरान 'नाजुक पांच' मुद्राएं कहा जाता था)। इस खंड में चुनिंदा मुद्राओं के उतार-चढ़ाव के रुझानों पर भी चर्चा की गई है। खंड III भारतीय रुपये की अस्थिरता की प्रवृत्ति के बारे में पड़ताल किया गया है, जबकि खंड IV सामान्य रूप से ईएमई और विशेष रूप से आईएनआर की अस्थिरता में गिरावट के कारणों पर चर्चा करता है। खंड V में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

II. चुनिंदा ईएमई मुद्राओं की अस्थिरता की प्रवृत्ति

निहित अस्थिरता की प्रवृत्ति

चुनिंदा ईएमई मुद्राओं की अस्थिरता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए, अमेरिकी डॉलर की तुलना में चुनिंदा ईएमई मुद्राओं (एक महीने की अवधि) के समान भारित निहित अस्थिरता सूचकांक की गणना की गई है। जैसा कि चार्ट 1 में देखा जा सकता

* यह लेख वित्तीय बाजार संचालन विभाग से सौरभ नाथ, विक्रम राजपूत और गोपालकृष्णन एस द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध 2020 पर आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 63 मुद्राएं 'फ्लोटिंग/ फ्री-फ्लोटिंग' ब्रैकेट में आई हैं।

[2] बीआईएस त्रिवार्षिक केंद्रीय बैंक सर्वेक्षण, 2019

चार्ट 1: अमेरिकी डॉलर की तुलना में चुनिंदा ईएमई मुद्राओं की औसत 1 महीने की निहित अस्थिरता प्रवृत्ति

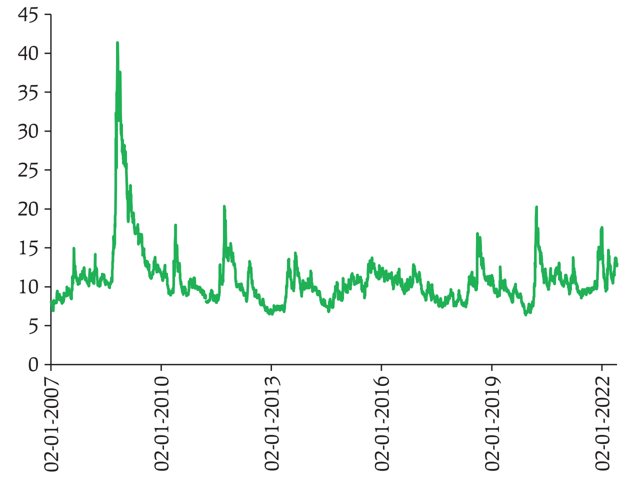

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

चार्ट 2: 1-सिग्मा चाल से अधिक उच्च अस्थिरता एपिसोड- चुनिंदा ईएमई मुद्राएं

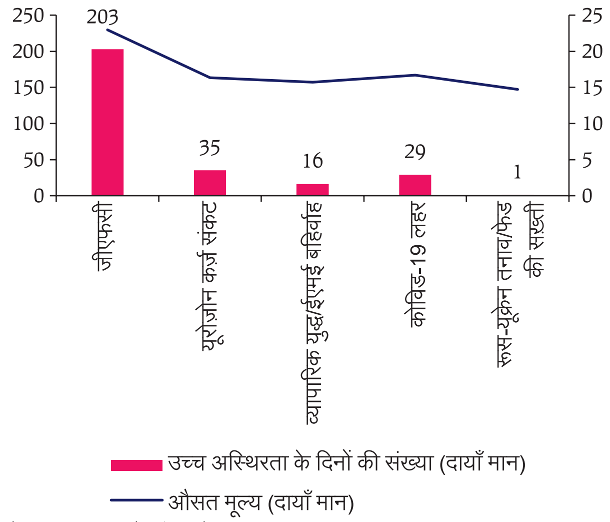

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

है, 2007 के बाद, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) (2008-09), यूरोज़ोन राष्ट्रीय ऋण संकट (2010-11), व्यापार युद्ध (2018), कोविड -19 महामारी की शुरुआत (2020), रूस-यूक्रेन संघर्ष और फेड सख्ती (2022) से अस्थिरता कई बार बढ़ी है। ईएमई मुद्राओं के लिए अस्थिरता माप जीएफसी के दौरान लगभग 40 के चरम मूल्य के साथ उच्चतम था, जबकि ऊपर उल्लिखित उसके बाद के उच्च अस्थिरता प्रकरणों में चरम अस्थिरता का स्तर कम देखा गया है।

इसमें दूसरा अवलोकन प्रत्येक प्रकरण में उस अवधि से संबंधित है जिसके दौरान अस्थिरता उच्च यानी, संगणित सूचकांक मूल्यों के एक मानक विचलन से ऊपर बनी हुई है। जैसा कि चार्ट 2 में देखा जा सकता है, यह जीएफसी में 203 व्यापारिक दिनों की अवधि में भी नीचे आ गया है, जिसमें इसका माप 14.71 के एक-सिग्मा स्तर से अधिक था, जो जारी अस्थिरता चरण (रूस-यूक्रेन संघर्ष / फेड सख्ती) (मई 2022 के अंत तक) के दौरान सिर्फ एक[3] तक आ गया। इसके अलावा, प्रत्येक प्रकरण के दौरान औसत निहित अस्थिरता भी जीएफसी के दौरान लगभग 23 से घटकर जारी अस्थिरता चरण के दौरान 15 से कम हो गई है।

आम तौर पर, मुद्रा अस्थिरता लगभग हमेशा ईएमई मुद्राओं या कम विकसित देशों के साथ जुड़ी होती है, हालांकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में अस्थिरता में वृद्धि पूरी तरह से असामान्य[4] नहीं है।

चुनिंदा ईएम मुद्राओं की ऐतिहासिक अस्थिरता की प्रवृत्ति

अमेरिकी डॉलर की तुलना में व्यक्तिगत आधार पर चुनिंदा ईएम मुद्राओं के दैनिक रिटर्न की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि अधिकांश मुद्राओं की अस्थिरता 2008-

[3] हालांकि ऐसा केवल एक दिन हुआ जब मौजूदा संकट में संगणित मान एक-सिग्मा से अधिक था, संकट शुरू होने से ठीक पहले ऐसे दिनों की संख्या 12 थी, मुख्य रूप से तुर्की लीरा में अत्यधिक उच्च अस्थिरता के कारण, 22 दिसंबर, 2021 और 6 जनवरी, 2022 के बीच यह औसतन 76% था। अस्थिरता में वृद्धि स्थानीय कारकों के कारण थी और अन्य मुद्राओं में नहीं देखी गई थी।

[4] एशियाई वित्तीय संकट (1997), रूसी वित्तीय संकट (1998) और दीर्घकालिक पूंजी प्रबंधन निधि (काई एवं अन्य) के पतन के बीच जापानी येन को अत्यधिक मूल्यह्रास दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि, 7 अक्तूबर, 1998 को, येन अचानक 133.90/ अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) से बढ़कर 120.55/यूएसडी हो गया - 1974 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ा प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया गया (फेडरल रिज़र्व बुलेटिन, 1999)। येन की तेजी से वृद्धि निवेशकों द्वारा अचानक 'येन-कैरी' ट्रेड में पोजीशन को खोलने से जुड़ी थी, जहां निधियों को शून्य के करीब ब्याज दरों पर येन उधार लिया था और फिर जापान के बाहर उच्च प्रतिफल वाली प्रतिभूतियों में निवेश किया था। बैंक ऑफ जापान ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की, जिससे जापानी प्रतिफल में वृद्धि हुई। येन ने दिसंबर 1998 को समाप्त तिमाही को 112.80 / यूएसडी पर समाप्त किया। एई मुद्रा में बढ़ी हुई अस्थिरता की एक और घटना ब्रेक्सिट से संबंधित है। 23 जून, 2016 को, यूके ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान किया जिसने बाजारों को आश्चर्यचकित कर दिया। स्टर्लिंग जो शुरू में 1.50 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, ने दशकों में अपने सबसे बड़े अंतर्दिवसीय मूल्यह्रास का अनुभव किया, जो लगभग 1.32 के स्तर तक नीचे चला गया।

चार्ट 3: चुनिंदा ईएम मुद्राओं में वन-सिग्मा से अधिक का परिवर्तन

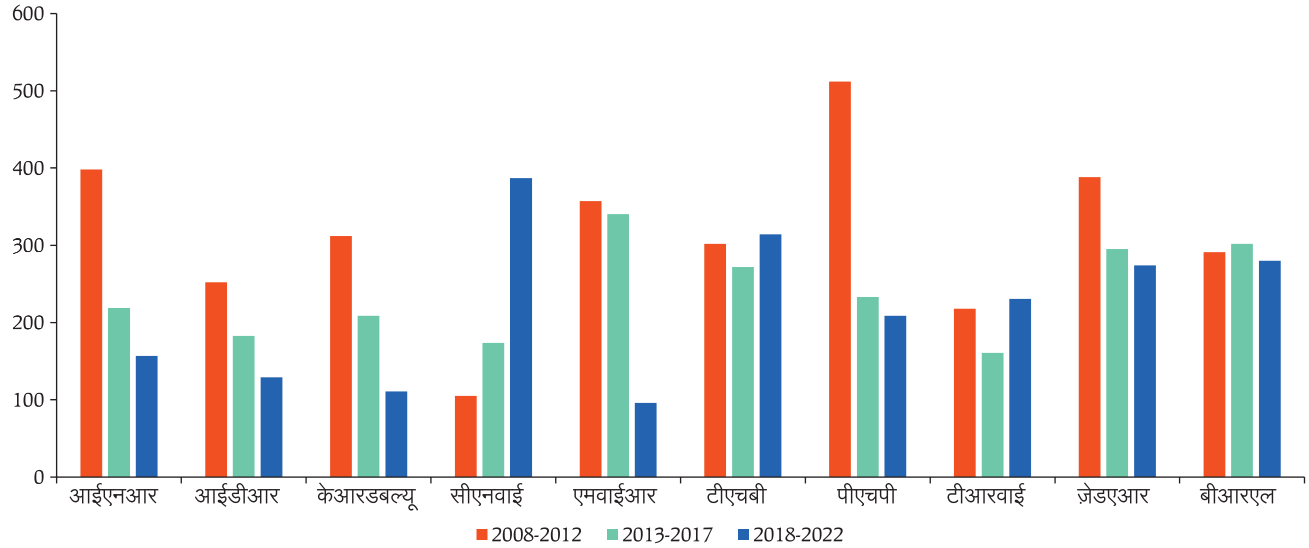

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

12 की अवधि (और ज्यादातर मामलों में 2013-17 के सापेक्ष भी) के सापेक्ष 2018 के बाद से गिर गई है। चार्ट 3 और 4 ऐसे दिनों की संख्या की ओर संकेत करते हैं, जिनमें दैनिक रिटर्न एक और दो मानक विचलन से अधिक हैं।

2008-12 के दौरान 1-सिग्मा स्तर का आईएनआर का उल्लंघन 398 दिनों से घटकर चालू अवधि में 157 दिन हो गया। जब हम दो-सिग्मा चालों पर विचार करते हैं तो आईएनआर के लिए एक समान प्रवृत्ति दिखाई देती है। जहां तक सीएनवाई की अस्थिरता में वृद्धि का संबंध है, इसे 2018 और 2019 के व्यापार-युद्ध युग के दौरान मुद्रा के मूल्यह्रास के साथ-साथ 2020 की पहली छमाही में कोविड के प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, 2017 में युआन के दैनिक निर्धारण (केंद्रीय समता दर) की गणना करने के लिए अपने मॉडल में चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा "प्रति-चक्रीय" घटक की शुरूआत ने केंद्रीय

चार्ट 4: चुनिंदा ईएम मुद्राओं में दो-सिग्मा से अधिक का परिवर्तन

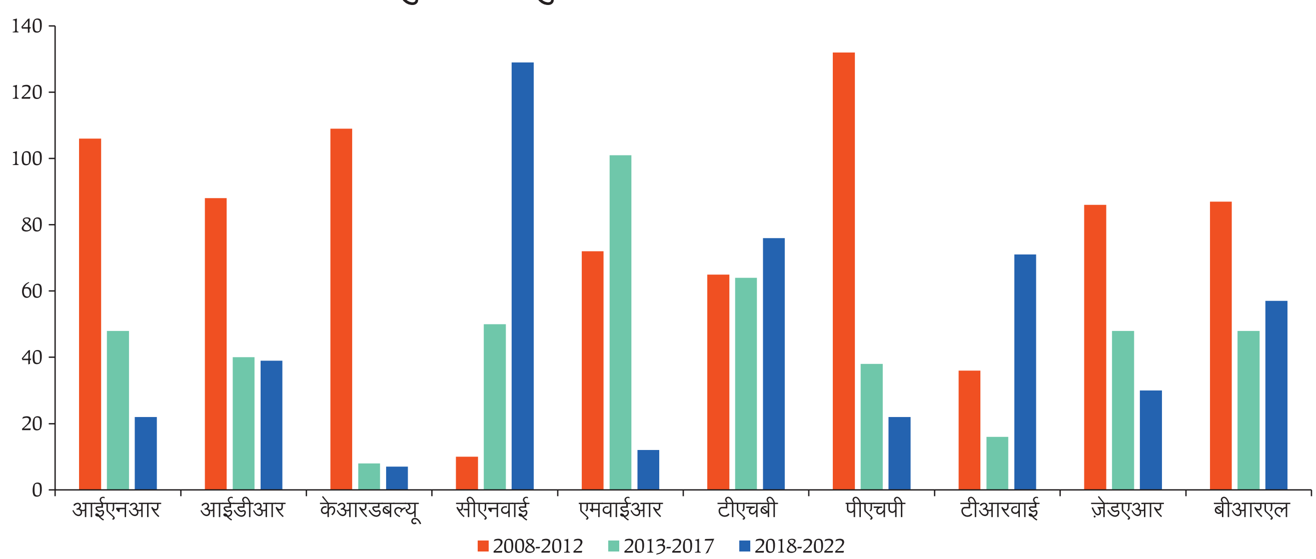

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

बैंक को मुद्रा पर अधिक नियंत्रण दिया, जिससे निवेशकों के लिए युआन के मूल्य की भविष्यवाणी करना कठिन हो गया। प्रति-चक्रीय कारक की शुरूआत को बैंक द्वारा निर्धारण के विवेकाधीन पहलू की भारिता को बढ़ाने और युआन विनिमय दर को अधिक बाजार नियंत्रित बनाने से एक कदम पीछे देखा गया (ची लो, 2017)। एक अन्य अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि युआन अवमूल्यन (हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण, 2021) के बाद रेनमिनबी की अस्थिरता 2015 से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। इसके अलावा, तुर्की लीरा (टीआरई) और थाई बहत (टीएचबी) के मामले में भी अस्थिरता बढ़ी है, हालांकि सीएनवाई की तुलना में यह कुछ कम है।

हालांकि मुद्रा अस्थिरता सामान्य रूप से आर्थिक मूल सिद्धांतों या देश विशिष्ट जोखिमों पर निर्भर करती है, डेल्टा हेजिंग जैसे कारक भी इसे बढ़ा सकते हैं (बॉक्स 1)

बॉक्स 1: डेल्टा हेजिंग के कारण मुद्राओं में अस्थिरता

ट्रेडर, मुआवजे के बदले ऑप्शन खरीदने या बेचने के लिए तैयार होकर तरलता उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उनको अल्पावधिक ऑप्शन खरीद से जुड़ी संभावित बड़ी गिरावट का खतरा हो जाता है। इस संदर्भ में, डेल्टा हेजिंग व्यापारियों को अल्पावधिक ऑप्शन खरीद के ऋणात्मक जोखिम को हेज करने की अनुमति देता है (डेल्टा – ऑप्शन ग्रीक में से एक - अंतर्निहित संपत्ति की कीमत में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन की खरीद में परिवर्तन को मापता है, जबकि गामा अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन की तुलना में डेल्टा में परिवर्तन की दर है)। हालांकि, डेल्टा-हेजिंग अपूर्ण है क्योंकि डेल्टा अंतर्निहित संपत्ति की कीमत में बदलाव के साथ बदलता है, इस प्रकार हेज के निरंतर पुनर्संतुलन की आवश्यकता होती है। उन वायदों के लिए जो इन-द-मनी या आउट-ऑफ-द-मनी हैं या एक्सपायरी से दूर हैं, डेल्टा आम तौर पर स्थिर है (गामा नीचे है), और हेज को फिर से संतुलित करने की कम आवश्यकता है। हालांकि, एट-द-मनी वायदों और / या एक्सपायरी के करीब वायदों के लिए, डेल्टा में जल्दी से उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गामा ऊँचा जा सकता है, जिसके कारण हेज पुनर्संतुलन बहुत मुश्किल हो जाता है। (इकबाल, 2018)।

ट्रेडर, ऑप्शन खरीदते समय, बीती अस्थिरता की तुलना में मुद्राओं की निहित अस्थिरता की प्रवृत्ति पर नजर रखते हैं। यदि मुद्रा-द्वय के लिए निहित अस्थिरता (जैसे- यूएसडी-भार.रु.- यूएसडी आधार मुद्रा) ऐतिहासिक मानकों से ऊपर है, जिसके परिणामस्वरूप निहित और ऐतिहासिक अस्थिरता का अनुपात 1 से ऊपर होता है, तो इसके परिणामस्वरूप यह मतलब हो सकता है कि अस्थिरता अधिक कीमत वाली है।

इस प्रकार, ट्रेडर, ऐसे ऑप्शन (उदाहरण के लिए शॉर्ट स्ट्रैडल) जो शॉर्ट गामा पोजिशन में परिणत हो जाते हैं, को बेचकर शॉर्ट वेगा (वेगा, अंडरलाइंग की अस्थिरता में परिवर्तन की तुलना में ऑप्शन पोजिशन में परिवर्तन की दर है) पोजिशन बनाने की ताक में रहते हैं। यदि ट्रेडरों की कम अस्थिरता की प्रत्याशाएँ सही हैं और ऑप्शन कांट्रैक्ट की अवधि के दौरान बाजार एक विशेष रेंज के भीतर है, तो ऑप्शन बेचने की रणनीति लाभदायक है क्योंकि प्रीमियम अर्जित किया जा सकता है। हालांकि, अगर मुद्रा अपेक्षित सीमा से बाहर टूटती है, तो यह रणनीति ट्रेडरों को असीमित जोखिम में ले जा सकती है। जितना अधिक मुद्रा में उतार-चढ़ाव होता है, उतना ही अधिक नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, यदि यूएसडी-भार.रु. का स्तर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है (यानी, भा.रु. का मूल्यह्रास होता है), तो शॉर्ट कॉल पोजिशन वाले व्यापारियों को जोखिम को हेज करने के लिए अधिक मात्रा में यूएसडी खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा, जबकि यदि स्तर तेजी से गिरता है (यानी, भार.रु. में मूल्यवृद्धि होती है), तो शॉर्ट पुट पोजिशन वाले व्यापारियों को नुकसान को सीमित करने के लिए यूएसडी बेचना पड़ सकता है। इस तरह के कार्यों का दूरस्थ प्रभाव यह है कि ऑप्शन प्लेयर बाजार की दिशात्मक प्रोफ़ाइल में सहायता करते हैं (इवान, 2019)। यही कारण भी है कि बड़े ओपन इंटरेस्ट वाले वाले ऑप्शन की समाप्ति के दौरान मुद्रा की अस्थिरता बढ़ जाती है।

स्पॉट मार्केट की अस्थिरता बढ़ जाती है - यदि ट्रेडर का हेज अनुपात, जिसके पास नेट शॉर्ट ऑप्शंस हैं (और इसलिए ऋणात्मक गामा जोखिम है), उस ट्रेडर के हेज अनुपात से अधिक है जिसके पास नेट लांग ऑप्शन हैं। इसके अलावा, टिपिकल ऑप्शन मार्केट मेकर (ओएमएम), जैसे, बड़े बैंक, गतिशील रूप से अपनी स्थिति की हेजिंग करते हैं, जबकि ऑप्शन मार्केट टेकर (ओएमटी), जैसे, निवेशक, गतिशील रूप से अपनी स्थिति को हेज नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक असममित नेट डेल्टा हेज की मांग होती है, जिससे स्पॉट मार्केट अस्थिरता में वृद्धि होती है (यदि ओएमएम शॉर्ट ऑप्शन या ऋणात्मक गामा है) और इसके विपरीत भी होता है (एंडरेग और अन्य, 2022)। हाल के कुछ अवलोकन उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। अप्रैल 2022 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में जेपीवाई का मूल्यह्रास (यह 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया) ऋणात्मक गामा पोजीशन (शॉर्ट कॉल) के कारण तेज हो गया, जबकि इसकी 1 महीने की निहित अस्थिरता 2017 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई (कोविड -19 प्रकोप को छोड़कर)। इसी तरह, युआन को, अन्य कारणों के अतिरिक्त, शॉर्ट गामा पोजिशन रखने वाले ट्रेडरों द्वारा नुकसान उठाने के कारण मूल्यह्रास दबाव में वृद्धि का सामना करना पड़ा, और इसके 1 महीने का जोखिम व्युत्क्रमण मार्च 2020 के बाद से 20 अप्रैल 2022 में उच्चतम स्तर तक बढ़ गया।

III. भारतीय रुपये की अस्थिरता की प्रवृत्ति

यह खंड विभिन्न अस्थिरता उपायों का उपयोग करके आईएनआर अस्थिरता की सामान्य प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और पाता है कि रिज़र्व बैंक आईएनआर की विनिमय दर अस्थिरता को कम रखने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जो वास्तविक अस्थिरता, अस्थिरता शंकु और अंतर दिवसीय सीमा के रुझानों में परिलक्षित होता है। इसके अलावा, अध्ययन अवधि के दौरान मुद्रा की अस्थिरता की प्रत्याशा भी कम हो गई हैं, जैसा कि निहित अस्थिरता, जोखिम व्युत्क्रमण और बटरफ्लाई आदि के रुझानों से पुष्टि होती है।

i. ऐतिहासिक अस्थिरता की तुलना में निहित अस्थिरता

यूएसडीआईएनआर की ऐतिहासिक अस्थिरता ज्यादातर समय निहित अस्थिरता से नीचे रही है (चार्ट 5)। इसके अलावा, यदि हम निहित अस्थिरता की प्रवृत्ति को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यह पिछले कुछ वर्षों में कम हो गया है। इसलिए, कभी-कभी वृद्धि के बावजूद, यूएसडीआईएनआर विकल्प प्रीमियम द्वारा परिलक्षित हेजिंग लागत में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है जो इस अवधि के दौरान भारत के समष्टि-आर्थिक और बाहरी क्षेत्र के बुनियादी सिद्धांतों में सुधार के साथ-साथ निवेशकों द्वारा प्रदर्शित विश्वास की ओर भी इशारा करती है।

चार्ट 5: भारतीय रुपए की निहित अस्थिरता की तुलना में 1 महीने की ऐतिहासिक अस्थिरता

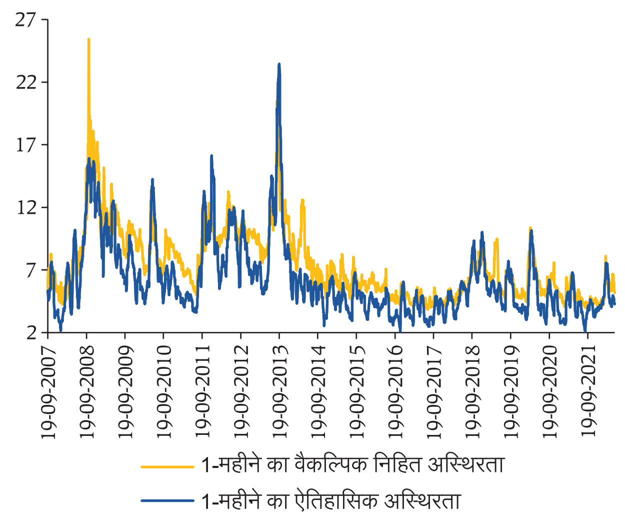

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 6: भारतीय रुपए की निहित अस्थिरता -ऐतिहासिक अस्थिरता में अंतर

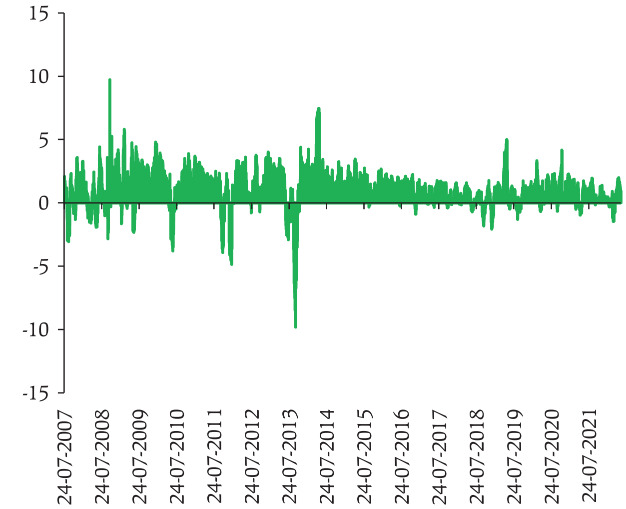

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

इसमें प्रसार न केवल ज्यादातर समय धनात्मक क्षेत्र में रहा है, बल्कि यह पिछले 15 वर्षों में संकुचित हो गया है, जिसका अर्थ है कि ऑप्शन कीमतों का उपयोग करके अनुमानित अस्थिरता इन वर्षों में अधिक सटीक हो गई है। महत्वपूर्ण रूप से, यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार अधिक प्रसारित हो गया है और इस अवधि में अधिक चल हो गया है, जिससे लिखतों के उचित मूल्य निर्धारण हो पाती है (चार्ट 6)।

ii. अस्थिरता शंकु

अस्थिरता में वृद्धि को देखने और तुलना करने का एक और तरीका अस्थिरता शंकु है, जिसे 2007 के बाद से दैनिक निहित अस्थिरता मानों का उपयोग करके प्लॉट किया जा सकता है। विशिष्ट प्रकरण के दौरान आईएनआर की उच्चतम प्राप्त अस्थिरता की तुलना निहित अस्थिरता के ऐतिहासिक उच्च, निम्न, माध्य आदि के साथ की जा सकती है, ताकि आईएनआर में उतार-चढ़ाव की चरम सीमा को मापा जा सके। हालांकि, टेपर-टंट्रम के दौरान आईएनआर की प्राप्त अस्थिरता सबसे अधिक थी, फिर भी यह अध्ययन अवधि के दौरान देखे गए उच्चतम निहित अस्थिरता मानों से नीचे है। महत्वपूर्ण रूप से, वर्तमान संकट के दौरान, एक महीने का उच्चतम प्राप्त मान औसत निहित अस्थिरता मान (चार्ट 7) के करीब है।

चार्ट 7: निहित अस्थिरता शंकु की तुलना में विभिन्न एपिसोड के दौरान प्राप्त उच्चतम अस्थिरता

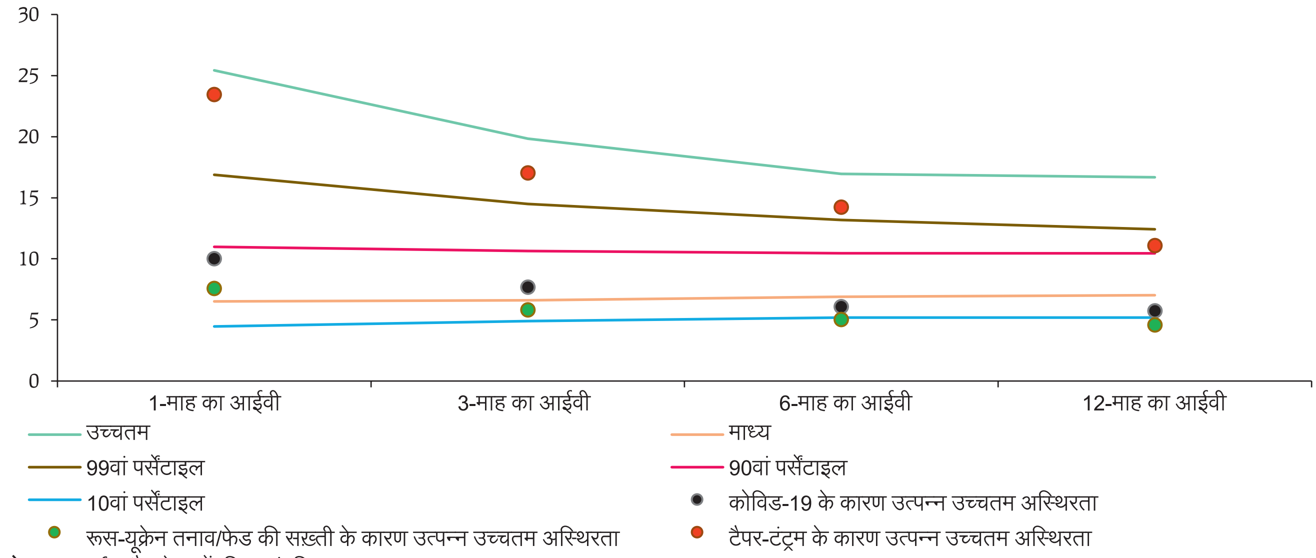

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

iii. उच्च-निम्न प्रसार

औसत उच्च-निम्न प्रसार (रुपये में) टेपर-टंट्रम की अशांत अवधि की तुलना में कम हो गया है, जबकि दैनिक स्पॉट क्लोजिंग कीमतों के प्रतिशत के रूप में स्प्रेड का औसत भी 2013 में लगभग 0.80 से घटकर 2014 में लगभग 0.40 के स्तर पर आ गया है और वर्तमान में लगभग 0.30 के स्तर पर है (चार्ट 8)।

iv. जोखिम व्युत्क्रमण

यूएसडीआईएनआर जोड़ी के 25-डेल्टा जोखिम व्युत्क्रमण[5] का उतार-चढ़ाव इस बात पर प्रकाश डालता है कि आउट-ऑफ-

चार्ट 8: भारतीय रुपए का उच्चतम-निम्नतम स्प्रेड

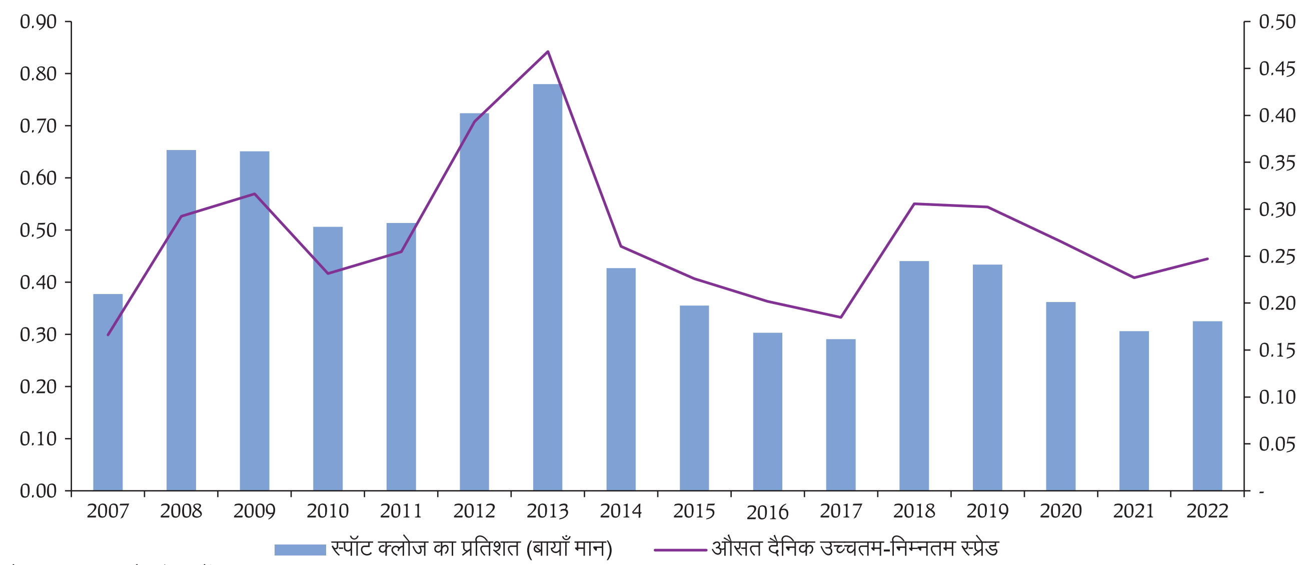

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

[5] बाजार मूल्य से अधिक खरीद और बिक्री विकल्प निहित अस्थिरता के बीच का अंतर।

चार्ट 9: भारतीय रुपए का 25-डेल्टा जोखिम का पलटना

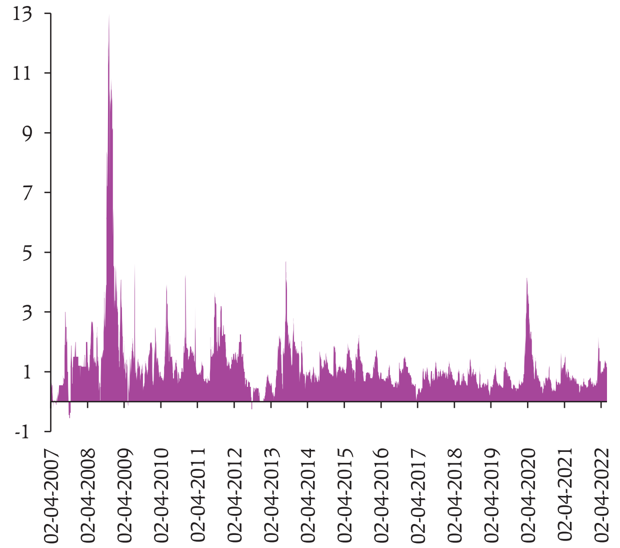

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 10: सीएनवाई की तुलना में भारतीय रुपए की 25-डेल्टा 1-माह बटरफ्लाई की प्रवृत्ति

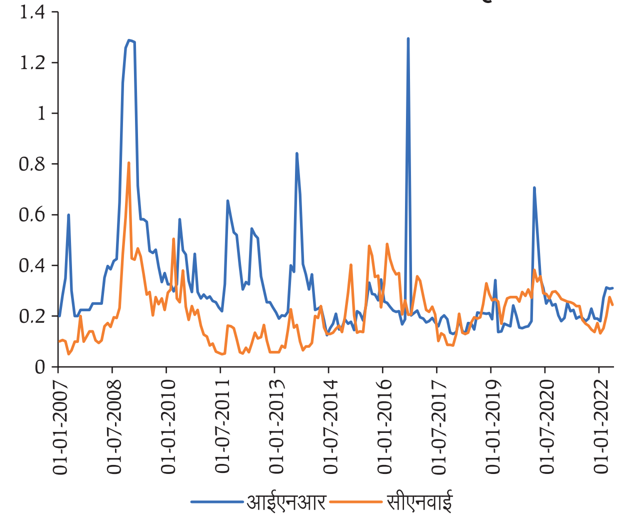

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

द-मनी कॉल विकल्प लगभग हमेशा संबंधित पुट विकल्पों की तुलना में अधिक महंगे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि भारतीय रुपये[6] के मूल्यह्रास की उम्मीदें अधिमूल्यन के प्रत्याशाओं पर हावी हैं (चार्ट 9)। बाजार हमेशा रुपये के अवमूल्यन की ओर झुका है, जो भारत और अमेरिका के बीच धनात्मक ब्याज दर अंतर को देखते हुए अपेक्षित है। हालांकि संकट की घटनाओं के दौरान वृद्धि देखे गए हैं, जो निहित अस्थिरता और आईवी-एचवी प्रसार में गिरावट की प्रवृत्ति के समान है, अध्ययन अवधि में आरआर में वृद्धि की मात्रा में गिरावट आई है, जो भारत के मजबूत आर्थिक मूल सिद्धांतों के साथ-साथ आईएनआर अस्थिरता को नियंत्रित करने में आरबीआई के कदमों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

v. बटरफ्लाइज़

यूएसडीआईएनआर के लिए एक महीने की बटरफ्लाई[7] की प्रवृत्ति 2015 के बाद उतार-चढ़ाव में एक स्पष्ट बदलाव दिखाती है। इससे पहले, 0.6 से ऊपर के उल्लंघनों के साथ बड़े परिवर्तनों की अधिक प्रत्याशाएँ थीं जो असामान्य नहीं थीं; हालांकि, 2015 के बाद, इसका मान संकुचित हो गया है, ज्यादातर समय 0.6 स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है (चार्ट 10)। इसके अलावा, आईएनआर का बटरफ्लाई माप पहले सीएनवाई से बहुत ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब यह सीएनवाई के स्तर के पास कारोबार कर रहा है, जिसका अर्थ है कि आईएनआर के लिए अधिक मात्रा में परिवर्तन की बाजार की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं और यह सीएनवाई के लगभग बराबर हैं। यह अवलोकन वर्षों से भारत के बेहतर बाहरी मैट्रिक्स के महत्व पर प्रकाश डालता है।

vi. अस्थिरता की अवधि संरचना

2009 से 2022 तक (दैनिक औसत के आधार पर) अस्थिरता की अवधि संरचना (मई 2022 के अंत तक) की प्रवृत्ति से पता चलता है कि 2009 से 2013 के बीच लगभग सभी अवधियों के लिए दैनिक औसत निहित अस्थिरता 8 प्रतिशत से अधिक मूल्य के साथ बढ़ी थी, लेकिन वक्र 2015 में 8 प्रतिशत के स्तर से पूरी तरह से नीचे चला गया (चार्ट 11)। इसके अलावा, वक्र कभी भी 7 प्रतिशत के स्तर को पार नहीं कर सका, जिसका अर्थ है कि स्थायी आधार पर सभी अवधि में रुपये की अस्थिरता की प्रत्याशा कम हो गई है।

---

6 अमेरिकी डॉलर का आधार मुद्रा होने के कारण

7 मुद्रा विकल्पों की तुलना में बाजार मूल्य से अधिक विकल्पों (कम डेल्टा विक्रय और क्रय) की मांग का माप- विकल्पों की परिपक्वता अवधि में किसी भी दिशा (बड़ी मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास) में मुद्रा में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव की अपेक्षाओं के रूप में व्याख्या की जाती है, - मूल्य जितना अधिक होगा, अपेक्षाएं उतनी ही अधिक होंगी।

चार्ट 11: अस्थिरता अवधि संरचना 2009-22

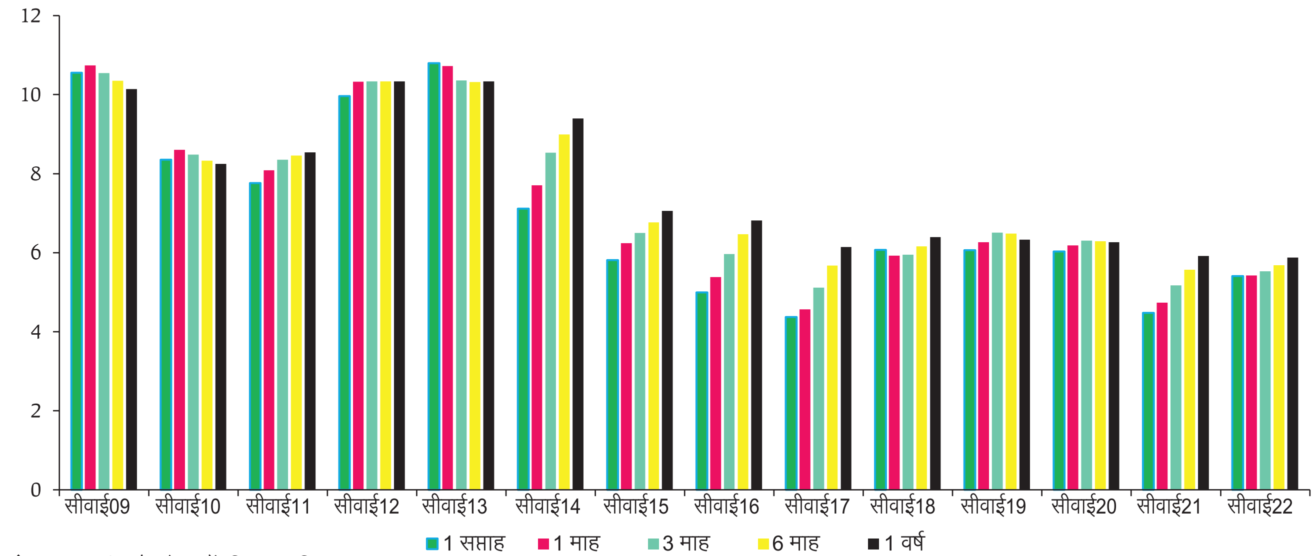

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

vii. अस्थिरता अवधि स्प्रेड

1-सप्ताह/1-महीने की अवधि की अंतर्निहित अस्थिरता के बीच स्प्रेड के रूप में मापी गई अवधि संरचना की तीव्रता, 2014 में चरम पर पहुंचने के बाद वर्षों में (2021 को छोड़कर) गिर गई है, जिसका अर्थ है कि अवधि में अस्थिरता की सकारात्मक अपेक्षाएं हैं (चार्ट 12)।

IV. ईएमई मुद्रा अस्थिरता

जीएफसी के बाद, आर्थिक स्थिति जब भी कठिन दौर में रही, एई केंद्रीय बैंकों ने बाजारों में चलनिधि की बाढ़ ला दी, जिससे आम तौर पर आस्तियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम हो गया, जिसमें उनके तुलन पत्र का बड़ा विस्तार शामिल था (चार्ट 13)। इसके अलावा, चूंकि एई केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर

चार्ट 12: भारतीय रुपए का अस्थिरता अवधि स्प्रेड

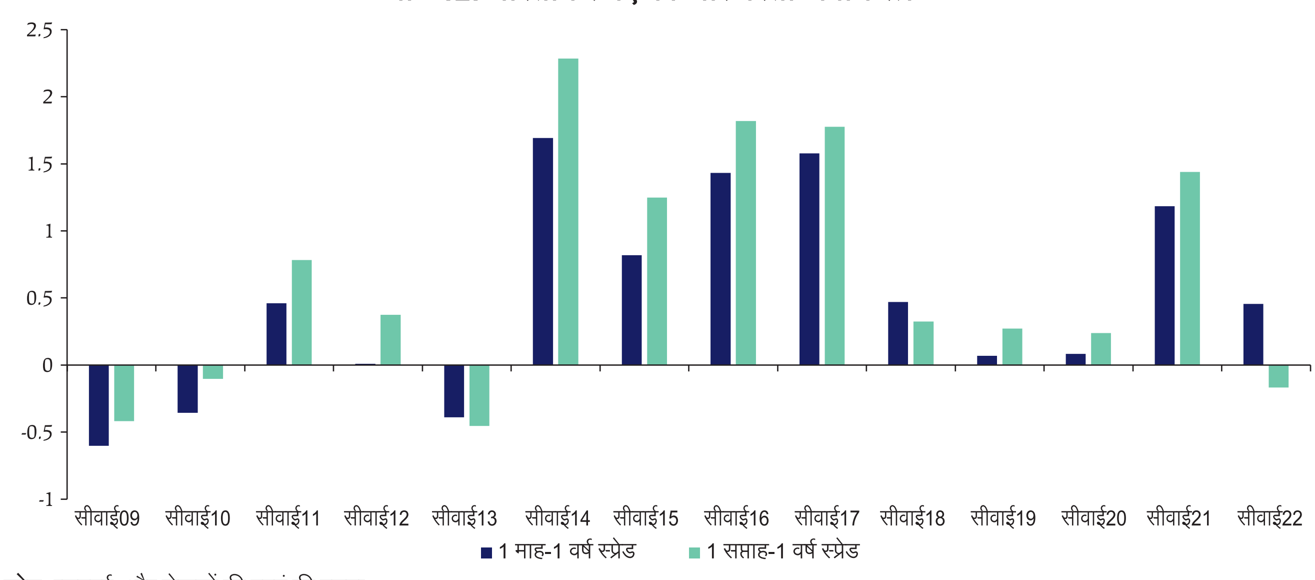

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

चार्ट 13: ईसीबी, फेडरल रिज़र्व और बैंक ऑफ जापान की आस्तियों की प्रवृति

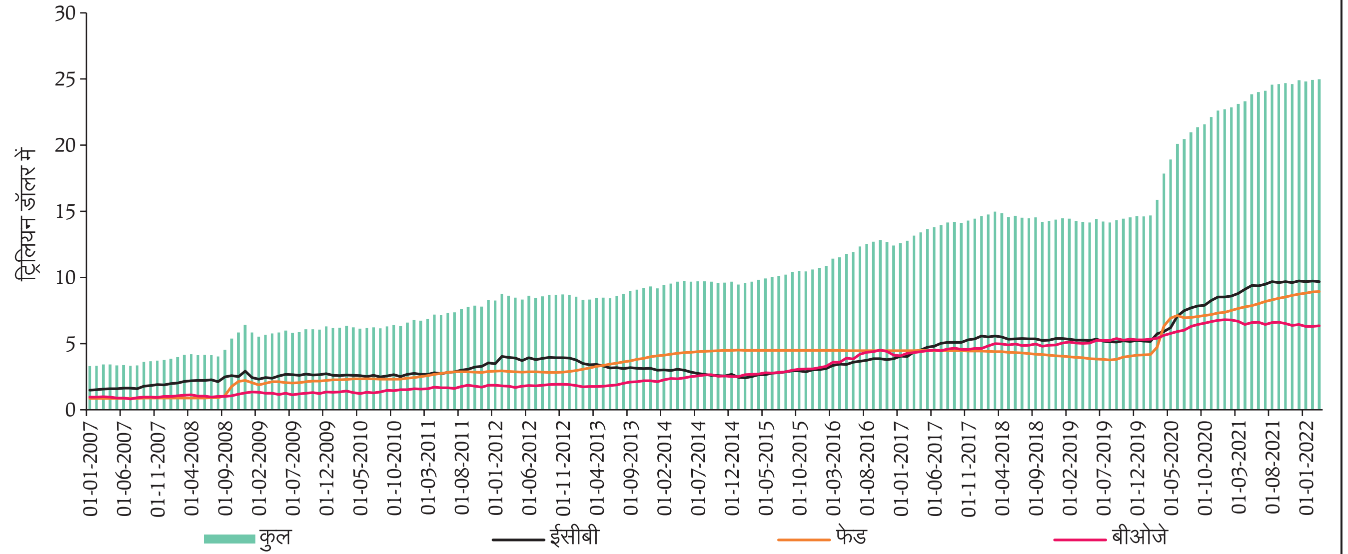

स्रोत: रिफिनिटिव; और लेखकों की स्वयं की गणना।

लॉक स्टेप में चले गए, प्रतिफल के बीच अंतर - विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रमुख चालक - भी संकुचित रहा।

समय के साथ कम ईएमई मुद्रा अस्थिरता के महत्वपूर्ण कारणों में से एक ईएमई केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार का संचय है। यह प्रवृत्ति जीएफसी के बाद स्पष्ट हो गई है, जब एई केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि का अंतः प्रवाह दर शून्य के करीब/से नीचे आ गई और प्रतिफल के लिए लालायित निवेशकों ने ईएमई (चार्ट 14 और 15) में पैसा लगाया।

ईएमई केंद्रीय बैंकों ने विभिन्न कारणों से आरक्षित निधि जमा किया। एक विशिष्ट स्पष्टीकरण आरक्षित निधि रखने की एहतियाती भूमिका पर प्रकाश डालता है, हालांकि आरक्षित निधि को अन्य कारकों के उप-उत्पाद के रूप में भी जमा किया गया था,

चार्ट 14: कुल आरक्षित निधियों में वृद्धि – चुनिंदा ईएमई

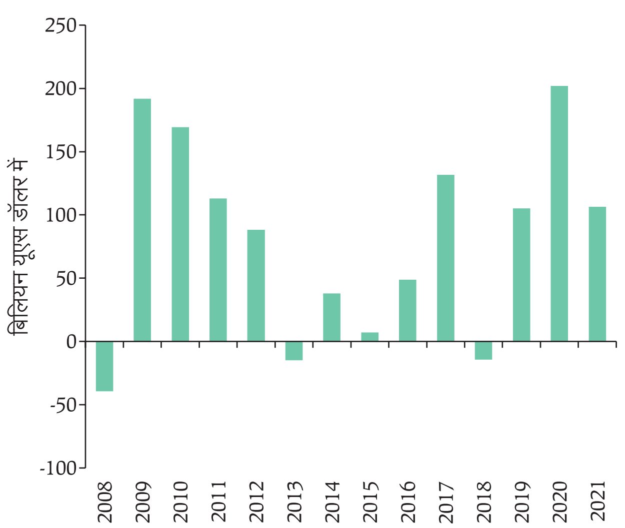

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

चार्ट 15: चुनिंदा ईएमई का कुल विदेशी आरक्षित निधि

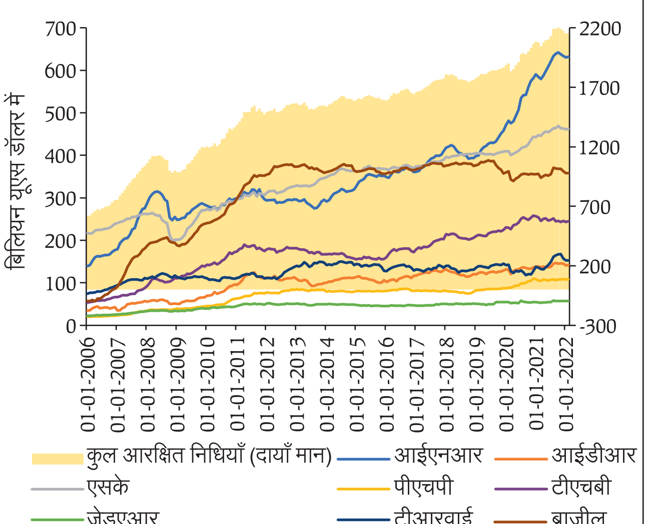

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

चार्ट 16: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, निहित और ऐतिहासिक अस्थिरता

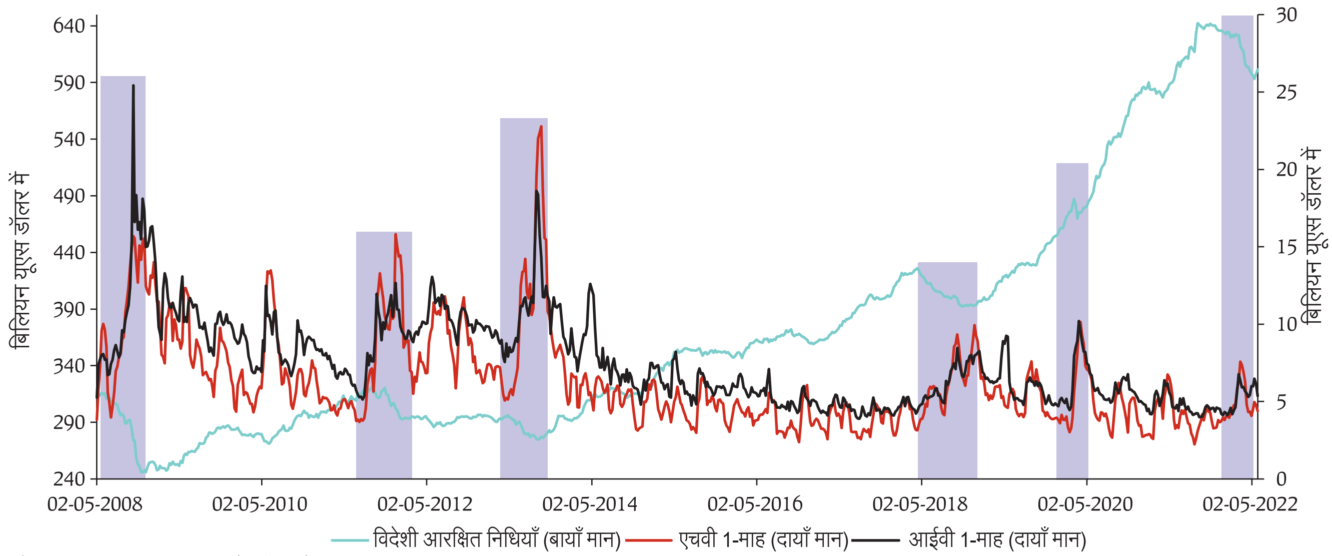

स्रोत: डीबीआईई; ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

जिसमें मूल्य और वित्तीय स्थिरता का निर्धारण और यहां तक कि निर्यात प्रतिस्पर्धा (बीआईएस, 2019) भी शामिल थी। ईएमई ने 1980 के दशक से लगातार संकट का अनुभव किया है: 1980 के दशक में लैटिन अमेरिका, 1995 में मेक्सिको, 1997 में पूर्वी एशिया, 1998 में रूस, 1994 और 2001 में तुर्की, 1999 में ब्राजील और 2002 और 2018 में अर्जेंटीना। इन संकटों की एक प्रमुख विशेषता पूंजी प्रवाह में अचानक ठहराव रही है, जिसने वित्तीय प्रणाली को बाधित किया। इसके अलावा पूरी तरह से पर्याप्त वैश्विक सुरक्षा प्रणाली के अभाव को देखते हुए, ईएमई ने स्व-बीमा के रूप में आरक्षित निधि जमा किया है। इसके अलावा, अंतर्निहित अनिश्चितता को देखते हुए, आरक्षित पर्याप्तता का आकलन करना बहुत चुनौती पूर्ण रहा है, जिसके कारण, भविष्य की तैयारी को प्रोत्साहन मिला है। जीएफसी के दौरान और बाद का अनुभव बताते हैं कि आरक्षित निधि ईएमई को तूफानी समुद्र को पार करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, जीएफसी के दौरान, अपेक्षाकृत अधिक आरक्षित निधि रखने वाले ईएमई ने छोटे मुद्रा मूल्यह्रास का अनुभव किया, जो 2013 में टेपर-टंट्रम के दौरान भी इसी प्रकार हुआ था।

रुपये की अस्थिरता में कमी

चार्ट 16 में घरेलू विदेशी मुद्रा भंडार की प्रवृत्ति के साथ-साथ रुपए की 1 माह की निहित और वास्तविक अस्थिरता के रुझानों को दर्शाया गया है, जिसमें नीले बक्से प्रमुख संकट प्रकरण के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार और अस्थिरता की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट मुख्य रूप से इन प्रकरणों के दौरान अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण है।

उच्च अस्थिरता प्रकरण में से प्रत्येक के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार (क्षैतिज अक्ष के नीचे नीला भाग) में ऋणात्मक परिवर्तन के साथ-साथ आम तौर पर वास्तविक अस्थिरता (क्षैतिज अक्ष के ऊपर लाल भाग) में धनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद अपेक्षाकृत स्थायी आधार पर वास्तविक अस्थिरता में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है (क्षैतिज अक्ष के नीचे लाल भाग) (चार्ट 17)। इसके अलावा, क्षैतिज अक्ष के नीचे नीले हिस्से की लंबाई और चौड़ाई आमतौर पर अध्ययन अवधि में कम हो गई है, जिसका अर्थ है अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में उत्तरोत्तर कम निकासी।

2020 के बाद की अवधि के लिए (वर्तमान उच्च अस्थिरता चरण की शुरुआत तक), रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा संचय हुआ है (क्षैतिज रेखा के ऊपर नीला हिस्सा)। 2017-2021 के बीच की अवधि के बड़े हिस्सों के दौरान, बड़े पैमाने पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह (2018 के दौरान गिरावट के दबाव को छोड़कर और 2020 में कोविड प्रकोप के आसपास) के कारण आईएनआर को महत्वपूर्ण वृद्धि दबाव का सामना करना

चार्ट 17: एचवी में परिवर्तन की तुलना में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में साप्ताहिक परिवर्तन

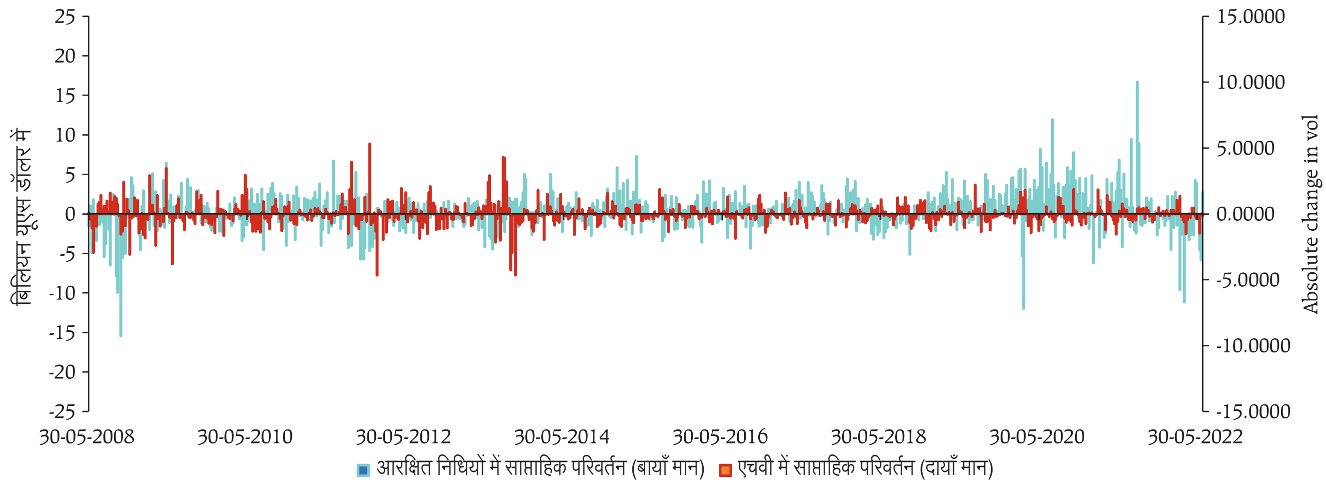

नोट: अस्थिरता के वर्तमान चरण में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में गिरावट (रूस-यूक्रेन युद्ध / फेड की सख्ती) में 2019 में आयोजित खरीद-बिक्री स्वैप (मार्च और अप्रैल 2022 में परिपक्व) के $ 10 बिलियन की बिक्री और मार्च तथा अप्रैल 2022 में आयोजित बिक्री-खरीद स्वैप के $ 10 बिलियन के बिक्री शामिल है। इस प्रकार, स्वैप नीलामी के कारण आरक्षित निधियों में कुल $ 20 बिलियन की कमी आई है

स्रोत: डीबीआईई; ब्लूमबर्ग; और लेखकों की स्वयं की गणना।

पड़ा। इसके बावजूद, इस अवधि के दौरान वास्तविक अस्थिरता कम रही है, क्योंकि आरबीआई ने आईएनआर की अस्थिरता को कम रखने के अपने उद्देश्य के अनुरूप बड़ी मात्रा में अंतः प्रवाह को अवशोषित किया है।

जीएफसी के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 70 बिलियन डॉलर की कमी आई थी जो कोविड-19 के प्रकोप के

चार्ट 18: प्रमुख संकट के समय विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में कमी

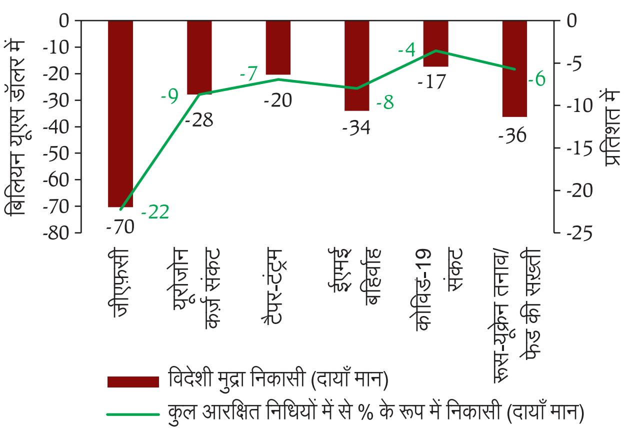

नोट: वर्तमान संकट में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में कमी (रूस-यूक्रेन तनाव / फेड की सख्ती) में स्वैप नीलामी ($ 20 बिलियन) बिक्री शामिल नहीं हैं। (कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रतिशत के रूप में परिवर्तन की गणना करने के लिए, प्रत्येक एपिसोड के आरंभ में बकाया आरक्षित निधियों को लिया गया है)।

स्रोत: डीबीआईई; और लेखकों की स्वयं की गणना।

दौरान घटकर 17 बिलियन डॉलर रह गई (चार्ट 18)। वर्तमान रूस-यूक्रेन संकट और फेड सख्ती प्रकरण में, जबकि भंडार में निकासी $ 56 बिलियन (29 जुलाई, 2022 तक) है, निवल निकासी बहुत कम है जब स्वैप नीलामी ($ 20 बिलियन) के बिक्री चरणों और मूल्यांकन नुकसान के कारण भंडार में कमी पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कुल विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का आकार जीएफसी के दौरान लगभग 22 प्रतिशत से घटकर रूस-यूक्रेन संघर्ष और फेड सख्ती प्रकरण के दौरान छह प्रतिशत हो गया है।

इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययन अवधि के दौरान भारतीय रुपये की अस्थिरता की अपेक्षाओं में सामान्य कमी के कारण और विदेशी मुद्रा भंडार के संचय और समय पर उपयोग के कारण, रिज़र्व बैंक भंडार में उत्तरोत्तर कम प्रतिशत निकासी के साथ अपने हस्तक्षेप उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

V. निष्कर्ष

लेख 2007 के बाद से अमेरिकी डॉलर की तुलना में चुनिंदा ईएमई मुद्राओं के अस्थिरता रुझानों का विश्लेषण करता है। यह वैश्विक स्पिलओवर प्रेरित विनिमय बाजार दबाव और रिज़र्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप की प्रभावशीलता के विभिन्न एपिसोड के दौरान आईएनआर की अस्थिरता में वृद्धि की भी जांच करता है। अध्ययन

में पाया गया है कि समय अवधि के साथ आईएनआर की अस्थिरता की उम्मीदों में कमी आई है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार में उत्तरोत्तर कम प्रतिशत निकासी के साथ अपने हस्तक्षेप उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

संदर्भ:

Anderegg, Benjamin, Ulmann, Florian and Sornette Didier (2022). The impact of option hedging on the spot market volatility. *Journal of International Money and Finance 124, 102627.*

Arslan, Yavuz and Carlos Cantú (2019). The size of foreign exchange reserves. *BIS Papers no. 104.*

Cai, Jun, Cheung, Yan-Leung, Lee, Raymond S.K. and Michael Melvin (2001). 'Once-in-a-generation' yen volatility in 1998: fundamentals, intervention, and order flow. *Journal of International Money and Finance.*

Egea, Ivan Delgado (2019). What is Gamma Scalping and why it matters to trade forex markets. Accessed from https://www.nasdaq.com/articles/what-gamma-scalping-why-it-matters-trade-forex-markets-2019-01-04#:~:text=In%20a%20nutshell%2C%20gamma%20scalping,of%20a%20long%20gamma%20portfolio

Bonanca, Jason J. (March 1999). Treasury and Federal Reserve Foreign Exchange Operations. *Federal Reserve Bulletin.*

How Has the Value of the Pound Changed Since Brexit?. Accessed from https://www.ig.com/en/financial-events/brexit/value-of-the-pound-since-brexit

Iqbal, Adam S. (2018). *Volatility Practical Options Theory.* Wiley.

Lo, Chi (2017). PBoC introduces a 'counter-cyclical' factor in fixing of the renminbi. Accessed from https://investors-corner.bnpparibas-am.com/investing/pboc-introduces-a-counter-cyclical-factor-in-fixing-of-the-renminbi/

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	145
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	146
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	147
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	148
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	149
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	149
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	150
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	151
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	152
9	कुल चलनिधि राशियां	152
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	153
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	153
12	वाणिज्यिकिक बैंक सर्वेक्षण	154
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	154
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	155
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	156
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	157
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	158
	कीमत और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	159
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	159
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	159
21	थोक मूल्य सूचकांक	160
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	164
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	164
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	165
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	165
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	166
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	167
28	वाणिज्यिकिक पत्र	167
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	167
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	168

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	169
32	विदेशी मुद्रा भंडार	169
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	169
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	170
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	170
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	171
37	बाह्य वाणिज्यिकिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	172
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	173
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	174
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	175
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	176
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	177
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	178
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	180
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	181
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	182
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	183
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	184
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	185
50 (ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार	186
50 (बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक	189

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2021-22	2020-21		2021-22	
		ति3	ति4	ति3	ति4
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.1	2.1	5.7	4.7	3.9
1.1.1 कृषि	3.0	4.1	2.8	2.5	4.1
1.1.2 उद्योग	9.8	6.2	11.6	1.5	1.0
1.1.3 सेवाएं	8.8	0.04	4.3	6.6	5.0
1.1ए अंतिम खपत व्यय	7.0	0.4	9.6	6.8	2.3
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	15.8	-0.6	10.1	2.1	5.1
	2021-22	2021		2022	
		मई	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	11.4	27.6	13.8	19.6	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	8.9	9.5	9.8	8.8	8.6
2.1.2 ऋण	9.6	5.9	6.1	12.5	13.3
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9.7	5.8	6.1	13.0	13.9
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6.0	11.7	10.4	6.0	6.2
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	13.0	18.3	16.9	10.4	10.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.8	10.3	10.7	8.8	7.8
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.7	4.8	4.7	5.2	5.3
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.2	70.9	71.1	72.7	73.5
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	77.2	-84.4	-56.5	129.9	235.8
3.6 निवेश-जमा अनुपात	28.7	29.9	30.1	29.1	29.5
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	19.7	65.0	87.1	76.9	124.8
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.40	4.90
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़) दर*	-	-	-	4.15	4.65
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.65	5.15
4.5 आधार दर	4.25	4.25	4.25	4.65	5.15
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.25/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.25/8.80	7.25/8.80
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.45/7.00	6.55/7.05	6.55/7.05	6.60/7.00	6.70/7.30
4.8 बचत जमा दर	5.00/5.60	4.90/5.50	4.90/5.50	5.00/5.75	5.00/5.75
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.34	3.18	3.15	4.09	4.61
4.11 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	3.40	3.44	4.89	5.16
4.12 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	3.60	3.72	5.43	5.79
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	4.58	3.73	3.89	5.91	6.29
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ	6.86	6.28	6.36	7.43	7.50
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	76.18	72.48	74.18	77.66	78.33
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.01	88.23	88.57	83.49	82.56
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमिआ 1-माह (%)	5.67	5.46	3.80	3.55	2.76
3-माह (%)	4.46	5.63	3.99	3.63	2.86
6-माह (%)	4.10	5.49	4.13	3.66	2.89
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.51	6.3	6.3	7.0	7.0
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.13	5.3	5.6	7.0	6.2
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	12.97	13.1	12.1	15.9	15.2
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	10.25	9.4	8.6	19.7	19.2
6.3.2 ईंधन और पावर	32.50	36.7	29.3	40.6	40.4
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	11.10	11.3	11.0	10.1	9.2
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	55.31	69.9	97.4	62.9	57.5
7.2 निर्यात	44.58	68.3	47.9	20.9	23.5

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

*: 8 अप्रैल 2022 दिनांकित प्रेस अधिसूचना सं.2022-2023/41के अनुसार।

#: 3 दिसंबर, 2021 से सभी पखवाड़ों के लिए बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2021-22	2021	2022				
		जुला.	जुला. 1	जुला. 8	जुला. 15	जुला. 22	जुला. 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3107637	2919525	3173670	3196521	3187360	3175269	3156104
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	15	15	11	10	10	10	10
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3107652**	**2919541**	**3173681**	**3196531**	**3187371**	**3175279**	**3156114**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	128208	115119	122763	118767	116429	116802	119129
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2978927	2803636	3050543	3077216	3070418	3057985	3036520
1.2.3 रुपया सिक्का	518	786	374	548	524	492	465
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1794574	1959069	1677967	1632175	1591629	1568546	1543010
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	101	100	101	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	43	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	683437	674997	793717	757839	795474	754119	834457
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7123	7455	8759	7812	8102	7791	8140
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4121	3582	4627	4560	4616	4361	4384
2.1.1.7 अन्य बैंक	37589	37177	43587	42971	43317	43071	45065
2.1.1.8 अन्य	988819	1209139	777358	763674	698159	719843	600009
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	73343	26576	49776	55177	41817	39218	50814
2.1.2 अन्य देयताएं	1359254	1383256	1283483	1275026	1285485	1320659	1336039
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3153828**	**3342325**	**2961451**	**2907202**	**2877114**	**2889205**	**2879049**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	15	15	11	10	10	10	10
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1243853	1511979	1118348	1056765	1042506	1046147	1042764
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	670	836	12424	17624	17760	12688	6083
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	94299	91796	94828	94618	95337	109704	94387
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	24927	16731	14857	14857	14857	14857	9668
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	8077	6609	31028	31028	31028	31821	32683
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	72741	26670	49884	55237	41872	39351	50932
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	1491042	1518026	1436900	1438165	1436690	1436458	1439687
2.2.6 अन्य आस्तियां	218203	169662	203171	198898	197052	198169	202834
2.2.6.1 स्वर्ण	201354	164967	196292	191932	189987	190964	195144

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तनशील रिपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	बाज़ार स्थिरीकरण योजना		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून 1, 2022	-	-	-	-	304	194418	–	-	-	-194114
जून 2, 2022	-	-	-	-	100	181860	1300	-	-	-180460
जून 3, 2022	-	-	-	64965	547	369177	4000	-	-	-429595
जून 4, 2022	-	-	-	-	11	36922	–	-	-	-36911
जून 5, 2022	-	-	-	-	6	3279	–	-	-	-3273
जून 6, 2022	-	-	-	-	313	357750	8545	-	-	-348892
जून 7, 2022	-	-	-	-	302	354623	–	-	-	-354321
जून 8, 2022	-	-	-	-	6	366780	–	-	-	-366774
जून 9, 2022	-	-	-	-	0	359114	–	-	-	-359114
जून 10, 2022	-	-	-	-	0	392400	–	-	-	-392400
जून 11, 2022	-	-	-	-	163	8240	–	-	-	-8077
जून 12, 2022	-	-	-	-	115	7042	–	-	-	-6927
जून 13, 2022	-	-	-	-	305	395240	–	-	-	-394935
जून 14, 2022	-	-	-	33456	310	398525	-2	-	-	-431673
जून 15, 2022	-	-	-	-	102	384055	–	-	-	-383953
जून 16, 2022	-	-	-	-	100	324432	–	-	-	-324332
जून 17, 2022	-	-	-	165184	7	166192	–	-	-	-331369
जून 18, 2022	-	-	-	-	107	24184	–	-	-	-24077
जून 19, 2022	-	-	-	-	44	2182	–	-	-	-2138
जून 20, 2022	-	-	-	-	572	152479	–	-	-	-151907
जून 21, 2022	-	-	-	-	85	146287	-5500	-	-	-151702
जून 22, 2022	-	-	-	-	3054	145947	–	-	-	-142893
जून 23, 2022	-	-	-	-	56	130406	–	115	-	-130465
जून 24, 2022	-	-	-	-	219	133218	1000	185	-	-132184
जून 25, 2022	-	-	-	-	226	5525	–	-	-	-5299
जून 26, 2022	-	-	-	-	27	5000	–	-	-	-4973
जून 27, 2022	-	-	-	-	175	149138	–	-	-	-148963
जून 28, 2022	-	-	-	-	181	168722	–	-	-	-168541
जून 29, 2022	-	-	-	-	3411	186977	450	-	-	-183116
जून 30, 2022	-	-	-	-	640	223562	–	-	-	-222922

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा, एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	17312	18633	2001	-3719
1.1 क्रय (+)	113991	21923	10143	18960
1.2 विक्रय (-)	96679	3290	8142	22679
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	134629	138217	14789	-29401
3 संचयी (मार्च के के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	17312	28687	3966	247
(करोड़ ₹)	134629	213952	28850	-551
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	65791	49573	49191	30856

ii) मुद्रा वायदा भाग में परिचालन

मद	2021-22	2021	2022	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	2370	550	2085	3570
1.2 विक्रय (-)	2370	550	2085	3570
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	0	-1200	-2406

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	30 जून 2022 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	5596	15386	-9790
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	12713	1389	11324
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	21037	1850	19187
4. 1 वर्ष से अधिक	10135	0	10135
कुल (1+2+3+4)	**49481**	**18625**	**30856**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2021-22	2021	2022					
		जुला. 30	फर. 25	मार्च 25	अप्रै. 22	मई 20	जून 17	जुला. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	11	254	1858	11	140	1009	7	139
3.1 सीमा								
3.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया								
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 Outstanding	–	0	0	0	0	0	0	1655
4 Others								
4.1 Limit	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 Outstanding	32401	23296	24401	32401	31021	35521	49364	40314
5 Total Outstanding (1+2.2+3.2+4.2)	32412	23550	26259	32412	31161	36530	49371	42108

टिप्पणीः 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्ज़िम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिड़बी/एनएचबी यू /एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2021-22	2021	2022		
		जून 18	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3035689	2887260	3117960	3095774	3102251
1.1 संचलन में नोट	3105703	2961524	3197840	3195019	3198495
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	27270	26252	27417	27550	27550
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	98028	101259	108039	127538	124537
2 जनता की जमाराशियां	2271436	1937646	2180138	2179351	2141695
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	2212992	1887452	2126310	2124931	2087340
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	50194	53828	54419	54355
3 एम$_1$ (1 + 2)	**5307125**	**4824907**	**5298098**	**5275125**	**5243946**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	187061	172973	187061	187061	187061
5 एम$_2$ (3 + 4)	**5494186**	**4997880**	**5485159**	**5462186**	**5431007**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	15186605	14344659	15384209	15544774	15417971
7 एम$_3$ (3 + 6)	**20493729**	**19169565**	**20682307**	**20819899**	**20661917**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	1008539	897007	1008539	1008539	1008539
9 एम$_4$ (7 + 8)	**21502268**	**20066572**	**21690846**	**21828438**	**21670456**

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जून 18	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**6477629**	**5921492**	**6264552**	**6337282**	**6261159**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1450596	1049521	1196325	1192830	1081805
1.1.1 सरकार पर दावे	1490991	1487439	1449291	1442983	1434456
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1489324	1475641	1440787	1431610	1426587
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1667	11799	8504	11372	7869
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	40394	437918	252966	250153	352651
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	40352	437875	252924	250110	352608
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	5027033	4871971	5068228	5144452	5179354
2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**12616520**	**11552794**	**12769728**	**12876990**	**12901572**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिकिक क्षेत्र को ऋण	16571	5749	15275	20613	29081
2.2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	12599950	11547046	12754453	12856377	12872491
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	11891314	10841852	12038120	12141035	12150353
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	690201	687562	699492	698653	695940
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18435	17631	16841	16689	26198
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**4854063**	**4777903**	**4895017**	**4920752**	**4869550**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4442479	4434553	4483433	4509169	4457966
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4442720	4434789	4483667	4509403	4458204
3.1.2 विदेशी देयताएं	241	237	234	234	238
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	411583	343350	411583	411583	411583
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**28013**	**26995**	**28160**	**28293**	**28293**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**3482496**	**3109620**	**3275150**	**3343418**	**3398657**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1308500	1349809	1253040	1268376	1212556
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	2173996	1759811	2022109	2075042	2186101
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**20493729**	**19169565**	**20682307**	**20819899**	**20661917**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जून 18	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	5307125	4824907	5298098	5275125	5243946
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	12081049	11211401	12162730	12212473	12124564
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	20634885	19266197	20946605	21069433	20905548
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	2887260	3117960	3095774	3102251
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	17266157	16079663	17381047	17541261	17377601
1.2.1 मांग जमाराशियां	2212992	1887452	2126310	2124931	2087340
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	15053166	14192211	15254737	15416330	15290260
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6773925	6386495	6864632	6937348	6880617
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	68603	187763	190825	178170
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	8279241	7805716	8390105	8478981	8409643
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	50194	53828	54419	54355
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	274594	249080	393770	377979	371341
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	20080599	18443526	20122082	20300935	20253679
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	5921492	6264552	6337282	6261159
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1450596	1049521	1196325	1192830	1081805
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	5027033	4871971	5068228	5144452	5179354
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	13602969	12522034	13857529	13963654	13992520
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	39581	7433	38358	43779	52248
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13563389	12514601	13819171	13919874	13940272
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	952181	954872	1050868	1051168	1051364
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	26995	28160	28293	28293
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4705191	4691971	4708895	4715929	4599366
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4434553	4483433	4509169	4457966
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	262711	257419	225461	206760	141399
2.4 पूंजी खाता	3021858	2976399	3256699	3275018	3256980
2.5 अन्य मदें (निवल)	1157060	919896	655832	700705	718810

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2021-22	2021	2022		
		जून	अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**20630753**	**19266197**	**20859403**	**20946605**	**20905548**
2 डाकघर जमाराशियां	594633	528490	594633	594633	594633
3 एल$_1$ (1 + 2)	**21225386**	**19794687**	**21454036**	**21541238**	**21500181**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	49578	25961	41050	30285	51696
4.1 सावधि मुद्रा उधार	1824	3420	1758	2044	2136
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	39170	17525	39170	28070	41045
4.3 सावधि जमाराशियां	8584	5016	122	171	8514
5 एल$_2$ (3 + 4)	**21274964**	**19820648**	**21495085**	**21571524**	**21551877**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	66542	67234	..	..	66542
7 एल$_3$ (5 + 6)	**21341506**	**19887882**	..	..	**21618419**

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जून 18	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2988519	3226000	3223312	3226788
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	715442	863500	854952	856083
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	823632	669032	810295	799046	800142
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	50194	53828	54419	54355
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4068887	3754155	4143328	4132684	4137226
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	906895	642416	884775	863598	863522
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1450596	1049521	1196325	1192830	1081805
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1448972	1037765	1187863	1181500	1073979
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1488816	1474980	1440459	1431127	1426161
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1488816	1474980	1440459	1431127	1426161
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	508	661	329	483	426
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	40352	437875	252924	250110	352608
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1624	11756	8461	11330	7826
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-583282	-414538	-349908	-373011	-270530
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-560272	-412854	-326824	-349845	-247364
2.1.3 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	39581	7433	38358	43779	52248
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	23010	1684	23084	23167	23167
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	26995	28160	28293	28293
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4434553	4483433	4509169	4457966
2.3.1 सोना	322213	265576	316885	316976	316922
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4120283	4168994	4166566	4192210	4141062
2.4 पूंजी खाता	1254092	1250419	1365613	1381305	1359593
2.5 अन्य मदें (निवल)	54408	99390	-112573	-112929	-147037

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2021	2022				
		जून 25	मई 27	जून 3	जून 10	जून 17	जून 24
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4068887	3698987	4092142	4132684	4105588	4137226	4104025
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3133716	2980029	3219429	3223312	3238417	3226788	3217603
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	876726	668838	817317	854952	812875	856083	831996
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	58444	50120	55395	54419	54296	54355	54425
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1450596	1017177	1128141	1192830	1176680	1081805	1028590
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-560272	-452721	-309121	-349845	-373615	-247364	-222543
2.3 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	16571	6048	15275	20613	29158	29081	32581
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4467940	4510138	4509169	4489218	4457966	4493097
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	28013	27053	28293	28293	28293	28293	28451
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1308500	1366509	1280583	1268376	1244146	1212556	1256151

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2021-22	2021	2022		
		जून 18	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	16331874	15146092	16444802	16605194	16441606
1.1.1 मांग जमाराशियां	2072747	1751739	1985767	1984242	1946297
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	14259128	13394353	14459035	14620952	14495309
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6416607	6027459	6506566	6579428	6522889
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	176718	68603	187763	190825	178170
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7842520	7366894	7952469	8041524	7972420
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	274594	249080	393770	377979	371341
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	17575002	16382691	17864954	18040452	18098650
2.1.1 सरकार को ऋण	4728179	4580580	4770031	4843895	4878940
2.1.2 वाणिज्यिकिक क्षेत्र को ऋण	12846823	11802110	13094923	13196557	13219710
2.1.2.1 बैंक ऋण	11891314	10841852	12038120	12141035	12150353
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	11836304	10754940	11984866	12092407	12106795
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11522	12947	14113	12592	16680
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	769	1402	784	724	10274
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	943218	945909	1041906	1042206	1042402
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	262711	257419	225461	206760	141399
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	465464	470862	426756	407909	337352
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	133439	152448	129472	128444	127711
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	69314	60996	71822	72705	68242
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1268887	1171851	1232851	1263991	1159593
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	683437	669032	810295	799046	800142
2.3.2 उपलब्ध नकदी	85926	89965	95732	115100	112088
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-499524	-412854	-326824	-349845	-247364
2.4 पूंजी खाता	1743595	1701809	1866915	1869543	1873217
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	756537	714979	617779	658487	713478
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	571535	514429	565536	591451	598531
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	26533	62888	7741	3913	14199

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	25 मार्च 2022 की स्थिति	2021	2022		
		जून 18	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4728948	4581982	4770815	4844619	4889215
2 वाणिज्यिकिक पत्र LR)	-	-	160644	160365	159993
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर	55315	81474	58764	62124	61279
3.1 सरकारी उद्यम					
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	7642	10554	9784	10579	10497
3.3 अन्य	73814	68931	72112	70186	69508
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	5152	5125	5133	5073	5057
4.1 सरकारी उद्यम					
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	117860	113821	98683	93899	95727
4.3 अन्य	326188	321962	315849	306441	304928
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत	148753	153305	91104	92775	94188
5.1 म्यूचुअल फंड					
5.2 वित्तीय संस्थाएं	34404	39269	59599	50492	53431
				90273	187793

टिप्पणी : कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के डेटा अंतिम हैं, और कॉलम (4) एवं (5) के डेटा अनंतिम हैं।

'_': डेटा उपलब्ध नहीं है।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिकिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2021-22	2021	2022		2021-22	2021	2022	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बेंकों की संख्या	212	210	212	212	136	134	136	136
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**262674**	**240051**	**281473**	**285296**	**258649**	**235512**	**277568**	**281448**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	194143	181695	196517	192746	190570	177399	193068	189411
1.2 बैंकों से उधार राशि	38369	39462	50013	52754	38317	39456	50009	52745
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30162	18893	34943	39795	29762	18656	34491	39292
2 अन्य के प्रति देयताएं	**17832517**	**16517473**	**18094184**	**18047680**	**17380755**	**16078860**	**17645370**	**17603773**
2.1 कुल जमाराशियां	16899634	15692029	17028142	17018222	16465313	15272352	16597227	16592091
2.1.1 मांग	2117513	1788412	2030246	2000070	2072747	1748636	1985304	1953699
2.1.2 मीयादी	14782121	13903617	14997895	15018151	14392567	13523716	14611923	14638392
2.2 उधार	278985	257970	399209	376888	274594	252064	393281	371389
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	653898	567473	666833	652571	640848	554444	654863	640293
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**94299**	**90829**	**94368**	**94514**	**94299**	**90829**	**94368**	**94514**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	94299	90829	94368	94514	94299	90829	94368	94514
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	788725	732251	881424	900289	769363	713780	859658	878021
4.1 उपलब्ध नकदी	88732	93470	100874	105043	85926	91424	97922	101501
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	699993	638780	780550	795246	683437	622356	761736	776521
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**315282**	**245133**	**342124**	**351424**	**243637**	**188930**	**278517**	**290779**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	199434	169444	228875	226853	164240	134552	193977	192752
5.1.1 चालू खाते में	19733	16908	16545	16123	16691	14204	13681	13390
5.1.2 अन्य खातों में	179701	152536	212330	210730	147549	120347	180296	179362
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36905	26459	33081	39864	6982	9180	9843	18581
5.3 बैंकों को अग्रिम	39340	21525	31176	28852	35802	19910	29323	27414
5.4 अन्य आस्तियां	39603	27706	48992	55855	36613	25288	45374	52032
6 निवेश	**4874070**	**4739506**	**4973070**	**5031395**	**4728948**	**4601130**	**4830428**	**4887253**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4867102	4732584	4966935	5025387	4728179	4599956	4829622	4886445
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6968	6922	6135	6008	769	1175	806	807
7 बैंक ऋण	**12259048**	**11197090**	**12431471**	**12558512**	**11891314**	**10859820**	**12062731**	**12190256**
7क खाद्यान्न ऋण	90827	121177	96386	86635	55011	85358	50666	40915
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	12016486	10996327	12193291	12324542	11651337	10661149	11827177	11958930
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	36070	29559	34607	32204	36055	29544	34590	32188
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	155796	116154	155143	151301	154212	114793	153369	149482
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	19537	20268	20987	19739	19157	20057	20703	19518
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	31160	34783	27444	30727	30554	34277	26892	30138

टिप्पणी : कॉलम (4) एवं (8) के डेटा अनंतिम हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 18	मई 20	जून 17	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	**11891314**	**10736583**	**12027305**	**12149034**	**2.2**	**13.2**
II. खाद्यान्न ऋण	**55011**	**86912**	**53254**	**43559**	**-20.8**	**-49.9**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**11836304**	**10649671**	**11974051**	**12105475**	**2.3**	**13.7**
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**1461350**	**1328731**	**1482029**	**1500875**	**2.7**	**13.0**
2. उद्योग	**3152449**	**2894061**	**3165450**	**3168168**	**0.5**	**9.5**
2.1 सूक्ष्म और लघु[1]	532081	427870	551488	554398	4.2	29.6
2.2 मझौले	213996	149554	218501	220669	3.1	47.6
2.3 बड़े	2406372	2316637	2395460	2393101	-0.6	3.3
3. सेवाएं	**3017116**	**2721667**	**3037964**	**3070538**	**1.8**	**12.8**
3.1 परिवहन परिचालक	155353	139360	151538	152045	-2.1	9.1
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20899	19965	19235	19687	-5.8	-1.4
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	64369	59574	64100	63973	-0.6	7.4
3.4 शिपिंग	8437	7239	7617	7205	-14.6	-0.5
3.5 नौवहन	23979	28190	22381	21733	-9.4	-22.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	116743	109121	119495	120107	2.9	10.1
3.7 व्यापार	696349	628496	713178	733416	5.3	16.7
3.7.1 थोक व्यापार	351228	324592	369485	384026	9.3	18.3
3.7.2 खुदरा व्यापार	345121	303904	343693	349390	1.2	15.0
3.8 वाणिज्यिकिक स्थावर संपदा	291168	289057	301170	298732	2.6	3.3
3.9 गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1078447	909042	1093282	1101044	2.1	21.1
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	278979	253069	287920	283992	1.8	12.2
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	144121	85384	142580	140173	-2.7	64.2
3.10 अन्य सेवाएं [3]	561373	531624	545968	552596	-1.6	3.9
4 व्यक्तिगत ऋण	**3385827**	**2980902**	**3466512**	**3520062**	**4.0**	**18.1**
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27613	17178	29588	30461	10.3	77.3
4.2 आवास	1684424	1511985	1707462	1740921	3.4	15.1
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	78734	70048	78331	78429	-0.4	12.0
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6161	5385	6184	6547	6.3	21.6
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	147789	116994	154212	152931	3.5	30.7
4.6 शिक्षा	82723	77789	82662	84375	2.0	8.5
4.7 वाहन ऋण	402667	363427	418330	427654	6.2	17.7
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	75311	74447	74303	75024	-0.4	0.8
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	880406	743648	915440	923719	4.9	24.2
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *(मेमो)*						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	1485438	1339890	1456432	1450586	-2.3	8.3
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	1377138	1155564	1418321	1429973	3.8	23.7
5.3 मध्यम उद्यम [6]	351900	226623	361334	363489	3.3	60.4
5.4 आवास	614487	586328	615355	616839	0.4	5.2
5.5 शिक्षा ऋण	58118	58740	57912	57931	-0.3	-1.4
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	3538	2030	4024	3868	9.3	90.5
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2483	3058	2578	2586	4.2	-15.4
5.8 निर्यात ऋण [7]	23330	25293	20769	18582	-20.3	-26.5
5.9 अन्य	37159	25363	46082	46243	24.4	82.3
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1180928	954371	1186035	1190612	0.8	24.8

टिप्पणी : 1. डेटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर -खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण(एसआईबीसी) रिटर्न, के आधार पर हैं। जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल गैर खादय ऋण के लगभग 93 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और वृद्धि दर में कुछ बदलाव हुए हैं। टिप्पणी 3: चुनिंदा एससीबी द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए बैंकों की ऋण वृद्धि को समायोजित किया जाता है।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋणऔर पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 25, 2022	2021	2022		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 18	मई 20	जून 17	2022-23	2022
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3152449	2894061	3165450	3168168	0.5	9.5
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	49038	44817	46986	48459	–1.2	8.1
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	173243	154050	174697	175631	1.4	14.0
2.2.1 चीनी	26307	23948	25399	24107	–8.4	0.7
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18246	17287	17739	18322	0.4	6.0
2.2.3 चाय	5728	5318	6094	6382	11.4	20.0
2.2.4 अन्य	122962	107497	125465	126820	3.1	18.0
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	18176	17064	17777	17471	–3.9	2.4
2.4 वस्त्र	223508	207377	219503	218393	–2.3	5.3
2.4.1 सूती वस्त्र	90189	83889	87674	86492	–4.1	3.1
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	3509	2458	3567	3582	2.1	45.8
2.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38354	35633	38396	38363	0.0	7.7
2.4.4 अन्य वस्त्र	91456	85397	89866	89955	–1.6	5.3
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11481	10782	11427	11349	–1.1	5.3
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	16248	15281	16510	16658	2.5	9.0
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	40073	38240	40356	40885	2.0	6.9
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	107242	81630	104717	102685	–4.2	25.8
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	196179	179974	208697	207155	5.6	15.1
2.9.1 उवर्रक	33160	32507	37820	34780	4.9	7.0
2.9.2 औषधि और दवाइयां	61093	52520	62557	63009	3.1	20.0
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	19622	24607	21555	20896	6.5	–15.1
2.9.4 अन्य	82303	70340	86765	88470	7.5	25.8
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	71915	57615	71290	72228	0.4	25.4
2.11 कांच और कांच के सामान	5948	6175	5768	5916	–0.5	–4.2
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	47912	53777	47880	48310	0.8	–10.2
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	288395	290866	291957	292613	1.5	0.6
2.13.1 लोहा और स्टील	187443	199413	187713	187121	–0.2	–6.2
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	100952	91453	104244	105492	4.5	15.4
2.14 सभी अभियांत्रिकी	167680	150236	168674	166937	–0.4	11.1
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	38180	34179	38445	39191	2.7	14.7
2.14.2 अन्य	129500	116057	130229	127746	–1.4	10.1
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	89688	85050	91247	91996	2.6	8.2
2.16 रत्न और आभूषण	80411	71087	72009	73082	–9.1	2.8
2.17 निर्माण	117625	119946	114427	117986	0.3	–1.6
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1193965	1105817	1201605	1211341	1.5	9.5
2.18.1 पावर	610815	570921	615508	620478	1.6	8.7
2.18.2 दूरसंचार	130349	116653	129261	131922	1.2	13.1
2.18.3 सड़क	269896	236232	275426	278364	3.1	17.8
2.18.4 हवाई अड्डा	6646	9689	6767	6794	2.2	–29.9
2.18.5 बंदरगाह	8886	10373	7938	7954	–10.5	–23.3
2.18.6 रेलवे	10512	12532	11382	11494	9.3	–8.3
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	156861	149416	155323	154335	–1.6	3.3
2.19 अन्य उद्योग	253724	204277	259922	249073	–1.8	21.9

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2021	2022						
		मई 28	मार्च 25	अप्रै. 08	अप्रै. 22	अप्रै. 29	मई 06	मई 20	मई 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	33	33	33	33	33	31	31	32
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**125859.6**	**124193.8**	**129858.2**	**131377.4**	**130646.5**	**130356.1**	**126088.5**	**125524.8**	**126958.1**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**23736.9**	**27145.3**	**26116.3**	**26854.4**	**26800.8**	**26799.3**	**24951.1**	**23918.5**	**24062.9**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	5137.8	5902.5	5475.6	5677.3	5097.7	5178.3	5609.3	5845.9
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	15774.7	14459.2	15139.9	14945.7	14888.6	12730.8	12344.8	12752.4
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	829.8	0.0	60.0	90.0	579.8	664.8	444.9	619.8
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	5403.1	5754.5	6179.0	6087.8	6233.2	6377.3	5519.6	4844.8
2.2 मीयादी देयताएं	**179957.5**	**169907.2**	**189731.8**	**193780.5**	**189892.4**	**188046.3**	**185154.8**	**183304.2**	**183687.5**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	59567.6	71236.3	74235.3	70896.1	69276.0	68469.7	66818.1	66131.9
2.2.1.2 अन्य	111960.2	108419.1	115399.0	116237.5	115700.8	115467.5	113357.8	113180.0	114205.7
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	1118.9	853.7	1000.5	1000.0	1000.0	999.7	998.7	1024.3
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	801.6	2242.7	2307.1	2295.6	2302.9	2327.5	2307.4	2325.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	49932.4	66978.0	66398.8	63840.5	63081.2	62142.7	61405.1	61247.8
4.1 मांग	15691.8	11059.3	15765.8	13904.1	13317.7	13292.8	13229.4	13178.1	13228.8
4.2 मीयादी	47868.0	38873.1	51212.3	52494.8	50522.8	49788.3	48913.3	48227.0	48019.0
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**8151.1**	**9274.1**	**9725.6**	**11612.6**	**10679.3**	**10297.1**	**10261.9**	**11345.9**	**10695.3**
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	682.3	1014.8	1302.6	993.5	886.4	802.6	973.4	798.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	8591.8	8710.8	10310.0	9685.7	9410.7	9459.3	10372.5	9896.9
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**1148.1**	**1251.8**	**1651.7**	**1565.8**	**1413.3**	**1398.7**	**1098.2**	**1162.1**	**1227.5**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**64455.2**	**67366.8**	**75927.5**	**72724.3**	**72956.1**	**72964.6**	**71668.6**	**70980.1**	**71631.0**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**28835.7**	**21768.4**	**32935.8**	**29095.0**	**29100.2**	**28772.6**	**27555.1**	**25709.0**	**26130.0**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**114631.6**	**108118.7**	**111549.1**	**121123.8**	**120219.0**	**120025.5**	**118961.7**	**118897.7**	**119819.7**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**114612.1**	**108099.8**	**111529.1**	**121103.2**	**120198.3**	**120004.5**	**118940.8**	**118876.8**	**119798.9**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	84144.9	112645.5	112402.9	110021.7	108476.3	106788.7	106283.7	105636.7
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	18.9	20.0	20.7	20.7	21.0	20.9	20.9	20.9

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2021-22			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जून '21	मई'22	जून'22(अ)	जून'21	मई'22	जून'22(अ)	जून'21	मई'22	जून'22(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**162.8**	**168.7**	**165.0**	**160.5**	**170.8**	**172.4**	**166.2**	**177.5**	**179.3**	**162.6**	**173.3**	**174.9**
1.1 अनाज और उत्पाद	146.4	150.4	147.6	145.6	152.9	153.8	149.2	156.7	157.5	146.7	154.1	155.0
1.2 मांस और मछली	200.4	206.5	202.6	200.1	214.7	217.2	205.5	221.2	223.4	202.0	217.0	219.4
1.3 अंडा	173.3	176.0	174.4	179.3	161.4	169.5	182.8	164.1	172.8	180.7	162.4	170.8
1.4 दूध और उत्पाद	158.3	159.0	158.6	156.1	164.6	165.4	156.5	165.4	166.3	156.2	164.9	165.7
1.5 तेल और चर्बी	192.2	172.4	184.9	190.4	209.9	208.1	172.2	189.5	188.6	183.7	202.4	200.9
1.6 फल	155.3	163.5	159.2	158.6	168.0	165.8	171.5	174.5	174.1	164.6	171.0	169.7
1.7 सब्जी	156.1	192.8	168.5	144.7	160.4	167.4	176.2	203.2	211.6	155.4	174.9	182.4
1.8 दाल और उत्पाद	164.1	164.4	164.2	165.5	165.0	164.7	166.9	164.1	163.6	166.0	164.7	164.3
1.9 चीनी और उत्पाद	117.4	119.1	118.0	114.6	118.9	119.1	116.1	121.2	121.5	115.1	119.7	119.9
1.10 मसाले	171.2	167.5	170.0	170.0	186.6	188.9	165.5	181.4	183.5	168.5	184.9	187.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	167.8	154.7	162.3	165.5	173.2	174.1	152.3	158.5	159.1	160.0	167.1	167.8
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	173.0	175.8	174.3	171.7	180.4	181.9	173.3	184.9	186.3	172.4	182.5	183.9
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**190.3**	**196.5**	**191.9**	**189.1**	**192.9**	**192.9**	**195.6**	**197.5**	**198.3**	**190.8**	**194.1**	**194.3**
3 कपड़ा और जूते	**168.2**	**158.4**	**164.3**	**164.6**	**179.0**	**180.4**	**154.8**	**167.8**	**169.4**	**160.7**	**174.6**	**176.0**
3.1 कपड़ा	168.8	160.9	165.7	165.3	179.3	180.7	157.3	170.0	171.5	162.2	175.6	177.1
3.2 जूते	164.5	144.7	156.3	159.9	177.2	178.7	140.5	155.9	157.4	151.8	168.4	169.9
4 आवास	--	**163.0**	**163.0**	--	--	--	**160.5**	**167.5**	**166.8**	**160.5**	**167.5**	**166.8**
5 ईंधन और लाइट	**164.0**	**159.8**	**162.4**	**162.1**	**175.3**	**177.1**	**156.1**	**173.5**	**175.2**	**159.8**	**174.6**	**176.4**
6 विविध	**164.1**	**156.1**	**160.2**	**161.5**	**170.9**	**171.0**	**153.4**	**163.8**	**163.7**	**157.6**	**167.5**	**167.5**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	161.8	153.5	157.9	159.2	168.9	170.3	149.8	161.1	162.1	154.8	165.2	166.4
6.2 स्वास्थ्य	172.0	163.3	168.6	169.7	177.7	178.2	160.8	170.1	170.9	166.3	174.8	175.4
6.3 परिवहन और संचार	157.9	150.0	153.7	154.2	167.1	165.5	147.5	159.4	157.1	150.7	163.0	161.1
6.4 मनोरंजन	162.7	154.8	158.2	160.4	167.6	168.0	150.7	163.2	164.0	154.9	165.1	165.7
6.5 शिक्षा	168.4	160.1	163.5	166.8	171.8	172.5	158.1	165.2	166.5	161.7	167.9	169.0
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	161.3	160.8	161.1	159.4	168.5	169.5	158.0	168.2	169.2	158.8	168.4	169.4
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**164.5**	**163.1**	**163.8**	**162.1**	**172.5**	**173.6**	**160.4**	**170.8**	**171.5**	**161.3**	**171.7**	**172.6**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2021-22	2021	2022	
				जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	121.7	129	129.2
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1075	1057	1119	1125
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	1084	1065	1131	1137

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2021-22	2021	2022	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	47999	47891	50879	50804
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	65426	69960	61572	60936

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जून	अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य वस्तुएँ	**100.000**	**139.4**	**133.7**	**152.3**	**154.0**	**154.0**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**160.7**	**153.0**	**174.5**	**179.8**	**182.4**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**167.3**	**160.5**	**175.3**	**179.3**	**183.6**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	163.5	161.3	171.2	171.5	170.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	187.6	163.5	198.0	210.9	229.1
1.1.1.3 दूध	4.440	156.9	154.4	163.3	163.9	164.2
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	164.0	165.8	169.6	175.9	177.8
1.1.1.5 मसाले	0.529	159.8	151.1	173.8	177.9	177.9
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	168.3	167.2	178.4	173.3	172.1
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**158.1**	**148.4**	**177.5**	**180.0**	**176.3**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	158.4	142.5	216.1	235.1	228.1
1.1.2.2 तिलहन	1.115	214.4	211.7	227.2	223.7	217.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	119.9	115.9	127.3	127.7	128.6
1.1.2.4 फूल	0.204	217.0	138.7	230.8	217.1	196.3
1.1.3 खनिज	**0.833**	**197.2**	**191.8**	**208.2**	**228.9**	**208.2**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	193.3	188.6	204.0	229.9	204.0
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	211.0	203.0	222.9	225.6	223.2
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**110.3**	**99.5**	**152.5**	**165.5**	**176.4**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**124.6**	**110.7**	**151.2**	**154.4**	**155.4**
1.2.1 कोल	**2.138**	**129.0**	**127.3**	**130.9**	**130.9**	**130.9**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	143.0	141.9	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.8	119.8	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	170.5	138.1	212.6	212.6	212.6
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**126.2**	**111.0**	**167.9**	**173.1**	**174.8**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**117.4**	**98.2**	**122.2**	**122.2**	**122.2**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**135.0**	**131.6**	**144.7**	**144.8**	**143.7**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**157.9**	**155.8**	**169.9**	**170.9**	**169.6**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	142.8	144.3	143.3	145.3	147.1
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.1	139.7	147.4	146.2	144.0
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	122.3	121.9	123.6	125.3	123.9
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	187.2	184.5	210.7	212.8	207.3
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	149.4	147.9	159.4	160.8	160.5
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	145.6	144.0	151.4	151.5	152.2
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	133.3	124.7	156.6	157.7	155.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	146.2	142.9	155.0	155.5	159.4
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	122.9	118.8	125.4	126.2	125.9
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	130.5	128.9	134.5	135.2	134.6
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	136.7	133.5	160.6	163.1	156.5
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	171.1	178.5	178.7	183.1	187.4
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	157.5	153.8	168.8	170.6	169.6
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	137.0	140.2	142.6	140.8	140.9
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	153.5	147.5	173.8	170.4	177.1
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	200.9	197.7	213.7	210.9	209.2
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**126.8**	**125.6**	**127.7**	**128.1**	**128.5**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	123.6	122.4	126.2	127.4	127.6
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	130.5	127.4	133.6	134.3	135.5
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	128.6	128.8	125.0	124.1	124.0
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**160.2**	**157.6**	**164.6**	**165.0**	**164.0**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	160.2	157.6	164.6	165.0	164.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जून	अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**135.2**	**129.7**	**145.8**	**147.6**	**148.6**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	128.2	121.2	140.6	142.1	143.3
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	146.8	142.4	155.8	158.5	159.6
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	125.5	122.1	133.1	132.8	133.3
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	138.7	134.6	149.2	151.2	154.4
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	168.5	171.0	166.3	167.6	163.0
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	126.2	122.2	133.9	135.0	135.1
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**143.1**	**141.2**	**146.5**	**146.6**	**146.7**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	142.0	140.4	145.3	145.2	145.2
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	145.8	143.2	149.7	150.3	150.5
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**119.2**	**117.7**	**121.0**	**121.7**	**122.5**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	103.4	102.5	106.7	106.4	107.5
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	141.5	140.5	142.5	142.1	141.7
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	121.0	119.1	122.3	123.7	124.7
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**141.0**	**138.7**	**146.0**	**147.2**	**148.3**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	128.8	124.3	134.9	135.6	136.9
1.3.7.2 विनियर शीट,प्लायवुड का विनिर्माण,लॅमिन बोर्ड,पार्टिकल बोर्डऔर अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	141.9	140.4	147.7	149.3	150.0
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	193.9	194.5	201.5	201.5	203.0
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	134.1	129.9	134.1	134.2	136.8
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**137.5**	**133.0**	**153.7**	**153.8**	**155.8**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	141.4	136.5	156.9	156.5	158.4
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	137.8	134.9	150.0	149.0	152.6
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	131.0	125.3	152.5	154.5	154.9
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**157.8**	**153.6**	**167.6**	**167.7**	**167.3**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	157.8	153.6	167.6	167.7	167.3
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**133.5**	**128.3**	**145.7**	**146.3**	**147.5**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	143.8	135.8	162.7	165.1	166.3
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	129.6	126.4	137.6	137.1	141.3
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	140.3	133.5	153.5	152.4	150.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.1	128.4	142.3	142.8	143.7
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	130.4	124.3	141.6	143.4	142.3
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट,सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	128.1	126.2	136.0	138.1	139.0
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	130.3	124.7	142.9	143.5	144.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	106.6	102.5	115.8	114.9	116.0
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**135.9**	**134.7**	**139.6**	**139.4**	**139.9**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	135.9	134.7	139.6	139.4	139.9
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**124.8**	**120.6**	**131.7**	**131.9**	**131.6**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब,रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	104.3	102.3	107.2	108.2	109.2
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	101.9	99.9	105.7	106.0	106.3
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.0	132.4	147.3	147.0	146.0
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**123.7**	**121.4**	**130.5**	**130.6**	**132.6**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	139.1	136.3	150.9	151.5	155.9
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	115.6	113.0	118.9	118.8	118.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	119.3	110.9	135.5	136.0	140.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.9	110.4	116.2	117.4	117.2
1.3.13.5 सीमेन्ट,चूना और प्लास्टर	1.645	126.4	124.5	133.4	133.0	135.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(जारी)*

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जून	अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	129.2	129.0	132.7	133.2	133.2
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	122.2	123.3	122.6	124.4	123.8
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	90.6	81.5	104.9	104.3	103.9
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**140.1**	**134.0**	**161.2**	**158.7**	**150.2**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	150.8	138.2	181.9	174.7	159.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	147.7	143.4	178.4	174.3	161.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.1	116.5	134.5	134.1	129.0
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	137.4	131.7	159.1	158.0	152.7
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	157.5	154.9	179.1	174.5	162.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	133.7	129.4	156.8	154.8	147.0
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	141.7	133.3	173.1	168.1	148.1
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	155.9	145.4	183.1	179.1	169.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	139.7	132.5	156.2	155.7	152.0
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	118.9	116.5	125.7	126.3	128.0
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	159.0	155.6	166.9	171.4	169.9
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**130.5**	**127.5**	**138.8**	**139.7**	**139.3**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	123.9	122.3	131.1	131.5	133.1
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	156.2	152.3	168.5	170.3	165.7
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	96.1	96.8	97.0	97.0	97.5
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	117.5	109.6	129.4	132.1	133.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.2	106.4	112.2	112.2	112.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	136.5	134.1	143.7	143.9	143.2
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**113.7**	**112.7**	**116.4**	**116.0**	**116.1**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	106.0	103.4	113.2	114.8	115.0
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.7	134.8	134.8	135.0	134.9
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	121.7	120.7	128.2	128.2	128.0
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	102.1	101.6	101.0	98.6	98.6
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	108.4	108.5	112.3	112.7	112.7
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	145.6	142.4	149.3	149.6	152.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	106.1	106.6	109.9	109.6	108.3
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	98.3	98.5	99.6	99.6	98.3
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**122.3**	**120.2**	**127.4**	**126.4**	**128.3**
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स,जनरेटर,ट्रांसफार्मरऔरबिजलीवितरणऔरनियंत्रणसंबंधीउपकरण	1.298	119.7	118.0	123.3	121.3	124.2
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	121.8	117.5	129.4	129.6	131.7
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	103.1	101.1	105.3	108.0	112.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	140.7	137.1	153.3	151.9	151.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	114.5	113.8	116.2	117.0	116.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	128.4	125.2	133.3	132.1	134.1
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	113.2	113.6	114.3	114.9	116.4
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**120.0**	**118.1**	**124.3**	**124.4**	**124.7**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	119.2	116.6	125.4	125.8	125.7
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	122.1	120.3	125.5	125.2	127.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	115.1	113.9	117.4	117.2	117.5
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	118.1	117.5	121.1	120.0	120.9
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	74.2	74.2	78.5	78.1	78.5
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	120.0	116.8	125.4	125.4	124.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक *(समाप्त)*

(आधारः 2011-12=100)

कमोडिटी	भारांक	2020-21	2021	2022		
			जून	अप्रै.	मई (अ)	जून (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	133.4	132.9	143.6	145.3	142.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	128.4	124.8	133.5	133.9	134.3
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	114.2	110.3	118.1	118.0	118.3
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	78.2	76.8	80.3	80.4	84.2
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	130.1	128.5	131.0	129.7	129.4
1.3.18.13 कपड़ा,परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	125.3	123.8	127.9	128.3	126.9
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	134.7	134.1	136.6	136.8	137.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.6	66.4	67.8	68.3	68.3
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**122.7**	**120.5**	**126.1**	**126.8**	**127.7**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	122.6	120.7	124.6	125.1	126.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	122.7	120.2	127.8	128.8	129.4
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**131.7**	**128.6**	**134.5**	**134.8**	**135.5**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.9	158.8	159.1	159.1	159.1
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.4	103.8	103.7	103.7	104.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	131.0	127.3	134.4	134.8	135.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	137.2	136.3	139.4	139.9	139.9
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	135.9	132.4	145.5	146.5	147.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**150.1**	**144.8**	**155.2**	**159.4**	**155.8**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	150.1	144.8	155.2	159.4	155.8
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**137.9**	**138.4**	**147.5**	**144.3**	**139.6**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	136.0	136.7	146.0	142.5	137.7
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	192.3	195.3	184.4	186.8	192.1
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	140.4	137.5	146.6	147.9	148.2
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	150.9	150.4	158.6	156.1	160.6
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	171.8	170.7	176.4	175.7	173.5
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**163.8**	**158.7**	**173.3**	**176.1**	**178.4**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2020-21	2021-22	अप्रैल-मई		मई	
				2021-22	2022-23	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	118.1	131.6	120.6	136.2	115.1	137.7
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	101.0	113.3	108.0	118.2	108.3	120.1
1.2 विनिर्माण	77.63	117.2	131.0	118.1	133.2	111.5	134.5
1.3 बिजली	7.99	157.6	170.1	168.0	197.2	161.9	199.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	118.1	129.5	124.7	141.9	122.8	144.5
2.2 पूंजीगत माल	8.22	75.9	88.7	70.5	92.4	61.9	95.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	124.7	143.9	134.4	150.8	129.1	152.2
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	124.7	148.2	136.8	151.5	129.5	153.1
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	101.2	113.8	87.5	112.2	71.6	113.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	142.1	146.7	137.8	138.0	135.6	136.8

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23ः केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	Financial Year	अप्रैल-जून			
	2022-23 (बजट आकलन)	2022-23 (वास्तविक)	2021-22 (Actuals)	Percentage to Budget Estimates	
				2022-23	2021-22
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**2204422**	**568058**	**539997**	**25.8**	**30.2**
1.1 कर राजस्व (निवल)	1934771	505898	412680	26.1	26.7
1.2 करेतर राजस्व	269651	62160	127317	23.1	52.4
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**79291**	**27982**	**7402**	**35.3**	**3.9**
2.1 ऋण की वसूली	14291	3423	3406	24.0	26.2
2.2 अन्य प्राप्तियां	65000	24559	3996	37.8	2.3
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	**2283713**	**596040**	**547399**	**26.1**	**27.7**
जिसमें से:	3194663	772847	710148	24.2	24.2
4 राजस्व व्यय					
4.1 ब्याज भुगतान	940651	228595	184295	24.3	22.8
5 पूंजी व्यय	750246	175064	111496	23.3	20.1
6 कुल व्यय (4+5)	**3944909**	**947911**	**821644**	**24.0**	**23.6**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**990241**	**204789**	**170151**	**20.7**	**14.9**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1661196**	**351871**	**274245**	**21.2**	**18.2**
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	**720545**	**123276**	**89950**	**17.1**	**12.9**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2022-23।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		जून 25	मई 20	मई 27	जून 3	जून 10	जून 17	जून 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	5310	10543	9773	9431	8622	8628	8945	9455
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16705	34544	38528	36013	33408	32845	30712	34041
1.3 राज्य सरकारें	31320	41982	48200	53400	53900	62400	72000	70800
1.4 अन्य	72109	160981	91923	102756	111858	118498	126433	128325
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	70130	127372	91859	92683	95822	101204	103936	102032
2.2 प्राथमिक व्यापारी	63669	58473	97841	101768	100629	104040	110256	111392
2.3 राज्य सरकारें	15763	11839	22311	23811	25311	25311	27246	28246
2.4 अन्य	69259	99532	91222	95293	102229	102268	102314	110496
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	112386	134123	113652	112051	114852	119511	116331	113968
3.2 प्राथमिक व्यापारी	160461	135126	174768	179691	172875	174020	183022	181683
3.3 राज्य सरकारें	22836	17983	26369	26369	26296	26296	26296	26686
3.4 अन्य	118392	97843	125139	123857	129309	123631	119573	125126
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	289362	124998	147252	141999	165019	167030	159057	155906
4.4 अन्य	659	685	1025	862	1647	1320	341	934
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	758339	930341	931585	957123	975111	998652	1027066	1042250

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जून 1	13000	141	37448	5204	73	12796	5204	18000	98.78	4.9538
जून 8	13000	118	48808	12530	46	12970	12530	25500	98.77	4.9991
जून 15	13000	125	44471	12108	56	12992	12108	25100	98.76	5.0566
जून 22	13000	131	42080	2309	55	12991	2309	15300	98.75	5.0875
जून 29	13000	87	33195	7011	47	12989	7011	20000	98.73	5.1595
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जून 1	12000	129	24577	1504	80	11996	1504	13500	97.32	5.5227
जून 8	12000	97	24767	3	65	11997	3	12000	97.27	5.6278
जून 15	12000	156	25770	1953	87	11983	1953	13935	97.22	5.7347
जून 22	12000	161	32412	1023	82	11977	1023	13000	97.21	5.7559
जून 29	12000	185	33092	1015	75	11985	1015	13000	97.19	5.7899
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2022-23										
जून 1	8000	116	14127	3	98	7997	3	8000	94.28	6.0801
जून 8	8000	154	22606	7	78	7993	7	8000	94.25	6.1200
जून 15	8000	163	20760	10	91	7990	10	8000	94.11	6.2800
जून 22	8000	222	21356	404	135	7986	404	8390	94.11	6.2800
जून 29	8000	206	24833	1167	50	7973	1167	9139	94.10	6.2870

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
जून	1, 2022	2.35-4.50	4.13
जून	2, 2022	2.35-4.45	4.07
जून	3, 2022	2.35-4.55	4.10
जून	4, 2022	3.25-4.25	3.87
जून	6, 2022	2.35-4.50	4.15
जून	7, 2022	2.35-4.45	4.11
जून	8, 2022	2.35-4.95	4.36
जून	9, 2022	2.35-4.80	4.60
जून	10, 2022	2.35-4.80	4.54
जून	13, 2022	3.30-4.80	4.54
जून	14, 2022	2.30-4.80	4.55
जून	15, 2022	3.30-4.80	4.53
जून	16, 2022	2.35-4.80	4.54
जून	17, 2022	3.30-5.10	4.56
जून	18, 2022	3.80-4.51	4.28
जून	20, 2022	2.30-4.80	4.58
जून	21, 2022	2.35-5.15	4.62
जून	22, 2022	2.50-4.90	4.61
जून	23, 2022	2.50-4.85	4.62
जून	24, 2022	3.30-4.90	4.66
जून	27, 2022	2.50-5.00	4.67
जून	28, 2022	2.50-4.95	4.68
जून	29, 2022	3.30-4.95	4.75
जून	30, 2022	3.25-5.10	4.75
जुला.	1, 2022	3.30-5.20	4.72
जुला.	2, 2022	3.70-4.90	4.28
जुला.	4, 2022	3.00-4.95	4.72
जुला.	5, 2022	3.30-4.90	4.71
जुला.	6, 2022	3.00-4.85	4.68
जुला.	7, 2022	3.30-5.00	4.67
जुला.	8, 2022	3.30-4.95	4.69
जुला.	11, 2022	3.30-4.95	4.69
जुला.	12, 2022	3.30-4.90	4.66
जुला.	13, 2022	3.30-4.85	4.66
जुला.	14, 2022	3.30-4.85	4.67
जुला.	15, 2022	3.25-5.25	4.74

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2021	2022			
	जून 18	मई 6	मई 20	जून 3	जून 17
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	68209.42	185308.10	193034.11	189977.09	194418.87
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	6209.13	5508.80	26309.36	19242.58	25090.17
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.44-4.11	4.04-5.83	4.88-5.76	4.89-5.89	4.86-6.58

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2021	2022			
	जून 30	मई 15	मई 31	जून 15	जून 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	376117.85	384417.40	384544.00	389282.00	372542.35
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	97928.00	44342.95	72437.60	55172.75	67595.30
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.43-13.03	3.91-10.59	4.48-12.31	4.69-13.52	4.88-12.38

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2021-22	2021	2022					
		जून 25	मई 20	मई 27	जून 3	जून 10	जून 17	जून 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	14515	13148	15625	17938	19112	22986	18972	21624
2 नोटिस मुद्रा	2122	1009	6143	591	4808	520	5498	689
3 मीयादी मुद्रा	515	568	382	338	238	814	1166	238
4 त्रिपक्षीय रिपो	618526	476714	809662	664721	768346	660389	852668	710395
5 बाजार रिपो	383844	329177	447105	367359	501203	386824	466048	482415
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	4373	8737	1364	384	209	71	225	116
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	73797	80148	76519	83833	77157	89970	84579
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	51300	43103	57396	66154	57301	64408	51098	70092
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5570	6446	3119	4540	4649	3940	2601	5016
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4690	8852	5268	7611	8130	6746	5633	6131
10.2 182-दिवसीय	3440	3881	3696	2874	4230	5276	3368	4424
10.3 364-दिवसीय	3530	2396	5394	2914	3616	2958	2603	2916
10.4 नकदी प्रबंधन बिल								
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	68530	64678	74874	84094	77926	83328	65304	88578
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	145	328	810	317	1644	489	133

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2021-22		2021-22 (अप्रै-जून)		2022-23 (अप्रै-जून)*		जून 2021		जून 2022*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**164**	**138894**	**22**	**12864**	**45**	**18298**	**10**	**9550**	**12**	**1469**
1ए प्रीमियम	154	136893	21	12449	42	17493	10	9223	11	1347
1.1 पब्लिक	121	112567	16	12156	31	17103	8	9146	8	1344
1.1.1 प्रीमियम	119	111314	16	11821	30	16550	8	8881	8	1303
1.2 राइट्स	43	26327	6	709	14	1195	2	404	4	125
1.2.1 प्रीमियम	35	25580	5	629	12	943	2	342	3	44
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	**28**	**11589**	**6**	**3581**	**11**	**2525**	–	–	**3**	**842**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	28	11589	6	3581	11	2525	–	–	3	842
3.1.1 पब्लिक	28	11589	6	3581	11	2525	–	–	3	842
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	**192**	**150484**	**28**	**16445**	**56**	**20823**	**10**	**9550**	**15**	**2311**
4.1 पब्लिक	149	124157	22	15737	42	19627	8	9146	11	2186
4.2 राइट्स	43	26327	6	709	14	1195	2	404	4	125

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकडे कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2021-22	2021	2022				
			जून	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	3146186	238996	278585	339207	303051	301825	313343
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	421894	32491	37143	44489	39787	39036	40134
1.1 तेल	करोड ₹	503820	29072	51733	74744	60021	66248	67587
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	67468	3952	6897	9803	7880	8568	8657
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	2642366	209924	226852	264462	243029	235577	245756
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	354427	28538	30246	34686	31907	30468	31477
2 आयात	करोड ₹	4569443	309605	418745	480163	458525	489020	517727
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	612608	42090	55830	62977	60199	63247	66312
2.1 तेल	करोड ₹	1207782	78549	118171	161199	153257	148600	166306
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	161808	10678	15755	21142	20121	19219	21301
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	3361660	231057	300574	318964	305268	340420	351422
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	450800	31411	40075	41834	40078	44028	45011
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1423256	-70609	-140159	-140957	-155474	-187195	-204385
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-190713	-9599	-18687	-18487	-20412	-24211	-26178
3.1 तेल	करोड ₹	-703962	-49477	-66438	-86454	-93236	-82352	-98719
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94340	-6726	-8858	-11339	-12241	-10651	-12644
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-719294	-21133	-73721	-54502	-62238	-104843	-105666
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-96373	-2873	-9829	-7148	-8171	-13560	-13534

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2021	2022					
		जुला. 30	जून 24	जुला. 1	जुला. 8	जुला. 15	जुला. 22	जुला. 29
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**करोड ₹**	**4617303**	**4647773**	**4643705**	**4600703**	**4575190**	**4568803**	**4549652**
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	**620576**	**593323**	**588314**	**580252**	**572712**	**571560**	**573875**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	4287317	4145595	4141861	4107837	4086690	4077817	4053160
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	576224	529216	524745	518089	511562	510136	511257
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	280086	320594	319055	310699	306415	307766	314274
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	37644	40926	40422	39186	38356	38502	39642
	मात्रा (मैट्रिक टन)	711.18	767.89	768.82	774.76	779.42	780.36	781.29
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1087	13657	13657	13657	13657	13657	13657
	करोड ₹	11545	142649	143129	142814	142651	143587	142583
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	1552	18210	18133	18012	17857	17963	17985
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	38355	38934	39660	39353	39434	39632	39635
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5156	4970	5014	4966	4937	4960	4991

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2021-22	2021	2022		2021-22	2022-23
		जून	मई	जून	अप्रै.-जून	अप्रै.-जून
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**139022**	**141529**	**137089**	**135977**	**2525**	**349**
1.1 एफसीएनआर (बी)	16918	19699	15910	15681	-774	-1237
1.2 एनआर (ई) आरए	100801	102920	99928	98982	2782	981
1.3 एनआरओ	21303	18910	21250	21314	518	606

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021-22	2022-23	2021	2022	
		अप्रै.-जून	अप्रै.-जून	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**38587**	**11554**	**13614**	**354**	**4918**	**3735**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**56231**	**17237**	**16121**	**2555**	**5562**	**4724**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**84835**	**23147**	**22347**	**4525**	**8070**	**5902**
1.1.1.1.1 इक्विटी	59684	17773	16795	2734	6220	4047
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	1698	110	379	39	203	113
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	42932	10610	12405	2088	4281	2285
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	14143	6847	3805	538	1667	1580
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	910	206	206	69	69	69
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19347	4378	4378	1459	1459	1459
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5805	997	1174	332	390	395
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**28605**	**5910**	**6226**	**1970**	**2508**	**1178**
1.1.1.2.1 इक्विटी	27189	5818	5812	1939	2288	1074
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1416	92	414	31	220	103
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**17644**	**5683**	**2507**	**2201**	**644**	**989**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	10061	2532	1061	666	305	420
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3379	845	845	282	282	282
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7604	2849	1153	1434	217	476
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3400	542	552	181	159	189
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**-16777**	**402**	**-15063**	**1252**	**-4209**	**-6694**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	–	–	–	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	-14071	378	-15115	1244	-4458	-6586
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2706	-24	-53	-8	-249	108
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**21809**	**11956**	**-1449**	**1606**	**709**	**-2959**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2021-22	2021	2022		
		जून	अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**19610.77**	**1232.22**	**2023.70**	**2039.26**	**1984.68**
1.1 जमाराशियां	830.05	64.32	113.90	79.46	72.49
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	112.90	10.02	14.09	11.76	14.54
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	746.57	66.91	76.24	82.47	65.03
1.4 उपहार	2336.29	178.21	299.20	248.69	222.77
1.5 दान	16.55	1.59	0.85	1.01	1.12
1.6 यात्रा	6909.04	277.65	880.78	994.82	1043.08
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3302.37	241.57	385.57	336.96	304.85
1.8 चिकित्सा उपचार	37.79	2.52	4.51	4.43	4.39
1.9 विदेश में शिक्षा	5165.33	380.23	232.95	264.61	240.86
1.10 अन्य	153.88	9.20	15.59	15.04	15.55

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2020-21	2021-22	2021	2022	
			जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	93.92	93.13	92.63	92.63	92.07
1.2 रीर	103.46	104.66	104.85	104.02	103.65
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.59	93.55	92.79	93.95	93.50
2.2 रीर	102.96	103.48	103.54	102.70	102.45
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	88.45	87.03	86.66	87.40	86.88
1.2 रीर	101.84	102.27	102.09	103.32	103.16
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	98.39	97.97	98.80	98.23
2.2 रीर	100.00	100.42	100.24	101.45	101.30

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2021-22	2021	2022	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1086	87	95	109
1.2 राशि	28851	1485	1416	1789
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	18	0	1	1
2.2 राशि	11035	0	100	100
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1104	87	96	110
3.2 राशि	39886	1485	1516	1889
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	8.00	5.12	5.80	5.50
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.71	1.75	2.52	1.77
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-10.50	0.00-10.25	0.00-10.50	0.00-10.37
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12244	391	712	389
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	17023	802	456	131
ए) परिवहन	1597	0	0	0
बी) ऊर्जा	8215	293	54	125
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	10	0	10	0
डी) संचार	1,258	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	0	0	100	0
एफ)अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	4691	510	16	5
जी) अन्य उप -क्षेत्र	1252	0	276	1
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1570	132	129	661
IV. अन्य संस्थाएं	609	0	0	300
ए) एसई जेड़ में इकाई	9	0	0	0
बी) सिडबी				
सी) एक्जिम बैंक	600	0	0	300
V. बैंक	100	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	4	0	0	0
VII. एनबीएफसी	7995	119	210	406
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	5621	91	100	0
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	93	0	0	6
सी) एनबीफसी - अन्य	2282	29	110	400
VIII. गैर -सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	0	0	0	0
X. अन्य	341	40	9	2

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**336072**	**332683**	**3389**	**384903**	**400927**	**-16024**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**173382**	**181543**	**-8161**	**218823**	**232247**	**-13424**
1.1 पण्य	**91281**	**133025**	**-41745**	**118020**	**172503**	**-54483**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**82101**	**48518**	**33583**	**100803**	**59744**	**41059**
1.2.1 सेवाएं	56004	32520	23485	69876	41557	28319
1.2.1.1 यात्रा	2308	3141	-834	2757	5133	-2376
1.2.1.2 परिवहन	6080	5633	446	9398	11002	-1604
1.2.1.3 बीमा	647	566	82	904	428	476
1.2.1.4 जीएनआईई	159	241	-82	160	271	-111
1.2.1.5 विविध	46811	22938	23873	56657	24723	31934
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	26802	3327	23475	32786	3520	29266
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	13324	12847	478	16835	13867	2968
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1258	1402	-145	1615	1504	111
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	696	399	297	763	269	494
1.2.2 अंतरण	20927	2085	18842	23723	2591	21132
1.2.2.1 आधिकारिक	18	285	-267	21	239	-218
1.2.2.2 निजी	20909	1801	19108	23702	2353	21350
1.2.3 आय	5170	13913	-8743	7204	15596	-8392
1.2.3.1 निवेश आय	3517	13192	-9675	5589	14792	-9202
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1653	721	932	1614	804	810
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**162690**	**150429**	**12261**	**166081**	**167787**	**-1707**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**108195**	**98236**	**9959**	**95111**	**96550**	**-1439**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15393	12714	2679	24396	10620	13777
2.1.1.1 भारत में	13679	7928	5750	23281	6028	17253
2.1.1.1.1 इक्विटी	8553	7894	659	15845	5177	10669
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4519		4519	5229		5229
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	607	34	573	2207	851	1356
2.1.1.2 विदेश में	1714	4786	-3072	1115	4592	-3477
2.1.1.2.1 इक्विटी	1714	1197	517	1115	2132	-1017
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	845	-845
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	2835	-2835	0	1615	-1615
2.1.2 संविभाग निवेश	92802	85522	7280	70715	85930	-15215
2.1.2.1 भारत में	92500	84310	8190	70254	84543	-14289
2.1.2.1.1 एफआईआई	92500	84310	8190	70254	84543	-14289
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	81440	73679	7761	62553	75636	-13083
2.1.2.1.1.2 ऋण	11059	10631	428	7701	8907	-1206
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0		0
2.1.2.2 विदेश में	303	1212	-909	461	1387	-926
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**26446**	**18725**	**7721**	**33737**	**20826**	**12911**
2.2.1 बाह्य सहायता	5380	1387	3993	3988	1331	2657
2.2.1.1 भारत द्वारा	10	21	-11	13	16	-3
2.2.1.2 भारत को	5370	1366	4004	3976	1315	2661
2.2.2 वाणिज्यिकिक उधार	11834	5759	6075	11346	7913	3433
2.2.2.1 भारत द्वारा	683	745	-63	514	373	141
2.2.2.2 भारत को	11152	5014	6138	10832	7540	3292
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9232	11578	-2346	18403	11582	6821
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	8067	11578	-3511	14571	11582	2988
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1165	0	1165	3833	0	3833
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**16733**	**21158**	**-4425**	**27241**	**33202**	**-5961**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	16518	21158	-4640	27195	32602	-5407
2.3.1.1 आस्तियां	4141	7973	-3832	13120	17970	-4850
2.3.1.2 देयताएं	12377	13185	-808	14075	14632	-557
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	11350	11889	-539	13468	13309	159
2.3.2 अन्य	215	0	215	46	600	-554
2.4 रुपया ऋण चुकौती		7	-7	0	12	-12
2.5 अन्य पूंजी	11315	12302	-987	9991	17196	-7205
3 भूल-चूक		**711**	**-711**	0	**893**	**-893**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**3389**	**-3389**	**16024**	0	**16024**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	3389	-3389	16024	0	16024

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**2449502**	**2424800**	**24702**	**2895618**	**3016163**	**-120545**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**1263718**	**1323202**	**-59484**	**1646199**	**1747190**	**-100991**
1.1 पण्य	**665312**	**969572**	**-304260**	**887863**	**1297738**	**-409875**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**598406**	**353629**	**244776**	**758336**	**449452**	**308883**
1.2.1 सेवाएं	408194	237025	171170	525672	312631	213042
1.2.1.1 यात्रा	16819	22896	-6077	20740	38617	-17877
1.2.1.2 परिवहन	44312	41058	3254	70702	82770	-12068
1.2.1.3 बीमा	4719	4125	594	6801	3218	3583
1.2.1.4 जीएनआईई	1158	1759	-601	1201	2035	-834
1.2.1.5 विविध	341186	167187	173999	426228	185990	240238
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	195350	24250	171099	246649	26481	220167
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	97117	93634	3484	126651	104321	22330
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9166	10220	-1054	12147	11313	834
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5073	2905	2168	5742	2024	3718
1.2.2 अंतरण	152529	15199	137330	178471	19496	158975
1.2.2.1 आधिकारिक	129	2074	-1945	158	1796	-1638
1.2.2.2 निजी	152400	13125	139275	178313	17700	160613
1.2.3 आय	37682	101406	-63724	54193	117326	-63133
1.2.3.1 निवेश आय	25637	96153	-70517	42047	111277	-69230
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12045	5252	6793	12145	6049	6096
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**1185784**	**1096418**	**89366**	**1249419**	**1262257**	**-12838**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**788594**	**716008**	**72586**	**715520**	**726343**	**-10823**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	112193	92670	19523	183534	79893	103640
2.1.1.1 भारत में	99699	57788	41911	175144	45346	129797
2.1.1.1.1 इक्विटी	62338	57537	4801	119205	38945	80260
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	32935	0	32935	39334	0	39334
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4427	251	4176	16605	6401	10203
2.1.1.2 विदेश में	12493	34882	-22389	8390	34547	-26157
2.1.1.2.1 इक्विटी	12493	8726	3767	8390	16040	-7650
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5490	-5490	0	6355	-6355
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	20666	-20666	0	12153	-12153
2.1.2 संविभाग निवेश	676402	623338	53063	531986	646450	-114463
2.1.2.1 भारत में	674196	614505	59691	528521	636017	-107496
2.1.2.1.1 एफआईआई	674196	614505	59691	528521	636017	-107496
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	593588	537019	56569	470586	569008	-98422
2.1.2.1.1.2 ऋण	80608	77487	3122	57935	67009	-9074
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2206	8833	-6628	3465	10433	-6968
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**192758**	**136479**	**56279**	**253804**	**156675**	**97128**
2.2.1 बाह्य सहायता	39212	10111	29101	30003	10013	19989
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	95	120	-26
2.2.1.2 भारत को	39141	9958	29183	29908	9893	20015
2.2.2 वाणिज्यिकिक उधार	86255	41978	44276	85354	59528	25826
2.2.2.1 भारत द्वारा	4975	5433	-459	3867	2804	1062
2.2.2.2 भारत को	81280	36545	44735	81487	56723	24764
2.2.3 भारत को अल्पावधि	67291	84390	-17099	138447	87134	51313
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	58799	84390	-25591	109614	87134	22479
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	8492	0	8492	28833	0	28833
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**121962**	**154215**	**-32253**	**204931**	**249778**	**-44847**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	120397	154215	-33818	204584	245264	-40680
2.3.1.1 आस्तियां	30186	58112	-27927	98701	135191	-36490
2.3.1.2 देयताएं	90211	96103	-5892	105884	110073	-4190
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	82726	86651	-3925	101318	100121	1197
2.3.2 अन्य	1565	0	1565	347	4514	-4167
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	50	-50	0	93	-93
2.5 अन्य पूंजी	82471	89666	-7196	75165	129368	-54203
3 भूल-चूक	0	**5180**	**-5180**	0	**6716**	**-6716**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**24702**	**-24702**	**120545**	0	**120545**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	24702	-24702	120545	0	120545

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**173382**	**181517**	**-8135**	**218822**	**232225**	**-13404**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**147285**	**165545**	**-18260**	**187896**	**214060**	**-26164**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**91281**	**133025**	**-41745**	**118020**	**172503**	**-54483**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिकिक वस्तुएं	89691	115206	-25515	118046	164299	-46253
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	1590	0	1590	-26	0	-26
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		17819	-17819		8204	-8204
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**56004**	**32520**	**23485**	**69876**	**41557**	**28319**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	102	6	96	214	24	190
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	54	211	-157	44	440	-397
1.अ.ख.3 परिवहन	6080	5633	446	9398	11002	-1604
1.अ.ख.4 यात्रा	2308	3141	-834	2757	5133	-2376
1.अ.ख.5 निर्माण	752	713	39	596	720	-124
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	647	566	82	904	428	476
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1258	1402	-145	1615	1504	111
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	238	2107	-1868	193	2518	-2325
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	27574	3909	23665	33629	4009	29620
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	13324	12847	478	16835	13867	2968
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	727	878	-150	970	1224	-253
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	159	241	-82	160	271	-111
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	2781	865	1916	2560	416	2145
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**5170**	**13913**	**-8743**	**7204**	**15596**	**-8392**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1653	721	932	1614	804	810
1.आ.2 निवेश आय	2621	12952	-10331	4303	13417	-9113
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1363	7837	-6474	3206	8193	-4987
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	28	1633	-1605	80	1591	-1511
1.आ.2.3 अन्य निवेश	122	3481	-3359	96	3629	-3533
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1109	1	1107	922	4	918
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	896	240	656	1286	1375	-89
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**20927**	**2058**	**18868**	**23722**	**2570**	**21153**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20909	1801	19108	23702	2353	21350
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20224	1303	18920	22943	1677	21267
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	686	497	188	759	676	83
1.इ.2 सामान्य सरकार	17	258	-240	20	217	-197
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	**191**	**230**	**-38**	**244**	**173**	**71**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	87	38	49	117	29	88
2.2 पूंजी अंतरण	104	191	-88	127	144	-17
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**162499**	**153615**	**8884**	**181861**	**167636**	**14226**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**15393**	**12714**	**2679**	**24396**	**10620**	**13777**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	13679	7928	5750	23281	6028	17253
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13071	7894	5177	21074	5177	15897
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	8553	7894	659	15845	5177	10669
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4519		4519	5229		5229
3.1.अ.2 ऋण लिखत	607	34	573	2207	851	1356
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	607	34	573	2207	851	1356
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1714	4786	-3072	1115	4592	-3477
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1714	1950	-236	1115	2977	-1862
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1714	1197	517	1115	2132	-1017
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		753	-753		845	-845
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	2835	-2835	0	1615	-1615
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		2835	-2835		1615	-1615
3.2 संविभाग निवेश	**92802**	**85522**	**7280**	**70715**	**85930**	**-15215**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	92500	84310	8190	70254	84543	-14289
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	81440	73679	7761	62553	75636	-13083
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	11059	10631	428	7701	8907	-1206
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	303	1212	-909	461	1387	-926
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**2662**	**4929**	**-2267**	**4629**	**7403**	**-2774**
3.4 अन्य निवेश	**51642**	**47061**	**4581**	**66098**	**63683**	**2415**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	11565	11889	-324	13514	13909	-395
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	215	0	215	46	600	-554
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	11350	11889	-539	13468	13309	159
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	22382	16416	5966	29061	28537	524
3.4.3अ भारत को ऋण	21690	15650	6040	28534	28148	386
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	692	766	-74	527	389	138
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	27	43	-16	40	17	22
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9232	11578	-2346	18403	11582	6821
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	8435	7134	1301	5080	9637	-4557
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**3389**	**-3389**	**16024**	0	**16024**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	3389	-3389	16024	0	16024
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**162499**	**153615**	**8884**	**181861**	**167636**	**14226**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	99217	89707	9510	89872	92596	-2725
4.2 ऋण लिखत	54846	53384	1462	70886	65402	5484
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	8435	10524	-2088	21104	9637	11466
5. निवल भूल-चूक		**711**	**-711**		**893**	**-893**

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(करोड़ ₹)

मद	जन.-मार्च 2021			जन.-मार्च 2022 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**1263714**	**1323006**	**-59291**	**1646190**	**1747025**	**-100835**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1073506**	**1206597**	**-133090**	**1413535**	**1610368**	**-196833**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**665312**	**969572**	**-304260**	**887863**	**1297738**	**-409875**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिकिक वस्तुएं	653724	839694	-185970	888059	1236020	-347961
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	11588	0	11588	-196	0	-196
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	129878	-129878	0	61718	-61718
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**408194**	**237025**	**171170**	**525672**	**312631**	**213042**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	741	44	697	1613	184	1429
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	393	1536	-1143	329	3313	-2984
1.अ.ख.3 परिवहन	44312	41058	3254	70702	82770	-12068
1.अ.ख.4 यात्रा	16819	22896	-6077	20740	38617	-17877
1.अ.ख.5 निर्माण	5482	5199	283	4482	5418	-937
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4719	4125	594	6801	3218	3583
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9166	10220	-1054	12147	11313	834
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1737	15356	-13619	1454	18944	-17489
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	200979	28494	172485	252989	30162	222827
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	97117	93634	3484	126651	104321	22330
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	5300	6397	-1096	7300	9206	-1906
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1158	1759	-601	1201	2035	-834
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	20269	6308	13962	19262	3129	16133
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**37682**	**101406**	**-63724**	**54193**	**117326**	**-63133**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	12045	5252	6793	12145	6049	6096
1.आ.2 निवेश आय	19106	94405	-75299	32373	100933	-68559
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9937	57123	-47186	24116	61632	-37516
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	203	11901	-11699	602	11973	-11371
1.आ.2.3 अन्य निवेश	886	25372	-24486	721	27299	-26578
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	8080	10	8071	6935	29	6906
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	6530	1748	4782	9674	10344	-670
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**152526**	**15003**	**137523**	**178462**	**19331**	**159131**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	152400	13125	139275	178313	17700	160613
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	147403	9500	137903	172602	12613	159989
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4997	3625	1372	5711	5086	624
1.इ.2 सामान्य सरकार	126	1878	-1752	149	1631	-1482
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1393**	**1673**	**-280**	**1836**	**1303**	**533**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	636	278	358	879	220	660
2.2 पूँजी अंतरण	757	1395	-638	957	1084	-127
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**1184395**	**1119643**	**64752**	**1368137**	**1261119**	**107018**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**112193**	**92670**	**19523**	**183534**	**79893**	**103640**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	99699	57788	41911	175144	45346	129797
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	95272	57537	37735	158539	38945	119594
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	62338	57537	4801	119205	38945	80260
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	32935	0	32935	39334	0	39334
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4427	251	4176	16605	6401	10203
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4427	251	4176	16605	6401	10203
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	12493	34882	-22389	8390	34547	-26157
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	12493	14216	-1723	8390	22395	-14005
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	12493	8726	3767	8390	16040	-7650
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5490	-5490	0	6355	-6355
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	20666	-20666	0	12153	-12153
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	20666	-20666	0	12153	-12153
3.2 संविभाग निवेश	**676402**	**623338**	**53063**	**531986**	**646450**	**-114463**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	674196	614505	59691	528521	636017	-107496
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	593588	537019	56569	470586	569008	-98422
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	80608	77487	3122	57935	67009	-9074
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2206	8833	-6628	3465	10433	-6968
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**19402**	**35925**	**-16523**	**34822**	**55690**	**-20868**
3.4 अन्य निवेश	**376398**	**343008**	**33391**	**497250**	**479086**	**18164**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	84291	86651	-2360	101664	104634	-2970
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	1565	0	1565	347	4514	-4167
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	82726	86651	-3925	101318	100121	1197
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	163138	119653	43484	218623	214684	3939
3.4.3अ भारत को ऋण	158092	114067	44025	214662	211760	2902
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	5045	5586	-540	3961	2925	1037
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	198	313	-116	300	131	169
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	67291	84390	-17099	138447	87134	51313
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	61481	52000	9481	38216	72502	-34286
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**24702**	**-24702**	**120545**	**0**	**120545**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0	0	0	
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0	0	0	
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0	0	0	
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	24702	-24702	120545	0	120545
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**1184395**	**1119643**	**64752**	**1368137**	**1261119**	**107018**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	723159	653844	69315	676102	696601	-20499
4.2 ऋण लिखत	399754	389097	10657	533274	492016	41258
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	61481	76702	-15221	158761	72502	86259
5. निवल भूल-चूक	**0**	**5180**	**-5180**	**0**	**6716**	**-6716**

टिप्पणी: पीः प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2021-22		2021				2022	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	132765	493987	122726	456947	130904	487895	132765	493987
1.2 अन्य पूंजी	78807	27694	71203	25177	77192	26301	78807	27694
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	211573	521681	193929	482125	208096	514196	211573	521681
2.1 इक्विटी	1110	156381	2340	177278	6113	172794	1110	156381
2.2 ऋण	9533	105994	5596	101232	3603	104286	9533	105994
2 संविभाग निवेश	10642	262375	7936	278510	9716	277080	10642	262375
3.1 व्यापार ऋण	18603	118156	5644	100329	12891	113450	18603	118156
3.2 ऋण	10474	205023	13335	197527	8856	204063	10474	205023
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42081	140994	42436	143760	34796	143502	42081	140994
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19918	32203	19191	12384	19946	29833	19918	32203
3 अन्य निवेश	91075	496377	80606	454000	76489	490849	91075	496377
4 रिज़र्व्स	607309		576984		633614		607309	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	920599	1280433	859454	1214634	927915	1282125	920599	1280433
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-359834		-355180		-354210		-359834	

नोट: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि का हिस्सा और पुनर्निवेशित आय शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व 2020-21	2021	2022		वि.व 2020-21	2021	2022	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	33.01	2.90	3.32	3.42	206873112	17144527	19742339	22912930
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	12.22	1.01	1.23	1.32	142072939	11317988	13110275	15445511
1.1.1 आउटराईट	6.22	0.51	0.66	0.68	8793301	774292	832089	844409
1.1.2 रेपो	3.08	0.27	0.31	0.34	51015712	4653921	4940038	5627915
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.92	0.23	0.26	0.30	82263926	5889775	7338148	8973188
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	19.91	1.82	1.98	1.97	59775826	5408999	6039213	6778125
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.88	0.07	0.11	0.13	5024347	417541	592851	689294
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	–	–	–	–	–	–	–	–
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2078.39	154.14	195.72	194.42	128657516	10196989	11183947	12356054
1.1 ग्राहक लेनदेन	2063.73	152.92	194.53	193.18	113319292	8887546	9851274	10840909
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	14.66	1.22	1.19	1.24	15338225	1309444	1332673	1515145
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	577934.74	36684.40	72187.50	69921.27	42728006	3029728	4177865	4298158
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	9.76	1.06	0.58	0.62	575	64	36	37
2.2 एपीबीएस $	12573.33	1148.34	2268.03	1222.24	133345	8143	41011	23010
2.3 आईएमपीएस	46625.25	3038.45	4848.13	4557.01	4171037	284111	452328	443776
2.4 एनएसीएच जमा $	18757.82	1498.12	1794.53	1489.99	1281685	92266	97341	100909
2.5 एनईएफटी	40407.29	2923.27	3813.34	4022.33	28725463	2097771	2546928	2716013
2.6 यूपीआई @	459561.30	28075.16	59462.89	58629.08	8415900	547373	1040221	1014413
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	11.99	1.03	1.00	0.99	177	16	14	12
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	12189.49	981.70	1177.32	1225.96	1034444	86759	95542	100325
3.1 भीम आधार पे @	227.73	17.66	17.81	39.82	6113	417	571	1049
3.2 एनएसीएच नामे $	10754.74	878.73	1018.05	1048.14	1026641	86215	94752	99060
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1207.02	85.31	141.46	138.00	1689	128	218	216
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	61782.93	4493.75	5698.25	5378.79	1701851	113790	179520	169754
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	22398.82	1547.01	2378.03	2279.46	971638	62746	113694	108752
4.1.1 पीओएस आधारित $	11124.59	690.40	1220.26	1210.51	380643	23977	42266	40466
4.1.2 अन्य $	11274.23	856.61	1157.77	1068.95	590994	38769	71428	68286
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	39384.11	2946.74	3320.22	3099.33	730213	51044	65827	61002
4.2.1 पीओएस आधारित $	22967.10	1505.09	2150.28	2012.90	451550	28743	44273	39877
4.2.2 अन्य $	16417.00	1441.65	1169.94	1086.43	278663	22300	21554	21126
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	65782.75	4585.92	6529.11	6258.03	279416	18657	25698	24738
5.1 वालेट	53013.86	3906.02	5198.06	4979.19	220183	15849	19616	18488
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	12768.89	679.91	1331.05	1278.83	59233	2808	6082	6250
5.2.1 पीओएस आधारित $	1116.16	50.54	92.80	87.22	19546	667	1336	1301
5.2.2 अन्य $	11652.73	629.36	1238.25	1191.62	39687	2140	4746	4949
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6999.12	511.38	590.44	593.72	6650333	477430	594562	599196
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6999.12	511.38	590.44	593.72	6650333	477430	594562	599196
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	724689.03	47257.15	86182.62	83377.76	52394049	3726363	5073187	5192171
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	726767.42	47411.29	86378.35	83572.18	181051565	13923352	16257134	17548225
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	719768.30	46899.91	85787.91	82978.46	174401233	13445923	15662572	16949029

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2021	2022		वि. व. 2020-21	2021	2022	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	507531.37	32127.11	64186.29	62579.11	14973395	1033735	1753658	1714907
1.1 इंट्रा-बैंक $	40805.69	2829.58	4617.48	4309.49	2726360	196264	318478	305103
1.2 इंटर-बैंक $	466725.68	29297.53	59568.81	58269.61	12247035	837471	1435180	1409804
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	40726.59	3055.26	3751.53	3550.83	83159996	6709926	7259551	8206144
2.1 इंट्रा-बैंक @	9583.32	705.17	993.69	866.17	52142582	4355975	4340071	5134603
2.2 इंटर-बैंक @	31143.27	2350.09	2757.84	2684.67	31017413	2353951	2919480	3071541
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	65287.63	4761.69	5872.27	5734.36	3111948	229638	280267	271368
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	62.37	4.31	6.64	6.79	3130	219	328	336
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	64898.80	4735.38	5832.84	5694.37	3097741	228681	278833	269936
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	326.45	22.00	32.79	33.20	11076	738	1106	1096
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	91.17	7.87	2.23	2.30	728	59	22	22
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	79.42	7.03	2.20	2.27	557	44	22	22
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	11.75	0.84	0.03	0.03	171	15	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11126.04	856.89	1073.66	1167.16	299776	24187	29828	31318
5.1 एईपीएस @	11126.04	856.89	1073.66	1167.16	299776	24187	29828	31318

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	अप्रै. 2021 तक	2021	2022	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9912.93	9684.46	10002.10	10004.74
1.1 क्रेडिट कार्ड	736.27	628.15	768.77	787.23
1.2 डेबिट कार्ड	9176.66	9056.31	9233.33	9217.52
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	27411.16	22947.96	27989.08	30331.42
2.1 वालेट @	24645.40	20861.58	25302.43	27673.99
2.2 कार्ड @	2765.76	2086.38	2686.65	2657.43
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.48	2.40	2.52	2.53
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम $	2.16	2.14	2.20	2.20
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम $	0.32	0.26	0.32	0.33
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	7.81	4.54	8.81	9.40
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	60.70	45.93	61.69	65.91
6 भारत क्यूआर @	49.72	40.83	41.38	42.80
7 यूपीआई क्यूआर *	1727.34	1026.76	1880.15	1951.71

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड़ शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2020-21	2020	2021		
			दिसं.	अक्टू.	नवं.	दिसं.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**181237**	**16781**	**14339**	**13362**	**18175**
	बकाया	**1259585**	**1196084**	**1366427**	**1379793**	**1397878**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**132687**	**12407**	**10091**	**9584**	**13855**
	बकाया	**867494**	**827156**	**946406**	**955989**	**969847**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	39748	3307	1868	929	4475
	बकाया	205888	190437	221296	222225	226701
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	276	-21	-24	324	-366
	बकाया	3419	3086	3243	3566	3200
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	166	-3	-5	-2	2
	बकाया	175	-17	151	149	150
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	12211	1053	1263	1221	1228
	बकाया	221379	217980	230298	231519	232747
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	21009	2014	1953	1204	1929
	बकाया	97051	90914	111000	112205	114134
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41470	4330	3209	3020	3926
	बकाया	207557	195847	234088	237108	241034
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	108205	104601	114621	115037	116043
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7473	7324	7883	7885	7931
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7227	7330	6949	7028	6983
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	84652	76592	104635	107158	110077
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	17807	1727	1815	2899	2662
	बकाया	132029	128912	146323	149222	151885
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	12	-11	-1
	बकाया	-25	-24	-14	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	20	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**34860**	**3941**	**4109**	**3626**	**3978**
	बकाया	**286863**	**274905**	**313511**	**317142**	**321027**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	17361	1923	1844	1332	1860
	बकाया	135348	129270	147320	148653	150513
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-3	-1	0	0	0
	बकाया	159	158	158	158	158
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-7911	-669	-82	67	-426
	बकाया	-6776	-5121	-8093	-8029	-8455
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25340	2677	2347	2227	2544
	बकाया	147942	140538	163948	166175	168720
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	41	8	0	0	0
	बकाया	-114	-147	-114	-114	-114
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	32	3	0	0	0
	बकाया	-74	-103	-74	-74	-74
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10378	10310	10366	10373	10279
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**13690**	**433**	**139**	**152**	**342**
	बकाया	**105228**	**94023**	**106510**	**106662**	**107004**

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

श्रेणी	2021				2022
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**7635902**	**7882533**	**8235318**	**8439811**	**8529036**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.77	35.99	37.82	35.40	37.75
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.27	0.34	0.35	0.27	0.29
3. बीमाकृत कंपनियां	25.30	25.83	24.18	25.74	25.89
4. म्यूच्युअल फंड	2.94	2.82	2.91	3.08	2.91
5. सहकारी बैंक	1.82	1.82	1.50	1.82	1.81
6. वित्तीय संस्थाएं	1.00	1.43	1.17	1.69	0.94
7. कॉरपोरेट	1.06	1.39	0.72	1.37	1.47
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	1.87	1.79	1.81	1.66	1.56
9. भविष्य निधियां	4.44	4.04	3.77	4.33	4.60
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	16.20	17.11	16.98	16.92	16.62
11. अन्य	7.33	7.43	8.79	7.73	6.15
11.1 राज्य सरकार	1.69	1.67	1.67	1.69	1.82

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

श्रेणी	2021				2022
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**3879982**	**4028849**	**4153508**	**4257578**	**4410250**
1. वाणिज्यिक बैंक	33.69	33.75	35.94	34.41	34.39
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.48	0.39	0.44	0.40	0.38
3. बीमाकृत कंपनियां	30.04	29.67	27.50	28.85	28.42
4. म्यूच्युअल फंड	1.82	1.74	1.97	1.91	1.82
5. सहकारी बैंक	4.05	4.12	3.60	4.07	4.04
6. वित्तीय संस्थाएं	1.86	1.79	1.72	1.73	1.72
7. कॉरपोरेट	0.49	1.45	1.32	1.70	1.82
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.00	21.09	18.27	20.66	20.79
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.77	0.88	0.85	0.83	0.80
11. अन्य	4.77	5.10	8.38	5.40	5.81
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20

खज़ाना बिल

श्रेणी	2021				2022
	मार्च	जून	सितं	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**690646**	**901327**	**763582**	**692869**	**757198**
1. वाणिज्यिक बैंक	55.54	52.25	50.22	47.01	51.14
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.82	1.82	1.33	1.53	4.20
3. बीमाकृत कंपनियां	5.61	4.75	4.12	6.29	6.58
4. म्यूच्युअल फंड	17.80	19.93	17.72	13.72	14.01
5. सहकारी बैंक	2.43	1.60	1.32	1.49	1.79
6. वित्तीय संस्थाएं	1.24	2.56	2.12	2.36	3.53
7. कॉरपोरेट	3.16	3.00	2.40	3.13	3.47
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.15	0.72	0.49
9. भविष्य निधियां	0.22	0.10	0.37	0.85	0.21
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.49	2.58	2.63	0.00	0.00
11. अन्य	10.70	11.42	17.62	22.89	14.59
11.1 राज्य सरकार	5.98	7.97	12.64	18.92	11.54

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**4265969**	**4515946**	**5040747**	**5410887**	**6523916**	**7160694**
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	**4288432**	**4528422**	**5023352**	**5734166**	**6489736**	**7039032**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1064704**	**997097**	**1102729**	**1449230**	**2634928**	**2277532**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*27.7*	*26.4*	*26.7*	*26.6*	*33.0*	*32.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*27.9*	*26.5*	*26.6*	*28.2*	*32.9*	*31.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*20.3*	*19.8*	*20.1*	*18.9*	*19.4*	*21.0*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*17.0*	*17.4*	*17.4*	*15.9*	*16.1*	*17.2*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.9*	*5.8*	*5.8*	*7.1*	*13.3*	*10.2*

…: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बज़ट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2022 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	700.85	17	1660.00	15	695.61	6
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	156.17	7	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	98.13	2	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	53.81	7	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	891.87	20	448.61	10
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	18.12	27	193.21	27	203.56	8
17	मेघालय	115.48	8	74.30	7	-	-
18	मिज़ोरम	53.26	10	39.98	5	-	-
19	नगालैंड	112.45	30	149.77	21	101.00	4
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	1067.81	17	-	-	-	-
23	राजस्थान	3125.64	30	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	710.06	30	1003.23	28	1200.67	7
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जून 2022 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9520	939	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2069	3	0	0
3	असम	3354	71	0	0
4	बिहार	6440	0	0	8000
5	छत्तीसगढ़	5682	0	1	4308
6	गोवा	745	368	0	0
7	गुजरात	8313	552	0	1000
8	हरियाणा	1392	1400	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
11	झारखंड	993	0	0	0
12	कर्नाटक	10562	0	0	16000
13	केरल	2468	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	1055	0	0
15	महाराष्ट्र	53649	1165	0	18000
16	मणिपुर	177	115	0	0
17	मेघालय	900	63	9	0
18	मिज़ोरम	448	54	0	0
19	नगालैंड	1892	38	0	0
20	उड़ीसा	15010	1681	97	44900
21	पुदुचेरी	387	0	0	923
22	पंजाब	4179	0	8	0
23	राजस्थान	0	0	129	8600
24	तमिलनाडु	7680	0	28	9012
25	तेलंगाना	6509	1417	0	0
26	त्रिपुरा	698	15	0	1600
27	उत्तराखंड	3073	0	180	0
28	उत्तरप्रदेश	3957	156	0	0
29	पश्चिम बंगाल	10351	718	235	0
	कुल	**160448**	**9812**	**686**	**112343**

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2021-22						2022-23 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
						अप्रैल		मई		जून			
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	50896	41915	46443	36692	4000	2695	7390	6810	10500	9630	21890	19135
2	अरुणाचल प्रदेश	767	767	563	530	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असम	15030	14230	12753	10753	-	-	-	-	2000	2000	2000	2000
4	बिहार	27285	24685	28489	24334	-	-	-	-750	-	-	-	-750
5	छत्तीसगढ़	13000	10500	4000	913	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	3354	3054	2000	1450	-	-	-	-	100	100	100	100
7	गुजरात	44780	33280	31054	13554	-	-	-	-3000	4000	2500	4000	-500
8	हरियाणा	30000	25550	30500	20683	-	-650	3000	1000	8000	5625	11000	5975
9	हिमाचल प्रदेश	6000	3755	4000	1875	-	-	-	-	-	-430	-	-430
10	जम्मू और कश्मीर	9328	6020	8562	5373	-	-	1000	1000	-	-	1000	1000
11	झारखंड	9400	8900	5000	3191	-	-	-	-	-	-200	-	-200
12	कर्नाटक	69000	61900	59000	49000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	केरल	28566	23066	27000	18120	-	-1000	-	-1000	1500	1500	1500	-500
14	मध्य प्रदेश	45573	38773	22000	13900	-	-	-	-	2000	2000	2000	2000
15	महाराष्ट्र	69000	50022	68750	40790	4000	4000	16000	13500	10000	3500	30000	21000
16	मणिपुर	1302	1044	1476	1326	-	-75	250	250	150	150	400	325
17	मेघालय	1777	1587	1608	1298	-	-	-	-	200	200	200	200
18	मिज़ोरम	944	677	747	447	-	-65	150	150	100	100	250	185
19	नगालैंड	1721	1366	1727	1222	-	-	-	-	400	400	400	400
20	उड़ीसा	3000	500	0	-6473	-	-1500	-	-	-	-1000	-	-2500
21	पुदुचेरी	1390	790	1374	841	-	-	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	32995	23467	25814	12428	1500	400	1500	800	-	-1742	3000	-542
23	राजस्थान	57359	44273	51149	38243	-	-	3500	3000	6500	3688	10000	6688
24	सिक्किम	1292	1292	1511	1471	-	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	87977	76796	87000	72500	-	-	-	-622	8000	6150	8000	5528
26	तेलंगाना	43784	37365	45716	38667	-	-945	-	-420	7000	6370	7000	5005
27	त्रिपुरा	1916	1631	300	0	-	-	-	-	-	-125	-	-125
28	उत्तराखंड	75500	59185	62500	42355	-	-	-	-1500	-	-2733	-	-4233
29	उत्तरप्रदेश	6200	5208	3200	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
30	पश्चिम बंगाल	59680	50180	67390	45199	-	-2500	2500	-	5000	4500	7500	2000
	कुल	798816	651777	701626	492483	9500	360	35290	19218	65450	42183	110240	61761

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि करोड़ में)

मद	2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**252658.0**	**513118.4**	**400437.3**	**446254.3**	**1612468.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.1*	*10.6*	*7.8*	*8.7*	*8.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**413192.2**	**604322.7**	**538186.1**	**843385.9**	**2399086.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.4*	*12.4*	*10.5*	*16.4*	*12.0*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	13020.4	299089.8	138131.8	473183.4	923425.5
(ए) बैंक जमाराशि	-9769.4	280588.7	130328.0	465529.7	866677.0
i. वाणिज्यिक बैंक	-13293.8	269475.4	66666.7	446006.7	768855.0
ii. सहकारी बैंक	3524.4	11113.2	63661.3	19523.0	97822.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22789.9	18501.2	7803.7	7653.7	56748.5
2. जीवन बीमा निधियाँ	117394.9	107731.0	109895.6	37236.1	372257.5
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	110601.0	113593.0	113676.0	117235.0	455104.9
4. मुद्रा	61244.1	-26104.8	86832.6	160690.2	282662.1
5. निवेश	43936.8	43018.8	22655.1	-11953.8	97656.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	23303.5	38382.2	19191.1	-19191.1	61685.7
(बी) इक्विटि	18648.2	2172.4	936.2	4981.0	26737.8
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	65930.8	65930.8	65930.8	65930.8	263723.4
II. वित्तीय देयताएँ	**160534.2**	**91204.3**	**137748.8**	**397131.6**	**786618.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.2*	*1.9*	*2.7*	*7.7*	*3.9*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	160500.7	91170.8	137715.2	397098.1	786484.7
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	141332.5	58250.2	121754.0	200413.2	521749.9
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	135754.1	57135.0	87377.4	202214.2	482480.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	19168.2	32920.5	15961.2	196684.8	264734.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-519.7	22976.7	29930.7	198264.3	250652.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	17033.0	8093.1	-15710.4	-3093.1	6322.6
iii. बीमा कंपनियाँ	2655.0	1850.8	1740.9	1513.6	7760.2
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-1.0

सं. 50 (ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(जारी..)*

(राशि करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**623053.8**	**592327.3**	**506558.3**	**581769.1**	**2303708.6**
जीडीपी का प्रतिशत	*16.1*	*12.5*	*9.3*	*10.1*	*11.6*
I. वित्तीय आस्तियां	**828447.4**	**630907.1**	**676131.6**	**973510.9**	**3108997.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*21.4*	*13.4*	*12.4*	*16.9*	*15.7*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	297376.2	278589.7	158113.5	533651.5	1267730.9
(ए) बैंक जमाराशि	281155.1	264523.3	147037.2	535157.5	1227873.0
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	471730.9	1156333.7
ii. सहकारी बैंक	2144.6	2489.6	3478.6	63426.6	71539.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	122369.1	141443.4	155516.3	100812.3	520141.0
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	121582.5	124106.5	124949.5	130185.5	500824.0
4. मुद्रा	202432.7	21286.9	91456.0	66800.5	381976.1
5. निवेश	6249.8	-12956.4	67659.3	63624.0	124576.7
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटि	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	77381.6	77381.6	77381.6	77381.6	309526.3
II. वित्तीय देयताएँ	**205393.5**	**38579.8**	**169573.3**	**391741.8**	**805288.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*5.3*	*0.8*	*3.1*	*6.8*	*4.1*
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	205436.7	38623.0	169616.5	391785.8	805462.1
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211005.3	13211.7	139387.5	304100.8	667705.3
जिसमें :					
वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	242476.0	607463.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	87685.1	137756.8
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	61326.1	83424.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1022.9	2556.6
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.0	134.4
3. सामान्य सरकार	-77.0	-77.0	-77.0	-77.0	-308.0

सं. 50(ए): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	2021-22	
	ति1	ति2
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**760273.0**	**388307.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*14.8*	*6.9*
I. वित्तीय आस्तियां	**631184.5**	**567403.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*12.3*	*10.1*
जिसमें:		
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	146933.8	207184.4
(ए) बैंक जमाराशि	124803.6	201833.5
i. वाणिज्यिक बैंक	123282.3	200159.7
ii. सहकारी बैंक	1521.3	1673.8
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22130.2	5350.9
2. जीवन बीमा निधियाँ	114617.8	127356.0
3. भविष्य और पेंशन फंड (पीपीएफ़ सहित)	129821.9	132967.9
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2
5. निवेश	24929.6	82305.4
जिसमें:		
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3
(बी) इक्विटि	4502.5	13218.5
6. छोटी बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	85163.8	85163.8
II. वित्तीय देयताएँ	**-129088.5**	**179095.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*-2.5*	*3.2*
ऋण (उधार)		
1. वित्तीय कार्पोरेशन (ए+बी)	-129109.8	179074.5
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	-105750.5	124240.8
जिसमें :		
वाणिज्यिक बैंक	-98583.4	126251.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-23359.3	54833.7
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-31118.4	28880.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8
2. गैर-वित्तीय कार्पोरेशन (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	33.8	33.8
3. सामान्य सरकार	-12.5	-12.5

टिप्पणी: 1. हाउसहोल्ड के लिए निवल वित्तीय बचत का संदर्भ निवल वित्तीय आस्तियों के प्रवाह से है, जो हाउसहोल्ड द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन से वित्तीय देयताओं में परिवर्तन को घटाने से प्राप्त होता है।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।
3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए

सं. 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2019	सितं-2019	दिसं-2019	मार्च-2020
वित्तीय आस्तियां (एं+बी+सी+डी)	**16130869.8**	**16439609.3**	**16829228.1**	**17002698.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*83.7*	*84.4*	*85.3*	*84.7*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	8831785.7	9111489.5	9239027.3	9688573.4
i. वाणिज्यिक बैंक	8131543.2	8401018.6	8467685.3	8913692.0
ii. सहकारी बैंक	700242.5	710470.8	771341.9	774881.4
(बी) जीवन बीमा निधि	3883609.7	3930727.6	4049902.5	3884771.5
(सी) मुद्रा	2010842.9	1984738.1	2071570.7	2232261.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1404631.5	1412654.1	1468727.6	1197092.9
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**6490282.2**	**6581453.0**	**6719168.2**	**7116266.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*33.7*	*33.8*	*34.0*	*35.4*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5268304.7	5326554.9	5448308.9	5648722.1
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	4668496.4	4725631.3	4813008.7	5015222.9
ii. सहकारी बैंक	513013.7	513764.2	542994.4	529720.6
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1221977.5	1254898.1	1270859.3	1467544.1
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	451922.3	474899.0	504829.7	703094.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673312.1	681405.2	665694.8	662601.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(जारी.)*

(राशि करोड़ में)

मद	जुला.-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**17850174.9**	**18408441.6**	**19129606.6**	**19979862.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*93.9*	*97.6*	*99.7*	*100.9*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	9969728.5	10234251.8	10381289.0	10916446.4
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10070025.7
ii. सहकारी बैंक	777026.0	779515.6	782994.2	846420.7
(बी) जीवन बीमा निधि	4102000.7	4274424.9	4551882.0	4718718.2
(सी) मुद्रा	2434693.7	2455980.6	2547436.6	2614237.0
(डी) म्यूचुअल फंड	1343752.0	1443784.4	1648999.0	1730461.0
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7321703.0**	**7360326.0**	**7529942.6**	**7921728.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*38.5*	*39.0*	*39.3*	*40.0*
ऋण (उधार)				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	5859727.5	5872939.2	6012326.7	6316427.4
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5622686.4
ii. सहकारी बैंक	558551.1	558545.6	557545.8	608703.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1461975.5	1487386.9	1517615.9	1605301.0
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	786518.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक *(समाप्त)*

(राशि करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी)	**20533386.0**	**21086975.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*97.4*	*98.1*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	11041250.0	11243083.5
i. वाणिज्यिक बैंक	10193308.0	10393467.7
ii. सहकारी बैंक	847942.1	849615.9
(बी) जीवन बीमा निधि	4894238.5	5105262.1
(सी) मुद्रा	2742897.3	2674266.1
(डी) म्यूचुअल फंड	1855000.1	2064363.5
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**7793017.9**	**7972092.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*37.0*	*37.1*
ऋण (उधार)		
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	6210676.9	6334917.7
जिसमें:		
i. वाणिज्यिक बैंक	5524103.0	5650354.1
ii. सहकारी बैंक	596687.9	603180.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	1582341.0	1637174.6
जिसमें:		
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755399.6	784279.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7

टिप्पणी: 1. डेटा को केवल चुनिंदा वित्तीय लिखतों के लिए संकलित किया गया है(बैंकिंग क्षेत्र, एनबीएफ़सी और एचएफ़सी से ऋण) जिसके लिए डेटा उपलब्ध है।

2. जीडीपी अनुपात के रूप में डेटा की गणना 28 फरवरी 2022 को जारी राष्ट्रीय आय 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।

3. हो सकता है कि कॉलम में दिए गए अंकों को पूर्णांकन के कारण कुल योग में न जोड़ा जाए।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थांओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकडें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओं/शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -
- बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।
- जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए है, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिकिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया हैं।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिकिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत
कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बज़ट 2020-21 से लिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा https://dbie.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2022	₹350 एक प्रति (कांउटर पर) ₹400 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,800 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,600 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,840 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,880 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2021-22 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. Report on Currency and Finance 2021-22	₹575 per copy (over the counter) ₹625 per copy (inclusive of postal charges)	US$ 22 per copy (inclusive of air mail courier charges)
6. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (कांउटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8 अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 42, सं. 1, 2021	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in) ।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक सस्थांओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का सपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मंबुई - 400 001।

   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम.......... अभिदाता सं...........

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' **2 महीने के अंदर भेजी जाए।**
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**